देशबन्धु

{ संपादकीय }

नई दिल्ली, शुक्रवार 17 मई 2024

संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

मोदी की हिन्दू-मुस्लिम से तौबा का यथार्थ

भारत में पिछले 10 वर्षों के दौरान एक ऐसा मीडिया विकसित हुआ है जिसका प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से घरोबा जैसा है। यह कोई नवनिर्मित मीडिया नहीं है वरन विद्यमान मीडिया का ही बड़ा हिस्सा है जिसने अपने आप को मोदीमय कर लिया है। मोदी का वह समर्थक है सो वह भारतीय जनता पार्टी के हर काम-काज की तारीफ करता है। मोदी के मित्र उसके भी मित्र हैं और मोदी के दुश्मन उसके भी दुश्मन बन जाते हैं। मोदी के कहे को तर्कसंगत साबित करने से लेकर उनके हर फैसले को 'मास्टरस्ट्रोक' बतलाने वाला यह मीडिया कहने को स्वतंत्र है पर वह चलता है मोदी एवं उनकी पार्टी की विचारधारा के अनुरूप। देश के कुछ बड़े कारोबारी घरानों की मिल्कियत वाले इन मीडिया घरानों ने, जिनमें प्रकाशन वाला मीडिया है तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी- अपने उच्च शिक्षित व मोटी तनख्वाह वाले पत्रकारों को पिछले दशक भर से एक ही काम में लगा रखा है, वह है भाजपा की सरकार को बनाये रखना।

इनमें से कुछ पत्रकार बेहद मुंहलगे हैं जो भाजपा प्रवक्ताओं जैसे काम करते हैं। मोदी को जो कहना होता है, वे उनमें से कुछ को अपने साथ लेते हैं और कोई नयी बात करते हैं। इन बातों को प्रकाशित सामग्री के रूप में या स्टूडियो के जरिये लोगों तक पहुंचाया जाता है। इन्हीं पत्रकारों के जरिये लोगों को कभी पता चलता है कि मोदी ने कोई शिक्षा हासिल नहीं की है, तो वे ही जनता तक यह बात पहुंचाते हैं कि मोदी ने 35 साल भिक्षावृत्ति की है। उन्हीं के जरिये देश जान सका है कि मोदी जी ने कई वर्षों तक हिमालय में तपस्या की है। कुछ मोदी से सुनी तो कुछ अपनी कल्पना शक्ति के बल पर यह मीडिया दो हजार के नोट में चिप लगाता है तो गोबर में हीरा खोजता फिरता है। वैसे तो मोदी पत्रकारों से बहुत कम बात करते हैं। उनकी एक अदद प्रेस कांफ्रेंस के लिये पूरा देश 10 बरस से तरस रहा है। 'मन की बात' या जनता से बहुत दूर व सुरक्षित ऊंचाई पर बने मंचों से एकालाप के जरिये अपनी बात कहने के आदी हैं पीएम।

वाराणसी से लोकसभा के लिये तीसरी बार अपना नामांकन भरने के बाद पतित पावनी गंगा मैया के तटों पर विचरण करते हुए मोदी ने यकायक सेक्यूलर चोला ओढ़ लिया। उन्होंने मीडिया वाली से कहा- 'जिस दिन मैं हिन्दू-मुस्लिम करने लगूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रह जाऊंगा।' उनका यह बयान सभी लोगों, खासकर उनके अपने पार्टी कार्यकर्ताओं व समर्थकों के लिये आश्चर्य और सदमे की तरह रहा होगा, लेकिन उक्त पत्रकार ने उनके इस बयान को बिग ब्रेकिंग के रूप में प्रसारित कर नाम तो कमा लिया, लेकिन पत्रकार-धर्म को पूरी तरह से गंगा में विसर्जित करते हुए। प्रेस कांफ्रेंस में तो किसी भी पत्रकार को ज्यादा सवाल करने का अवसर अक्सर नहीं मिलता पर ऐसे एक्सक्लूज़िव साक्षात्कारों में न सवालों की सीमा होती है, न समय की बंदिश। फिर उपरोक्त महिला पत्रकार ने क्यों मोदी से यह नहीं कहा कि, 'मोदी जी, हाल ही में आपने तो कांग्रेस के न्यायपत्र पर 'मुसलिम लीग की छाया' बतलाया था और आपने लोगों से यह भी कहा था कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो आपके मंगलसूत्र छीनकर 'कई बच्चों वालों' को दे देगी,' या यह भी नहीं पूछा कि, 'मोदी जी, कांग्रेस का तो देश में पिछले 55 वर्षों तक राज रहा। उसने ऐसा तो कभी भी नहीं किया।' पत्रकार को मोदी जी के स्मरण में यह भी लाना था कि आप खुद कहते रहे हैं कि 'मैं कपड़े देखकर जान जाता हूं।' मोदी को वह सारा कुछ ध्यान दिलाना था कि कैसे 10 साल उन्होंने हिन्दू-मुसलिम और भारत-पाकिस्तान करते हुए गुजार दिये।

खैर, मोदी से जितने लोगों ने हाल के वर्षों में साक्षात्कार किये हैं, उन्हें ध्यान से देखा जाये तो इस आरोप में दम दिखता है कि सवाल भी पहले से तय होते हैं और जवाब भी। तभी तो किसी भी प्रकाशित या प्रसारित इंटरव्यू में ऐसे कोई सवाल नहीं होते जो मोदी या भाजपा को असहज करते हों। न उनमें नोटबन्दी समेत मोदी सरकार की तमाम असफल योजनाओं का जिक्र होता है, न ही मणिपुर का। न महिला पहलवानों के साथ होती ज्यादतियों का और न ही आदिवासी के सिर पर पेशाब करते भाजपा कार्यकर्ता का। न भ्रष्टाचारी कहे जाने वाले विरोधियों के भाजपा प्रवेश का और न ही इलेक्टोरल बॉन्डस का।

खैर, होगा भी नहीं। मोदी ने जो दावा किया था कि हिन्दू-मुस्लिम करने पर वे सार्वजनिक जीवन के योग्य नहीं रह जाते, वह (दावा) ज्यादा देर तक जिंदा न रह सका। अगली ही सुबह (बुधवार को) महाराष्ट्र के डिंडौरी की आम सभा में मोदी ने बयान दिया कि 'अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो वह सरकार के पूरे बजट का 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों को दे देगी।' फिर, उसी दिन मुंबई की सभाओं में उन्होंने राममंदिर का जिक्र किया और कहा कि शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे जीवित होते तो बहुत दुखी होते क्योंकि 'नकली शिवसेना' (उद्धव ठाकरे गुट) ने राममंदिर में प्राणप्रतिष्ठा का विरोध किया था जबकि बाल ठाकरे का सपना मंदिर निर्माण का था। सवाल है कि क्या मोदी व भाजपा का चुनावी विमर्श हिन्दू-मुस्लिम किये बिना सम्भव है? उत्तर है- नहीं, क्योंकि पिछले 100 वर्षों से भाजपा की मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वैचारिक आधार धार्मिक विभाजन ही तो है। मोदी ने इससे तौबा कर ली तो उन्हें हटाने में न भाजपा-संघ देर करेगा न समर्थक-कार्यकर्ता।

मोदी के चुनाव भाषण : झूठ और ज़हर का सैलाब

भाजपा की प्रचार मशीनरी काफी मजबूत है और पार्टी का पितृ संगठन आरएसएस इस मशीनरी की पहुंच को और व्यापक बनाता है। आरएसएस-भाजपा के प्रचार अभियान का मूल आधार हमेशा से मध्यकालीन इतिहास को तोड़मरोड़ कर मुसलमानों का दानवीकरण और जातिगत व लैंगिक पदक्रम पर आधारित प्राचीन भारत की सभ्यता और संस्कृति का महिमामंडन रहा है। संघ परिवार समय-समय पर अलग-अलग थीमों का प्रयोग करता आया है। एक थीम यह है कि मुस्लिम राजाओं ने हिन्दू मंदिरों को तोड़ा। राममंदिर आन्दोलन का मूल सन्देश यही था। फिर देश की सुरक्षा भी एक प्रमुख थीम है, जिसमें पाकिस्तान को भारत का दुश्मन बताया जाता है। बाबरी मस्जिद को ढहाए जाने के पहले वे अन्य मुस्लिम-विरोधी थीमों के अतिरिक्त, मुसलमानों के भारतीयकरण की बात भी किया करते थे।

पिछले एक दशक में उन्होंने 'अच्छे दिन' की बात की और कई दूसरे जुमले भी उछाले, जैसे महिलाओं की सुरक्षा, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख आएंगे और हर साल दो करोड़ लोगों को रोज़गार मिलेगा। कांग्रेस को भ्रष्ट पार्टी सिद्ध करने का प्रयास भी किया गया। आरएसएस से जुड़े संगठनों के समर्थन और उनके तत्वावधान में अन्ना आन्दोलन चलाया गया जिससे कई सालों तक लोगों के दिमाग में यह बैठा रहा कि कांग्रेस भ्रष्ट नेताओं की पार्टी है। फिर 2019 के चुनाव में पुलवामा-बालाकोट को मुद्दा बनाया गया और हमें बताया गया कि केवल भाजपा की सरकार ही देश की रक्षा कर सकती है। हालांकि इस पूरी अवधि में मुस्लिम-विरोधी प्रचार भी जारी रहा। कहने की ज़रुरत नहीं कि आरएसएस-भाजपा के प्रचारक सत्य और तथ्यों को बहुत महत्व नहीं देते।

इस (2024) के चुनाव में उम्मीद यह थी कि अयोध्या का राममंदिर भाजपा की नैया को किनारे लगा देगा। ज्ञानवापी का मुद्दा भी था। मगर जल्दी ही यह साफ़ हो गया कि राममंदिर-ज्ञानवापी जैसे मुद्दों से जनता थक चुकी है और उनका कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। लोगों को अपनी गिरती सामाजिक-आर्थिक स्थिति की चिंता ज्यादा है और भव्य राममंदिर की कम। इसके बाद भाजपा-आरएसएस ने अपने पुरानी तरकीब एक बार फिर अपनाने का निर्णय किया। वह तरकीब है मुसलमानों की खिलाफत और समाज को धार्मिक आधार पर बांटना।

श्री मोदी ने मुसलमानों को अपना चुनावी मुद्दा बना लिया और इसके लिए समाज के कमज़ोर वर्गों (आदिवासी, दलित और धार्मिक अल्पसंख्यकों) के साथ न्याय, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोज़गार और इंटर्नशिप आदि का वायदा करने वाले कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र का इस्तेमाल किया।

आरएसएस और उससे जुड़े संगठन, समाज के कमज़ोर वर्गों के साथ न्याय के पुराने विरोधी रहे हैं। सन् 1925 में आरएसएस की स्थापना ही इसलिए हुई थी क्योंकि दलित अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने लगे थे और महिलाओं की समाज में सक्रियता और हिस्सेदारी बढ़ने लगी थी। भाजपा को यह अहसास हो गया कि आरक्षण और सकारात्मक भेदभाव की नीतियों पर राहुल गांधी के जोर देने का जनता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अब भाजपा खुल कर तो यह कह नहीं सकती थी कि वह आरक्षण की विरोधी है साथ ही, उसे राहुल गांधी के बढ़ते ग्राफ से भी निपटना था। इस दिशा में पहला कदम था संघ के मुखिया की यह गलतबयानी कि आरएसएस कभी आरक्षण का विरोधी नहीं रहा है।

राम पुनियानी

> इस (2024) के चुनाव में उम्मीद यह थी कि अयोध्या का राममंदिर भाजपा की नैया को किनारे लगा देगा। ज्ञानवापी का मुद्दा भी था। मगर जल्दी ही यह साफ़ हो गया कि राममंदिर-ज्ञानवापी जैसे मुद्दों से जनता थक चुकी है और उनका कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। लोगों को अपनी गिरती सामाजिक-आर्थिक स्थिति की चिंता ज्यादा है और भव्य राममंदिर की कम।

दूसरी ओर मोदी नई खिचड़ी पका रहे हैं। वे कह रहे हैं, '...कांग्रेस दलितों और पिछड़ों के लिए निर्धारित कोटा को घटा कर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है, जो संविधान के खिलाफ है। बाबा साहेब ने आरक्षण का जो अधिकार दलितों, पिछड़े वर्गों और आदिवासियों को दिया था, उसे कांग्रेस और इंडी गठबंधन धर्म के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते हैं।'

मोदी ने कांग्रेस के घोषणापत्र में जाति जनगणना की बात और उसे समाज का एक्सरे बताए जाने का उपयोग भी अपने मुस्लिम-विरोधी प्रचार में किया। उन्होंने झूठ बोलने के नए रिकॉर्ड कायम करते हुए कहा कि कांग्रेस एक्सरे कर यह पता लगाएगी कि किस हिन्दू के पास सोना और धन है और फिर उसे घुसपैठियों (जो भाजपा का मुसलमानों के लिए प्रयुक्त किया जाने वाले शब्द है) में बांट देगी। हिन्दुओं और विशेषकर हिन्दू महिलाओं को डराने के लिए उन्होंने कहा, 'मेरी माताओं और बहनों, वे आपके मंगलसूत्र भी नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस के घोषणापत्र में कहा गया है कि अगर उनकी सरकार बनती है, तो देश के हर व्यक्ति की संपत्ति का सर्वेक्षण किया जायेगा। यह पता लगाया जाएगा कि हमारी बहनों के पास कितना सोना है और सरकारी कर्मचारियों की कितनी संपत्ति है...उन्होंने यह भी कहा है कि हमारी बहनों के पास जो सोना है, उसे सब लोगों में बराबर-बराबर बांटा जाएगा। क्या सरकार को आपकी सम्पति आपसे छीनने का हक़ है?' उन्होंने कहा कि 'हिन्दू महिलाओं का मंगलसूत्र छीन कर मुसलमानों को दे दिया जाएगा।'

यह सब कहकर वे एक तीर से कई निशाने लगाने का प्रयास कर रहे हैं। पहला, कांग्रेस के घोषणापत्र की आलोचना, दूसरा, मुसलमानों पर निशाना साधना और तीसरा, हिन्दू महिलाओं को डराना। आखिर कोई कितना झूठ बोल सकता है। उन्हें यह भरोसा है कि बड़ी संख्या में लोग उनके झूठ के पुलिंदे पर विश्वास कर लेंगे. वे जानते हैं कि संघ परिवार के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता, उसका आईटी सेल और कॉर्पोरेट घरानों द्वारा नियंत्रित टीवी चैनल और अखबार यह सुनिश्चित करेंगे कि इस सफ़ेद झूठ को आमजनों का एक बड़ा तबका गंभीरता से ले। यहां तक कि उन्होंने बेचारी भैंस, जिसे भाजपा के गौमाता-केन्द्रित नैरेटिव में कभी जगह नहीं मिली, को भी अपने प्रचार में घसीट लिया। 'अगर आपके पास दो भैंसे होंगीं, तो कांग्रेस उनमें से एक को आपके बाड़े से खोल ले जाएगी'।

और फिर भला यह कैसे संभव है कि भाजपा-मोदी के चुनाव अभियान में पाकिस्तान की चर्चा न हो। मोदीजी ने फ़रमाया कि पाकिस्तान चाहता है कि भारत में कमज़ोर सरकार बने। फहाद चौधरी नामक एक सज्जन, जो पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हैं, ने कहा था कि राहुल गांधी समाजवादी नीतियों की बात कर रहे हैं। मोदी का कहना है कि पाकिस्तान चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनें ताकि बालाकोट जैसे ऑपरेशन न हों। मोदीजी शायद भूल गए हैं कि राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने बांग्लादेश को स्वतंत्र करवाकर, पाकिस्तान को दो भागों में बांटने का साहसिक निर्णय लिया था- और वह भी पश्चिम के शक्तिशाली देशों की इच्छा के खिलाफ।

अब मुगलों को भी लाना था। इसके लिए मोदी ने तेजस्वी यादव के एक ट्वीट का उपयोग किया, जिसमें वे नवरात्रि के एक दिन पहले मछली खाते हुए दिख रहे हैं। मोदी ने कहा कि तेजस्वी नवरात्रि के पवित्र पर्व के दौरान मछली खाकर हिन्दुओं को उसी तरह अपमानित कर रहे हैं जिस तरह मुग़ल राजा, मंदिरों को गिरा कर किया करते थे। एक विपक्षी नेता की मामूली सी तस्वीर को मुगलों और वर्तमान मुसलमानों से जोड़ कर मोदी जी ने यह दिखा दिया है कि वे किसी भी चीज़ का उपयोग मुसलमानों और विपक्ष के नेताओं के दानवीकरण के लिए कर सकते हैं।

सचमुच, मोदी जी अद्भुत प्रतिभा के धनी है. वे जहां धुआं न भी हो, वहां आग पैदा करने में सक्षम हैं।

(अंग्रेजी से रूपांतरण अमरीश हरदेनिया।)

भारत के हथियार उद्योग में उछाल, निर्मित हो रहा है बड़ा बाजार

■ नन्तू बनर्जी

भारत का रक्षा विनिर्माण उद्योग तेजी से देश की अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उभर रहा है और चुपचाप नवीनतम शेयर बाजार में एक उछाल ला रहा है। रक्षा निर्माताओं के लिए इतना अच्छा समय पहले कभी नहीं था। निजी क्षेत्र के रक्षा विनिर्माण उद्यम भी पारंपरिक सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक हथियार निर्माताओं की तरह बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के 10 रक्षा शेयरों में पिछले एक साल में 446 फीसदी तक का उछाल आया है। शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में हैं : एचएएल, मझगांवडॉक, भारत फोर्ज, भारत डायनेमिक्स, पारस डिफेंस एंड स्पेस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आइडियाफोर्ज, एमटीएआर टेक्नालॉजीज, डेटापैटर्न, सोलर इंडस्ट्रीज, गोवा शिपयार्ड और तनेजा एयरोस्पेस।

एसीईइक्विटी डेटाबेस के अनुसार, निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स ने 12 महीने की अवधि में 142प्रतिशत की बढ़ोतरी की है, जो बेंचमार्क निफ्टी 50 से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, जिसने इसी अवधि में 26प्रतिशत रिटर्न दिया है। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स के कुल 15 शेयरों में से 14 ने निवेशकों को सकारात्मक रिटर्न दिया है। वहीं, 10 शेयरों में 100 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई। देश के आयुध विनिर्माण बाजार का आकार 2024 में 17.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। इसके 2029 तक 23.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत की हथियारों की मांग उनकी घरेलू आपूर्ति से कहीं अधिक है क्योंकि देश दुनिया का शीर्ष रक्षा उत्पाद आयातक बना हुआ है। ऐसा तब तक बने रहने की संभावना है जब तक घरेलू रक्षा उद्योग अमेरिका, रूस, चीन, यूके, जर्मनी, फ्रांस और इज़राइल जैसे दुनिया के शीर्ष हथियार विनिर्माण देशों में से कुछ के बराबर नहीं हो जाता।

> भूमि, समुद्र और एयरोस्पेस सहित भारत की सीमाओं पर सुरक्षा परिदृश्य और क्षेत्र में देश के मुख्य सैन्य आलोचक चीन के बढ़ते रणनीतिक विस्तार को ध्यान में रखते हुए, आने वाले वर्षों में इसके रक्षा बजट में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है। घरेलू रक्षा निर्माताओं को सशस्त्र बलों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए मजबूती से कमर कसने की जरूरत है। हालांकि, घातक हथियार बनाने की उच्च-स्तरीय प्रौद्योगिकियां आसानी से उपलब्ध नहीं हैं।

अब तक भारत का सैन्य बजट अपनी सेना को खिलाने के लिए काफी छोटा रहा है, जो चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। कागज पर भारत का रक्षा बजट अमेरिका (832 अरब डॉलर), चीन (227 अरब डॉलर) और रूस (109 अरब डॉलर) की तुलना में 74 अरब डॉलर के साथ चौथा सबसे बड़ा है। वास्तव में, भारत का अधिकांश रक्षा बजट सैन्य कर्मियों के वेतन और पेंशन पर खर्च किया जाता है। विडंबना यह है कि 1.4 अरब नागरिकों के साथ दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत का वार्षिक रक्षा खर्च सऊदी अरब के 72 अरब डॉलर के सैन्य बजट के करीब है। सऊदी अरब की कुल जनसंख्या 37 मिलियन से भी कम है।

भूमि, समुद्र और एयरोस्पेस सहित भारत की सीमाओं पर सुरक्षा परिदृश्य और क्षेत्र में देश के मुख्य सैन्य आलोचक चीन के बढ़ते रणनीतिक विस्तार को ध्यान में रखते हुए, आने वाले वर्षों में इसके रक्षा बजट में काफी वृद्धि होने की उम्मीद है। घरेलू रक्षा निर्माताओं को सशस्त्र बलों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए मजबूती से कमर कसने की जरूरत है। हालांकि, घातक हथियार बनाने की उच्च-स्तरीय प्रौद्योगिकियां आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) को हथियार निर्माताओं को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी।

अमेरिका समर्थित यूक्रेन-रूस युद्ध, इज़राइल-हमास लड़ाई, उत्तर कोरिया की वाशिंगटन विरोधी और सियोल विरोधी बयानबाजी और प्रशांत और भारत-प्रशांत क्षेत्रों और इसके बेल्ट के तहत अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों में चीन के लगातार सैन्य विस्तार आदि के परिणाम स्वरूप मांग और बढ़ेगी। सामरिक सड़क निर्माण की पहल और विश्व शांति और सुरक्षा के विवादास्पद मुद्दों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र की कमजोर स्थिति, आने वाले वर्षों में हथियारों और आपूर्ति की वैश्विक मांगों में भारी वृद्धि कर सकता है।

ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया में पीछे हटने की होड़ से अगले दशक में अकेले 7 देशों को करीब 10ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। इसकी सूचीबद्ध सुरक्षा चुनौतियों में रूस, अस्थिर पश्चिम एशिया और चीनी सेना द्वारा प्रशांत क्षेत्र की ओर अमेरिका का ध्यान आकर्षित करना शामिल है। इसमें कहा गया है कि वैश्विक पुनरुद्धार का एक नया युग भारी लागत पर गति पकड़ रहा है और पहले से ही अस्थिर सार्वजनिक वित्त से जूझ रही पश्चिमी सरकारों द्वारा कुछ कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। विश्व रक्षा खर्च पिछले साल रिकॉर्ड 2.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया।

क्या भारत वैश्विक सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज कर सकता है और चीनी सैन्य आक्रामकता को रोकने के लिए उन्नत हथियारों की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयात करके खुश रहना जारी रख सकता है? दिलचस्प बात यह है कि चीन ने पिछले पांच वर्षों में अपने हथियारों के आयात में कटौती की है। चीन ने विदेशी निर्मित हथियारों के स्थान पर अपनी 'स्वयं' तकनीक से निर्मित हथियारों का इस्तेमाल किया। चीनी निर्माता अमेरिकी सैन्य बुनियादी ढांचे में गहराई से जुड़े हुए हैं। फ्रांस उन्नत चिप प्रौद्योगिकी की चीन और रूस में संदिग्ध तस्करी की जांच कर रहा है।

चीन की विदेशी हथियारों की खरीद में अभी भी रूस का बड़ा योगदान है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के अनुसार, 2019-23 में चीन के हथियारों के आयात में पिछले पांच वर्षों की तुलना में 44 प्रतिशत की गिरावट आई, जिससे वह विदेशी हथियारों के दुनिया के सबसे बड़े खरीदारों की सूची में 10वें स्थान पर आ गया। रूस ने चीन की सैन्य खरीद का 77 प्रतिशत आपूर्ति की, जिसमें विमान के इंजन और हेलीकॉप्टर सिस्टम शामिल हैं। इसके बाद 13 प्रतिशत के साथ फ्रांस का स्थान है, जबकि भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक बना हुआ है।

भारतीय निवेशक देश के हथियार निर्माण उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं। घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार और उसके डीआरडीओ को मिलकर काम करने की जरूरत है। देश ने अपनी मिसाइल प्रणाली बनाने में काफी अच्छा काम किया है। स्वदेशी रूप से विकसित बख्तरबंद वाहन, सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस, वायु रक्षा प्रणाली आकाश, चौथी पीढ़ी के लड़ाकूविमान एलसीए तेजस उन भारतीय हथियार प्रणालियों में से हैं, जिन्होंने कई विदेशी खरीदारों की रुचि को आकर्षित किया है।

भारत को एक मजबूत और जीवंत रक्षा विनिर्माण उद्योग का निर्माण करके हथियारों के आयात में भारी कटौती करने के लिए और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। नतीजतन, भारत में रक्षा शेयरों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जायेगी, जिससे आने वाले वर्षों में उनके स्टॉक की कीमतों में वृद्धि होगी। रक्षा उद्योग की प्रकृति उच्च लागत वाली मशीनरी और अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं में पर्याप्त अग्रिम निवेश की मांग करती है, जिसके लिए भारी पूंजी की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि बड़े-बड़े औद्योगिक घराने विशिष्ट उत्पाद फोकस वाली अलग-अलग कंपनियों को बढ़ावा देकर रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में प्रवेश करें। बाजार ऐसे उद्यमों को गोद लेने के लिए तैयार है।

पावन प्रसंग

अनेक उलझनों से बचाता है वाकसंयम

अर्थपूर्ण वाणी बोल पाना मानव की उपलब्धि है। इस उपलब्धि का सदुपयोग होना चाहिये। विचार सम्प्रेषण मानव जीवन की अपरिहार्य प्रवृति है। वाणी विचार संप्रेषण प्रक्रिया को सार्थकता प्रदान कर देती है अत: जीवन में वाणी उच्चारण का बहुत महत्व है। मानव की वाणी अमृत वर्षा की तरह सुखद और आनन्द पूर्ण हो सकती है तो विष वर्षा की तरह कष्ट प्रद भी हो सकती है। मानव की वाणी के अनेक है, सत्य असत्य मिश्र स्पष्ट अस्पष्ट व्यंग्य कठोर कोमल आक्षेप पूर्ण, निरर्थक आदि अनेक तरह से वचन प्रयोग होते हैं। सबसे बड़ी विशेषता वचन प्रयोग की यह है कि उससे न केवल वचन प्रयोक्ता प्रभावित होता है अपितु श्रोता भी उस से अवश्य प्रभावित होता है। अत: वचन का प्रभाव बहुत व्यापक है। यही बात ध्यान में लेकर हमारे तत्वज्ञों ने वाकसंयम के अनेक संदेश उपदेश दिये हैं। मौन रह जाने को हमारे यहां व्रत का दर्जा दिया गया है। बहुत कम बोलने और उपयोगी बोलने की शिक्षा सभी महापुरुषों ने दी है। हम जो कुछ बोले उसे अपने मस्तिष्क की तुला पर तोल कर बोले त्वरित ही न बोल जाएं कि बाद में पश्चाताप करना पड़े। मानव के पास जितनी उलझने हैं उनमें अनेक उलझनें ऐसी जो गलत समय पर गलत बोल देने से पैदा हुई है। सही समय पर उचित और योग्य भाषा का प्रयोग किया जाए जो कोई कठिनाई पैदा हो, यह संभव ही नहीं है। एक बात यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि सारे विषय अपने बोलने के नहीं होते अनावश्यक प्रत्येक विषय में कुछ न कुछ बोल ही देना महत्व हीन तो होता ही है अनेक कठिनाइयां भी पैदा कर देता है। द्रौपदी के द्वारा दुर्योधनों को अन्धा कह देना दु:खद ही रहा। वाणी मानव की स्वाधीन विशेषता है, इस पर किसी का बन्धन नहीं होता वह चाहे तो अपनी वाणी को अमृत का स्वरूप प्रदान करे और वह चाहे तो वाणी से ही विष घोल दे। इसलिये वाणी के संयम के लिये व्यक्ति को स्वयं ही प्रशिक्षित होना पड़ेगा। बोलना कैसे? यह कोई और नहीं बता सकता। स्वयं को ही निर्णय करना होता है कि वह क्या बोले और कैसे बोले? राजनीति के रंगमंच में अभिव्यक्ति की आजादी के आड़ में चुभनभरी वाणी बोली जा रही है। उसके लिए निंदा के पात्र बनते है। जनता में संदेश भी गलत जाता है इसलिए सोचकर बोलना हितकर होगा।

कान्तिलाल मांडोत

आपके पत्र

समृद्ध नैतिकता आधारित शिक्षा नीति की जरुरत

हर राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा का अति महत्वपूर्ण किरदार होता है। जिस राष्ट्र में शिक्षा, संस्कृति जितनी गहरी और समृद्ध हो वह राष्ट्र उतना ही विकसित, पुष्पित, पल्लवित होता है। इसके साथ आर्थिक तथा वैज्ञानिक सोच भी अत्यंत विचारणीय है। हर देश में राष्ट्र के प्रति और राष्ट्रहित के प्रति चिंतन करने वालों का समूह होना चाहिए, जो प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक तथा राष्ट्रहित के विचारों और विकास के मूल मंत्र को नई ऊर्जा और आगे बढ़ने की सच्चाई को इंगित कर सकें। बिना संस्कृति, संस्कार और वैचारिक क्षमता के बिना कोई भी राष्ट्र वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय प्रगति करने की सोच भी नहीं सकता। वैचारिक और सैद्धांतिक अंतरधारा, सिद्धांतों को कुचला या नष्ट नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत वैचारिक अभिव्यक्ति भारत के संदर्भ में गणतंत्र की मूल आत्मा है।

विचार और सिद्धांत व्यक्ति की अंत:प्रज्ञा होती है। यह सिद्धांत तथा अंत: विचारधारा जनमानस तक पहुंचने से बाधित किया जाए तो अंतरात्मा को प्रभावित करती है। इसके गहरे प्रभाव से व्यक्ति वह सब कर सकता है, जो बिना मार्गदर्शन के व्यक्ति नहीं कर सकता। प्राचीन काल से अब तक मनीषियों के वैचारिक सिद्धांत और विचारधारा सदैव समाज के दिग्दर्शक मार्गदर्शक रहे हैं। इनकी भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रही है। यदि यही सिद्धांत और अंत: प्रज्ञा जनमानस आत्मसात कर लेता है, तो इसका प्रभाव एक जन आंदोलन का रूप ले लेता है और यहीं से युग परिवर्तन की लहर उत्पादित होती है। प्राचीन यूनान में एक बहुत ही कुरूप किंतु विद्वान व्यक्ति रहते थे, उनके विचारों में मौलिकता, नयापन जनजागृति की अद्भुत क्षमता थी। उनकी विद्वता के कारण आम जनमानस होने राजा से ज्यादा महत्व और बुद्धिमान मानते थे। राजकीय तानाशाही के चलते उनके विचारों के कारण उनको मृत्युदंड दे दिया गया। जहर का प्याला पीने के बाद भी विद्वान, चिंतक, सुकरात अमर हो गए, उनकी विचारधारा आज भी जीवित है, एवं लोग उसे अपनाकर अपना जीवन सुधारने में इसका उपयोग करते हैं। अब्राहम लिंकन के आंदोलनकारी विचार से तत्कालीन समय में अमेरिका के लोग घबरा गए थे, और उनकी हत्या कर दी गई थी। पर अब्राहम लिंकन के विचारों ने दास प्रथा के उन्मूलन की अंतर आत्मा को जागृत कर दिया था, और जनमानस ने अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए दास प्रथा से मुक्ति पाई थी।

स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। विचार एवं सिद्धांत ही व्यक्ति का निर्माण करता है। वही दुष्ट होने या महान होने का निर्णायक है और बिना विचार व्यक्त व्यक्ति का अस्तित्व ही नहीं। विवेकानंद जी के विचार सर्वकालीन प्रासंगिक है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने उनके जीवित रहते हुए थे। आज हमारे बीच विवेकानंद जी सशरीर मौजूद नहीं है, पर उनके विचारों की महत्ता कायम है। भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने से और भौतिक विचार तथा सिद्धांत उतनी ही तीव्रता रखते हैं, जो एक समाज में परिवर्तन ला सकती है। विचारों की यह अमरता तथा तीव्रता किसी भी तानाशाह के लिए इतनी खतरनाक है, जितनी कि सुप्त शेर की गुफा में रहना। जनता के मध्य शुद्ध विचारधारा के जागृत होने पर क्रांति लाई जा सकती है।

संजीव ठाकुर

https://t.me/AllNewsPaperPaid

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770

ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

थोक मुद्रास्फीति
बढ़त की आशंका

थोक मुद्रास्फीति अप्रैल में 13 महीने के सर्वोच्च स्तर 1.26 प्रतिशत पर पहुंच गई। अगले दो महीने में गरमी बढ़ने के साथ ही खाद्य पदार्थों की कीमत में संभावित वृद्धि देश में अनेक परिवारों की चिन्ता का कारण बन सकती है। थोक मुद्रास्फीति से खाद्य पदार्थ और ईंधन महंगे हो सकते हैं। हालांकि, मजेदार बात है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-सीपीआई के आधार पर मापे जाने वाली खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट आई है और वह 11 महीने के सबसे निचले स्तर 4.83 प्रतिशत पर पहुंच गई, जबकि पिछले महीने यह 4.85 प्रतिशत थी। भारतीय रिजर्व बैंक-आरबीआई मुद्रा नीति तय करने के लिए मुख्यत: खुदरा मुद्रास्फीति पर गौर करता है। लेकिन औसत व्यक्ति के लिए थोक मूल्य सूचकांक-डब्लूपीआई में वृद्धि चिन्ता का विषय है क्योंकि इसका प्रभाव मुख्यत: प्रसंस्कृत और गैर-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों तथा विनिर्मित वस्तुओं पर पड़ता है। वर्तमान समय में भारत भयानक गरमी का अनुभव कर रहा है जिससे सब्जियों के दाम बढ़ने की आशंका है। पूर्वानुमान है कि डब्लूपीआई मुद्रास्फीति मई, 2024 में 2-3 प्रतिशत बढ़ेगी और यह बढ़ते हुए जून, 2024 में अपने शिखर पर पहुंचेगी। डब्लूपीआई खाद्य मुद्रास्फीति में प्रमुख खाद्य पदार्थ तथा विनिर्मित खाद्य पदार्थ शामिल हैं। इसमें लगातार तीसरे महीने वृद्धि हुई है और यह अप्रैल में 8 महीने के सर्वोच्च स्तर 5.5 प्रतिशत पर पहुंच गई, जबकि अप्रैल 2023 में यह 0.4 प्रतिशत बढ़ी थी। विनिर्मित खाद्य पदार्थों में यह 15 महीने के सर्वोच्च स्तर 1.2 प्रतिशत पर पहुंच गई, जबकि प्रमुख खाद्य पदार्थों में यह चार महीने के सर्वोच्च स्तर 7.7 प्रतिशत पर पहुंची।

अप्रैल में डब्लूपीआई मुद्रास्फीति वृद्धि में मुख्यत: ईंधन और खाद्य पदार्थों का योगदान रहा है। लेकिन खाद्य मुद्रास्फीति के मामले में अच्छी खबर यह है कि सामान्य मानसून की उम्मीद से स्थिति में सुधार आएगा। सामान्य मानसून

से कृषि उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद है। वस्तुओं की कीमतों में चीन से बढ़ती मांग की उम्मीद में भी वृद्धि हो रही है। भारत में यह चुनाव वर्ष है। ऐसे में अनुमानों के आधार पर कीमतों में वृद्धि संभावित है जिसमें सरकारी नीतियों की निरंतरता पर संदेह शामिल है। इसके साथ ही चुनाव पर होने वाले भारी खर्च का खामियाजा भी आम आदमी को बढ़ी कीमतों के रूप में भुगतना पड़ता है। कार्पोरेट और व्यापारियों द्वारा राजनीतिक पार्टियों की फंडिंग के कारण अक्सर चुनाव के पहले और चुनाव के बाद कीमतें बढ़ सकती हैं। लाजिस्टिक बाधाओं, श्रमिकों की कमी तथा तेल की कीमतें बढ़ने के कारण परिवहन की लागत बढ़ने से कुल मिला कर मुद्रास्फीति पर दबाव बढ़ता है। इसके कारण खाद्य पदार्थों के उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं पर समान रूप से दबाव बढ़ जाता है। खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के कारण चुनाव चर्चा आर्थिक नीतियों तथा उनके प्रभावों पर केन्द्रित हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, वर्तमान समय में महंगाई तथा बेरोजगारी चुनाव में गरमागरम बहस के मुद्दे हैं। आमतौर से सत्तारूढ़ पार्टी को बढ़ती कीमतों का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है क्योंकि लोग उसे कीमतों पर लगाम लगाने का जिम्मेदार मानते हैं। मुद्रास्फीति पर प्रभावी नियंत्रण के लिए एक समग्र रणनीति की जरूरत है जिसमें अल्पकालीन हस्तक्षेपों के साथ दीर्घकालीन ढांचागत परिवर्तन शामिल हैं। लक्षित सब्सिडी तथा मूल्य स्थिरीकरण व्यवस्थाओं जैसे त्वरित कदमों से खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों से उपभोक्ताओं को अस्थाई राहत मिल सकती है।

जीर्णोद्धार की प्रतीक्षा में जानकी मंदिर

मां जानकी जहां प्रकट हुई थीं उस स्थान का नाम पुनौराधाम है। यह स्थान बिहार के सीतामढ़ी जिले में सीतामढ़ी शहर से साढ़े तीन किलोमीटर दूर स्थित है।

प्रभात झा
(लेखक, पूर्व भाजपा सांसद हैं)

भारत में सामान्य तौर पर किसी से भी पूछा जाए कि भगवान श्री राम लला का जन्म कहां हुआ, तो सभी तपाक से उत्तर देंगे अयोध्या। हर भारतीय के जुवां पर यह नाम है। इसी तरह यदि आप पूछें कि मां जानकी का जन्म कहां हुआ तो लोग उत्तर देते हैं जनकपुर जो सरासर गलत है। जनकपुर तो मां जानकी/सीता जी का ननिहाल और विवाह स्थल है। सत्य यह है कि मां जानकी जहां प्रकट हुई थीं उस स्थान का नाम पुनौराधाम है। यह स्थान बिहार के सीतामढ़ी जिले में सीतामढ़ी शहर से साढ़े तीन किलोमीटर दूर स्थित है। यह वही स्थान है, जहां एक बार अकाल पड़ने पर राजा जनकजी को कहा गया कि आप यदि स्वयं खेत में हल जोतेंगे तो अकाल समाप्त हो जायेगी और वरुण देवता प्रसन्न हो जाएंगे। उस समय जनकपुर भारत का हिस्सा हुआ करता था, पर आज जनकपुर नेपाल में है, पर मां सीताजी का प्राकट्यस्थल पुनौराधाम आज भी भारत में है। इसके शास्त्रों में प्रमाण भी उपलब्ध हैं।

वृहद विष्णुपुराण के मिथिला खंड में वर्णित है कि हम संसार में प्राणियों की सारी मनोकामनाएं पूरी करने वाली विशेष फलदायक यज्ञ स्थली पुण्योर्वरा (पुनौराधाम) की यात्रा और दर्शन विशेषकर चैत्र श्री रामनवमी और वैशाख श्री जानकी नवमी में मोक्ष की अभिलाषी को करने चाहिए, क्योंकि दोनों तिथि क्रमश: श्री राम जी का जन्मदिवस और मां सीता जी का प्राकट्य दिवस है। वर्णन है की एक बार सम्पूर्ण मिथिला में घोर दुर्भिक्ष पड़ गयाद्य अनावृष्टि से मिथिलावासियों में त्राहि-त्राहि मच गई। लोग अन्न और जल के अभाव में दम तोड़ने लगेद्य सब जीव-जंतु व्याकुल हो उठे। उस समय मिथिला महाराजा निमि के वंशज राजा जनक राज कर रहे थ। यज्ञ से वर्षा होती है और वर्षा के प्रभाव से अन्न उत्तपन्न होता है। इससे प्रभावित होकर राजर्षि जनक ने अपने राज्य के विद्वानों, ऋषि-मुनियों और ज्योतिषियों की आपातकालीन सभा बुलाकर भीषण दुर्भिक्ष की विभीषिका से त्राण पाने के उपाय पर विचार-विमर्श कियाद्य सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि राजा जनक को हलेष्ठी यज्ञ करना चाहिएद्य इसके निमित्त शोध के आधार पर पुण्यारण्य (पुण्डरीक आश्रम) को उपयुक्त स्थान के रूप में चयन किया गया।

वृहद विष्णुपुराण के मिथिला माहात्म्य के अष्टम अध्याय में वर्णित है कि राजर्षि जनक का जो प्राचीन दुर्ग था , उसके पारत: पंचकोशी चार विशाल द्वार थेद्य वे इन दिनों भी वर्तमान जनकपुरधाम से क्रमश: दस मील उत्तर की ओर धनुषा, दस मील दक्षिण की ओर गिरजा स्थान, दस मील पूरब की ओर हरिहरालय महादेव और दस मील पश्चिम जलेश्वरनाथ के नाम से लोक विदित है। यह स्पष्ट है कि महाराजा जनक इसी जलेश्वरनाथ(शिव जी का जलशयन स्थल) से पश्चिम भाग में शास्त्रवत अठासी ऋषियों एवं रानी सुनैना सहित तीन योजना के बाद हलेष्ठी यज्ञार्थ पुण्डरीक आश्रम पुण्यारण्य पधारे थे, जहां हलेष्ठी यज्ञ की सिद्धि प्राप्त हुई और मां जानकी का प्राकट्य हुआ।

पद्मपुराण में वर्णन है कि जानकी नाम तो जनक जी के वंशानुगत जनक शब्द से रखा गया, लेकिन शास्त्रानुसार उनका नाम सीता होना अपेक्षित है, क्योकि सीत(फार का नुकीला अग्र भाग) और सीता(सिराउर) के संयोग से उत्पत्ति होने के कारण सीता नाम की पुष्टि होती है। जन्म के बाद लौकिक एवं वैदिक रीतियों से वर्षा से बचाने के लिए मड्डई (मढ़ी) में मां सीता जी रखी गईं तथा उस स्थान का नाम सीतामढ़ी हुआ।

पुण्डरीक क्षेत्र अर्थात पुनौराधाम,जहां मां जानकी जी का प्राकट्य हुआ, वहां कई पुरातन स्मृतियां हैं, जिनका वर्णन और वहां की भाषाएं का उल्लेख रामायण, पुराणों, संहिताओं एवं इतिहास के पृष्ठों में स्वर्णाक्षरों में वर्णित है, सनातन में अविस्मरणीय-अमिट हैद्य पुनौराधाम में प्रवेश मात्रा से प्राणी पवित्र हो जाता हैद्य मां जानकी कुण्ड में जलस्पर्श एवं स्नान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैद्य मां जानकी जन्म कुण्ड को पुण्यनिधि कहा गया हैद्य शास्त्रों-पुराणों में वर्णन है कि यहां तीर्थाटन करने से सभी पापों, संकटों से मुक्ति पाकर श्रद्धालु पुण्यलोक की प्राप्ति कर सकते हैं। जगतगुरु रामभद्राचार्य जी ने इसका शास्त्रों में प्रमाण देते हुए वर्णन किया है कि: सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणी, वंदे विशुद्ध विज्ञानों कवीश्वर कपीश्वर (बालकाण्ड संख्या-3)। इसका अर्थ है कि श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्रता में विहार करने वाली पुण्यारण्य अर्थात पुनौराधाम विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूं। जगतगुरु रामभद्राचार्य जी गत 12 वर्षों से लगातार पुनौराधाम में जानकी नवमी आने के नौ दिन पूर्व से जगत जननी मां जानकी की जन्म स्थली पर नौ दिन कथा कर जानकी नवमी सम्पन्न कर समाज को सदैव संदेश देते हैं कि पुनौराधाम ही मां जानकी का प्राकट्यस्थल है। मैं और जगतगुरु रामभद्राचार्य जी बिहार के तत्कालीन राज्यपाल के साथ-साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इस आशय की जानकारी भी दीद्य आजादी के बाद पहली बार कोई संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्तित्व तत्कालीन राज्यपाल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पुनौराधाम पहुंचेद्य उन्होंने हजारों की सभा में कहा कि पुनौराधाम के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था कि यह मां जानकी जी का प्राकट्यस्थल है। यह तो मैं प्रभात झा जी जो हमारे मिथिला के ही गौरव हैं, ने जब बताया तो जानकारी मिलीद्य जगतगुरु रामभद्राचार्य जी ने कहा कि आप जानकी नवमी पर आईये तो मैं वहां पहुंचा। नीतीश जी ने कहा कि बिहार सरकार पुनौराधाम स्थित मां जानकी के प्राकट्यस्थल का धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विस्तार करने की दिशा में अनेक कदम भविष्य में उठाये जाएंगे।

अयोध्या में भगवान रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर वर्षों के संघर्ष के बाद न्यायालय के फैसले से बनकर तैयार हो गयाद्य अभी अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर का प्रथम चरण बना है जिसकी जिसकी प्राणप्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा किया गया। कहा जाता है कि %बिना राम के सीता नहीं और बिना सीता के राम नहीं। पूरे विश्व से अयोध्या में बने भगवान रामलला के भव्य दिव्य मंदिर के दर्शनार्थ आज लाखों लोग पधार रहे हैं। अयोध्या का विकास इतना हो रहा है कि आने वाले दिनों में अयोध्या विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन स्थल बन जाएगाद्य ऐसा होना हमारी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाएगा भी। पर दूसरी ओर, मां जानकी(सीताजी) का प्राकट्यस्थल पर न चर्च है , न मस्जिद है, न किसी तरह का जमीनी विवाद है, और तो और वहां मां जानकी का एक छोटा मंदिर भी बना हैद्य वहां वह स्थल भी मौजूद है जहां राजा जनक ने हल जाता था और मां सीता हल जोतते समय एक मटके से हल के अगले हिस्से जिसे सीत कहा जाता है, के लगने से प्रकट हुईं।'सीत' जो हल का अगला हिस्सा होता है उसके लगने से ही मां सीता प्रकट हुईं।'सीत' के कारण ही उनका नाम 'सीता' पड़ा । पुनौराधाम से राजा जनक ने उन्हेंएक 'मढ़ी' में लेकर गए, आज जिसे 'सीतामढ़ी' कहा जाता है। उसके पीछे की कहानी जानकार लोग यही कहते हैं।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जब भी अयोध्या में गए थे जय श्री राम नहीं बोले वह हमेशा 'जय सियाराम' ही बोले। अब सवाल उठता है की मां जानकी सीता जी के प्रकट स्थल का जीर्णोद्धार कब होगा। जगतगुरु रामभद्राचार्य जी ने प्रण लिया हुआ है कि जब तक मां सीता जी के प्रकट स्थल का जीर्णोद्धार और यह भारत का श्रेष्ठ धाम नहीं बनेगा मेरी कथा सदैव जानकी नवमी पर यहां होती रहेगी। मैं स्वयं राज्यसभा में भी पुनौरा धाम का मामला और वहां मां जानकी के प्राकट्य स्थल के संपूर्ण विकास का मामला उठाया था सदन में सभी दलों ने इसका समर्थन भी किया था। बहुत मुश्किल से भारत में लोगों को अब यह जानकारी हुई है कि पुनौराधाम जो सीतामढ़ी से मात्र साढ़े तीन किलोमीटर दूर है, मां सीता का प्राकट्यस्थल है। नहीं तो लोगों के मन में तो अभी भी जनकपुर का नाम ही बैठा था।

जनकपुर इसलिए प्रसिद्ध हुआ कि वहां मां जानकी ने भगवान शंकर के धनुष को सहज उठाकर रख दिया था। यह देख राजा दशरथ आश्चर्यचकित हो गए इसके बाद उन्होंने घोषणा की थी की जो व्यक्ति इस धनुष को उठा लेगा मैं उसी से अपनी बेटी सीता का विवाह कर दूंगा। जनकपुर में बहुत लोग आए पर सभी को ज्ञात है कि भगवान श्री राम ने ही वह धनुष उठाया प्रत्यंचा चढ़ा दी इसके बाद मां सीता का स्वयंवर रचा और भगवान श्री राम से उनका विवाह हुआ।

पुनौराधाम भारत के बिहार राज्य में स्थित सीतामढ़ी में है। अत: भारत सरकार और बिहार सरकार का यह आध्यात्मिक और नैतिक दायित्व बनता है की पुनौराधाम को भारत का श्रेष्ठ धाम बनाने की दिशा में पुरजोर प्रयास करें। अयोध्या स्थित रामलाल के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए निमित्त ट्रस्ट से जुड़े श्री कामेश्वर चौपाल जी, जिन्होंने भव्य राम मंदिर के निर्माण की पहली ईट सबसे पहले लगाई थी का कहना है कि बिहार सरकार पुनौराधाम ट्रस्ट को यदि हमारे अयोध्या स्थित ट्रस्ट को सौंप दे तो हम सभी पुनौराधाम को अयोध्या की तर्ज पर भव्य दिव्य मंदिर और भारत का श्रेष्ठ धार्मिक पर्यटन बनाने की दिशा में विचार कर सकते हैं। उनका भी मानना है कि अयोध्या की मान्यता विश्व में भगवान राम लला को लेकर है तो मां सीता जी (मां जानकी) को लेकर पुनौराधाम का नाम विश्व में क्यों नहीं हो सकता।

भारत की जनता अब पुनौराधाम आने लगी है। जानकी नवमी को वहां बहुत बड़ा मेला लगता है। प्राकृतिक कुंड के सामने जानकी नवमी वाले दिन जगत गुरु रामभद्राचार्य जी पूजा अर्चना कर सभी को आशीर्वाद देते हैं। वहां 9 दिन तक भंडारा चलता है। देश भर से माता बहने आती हैं और अपने-अपने नवजात बच्चों और अनय बच्चों के सर पर मां जानकी के प्राकट्यस्थल का रज लगती है। यहां कहावत कहीं जाती है कि यहां का रज जिस नवजात बच्चे की ललाट पर लगता है उसमें लव कुश के संस्कार सहज आ जाते हैं। जगत जननी मां सच में इंतजार कर रही है कि और कह रही है कि जिनके कारण मेरा धरा पर अस्तित्व है उनका भव्य मंदिर बनने पर मैं बहुत खुश हूं पर मैं भी उनके साथ पतिव्रता अर्धांगिनी बनकर सदैव हर समय खड़ी रही, तो मेरे साथ भी न्याय होना चाहिए।

कृषि में कृत्रिम बुद्धि के क्रांतिकारी प्रभाव

> **एआई किसानों को संसाधन आवंटन को अनुकूलित करने, पर्यावरणीय गिरावट को कम करने और फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए सशक्त बनाती है।**

प्रेरणा नेगी
(लेखिका, एक शोधकर्ता हैं)

कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से भोजन की बर्बादी में नाटकीय रूप से वृद्धि होने की आशंका है, जलवायु परिवर्तन और अन्य मुद्दों के कारण लगभग एक अरब लोग भूखे और कुपोषित रह रहे हैं, भले ही दुनिया सभी को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन का उत्पादन करती है। 2050 तक 9.7 अरब लोगों के ग्रह पर निवास करने की उम्मीद के साथ, कृषि क्षेत्र पर कम संसाधन उपयोग और कम पर्यावरणीय प्रभाव के साथ भोजन उपलब्ध कराने का दबाव बढ़ रहा है। शुक्र है, कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के अनुप्रयोग ने खाद्य प्रणालियों में क्रांति लाने और विश्व खाद्य समस्या को कम करने का वादा किया है। एआई कई स्रोतों से डेटा का विश्लेषण करके किसानों को डेटा-संचालित विकल्प बनाने, संसाधन खपत को अनुकूलित करने और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने में सहायता कर सकता है। विश्व आर्थिक मंच के विश्लेषण के अनुसार, एआई को कृषि में एकीकृत करने से कीटनाशकों के उपयोग में 60 प्रतिशत की कमी और पानी के उपयोग में 50 प्रतिशत की कमी हो सकती है।

बाज़ार मांग विश्लेषण समकालीन कृषि का एक अनिवार्य घटक है। मौसम संबंधी डेटा और उपग्रह तस्वीरों का विश्लेषण करने के अलावा, एआई किसानों को उत्पादन या बिक्री के लिए सर्वोत्तम फसल चुनने में सहायता कर सकता है और कब बोना है और किस प्रकार की फसल उगानी है, इस पर व्यावहारिक सलाह दे सकता है। डेटा पैटर्न की जांच करके लाभप्रदता का अनुकूलन करते हुए कुछ फसलों के लिए बाजार की मांग का पूर्वानुमान लगाना संभव है। किसान पूर्वानुमान और भविष्य कहनेवाला विश्लेषण का उपयोग करके फसल विफलता की संभावना को कम कर सकते हैं। यह ऐसे सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन बनाएगा जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और कंप्यूटर विज़न विधियों का उपयोग करके फलों और सब्जियों का विश्लेषण करेंगे और उनकी गुणवत्ता, ताजगी और आकार के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। फसलों में खामियों और बीमारियों की पहचान करने के अलावा, ये एआई प्रौद्योगिकियां किसानों को फसलों के प्रभावित होने से पहले निवारक कार्रवाई करने की अनुमति देती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) पौधों की वृद्धि पर डेटा एकत्र करके ऐसी फसलों के उत्पादन में सहायता कर सकता है जो मौसम और रोग के अनुकूल हों। वैज्ञानिक सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले पौधों की किस्मों को खोजने के लिए एआई का उपयोग कर सकते हैं और उन्हें और भी बेहतर संकर बनाने के लिए क्रॉसब्रीड कर सकते हैं। एआई सिस्टम लापता पोषक तत्वों का विश्वसनीय रूप से अनुमान लगाने और रासायनिक मिट्टी विश्लेषण करने में सक्षम हैं।

उनका एक उत्पाद, पोषक तत्व स्कैनर, मिट्टी के नमूनों से जानकारी इकट्ठा करता है और किसानों को उन पोषक तत्वों की कमी और मिट्टी की सामान्य स्थिति का सटीक अनुमान देता है। यह किसानों को सिंचाई कार्यक्रम और उर्वरक अनुप्रयोगों को संशोधित करके फसल विकास को अनुकूलित करने और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में सक्षम बनाता है। एआई पौधों की स्थिति की निगरानी करके बीमारियों का पता लगा सकता है और उनकी भविष्यवाणी कर सकता है, खरपतवारों की पहचान कर सकता है और उन्हें हटा सकता है और कीटों के प्रभावी उपचार की सिफारिश कर सकता है। यह कीटों के लिए सबसे प्रभावी उपचार का सुझाव भी दे सकता है, जिससे व्यापक स्पेक्ट्रम कीटनाशकों की आवश्यकता कम हो जाती है जो लाभकारी कीड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कीटनाशक प्रतिरोध को जन्म दे सकते हैं। किसानों को फसल की वृद्धि और परिपक्वता का अनुमान लगाना कठिन और समय लेने वाला लगता है, लेकिन एआई इस काम को सटीक और तेजी से पूरा कर सकता है। सेंसर और छवि पहचान उपकरणों जैसे एआई-संचालित गियर के उपयोग से फसल परिवर्तनों की निगरानी और ट्रैकिंग करके किसान सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं कि फसल कब आदर्श परिपक्वता प्राप्त करेगी। अध्ययनों के अनुसार, फसल परिपक्वता का पूर्वानुमान लगाने के लिए एआई को नियोजित करने से प्राप्त सटीकता दर मानव पर्यवेक्षकों की तुलना में अधिक थी। इस बेहतर परिशुद्धता के परिणामस्वरूप किसानों को बड़ी लागत बचत और बेहतर राजस्व से लाभ हो सकता है। किसान सेंसर और एआई सिस्टम को एकीकृत करके मिट्टी में पानी और पोषक तत्वों की मात्रा को सटीक रूप से ट्रैक कर सकते हैं। तापमान, पीएच स्तर, पोषक तत्व सामग्री और मिट्टी की नमी जैसे कई कारकों का पता लगाने वाले उपकरणों को तैनात करना सेंसर-आधारित मिट्टी निगरानी प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। ये सेंसर डेटा को एआई सिस्टम में वापस भेजते हैं, जो इसे संसाधित करते हैं, इसका मूल्यांकन करते हैं और किसानों को उनके द्वारा खोजी गई मिट्टी की स्थितियों के आलोक में उनकी फसलों को संभालने के सर्वोत्तम तरीकों पर सलाह देते हैं। एआई-संचालित प्रौद्योगिकियां किसानों को पौधों की बीमारियों और कीड़ों की पहचान लोगों की तुलना में तेजी से करने में मदद कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, एक एआई-संचालित प्रणाली स्ट्रॉबेरी के खेत में एफिड संक्रमण की पहचान कर सकती है, जानकारी को किसान के स्मार्टफोन पर वापस भेज सकती है और फिर सर्वोत्तम कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है।

एक जुड़े हुए स्प्रेयर के माध्यम से, यदि आवश्यक हो तो उपकरण कीटनाशकों के छिड़काव को भी स्वचालित कर सकता है। एआई तकनीक का उपयोग कीट या खरपतवार नियंत्रण को स्वचालित करने के लिए किया जा सकता है। माना जाता है कि कंप्यूटर विज़न के उपयोग से रोबोटिक निराई असाधारण रूप से सटीक होती है, जिससे कीटनाशकों के उपयोग से 90 प्रतिशत की बचत होती है। ये समाधान फसल के प्रकार, मिट्टी की स्थिति और क्षेत्र के इतिहास के बारे में जानकारी के आधार पर यह निर्धारित करने के लिए डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र के लिए कितने कीटनाशक की आवश्यकता है। आने वाले वर्षों में, कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के नाटकीय रूप से बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि यह दक्षता बढ़ाकर, अपशिष्ट कम करके और फसल की पैदावार बढ़ाकर उद्योग को पूरी तरह से बदल सकता है।

आप की बात

सराहनीय कदम

पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान व बांग्लादेश में प्रताड़ना के कारण भारत आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन कानून-सीएए के तहत भारतीय नागरिकता देने का काम शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह सचिव ने अपने कार्यालय में 14 शरणार्थियों को भारत की नागरिकता का सर्टिफ़िक्रेट सौंपकर कर इसकी शुरुआत की। वैसे देश भर में कुल 300 शरणार्थियों को सीएए के तहत नागरिकता प्रदान की गई। अन्य लोगों को ईमेल के जरिए नागरिकता सर्टिफ़िक्रेट भेजे गए। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि शरणार्थियों का दशकों का इंतजार खत्म हुआ। उन्होंने इसे मोदी की गारंटी, यानी वादा पूरा होने की गारंटी बताया। दिसंबर 2019 में पास सीएए कानून का अमल विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए टाला गया था।अब सरकार ने इसे क्रियान्वित कर एक सराहनीय कदम उठाया है। नागरिकता आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पूरी प्रक्रिया डिजिटल है और केन्द्र सरकार ने इसके लिए एक खास पोर्टल लांच करने के साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। अब ममता बनर्जी जैसे नेताओं को अपनी जिद छोड़ कर उत्पीड़ित हिंदुओं, सिखों, जैनों, बौद्धों व ईसाइयों के प्रति मानवता दिखाते हुए सीएए का समर्थन करना चाहिए।

– **सदन जी,** पटना

सीएए क्रियान्वित

केंद्र सरकार ने सीएए- नागरिक संशोधन कानून के तहत शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देते हुए उन्हें नागरिकता प्रमाणपत्र देने शुरू कर दिए। इसके तहत पहली बार 14 शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाणपत्र सौंपे गए हैं। इसके साथ ही देश भर में रह रहे 31हजार के लगभग गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने की शुरुआत हो गई है। यह उन सीएए-विरोधियों के मुंह पर एक तमाचा है जो इसका विरोध काफी समय से कर रहे थे। लोकसभा चुनाव में भी सीएए बड़ा मुद्दा है। विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल दल न केवल इसकी तीखी आलोचना कर रहे हैं बल्कि सत्ता में आने पर इसे खत्म करने का वादा भी कर रहे हैं। भाजपा इस कानून के विरोधियों को हिंदू-विरोधी तथा मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने वाला बताती रही है। तीन देशों से भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले के शरणार्थी भारतीय नागरिकता की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश एवं अफ़ग़ानिस्तान के धार्मिक रूप से उत्पीड़ित हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई व पारसी हैं। भारत द्वारा सीएए का क्रियान्वयन महत्वपूर्ण कदम है। इससे वह अपनी प्राचीन सभ्यता व संस्कृति के आधार पर पीड़ितों के लिए मुक्तिदाता के रूप में सारी दुनिया में उभरेगा।

– **एमएम राजावत,** शाजापुर

एआई की दुनिया

ओपन एआई ने आर्टिफ़िशाल इंटेलिजेंस-एआई की दुनिया में नया धमाका करते हुए सोमवार को लार्ज लैंग्वेज मॉडल का लेटेस्ट वर्जन जारी कर दिया है। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का यह तो मात्र एक ट्रेलर है। दुनिया देखेगी कि आगामी कुछ ही वर्षों में खुद एआई अपने आप को मॉडिफ़ाई करता रहेगा और इंसानी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपरिहार्य बनता जाएगा। इससे मानव जीवन अधिक सुविधा पूर्ण बनेगा और यह मानव मस्तिष्क को भी अधिक विकसित करने में सहायक सिद्ध होगा। विशेष तौर से अंतरिक्ष यात्रा में अंतरिक्ष यानों और यात्रियों को लाने ले जाने, अंतरिक्ष में मानवों को बसाने से लेकर अनेकानेक रूपों में इसकी उपयोगिता बढ़ती जाएगी। एआई का मानव से प्रतिद्वंदता का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन चीन या साउथ कोरिया जैसे तानाशाह देश इसका अधिकाधिक दुरुपयोग मानवता को हानि पहुंचाने और अपनी तानाशाही मजबूत करने में कर सकते हैं। मगर इस बुरे पहलुओं को लेकर एआई से भयभीत होने के बजाय एआई द्वारा ही एआई का दुरुपयोग रोकने के उपाय खोजने होंगे। एआई से लोगों के रोजगार खत्म होने की आशंका भी व्यर्थ है क्योंकि ऐसी आशंका कंप्यूटर से भी जताई गई थी, जबकि इससे नए रोजगार पैदा हुए हैं।

सुभाष बुडावन वाला, रतलाम

गरमी में चुनाव

मई का महीना, सूरज का आग उगलना, उत्तराखंड में जंगल की आग और पूरे देश में चुनावी गरमी ने हर शख्स को झुलसा दिया है। आम आदमी तो यूँ भी लू की लपेट में आ ही जाता है, किन्तु इन दिनों खास को भी वातानुकूलित दफ्तर, दूकान और कुर्सी छोड़कर तपती सड़क पर बारम्बार उतरना पड़ रहा है। इसका कारण लोकसभा चुनाव में मतदान करना और अधिकाधिक मतदाताओं को अपने पक्ष में जुटाना है। राजनेताओं की सारी उहापोह नई सरकार के बनने के बाद समाप्त हो जाएगी और वे सरकार बनाने या अपना एजेंडा लागू करने की जुगत में लग जाएंगे। लेकिन राजनेताओं को इस भयानक गरमी में चुनाव की समस्याओं से सबक लेना चाहिए। यदि चुनाव गरमी का मौसम शुरू होने से पहले ही मार्च तक करा लिए जाएं तथा बच्चों की बोर्ड परीक्षायें चुनावों के बाद रखी जाएं तो बेहतर होगा। शिक्षकों को चुनाव संबंधी कामों से अलग रखने का निर्णय भी होना चाहिए। यदि देश में -एक देश, एक चुनाव जैसी व्यवस्था लागू हो जाए तो निर्वाचन आयोग को मतदान कराने में सुविधा होगी तथा जनता के दैनिक जीवन में बाधा भी कम होगी।

– **शकुंतला महेश नेनावा,** इंदौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

https://t.me/

संपादकीय

नहीं मिले सारे जवाब

रुपेश कुमार सिंह
संपादक
चौथी वाणी

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की हत्या मामले में कई अहम सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिल पाए हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में आरोपियों को दोषी करार दिया है। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के करीब 11 साल बाद आया विशेष अदालत का फैसला कम से कम यह संतोष देता है कि इस मामले में न्याय प्रक्रिया का एक चक्र पूरा हुआ। हालांकि कई अहम सवालों के जवाब अभी भी नहीं मिले हैं। लिहाजा यह नहीं कहा जा सकता कि यह प्रकरण अपनी तार्किक परिणति तक पहुंच गया।

हत्या का सिलसिला : 20 अगस्त 2013 की सुबह हुई डॉ. दाभोलकर की हत्या ने अगर पूरे देश को सकते में डाल दिया था, तो वह बेवजह नहीं थी। माना गया कि उनकी हत्या उनके विचारों को दबाने के मकसद से की गई है। उसके बाद फरवरी 2015 में गोविंद पानसरे, अगस्त 2015 में एम एम कलबुर्गी और सितंबर 2017 में हुई गौरी लंकेश की हत्या को इसी श्रेणी में रखकर देखा जा रहा था। टिकी थीं निगाहें : शुरूआती जांच में कुछ ऐसे बिंदु मिले भी थे जिनसे लगता था कि कहीं न कहीं इन हत्या की साजिशों के तार एक-दूसरे से जुड़े हैं। इस लिहाज से भी नरेंद्र दाभोलकर हत्या से जुड़े इस मामले पर सबकी नजरें टिकी थीं। लग रहा था कि अदालत में अगर इन साजिशों की परतें खुलें और कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचे तो देश में अपनी तरह के इन हत्याकांडों के पीछे की सचाई सामने आएगी।

साजिश नहीं खुली : अदालत ने उन दो लोगों के खिलाफ दोष साबित हो गया, जिन्होंने 20 अगस्त 2013 की सुबह डॉ. दाभोलकर पर गोलियां चलाई थीं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन लोगों ने यह हत्या की क्यों? क्या इनकी डॉ. दाभोलकर से कोई निजी दुश्मनी थी? सीबीआई के मुताबिक हत्या का कारण वैचारिक टकराव था। अभियोजन पक्ष ने हत्या की साजिश के मामले में तीन अन्य लोगों को आरोपी बनाया था। लेकिन जांच एजेंसियां इन आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं जुटा सकीं।

कमजोर जांच-पड़ताल : जाहिर है, कमजोर जांच-पड़ताल की वजह से हत्या के पीछे की साजिश उजागर नहीं हो सकी। हत्या के पीछे कोई दूसरा ठोस, तर्कसंगत कारण भी स्थापित नहीं हो पाया। नतीजा यह कि हत्या करने वालों को सजा सुना दिए जाने के बाद भी, देश इस बात को लेकर अंधेरे में है कि आखिर इस हत्या के पीछे किन लोगों की और कैसी साजिश थी।

कोई निष्कर्ष नहीं : इसी वजह से यह सवाल भी अनुत्तरित ही है कि उसके बाद हुई तीन हत्याओं- गोविंद पानसरे, एम एम कलबुर्गी और गौरी लंकेश की हत्या को एक साथ जोड़कर देखने का कोई ठोस आधार है या नहीं। क्या इन चारों हत्याओं की साजिश के पीछे एक ही संगठन से जुड़े समान सोच वाले लोगों का हाथ था? जाहिर है, ठोस जवाब के अभाव में ऐसी हत्याओं तक ले जाने वाले कारकों से निपटने के तरीके ढूंढना भी आसान नहीं होगा।

नेशनल साइबर क्राईम रिर्पोटिंग पोर्टल पर साइबर अपराधियों द्वारा धमकियों की शिकायतें बढ़ी

अटेंशन प्लीज! ब्लैकमेल,जबरन वसूली व डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो सकते हैं

लेखक
किशन सनमुखदास भावनानी
गोंदिया (महाराष्ट्र)

केंद्रीय गृह मंत्रालय का देशव्यापी अलर्ट-सीमा पार बैठे अपराधी सिंडिकेट का ब्लैकमेल,जबरन वसूली व डिजिटल अरेस्ट के फंडे से सावधान रहना जरूरी : एडवोकेट किशन भावनानी

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर जैसे- जैसे प्रौद्योगिकी विज्ञान दूरसंचार तकनीकी व टेक्निकल कनेक्टिविटी सुविधाओं में हवा से भी तेज गति से वृद्धि हो रही है, तो स्वाभाविक ही है कि मानवीय हस्तक्षेप वह क्रिएटिविटी में कमी होगी क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के आधार पर पूरा मानवीय कार्य कर सकने में अब प्रौद्योगिकी सक्षम हो चुकी है, जिसमें बैठे बिठाये सभी काम संबंधित व्यक्तित्व के हो जाते हैं।परंतु भारत में बड़े बुजुर्गों की कहावत है कि जितना सुख ढूंढोगे उतना दुख भी तुम्हें ढूंढेगा, दुख विकसित सुख माही यानें यदि हम सुख सुविधा चाहते हैं तो वहीं से दुखों का भी विकास होता है, यही बात हमारे प्रौद्योगिकी व दूरसंचार तकनीकियों की सुख सुविधा प्राप्त होने से हो रही है। यानें हर बार हम साइबर अपराध के नए-नए फंडों से हम फंसते हुए देखते आ रहे हैं।कुछ सैकड़ों में ही लाखों करोड़ों बैंक से उड़ जाते हैं। दिनांक 14 मई 2024 को हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन रिंकू मनोहर आसवानी ने कल ग्रुप में अलर्ट भी किया था कि कोई भी एप्लीकेशन व्हाट्सएप पर आए तो उसे डाउनलोड नहीं करना है, मोबाइल हैंग होकर ओटीपी जनरेट होकर उसके आधार पर बैंक से पैसे कटते जा रहे हैं। हम किसी ठगी का शिकार हो जाते हैं कोई लिंक आई उसे टच किया कि हमारी सीक्रेट्स उनके पास पहुंची और पक्का इसका दूरगामी दुरुपयोग हुआ समझो। परंतु अभी हाल ही में कुछ दिनों से एक नई साइबर क्राइम तकनीकी शायद सीमा पार बैठे साइबर अपराधियों द्वारा की जा रही है।ब्लैकमेल,जबरन वसूली व डिजिटल अरेस्ट जैसी धमकियों का शिकार अनेक लोग हो रहे हैं जिनकीशिकायतें साइबर क्राइम पोर्टल पर बढ़ती जा रही है क्योंकि दिनांक 14 मई 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश व्यापी अलर्ट जारी किया गया है।इसलिए आज हम मीडिया पीआईबी में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे,अटेंशन प्लीज ब्लैकमेल जबरन वसूली व डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो सकते हैं। साथियों बात अगर हम एमएचए द्वारा 14 मई 2024 को जारी किए गए अलर्ट की करें तो, डिजिटल अरेस्ट को संगठित ऑनलाइन आर्थिक अपराध बताया है और मंगलवार को ऐसे अपराध के खिलाफ देशव्यापी अलर्ट जारी किया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक, सीमा पार बैठे आपराधी इस सिंडिकेट को संचालित कर रहे हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इन आपराधियों के कारण देश भर में कई पीड़ितों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यह संगठित ऑनलाइन आर्थिक अपराध है और ऐसा पता चला है कि सीमा पार बैठे अपराधी गिरोह द्वारा संचालित किया जा रहा है।अब गृह मंत्रालय ने नागरिकों से इस प्रकार की धोखाधड़ी के बारे में सतर्क रहने और जागरूकता फैलाने की अपील की है। बयान में कहा गया है कि फ्रॉड कॉल आने पर नागरिकों को तुरंत सहायता के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 या मेल पर घटना की सूचना देनी चाहिए। ये धोखेबाज आमतौर पर संभावित पीड़ित को कॉल करते हैं और कहते हैं कि पीड़ित ने कोई पार्सल भेजा है या प्राप्त किया है जिसमें अवैध सामान, ड्रग्स, नकली पासपोर्ट या कोई अन्य प्रतिबंधित वस्तु है। कभी कभी, वे यह भी सूचित करते हैं कि पीड़ित का कोई करीबी या प्रिय व्यक्ति किसी अपराध या दुर्घटना में शामिल पाया गया है और उनकी हिरासत में है। ऐसे कथित केस में समझौता करने के लिए पैसे की मांग की जाती है। कुछ मामलों में, पीड़ितों को डिजिटल अरेस्ट का सामना करना पड़ता है और उनकी मांग पूरी न होने तक पीड़ित को स्काइप या अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म पर धोखेबाजों के लिए उपलब्ध रहने पर मजबूर किया जाता है। ये जालसाज पुलिस स्टेशनों और सरकारी कार्यालयों की तर्ज पर बनाए गए स्टूडियो का उपयोग करने में माहिर होते हैं और असली दिखने के लिए वर्दी पहनते हैं।देशभर में कई पीड़ितों ने ऐसे अपराधियों के जाल में फंस कर बड़ी मात्रा में धन गंवाया है। यह एक संगठित ऑनलाइन आर्थिक अपराध है और ऐसा माना जाता है कि इसे सीमापार आपराधिक सिंडिकेट द्वारा संचालित किया जाता है।देशभर में कई पीड़ितों ने ऐसे अपराधियों के जाल में फंस कर बड़ी मात्रा में धन गंवाया है। यह एक संगठित ऑनलाइन आर्थिक अपराध है और ऐसा माना जाता है कि इसे सीमापार आपराधिक सिंडिकेट द्वारा संचालित किया जाता है।गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र , देश में साइबर अपराध से निपटने से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करता है। गृह मंत्रालय इन साइबर अपराधों से निपटने के लिए अन्य मंत्रालयों और उनकी एजेंसियों, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है। आईफोरसी ऐसे मामलों की पहचान और जांच के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस अधिकारियों को इनपुट और तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है।आईफोरसी ने माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से ऐसी गतिविधियों में शामिल एक हजार से अधिक स्काइप आईडी को भी ब्लॉक कर दिया है। यह धोखेबाजों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सिम कार्ड, मोबाइल उपकरणों और म्यूल खातों को ब्लॉक करने में भी मदद कर रहा है। आईफोरसी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म साइबरदोस्त पर इन्फोग्राफिक्स और वीडियो के माध्यम से विभिन्न अलर्ट भी जारी किए हैं, जैसे कि एक्स , फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स।नागरिकों को इस प्रकार की जालसाजी से सावधान रहने और इनके बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी जाती है। साथियों बात अगर हम नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल की करें तो, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) पर साइबर अपराधियों द्वारा धमकी, ब्लैकमेल, जबरन वसूली और डिजिटल अरेस्ट के संबंध में बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं। ये अपराधी खुद को पुलिस, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई),नारकोटिक्स विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) प्रवर्तन निदेशालय और अन्य जांच एजेंसियों के अधिकारी बताते हैं और लोगों से जबरन वसूली करते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा कि साइबर अपराधी आम तौर पर लोगों को फोन करते हैं और बताते हैं कि उसने पार्सल भेजा है या वह ऐसा पार्सल रिसीव किया है, जिसमें अवैध सामान, ड्रग्स, नकली पासपोर्ट या कोई अन्य प्रतिबंधित वस्तु है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर साइबर अपराधियों द्वारा पुलिस अधिकारियों, केंद्रीय जांच ब्यूरो,नारकोटिक्स विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रवर्तन निदेशालय और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों का रूप धारण कर धमकी, ब्लैकमेल, जबरन वसूली और डिजिटल अरेस्ट जैसी वारदातों को अंजाम देने के संबंध में बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज की जा रही हैं।

साथियों बात अगर हम डिजिटल अरेस्ट को समझने की करें तो, डिजिटल अरेस्ट ब्लैकमेल करने का एक एडवांसतरीका है। डिजिटल अरेस्ट स्कैम के शिकार वही लोग होते हैं जो अधिक पढ़े लिखे और अधिक होशियार होते हैं। डिजिटल अरेस्ट का सीधा मतलब ऐसा है कि कोई हमको ऑनलाइन धमकी देकर वीडियो कॉलिंग के जरिए हम पर नजर रख रहा है। डिजिटल अरेस्ट के दौरान साइबर ठग नकली पुलिस अधिकारी बनकर लोगों को धमकाते हैं और अपना शिकार बनाते हैं। कई बार डिजिटल अरेस्ट वाले ठग लोगों को फोन करके कहते हैं कि वे पुलिस डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हमारे पैन और आधार का इस्तेमाल करते हुए तमाम चीजें की खरीदी गई हैं या फिर मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। इसके बाद वे वीडियो कॉल करते हैं और सामने बैठे रहने के लिए कहते हैं। इस दौरान किसी से बात करने, मैसेज करने और मिलने की इजाजत नहीं होती। इस दौरान जमानत के नाम पर लोगों से पैसे भी मांगे जाते हैं। इस तरह लोग अपने ही घर में ऑनलाइन कैद होकर रह जाते हैं। पिछले कुछ समय में ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम के काफी मामले सामने आए हैं। फ्रॉड के साथ साथ डिजिटल अरेस्ट के मामले भी तेजी से देखने को मिले हैं। अब साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए और फ्रॉड के मामलों पर रोक लगाने के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ऐसे साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ अलर्ट जारी किया गया है जो एनसीबी, सीबीआई, आरबीआई और कानून प्रवर्तन अधिकारी के साथ साथ प्रदेश पुलिस के जवान बनकर लोगों को धमकाते और ठगते हैं। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि अटेंशन प्लीज! ब्लैकमेल जबरन वसूली व डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो सकते हैं नेशनल साइबरक्राइम रिपोर्टिंग पोर्टलपर साइबर अपराधियों द्वाराधमकियों की शिकायतें बढ़ी।केंद्रीय गृह मंत्रालय का देशव्यापी अलर्ट सीमा पार बैठे अपराधी सिंडिकेट का ब्लैकमेल,जबरन वसूली व डिजिटल अरेस्ट के फंडे से सावधान रहना जरूरी है।

शिक्षा की ठोष वैज्ञानिक पृष्ठ भूमी, राष्ट्र की आवश्यकता

(समृद्ध नैतिकता आधारित शिक्षा नीति की जरूरत)

हर राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा का अति महत्वपूर्ण किरदार होता है जिस राष्ट्र में शिक्षा,संस्कृति जितनी गहरी और समृद्ध हो वह राष्ट्र उतना ही विकसित,पुष्पित, पल्लवित होता है। इसके साथ आर्थिक तथा वैज्ञानिक सोच भी अत्यंत विचारणीय है।हर देश में राष्ट्र के प्रति और राष्ट्रहित के प्रति चिंतन करने वालों का समूह होना चाहिए,जो प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक तथा राष्ट्रहित के विचारों और विकास के मूल मंत्र को नई ऊर्जा ताजा हवा और आगे बढ़ने की सच्चाई को इंगित कर सकें' बिना संस्कृति ,संस्कार और वैचारिक क्षमता के बिना कोई भी राष्ट्र वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय प्रगति करने की सोच भी नहीं सकता' वैचारिक और सैद्धांतिक अंतरधारा, सिद्धांतों को कुचला या नष्ट नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत वैचारिक अभिव्यक्ति भारत के संदर्भ में गणतंत्र की मूल आत्मा है। विचार और सिद्धांत व्यक्ति की अंतःप्रज्ञा होती है। यह सिद्धांत तथा अंतः विचारधारा जनमानस तक पहुंचने से बाधित किया जाए तो अंतरात्मा को प्रभावित करती है। इसके गहरे प्रभाव से व्यक्ति वह सब कर सकता है, जो बिना मार्गदर्शन के व्यक्ति नहीं कर सकता। प्राचीन काल से अब तक मनीषियों के वैचारिक सिद्धांत और विचारधारा सदैव समाज के दिग्दर्शक मार्गदर्शक रहे हैं। इनकी भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रही है।यदि यही सिद्धांत और अंतः प्रज्ञा जनमानस आत्मसात कर लेता है, तो इसका प्रभाव एक जन आंदोलन का रूप ले लेता है और यही से युग परिवर्तन की लहर उत्पादित होती है। प्राचीन यूनान में एक बहुत ही कुरूप किंतु विद्वान व्यक्ति रहते थे,उनके विचारों में मौलिकता,नयापन जनजागृति की अद्भुत क्षमता थी। उनकी विद्वता के कारण आम जनमानस होने राजा से ज्यादा महत्व और बुद्धिमान मानते थे। राजकीय तानाशाही के चलते उनके विचारों के कारण उनको मृत्युदंड दे दिया गया। जहर का प्याला पीने के बाद भी विद्वान, चिंतक, सुकरात अमर हो गए, उनकी विचारधारा आज भी जीवित है, एवं लोग उसे अपनाकर अपना जीवन सुधारने में इसका उपयोग करते हैं। अब्राहम लिंकन ने अमेरिकी स्वतंत्रता के बाद दास प्रथा के बारे में कहा था कि दास भी मनुष्य हैं, उन्हें भी उतना ही जीने का अधिकार है जितना स्वामी को है। अब्राहम लिंकन के आंदोलनकारी विचार से तत्कालीन समय में अमेरिका के लोग घबरा गए थे,और उनकी हत्या कर दी गई थी। पर अब्राहम लिंकन के विचारों ने दास प्रथा के उन्मूलन की अंतर आत्मा को जागृत कर दिया था, और जनमानस ने अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए दास प्रथा से मुक्ति पाई थी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। विचार एवं सिद्धांत ही व्यक्ति का निर्माण करता है। वही दुष्ट होने या महान होने का निर्णायक है। और बिना विचारों सिद्धांतों के व्यक्त व्यक्ति का अस्तित्व ही नहीं । विवेकानंद जी के विचार सर्व कालीन प्रासंगिक है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने उनके जीवित रहते हुए थे। आज हमारे बीच विवेकानंद जी स शरीर मौजूद नहीं है, पर उनके विचारों की महत्ता कायम है।भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने से और भौतिक विचार तथा सिद्धांत उतनी ही तीव्रता रखते हैं, वेग रखते हैं, जो एक समाज में परिवर्तन ला सकती है ।विचारों की यह अमरता तथा तीव्रता किसी भी तानाशाह के लिए इतनी खतरनाक है, जितनी की सुप्त शेर की गुफा में रहना। जनता के मध्य शुद्ध विचारधारा के जागृत होने पर क्रांति लाई जा सकती है। फिर चाहे वह फ्रांस के वर्साय के महल का विध्वंस हो अथवा भारत की स्वतंत्रता हेतु वृहद आंदोलन हो। व्यक्ति या व्यक्तियों के दबाव को दबाने के बाद विचारों की पीड़िता ने जनसामान्य को एक गरजते हुए सिंह में तब्दील कर दिया था। यह शाश्वत सत्य है कि व्यक्ति को जरूर आप दबा सकते हैं,पर विचारधारा सिद्धांत अजर अमर होते हैं,और वही युग निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाते हैं। विचारों के संदर्भ में कहा जाता है कि एक व्यक्ति का विचार तब तक उस व्यक्ति के पास है, जब तक वह अकेला है किंतु जैसे ही विचारधारा एवं सिद्धांत का प्रचार प्रसार होता है, तो वह व्यक्ति अकेला ना रह कर उस जैसे हजारों लाखों लोग उसके साथ हो जाते हैं। तब वह अकेला नहीं रह जाता। वह अपने विचारों के माध्यम से जन सामान्य को प्रभावित कर लोगों को उस लड़ाई में शामिल कर लेता है, जिस लड़ाई के वह कभी अकेले नहीं लड़ सकता था। विचारों सिद्धांतों की तीव्रता आवेश तथा सघनता किसी भी क्रांतिकारी लक्ष्य की प्राप्ति में एक बड़ा साधक हो सकता है। विचार व सिद्धांत एक से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरित होते रहते हैं। जिसमें विचारों को सघनता प्राप्त होती है।

लेखक
संजीव ठाकुर
चिंतक, रायपुर (छत्तीसगढ़)

सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई हरकत के बाद उजागर हो रहा है आम आदमी पार्टी का असली चेहरा

आम आदमी पार्टी की तरफ से महिला सम्मान पर डबल स्टैंडर्ड का एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया। एक तरफ हरियाणा में अरविंद केजरीवाल पहलवान बेटियों के सम्मान पर वोट मांग रहे थे। दूसरी तरफ दिल्ली में 32 घंटे की चुप्पी के बाद उनकी ही पार्टी ने कबूल कर लिया कि उनकी ही पार्टी की महिला सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास में बदसलूकी हुई। बाहर भले ही केजरीवाल की तरफ से महिला सुरक्षा, महिला सम्मान को लेकर नई गारंटी दी जा रही हो। लेकिन सीएम आवास में ही महिला सुरक्षित नजर नहीं आ रही हैं। वो भी किसी और ने नहीं बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल के करीबी और उनके पीए पर महिला सांसद के साथ बदसलूकी के आरोप लगे हैं। घंटे दर घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली आम आदमी पार्टी ने ये मानने में 32 घंटे लगा दिए कि केजरीवाल के शीशमहल में उनकी ही पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है। घंटों इंतजार के बाद आम आदमी पार्टी मीडिया को ये बता पाई कि केजरीवाल के पीए विभव ने ही बदतमीजी की थी। इसके साथ ही आप ये भी मान रही है कि केजरीवाल के आवास पर स्वाति मालीवाल ने पुलिस तक बुलाई थी। इस घटना के बाद बताया जा था कि विभव कुमार गुम है पर हाल ही में विभव कुमार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ दिखे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट से बुधवार की रात को एक तस्वीर आई, जिसमें अरविंद केजरीवाल के साथ उनके पीए विभव कुमार नजर आए। भाजपा ने इस तस्वीर को सोशल मीडिया मंच एक्स पर शेयर किया है और इसे लेकर हमला बोला है। इस तस्वीर को लेकर भाजपा का कहना है कि अब सबकुछ स्पष्ट हो गया है। इस फोटो में अरविंद केजरीवाल के साथ-साथ संजय सिंह भी नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की यह तस्वीर ऐसे वक्त में आई है, जब दो दिन पहले ही संजय सिंह ने कहा था कि स्वाति मालीवाल के साथ बिभव ने बदसलूकी की थी और अरविंद केजरीवाल एक्शन लेंगे। इस तस्वीर को हथियार बनाकर भाजपा ने आम आदमी पार्टी को घेरा है। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, ह्यलखनऊ एयरपोर्ट की कल रात की ये फोटो। काली शर्ट में बिभव हैं जिसने स्वाति मालीवाल को मारा। साथ में संजय सिंह जिन्होंने बताया कि बिभव ने बहुत गलत किया, केजरीवाल नाराज हैं। तीसरे खुद केजरीवाल जिन पर स्वाति को पिटवाने का आरोप(ह्य दावा है कि यह तस्वीर बुधवार रात लखनऊ एयरपोर्ट की है, जहां सपा मुखिया अखिलेश संग पीसी करने अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं।कपिल मिश्रा के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक वीडियो संदेश में कहा, ह्यअब यह स्पष्ट हो गया है कि आप की महिला सांसद स्वाति मालीवाल पर हमले के पीछे अरविंद केजरीवाल थे, क्योंकि पार्टी ने संजय सिंह के बयान के 72 घंटे बाद भी बिभव के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की थी।ह्य उन्होंने कहा कि बिभव अभी भी आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ घूम रहे हैं, इससे यह स्पष्ट है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के इशारे पर स्वाति मालीवाल पर हमला किया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने मंगलवार को माना था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार ने मुख्यमंत्री आवास पर पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ ह्यबदसलूकीह्य की और अरविंद केजरीवाल इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेंगे। स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मांग की है कि संजय सिंह के बयान के आधार पर पुलिस को तत्काल प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए और दोषियों पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए।वहीं, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्हें अभी तक औपचारिक शिकायत नहीं मिली है लेकिन उन्होंने डीडी (दैनिक डायरी) प्रविष्टि बंद नहीं की है क्योंकि मालीवाल सोमवार को थाने आई थीं और उन्होंने कहा था कि वह शिकायत दर्ज कराने के लिए आएंगी। स्वाति मालीवाल ने कॉल और संदेशों का कोई जवाब नहीं दिया। मालीवाल दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की प्रमुख रह चुकी हैं। वहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की प्रमुख रेखा शर्मा ने ह्यएक्सह्य पर एक पोस्ट में मालीवाल की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें आवाज उठानी चाहिए। बताया जाता है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से दो बार स्वाति मालीवाल को बुलाया गया है। स्वाति मालीवाल ने पुलिस से बातचीत भी की है। संजय सिंह ने ये भले कहा कि बिभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई होगी क्योंकि उन्होंने बदतमीजी की है। लेकिन ये नहीं बताया कि क्यों बदतमीजी की और इसका आधार क्या है? सीएम के आवास में ड्राइंग रूम के अंदर वो बैठकर अरविंद केजरीवाल का इंतजार कर रही थीं। स्वाति मालीवाल केजरीवाल के साथ पिछले 15 सालों से जुड़ी हैं। उन्होंने केजरीवाल के साथ कई प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। आप की तरफ से उन्हें पहले दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष और फिर राज्यसभा भी भेजा गया। स्वाति मालीवाल ने जल्दबाजी में पुलिस को फोन तो कर दिया। लेकिन फिर कोई शिकायत नहीं दर्ज करवाई। वैसे बदसलूकी की बात की जाए तो आपको याद होगा कि योगेंद्र यादव और कई नेताओं ने मीटिंग से धक्के मारकर बाहर करने के आरोप लगाए थे। दिल्ली में अरविंद की आम आदमी पार्टी का जब गठन नहीं हुआ था, उस समय यह राजनीतिक पार्टी एक आंदोलन बनकर पूरे देश में अपनी पहचान हासिल कर चुकी थी। एक आंदोलन जिसे देश में अन्ना आंदोलन के नाम से पहचाना गया। अन्ना को बहुत बाद में यह समझ में आया कि अरविंद केजरीवाल ने उनका इस्तेमाल किया था। आंदोलन के बहाने से अरविंद अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहते थे। आम आदमी पार्टी के चाल और चरित्र की बात करें तो अन्ना हजारे ने जब अरविंद की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए तैयार हुई राजनीतिक पार्टी से जब अपने आप को पूरी तरह अलग कर लिया। उस समय किसी ने जहर देकर उनकी हत्या का प्रयास किया था। इस बात की चर्चा मीडिया में बहुत कम हुई। वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने अपने ब्लॉग में लिखा और उनकी चिकित्सा से जुड़े एक व्यक्ति ने बातचीत में इस बात को कन्फर्म किया था। चिकित्सा से जुड़े व्यक्ति ने बातचीत के क्रम में बताया था कि उनके नाम के खुलासे से उनके व्यवसाय और उनकी जान को खतरा हो सकता है। अन्ना की चिकित्सा से जुड़े उस व्यक्ति ने बताया था कि कैसे गुड़गांव के एक अस्पताल के मालिक ने उन्हें फोन करके कहा कि अन्ना हजारे उनके यहां भर्ती हैं। पूरे शरीर में जहर का असर है। इसका सबसे अच्छा उपचार प्राकृतिक चिकित्सा से ही हो सकता है। यह सुनने के बाद अन्ना को गुड़गांव से उन्होंने अपने पास बुला लिया। पद्म भूषण अन्ना हजारे की हत्या के इस प्रयास की कोई जांच नहीं हुई। कौन अन्ना की हत्या चाहता था, किसने उन्हें जहर देकर मारने का प्रयास किया। यह सारी बातें अब तक रहस्य हैं। आज भी अन्ना हजारे भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वे लोगों से अपील कर रहे हैं कि सभी इस लोकसभा चुनाव में सही उम्मीदवार चुनें क्योंकि देश की चाबी गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए। अन्ना के अनुसार, ऐसे लोगों को कभी नहीं चुनें, जिसके पीछे ईडी पड़ी हो। अन्ना ने मतदान करके लौटते समय मीडिया से यह बात कही।अन्ना हजारे ने केजरीवाल पर शराब घोटाले को लेकर कटाक्ष किया कि हमेशा याद रखें सही उम्मीदवारों को चुनें जो सही छवि वाला राजनेता हो। जेल से लौटने के बाद, शराब माफिया वाली आम आदमी पार्टी के नेताओं की छवि को सही नहीं कहा जा सकता है।

लेखक
अशोक भाटिया
वसई पूर्व, मुंबई

स्वाद बनाम सेहत

विजय गर्ग

किसी का जन्मदिन हो, विवाह समारोह या फिर कोई भी मौका, आज देखते ही देखते हर तरह के जश्न में 'फास्ट फूड' की उपस्थिति अनिवार्य - सी हो गई है। हमारे समय का हलवा पूरी और पुदीने की चटनी अब चलन से बाहर हो चुके और एक 'पिछड़ी' हुई रुचि का खाद्य मान लिए गए हैं। अब कोई इनका जिक्र तक नहीं करना चाहता । पिज्जा और बर्गर की पहुंच तो कस्बे ही नहीं, गांव-गांव तक हो गई है। इसलिए अब पेस्ट्री और पास्ता के लिए गांवों में रहने वालों को शहर नहीं भागना पड़ता। पेशेवर तौर पर तैयार खाना घर पहुंचाने वाली कुछ कंपनियां तकनीक में ऐसी चाक-चौबंद और मुस्तैद हैं कि बहुत कम वक्त में अपनी छाप छोड़ चुकी है। यहां भी बच्चों का स्वाद बदलने के लिए आती ही जा रही है। भारत के चौबीस हजार से अधिक गांवों के नाम आज पांच फास्ट फूड पहुंचाने वाली कंपनियों के पास दर्ज हैं। आगे भी तैयारी चल रही है। गांव में कार्यक्रमों का आयोजन करके शायद बाकी गांवों में छा जाने का लक्ष्य है। माता-पिता का नाम, पास्ता और सैंडविच के प्रकार अब स्कूल जाते बहुत सारे पांच साल के बच्चे को भी याद होते हैं। करीब पांच साल के दूर बच्चे तो मंचूरियन को भी पहचान लेते है। आज भारतीय समाज मे बच्चों की स्वाद ग्रंथि पर इन मीठे और नमकीन फास्ट फूड ने जितना गहरा स्थान बना लिया है, उतना नवरत चटनी, घी आटे का हलवा, लड्डू, नारियल की खीर, पकौड़े, चटपटे आलू जैसे देसी व्यंजन नहीं बना सके। ये पुरानी चीजें अब भुलाई जा रही हैं। तुरंता आहार या फास्ट फूड के कारोबार में हर दिन नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इनका आकार प्रकार, इस्तेमाल होने वाले रसायन, स्वाद, खुशबू, रंग, विविधता, खाने में सुविधाजनक होना फास्ट फूड की लोकप्रियता का प्रमुख कारण है। यह बेवजह नहीं है कि पारंपरिक भोजन और भोजन शैली की जगह अब तेजी से सिकुड़ती जा रही है। लोगों के स्वाद बदल रहे हैं। इसके प्रति ऐसा आकर्षण पैदा हुआ है कि कुछ लोग मानने लगे हैं कि यह दबी हुई भूख को जाग्रत कर देता है । पिज्जा या बर्गर का नाम लेते ही कुछ लोगों के मन में एक जायकेदार छवि बनने लगती है। एक लत की तरह की रुचि का अध्ययन करने की जरूरत है कि अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है ! इसमें कौन-सी ऐसी चीज का प्रयोग किया जाता है कि लोग ऐसा सोचने लगते हैं ! आज हालत यह है कि बर्गर का एक टुकड़ा मुंह में रखकर आंखें बंद कर आनंद से खाने वाला अगर पराठा खाए तो शायद उसे अरुचि हो । जबकि पराठे के गुण पिज्जा से हर हाल में कई- कई गुना अधिक है।

प्रकाशक, संपादक, मुद्रक रूपेश कुमार सिंह, रैप एक्सप्रर्टस प्राइवेट लिमिटेड पटना द्वारा, कौमी तंजीम पब्लिसर्स प्रा. लिमिटेड, अमीन मंजिल, सब्जीबाग, पटना-800004 से मुद्रित। ज्योति प्रकाश भवन, जकरियापुर एसएफसी कॉलोनी, जीरो माइल गंगा पेट्रोल पंप के नजदीक, पटना से प्रकाशित। संपर्क सूत्र : 9835055017@7004145686] RNI NO&BIHHIN/2021/85413, RNI TITLE CODE : BIHHIN/11898

दैनिक इबादत

सम्पादकीय

कश्मीर शांत, पीओके अशांत

आपको 2014 से पहले का कश्मीर याद होगा जब आप टीवी पर भारतीय सेना के काफिले पर कश्मीरी युवाओं को पत्थरबाजी करते हुए देखते थे। जब भारतीय सेना किसी आतंकवादी को घेरने के लिए जाती थी तो आतंकवादियों को बचाने के लिए कश्मीरी महिलाएं उनका रास्ता रोक देती थी। इसके अलावा रोज कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में धरना प्रदर्शन और हड़ताल की खबरें आती थी। सड़कों पर पाकिस्तान का झंडा लेकर भीड़ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती थी और कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने की मांग करती थी। ऐसा लगता था कि कभी भी कश्मीर भारत से निकलकर पाकिस्तान का हिस्सा बन सकता है। आज 2024 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पुराने भारतीय कश्मीर जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पीओके की जनता पाकिस्तानी सैनिकों को सड़को पर पीट रही है और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। पाकिस्तान ने बड़ी सेना पीओके की ओर रवाना कर दी है ताकि वहां हालात पर काबू पाया जा सके। आज पीओके की जनता भारत का झंडा लेकर भारत जिंदाबाद के नारे लगा रही है और भारत में शामिल होने की मांग कर रही है। जैसे पहले कश्मीर में हिंसक प्रदर्शन होते थे और आगजनी होती थी, उसी प्रकार आज पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं और जनता आगजनी कर रही है। जो पाकिस्तान भारत पर कश्मीरी मुसलमानों के उत्पीड़न का आरोप लगाता था, आज उसकी सेना पीओके की जनता पर जुल्म कर रही है। भीड़ पर गोलियां चलाई जा रही है और उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। पाकिस्तान की सरकार जबरदस्त दबाव में है और पीओके में हालात को काबू करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। सवाल पैदा होता है कि भारतीय कश्मीर शांत कैसे हो गया है और पाकिस्तानी कश्मीर में भारतीय कश्मीर जैसे हालात कैसे पैदा हो गये हैं। सब कुछ अपने आप नहीं हुआ है, इसके पीछे मोदी सरकार की जबरदस्त योजना और मेहनत है, दूसरी तरफ इसके लिए पाकिस्तान की गलत मानसिकता भी जिम्मेदार है।

एक तरफ पीओके की जनता नरक जैसी जिंदगी भुगत रही है तो दूसरी तरफ वो भारतीय कश्मीर को जन्नत बनता देख रही है। ये जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है और अब उसने बगावत कर दी है। पाकिस्तान की सेना बहुत ताकतवर है वो इस विद्रोह को दबा देगी लेकिन कब तक वो ऐसा कर पायेगी कहा नहीं जा सकता। इसका दूसरा असर भारतीय कश्मीर की जनता पर पड़ा है और वो खुद को खुशनसीब मान रही है कि वो भारतीय हिस्से में है। अब पाकिस्तान कश्मीर की जनता को भड़का नहीं सकता क्योंकि उसने अपने हिस्से वाले कश्मीर की हालत नरक से भी बदतर कर दी है। आने वाले समय में कश्मीर में पर्यटकों की बाढ़ आने वाली है जिसके कारण कश्मीर का जबरदस्त विकास होगा और अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। आज हमें अपने कश्मीर की चिंता नहीं है बल्कि चिंता यह है कि पीओके कब हमारा हिस्सा होगा। वैसे मेरा मानना है कि वो दिन जल्दी आने वाला नहीं है क्योंकि पीओके की स्थिति बहुत जटिल है और इसमें एक पक्ष चीन का भी है। चीन ने लगभग 30 अरब डॉलर का निवेश पीओके में किया हुआ है इसलिए वो आसानी से पीओके को हाथ से निकलने नहीं देगा। इसमें एक खतरा यह भी है कि जो पाकिस्तान खुद को बेचने के लिए तैयार बैठा है वो पीओके को कभी भी चीन को बेच सकता है।

करुणामयी और स्वाभिमानी थीं सिंधिया घराने की राजमाता माधवी राजे

– राकेश अचल

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां श्रीमती माधवी राजे सिंधिया नहीं रहीं। वे लम्बे अरसे से अस्वस्थ थीं। एक लम्बे अरसे से सार्वजनिक जीवन से दूर अपने परिवार में रमीं रहने वाली श्रीमती माधवी राजे सिंधिया अपने यशस्वी खानदान की अंतिम विधिक महारानी थीं,उन्हें क़ानूनन सिंधिया राजघराने के राज चिन्हों और प्रतीकों का इस्तेमाल करते हुए महारानी रहने का सुख केवल पांच साल ही मिल सक। 1971 में भारत सरकार ने देश के तमाम राजघरानों के साथ सिंधिया राजघराने के सभी विशेषाधिकार और प्रतीक चिन्ह छीन लिए थे। श्रीमती माधवी राजे सिंधिया 8 मई 1966 को नेपाल से सिंधिया घराने की महारानी बनकर आयीं थीं। उनका विवाह सिंधिया घराने के अंतिम राज प्रमुख श्री माधवराव सिंधिया से हुआ था। उस समय राजमाता की पदवी श्रीमती विजयाराजे सिंधिया के पास थी।

माधवी राजे नेपाल के कास्की और लामजुंग के महाराजा शमशेर जंग बहादुर राणा की पुत्री थीं। विवाह से पहले उनका नाम किरण राज लक्ष्मी देवी था। सिंधिया परिवार का हिस्सा बनते ही उनका नाम किरण से माधवी राजे हो गया। श्रीमती माधवी राजे की पहली संतान चित्रांगदा राजे थीं। उनका जन्म 1967 में हुआ,उनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया 1971 में जन्मे। परम्परा ने श्रीमती माधवी राजे सिंधिया को राजमाता उसी दिन बना दिया था जिस दिन उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया का विवाह हुआ था,लेकिन वैधानिक रूप से वे राजमाता नहीं बन पायीं थी। राजमाता के रूप में जो सम्मान उनकी सास श्रीमती विजया राजे सिंधिया को हासिल हुआ था,वो भी उन्हें शायद हासिल नहीं हुआ। इसकी वजह ये है कि वे अपनी सास की तरह न तो जनता से बहुत हिलीमिली थीं और न उनकी सार्वजनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपस्थिति थी,हालाँकि उनके विवाह के पांच साल बाद ही माधवीराजे के पति माधवराव सिंधिया राजनीति में उतर आए थे। माधवराव सिंधिया ने 1971,1977 और 1980 का लोकसभा चुनाव लड़ा और जीता था।

राजघराने की परम्पराओं से बंधी श्रीमती माधवी राजे ने पहली बार राजमहल की सीढ़ियां लांघने का साहस 1985 में तब दिखाया जब उनके पति माधवराव सिंधिया ग्वालियर से भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे। मुझे खूब याद है कि उस चुनाव में श्रीमती माधवी राजे सिंधिया ने अपने पति के लिए कंधे से कन्धा मिलाकर चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया था। वे छोटी-छोटी नुक्कड़ सभाओं में भाषण देने जातीं थीं। एक सामाजिक कार्यकर्ता मनमोहन घायल तथा कुछ और लोग पूरे चुनाव में माधवी राजे सिंधिया की सभाओं और जनसम्पर्क कार्यक्रमों की रूप रेखा बनाते थे। श्रीमती माधवी राजे का ग्वालियर से मोह तब तक ज्यादा था जब तक उनके पति जीवित रहे। 2002 में माधवराव सिंधिया के आकस्मिक निधन के बाद श्रीमती माधवी राजे का राजनीति से मोह भंग हो गया।

उन्होंने अपने आपको अपने परिवार बहू,बेटे और नाती-पोतों तक सीमित कर लिया। उनका ग्वालियर आना भी पहले के मुकाबले बहुत कम हो गया था। लेकिन वे अपने पति के समर्थकों को नाम से पहचानती और पुकारती थीं। वे बहुत स्वाभिमानी और करुणामयी थी। उन्होंने अपने पति के निधन के बाद अपने बेटे को राजनीति में स्थापित होते देखकर ही सुखानुभूति कर ली लेकिन वे कभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए चुनाव प्रचार करतीं नहीं दिखाई दीं। कुछ महल की मर्यादा और कुछ परिस्थितियां उन्हें एकाकी बनाती चली गयी। अन्तिम समय में उनके बहू,बेटे और नाती महाआर्यमन ने उनका भरपूर ख्याल रखा। उनकी कमी ग्वालियर को खलेगी,क्योंकि उनके जाने के बाद ग्वालियर की एक पूरी पीढ़ी का महल में कोई अपना कहने वाला नहीं रहा। श्रीमती माधवी राजे सिंधिया और राजमाता विजयाराजे सिंधिया में कोई समानता नहीं थी लेकिन वे महल की गरिमा को आजीवन बनाये रखने में कामयाब रहीं यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उनकी एक अन्य उपलब्धि यह भी थी कि वे कभी किसी विवाद में भी नहीं उलझी।

आधुनिक जीवन का अभिशाप है हाई ब्लडप्रेशर

उच्च रक्तचाप को अक्सर 'साइलेंट किलर' कहा जाता है क्योंकि आमतौर पर इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं जब तक कि यह गंभीर जटिलताएं पैदा न कर दे। नियमित रक्तचाप जांच से उच्च रक्तचाप का शीघ्र पता लगाने और जटिलताओं को रोकने के लिए समय पर हस्तक्षेप करने में मदद मिल सकती है। स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा बताई गई दवाएं लेना भी शामिल है।

– ललित गर्ग –

उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 17 मई को 'विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है।' वर्तमान में दुनिया भर में उच्च रक्तचाप से करीब डेढ अरब से अधिक लोग पीड़ित हैं। दुनिया भर में उच्च रक्तचाप वाले अनुमानित 46 फीसदी लोग इस बात से अनजान हैं कि उन्हें उच्च रक्तचाप है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक उच्च रक्तचाप वाले पांच में से सिर्फ एक वयस्क इसे नियंत्रण में रखता है, जिसका अर्थ है कि 80 फीसदी को भारी खतरा है, जिसमें दिल का दौरा, स्ट्रोक, अनियमित दिल की धड़कन और गुर्दे को नुकसान पहुंचना आदि शामिल है। इस वर्ष की थीम के तहत 'अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापें, इसे नियंत्रित करें और लंबे समय तक जीवित रहें', इस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उच्च रक्तचाप के प्रमुख कारण हैं मोटापा, तनाव, अस्वास्थ्यकर जीवनशैली, नियमित शारीरिक गतिविधि न करना, धूम्रपान, अल्कोहल, आहार में सोडियम (नमक) की अत्यधिक मात्रा और मधुमेह जैसी कुछ स्थितियाँ भी इसका कारण बन सकती हैं। गर्भावस्था के दौरान भी उच्च रक्तचाप हो सकता है। नयी सदी की दहलीज पर खड़े महत्त्वाकांक्षी युवा-वर्ग के सामने प्रतिस्पर्धाओं का अंतहीन माहौल है। यदि वह इस बाधा दौड़ में हारता है, तो नकारात्मक तनावों से घिर जाता है, यदि जीतता है तो नयी-नयी स्पर्धाओं का चुनौति भरा संघर्ष फिर शुरू हो जाता है। अपनी विजय को स्थायी रखने तथा नये-नये कीर्तिमान स्थापित करने के लिए छल-प्रपंच और झूठ का सहारा लेता है। वैज्ञानिक कहते हैं दुनिया में जितना अधिक झूठ बढ़ा है, उतना ही अधिक हाई ब्लड प्रेशर का खतरा भी बढ़ा है। झूठ का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। उबड़-खाबड़, टेढ़ा-मेढ़ा और घुमावदार होता है वह। कुटिल व्यक्ति के विचार सदा प्रदूषित रहते हैं। यह मन का प्रदूषण उच्च रक्तचाप की जड़ है। उच्च रक्तचाप से जुड़े तमाम खतरों के बीच प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुओं (अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड) का बढ़ता चलन चिंताजनक है। चिंता इसलिए कि खतरों को जानते-बूझते भी ऐसे खाद्य पदार्थों की बाजार में उपलब्धता ज्यादा होने लगी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हाल ही में सामने आए एक अध्ययन में बताया गया है कि नियमित रूप से प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ खाने से समय पूर्व मौत का जोखिम चार फीसदी बढ़ जाता है, जिसमें उच्च रक्तचाप प्रमुख है। आमतौर पर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ रेडी टू यूज होते हैं। पैकेट वाले स्नैक्स, डिब्बाबंद फूड, कोल्ड ड्रिंक इसकी श्रेणी में आते हैं। हाई ब्लडप्रेशर का खतरा महिलाओं से ज्यादा पुरुषों में होता है। इससे बचने के लिए न केवल डाइट और लाइफ स्टाइल पर ध्यान देने की जरूरत है बल्कि तनाव को कम करना और शरीर को सक्रिय बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज भी बेहद जरूरी है। आजकल 18 साल से 50 वर्ष के लोग हाइपरटेंशन के अधिक शिकार हैं। हालांकि साठ साल की उम्र से पहले पुरुषों में उच्च रक्तचाप का खतरा ज्यादा रहता है, पर बाद में स्त्री-पुरुष दोनों में ही खतरे की आशंका बराबर होती है। देखा गया है कि जो व्यक्ति गुस्सा नहीं करते, वो कम बीमार होते हैं। जिस व्यक्ति को गुस्सा ज्यादा आता है, उनमें ब्लडप्रेशर, हाइपरटेंशन, गंभीर रूप से पीठ में दर्द की शिकायत देखी गई है। इसके साथ ही ऐसे लोगों को पेट की शिकायत भी हो सकती है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस उच्च रक्तचाप की रोकथाम और नियंत्रण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसमें नियमित व्यायाम करना, स्वस्थ भोजन और संतुलित आहार खाना, तंबाकू, अत्यधिक शराब और धूम्रपान से बचना शामिल है। जीवनशैली में ये बदलाव उच्च रक्तचाप और इसकी जटिलताओं के जोखिम को कम करने में मदद कर सकते हैं। व्यक्ति की भावनाएं, सोच, विचार और आदत में अन्तरसंबंध होता है। हमारे विचार, हमारे सोच को प्रभावित करते हैं और सोच से आदत बदलती है। इसके लिए आपको नियमित व्यायाम करना चाहिए। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस का एक प्रमुख संदेश नियमित रक्तचाप की निगरानी का महत्व है। उच्च रक्तचाप को अक्सर 'साइलेंट किलर' कहा जाता है क्योंकि आमतौर पर इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं जब तक कि यह गंभीर जटिलताएं पैदा न कर दे। नियमित रक्तचाप जांच से उच्च रक्तचाप का शीघ्र पता लगाने और जटिलताओं को रोकने के लिए समय पर हस्तक्षेप करने में मदद मिल सकती है। स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर द्वारा बताई गई दवाएं लेना भी शामिल है।

चिकित्सा-विज्ञान की अपूर्व प्रगति ने मनुष्य को इस जीवनघाती व्याधि से बचाने में कल्पनातीत सहयोग दिया है। रोग-निदान करने वाले अति संवेदी सूक्ष्म उपकरण, औषध-विज्ञान और सफल शल्य-क्रिया-ये सब किसी मृत्युंजयी तत्त्व से कम नहीं हैं। आश्चर्य तो इस बात का है कि इतना सब कुछ होते हुए भी उच्च रक्तचाप जैसी जानलेवा बीमारी का राक्षसी-पंजा नियंत्रण के बाहर है। जो चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, वे आम-आदमी के लिए अलभ्य हैं। इस महंगी चिकित्सा-सेवा के द्वारा संपन्न व्यक्ति भले ही मृत्यु के निमंत्रण को एक अवधि तक टाल दें, किंतु गरीबों की दयनीय दशा की कल्पना कौन कर सकता है? मियामी विश्वविद्यालय अमेरिका के वैज्ञानिकों/डॉक्टरों ने अपनी संयुक्त विज्ञप्ति में अपील की है कि मानसिक तनावों को अपने पर हावी न होने दें। इस संबंध में लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के तौर-तरीके सिखाने चाहिए। उनका मानना है कि निरंतर तनाव-ग्रस्त रहने और भोजन में चिकने पदार्थों का अधिक सेवन करने वालों पर हाई ब्लड प्रेशर का आक्रमण आसानी से हो जाता है। तनाव मुक्त रहने से शरीर की रोग-प्रतिरोधक शक्ति सुरक्षित रहती है। तमाम तरह के शोध इस बात का खुलासा करते रहे हैं कि ऐसे डिब्बा बन्द खाद्य पदार्थों में शुगर, फैट और नमक की मात्रा काफी अधिक होती है, जबकि फाइबर व अन्य पोषक तत्व कम होते हैं। इसीलिए प्रसंस्कृत खाद्य वस्तुएं उच्च रक्तचाप से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा देती हैं। लोग बेपरवाह होकर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। खास तौर से नई पीढ़ी को ऐसी खाद्य वस्तुएं अधिक लुभा रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस की ओर से जारी एक रिपोर्ट में पाया गया कि भारत का प्रसंस्कृत खाद्य बाजार 2011 से 2021 तक 13.37 फीसदी की सालाना दर से बढ़ा है। हालांकि कोविड-19 महामारी के दौरान इस क्षेत्र की वृद्धि दर घटकर 5.50 प्रतिशत रह गई थी, लेकिन यह अस्थायी दौर था। इसके बाद फिर इनकी उपलब्धता सहज होने लगी। उच्च रक्तचाप से ग्रस्त रोगियों में नियंत्रित परीक्षणों से पता चलता है कि पूरक पोटेशियम, फाइबर, एन-3 फैटी एसिड और फलों और सब्जियों से भरपूर और कम संतृप्त वसा वाले आहार से रक्तचाप में कमी आती है। कुछ जनसंख्या अध्ययन आहार प्रोटीन और रक्तचाप के स्तर के बीच विपरीत संबंध दिखाते हैं। नियमित रूप से कॉफी पीने से उच्च रक्तचाप के रोगियों में रक्तचाप बढ़ जाता है। 'तनाव' की भूमिका रहस्यमय बनी हुई है, 'नौकरी का तनाव' एवं 'पारिवारिक तनाव' उच्च रक्तचाप के लिए एक संभावित स्वतंत्र जोखिम कारक है। चिंता इस बात की है कि खतरनाक बन रही खाद्य वस्तुओं को बाजार से हटाने का भारत में मजबूत तंत्र नहीं है। यहां तक कि शराब और धूम्रपान जैसे नशे की चीजों को नियंत्रित करने के लिए भी कोई ठोस नीति नहीं है। असल में उच्च रक्तचाप को लेकर सरकारी स्तर पर कोई चिंतन एवं चिन्ता भी नजर नहीं आती। यह बात सही है कि केंद्र और राज्य की सरकारों ने लोगों के पोषक आहार के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं, लेकिन बाजार में बिक रही उच्च रक्तचाप के लिए नुकसानदेह वस्तुओं पर लगाम लगाने के लिए कोई ठोस नीति नहीं है। लुभाने वाले विज्ञापन इन उत्पादों को बढ़ावा दे रहे हैं। लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। जरूरी है कि सरकार नुकसानदायक खाद्य पदार्थों को लेकर सख्त विज्ञापन और विपणन नीति तो बनाए ही, इसे सख्ती से लागू भी करे।

नेताओं के एग्जिट पोल

– बाल मुकुन्द ओझा

चुनाव आयोग ने किसी भी तरह के एग्जिट पोल पर रोक लगा रखी है मगर नेताओं के एग्जिट पोल मीडिया में सुर्खियां लिए हुए है। चुनाव प्रचार के दौरान नेता तरह तरह की घोषणा कर रहे है इनमें विरोधी पार्टी की सीटों की संख्या की घोषणा भी शामिल है। इंडि गठबंधन के नेता भाजपा की सीटें 100 से 200 तक बता रहे है। बहरहाल चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। लोकसभा चुनाव के चार चरण पूरे हो गए है। दो तिहाई सीटों पर मतदान के बाद सभी पार्टियां अपनी जीत के दावे कर रही है। मतदान के बाद अब जीत-हार की चर्चा तेज हो गई है। गुणा-भाग जारी रही। बढ़े हुए मतदान प्रतिशत को लेकर सभी दलों के कार्यकर्ता अपने लिए शुभ संकेत बता रहे हैं। चौक चौराहों पर लोग चुनावी बतरस में व्यस्त है। सब की जुबान पर एक ही बात है कि सरकार कौन बना रहा है। चाय पान की थड़ियों, होटलों, परचून की दुकानों में लग रही चौपालों में समूहों में बैठे पार्टियों के कार्यकर्ता तथा समर्थक अपने-अपने आंकड़े बताकर जीत का दावा-प्रतिदावा कर रहे हैं। सियासी नेता अपनी जीत के साथ दूसरी पार्टियों की हार के दावे कर रहे है। इंडि गठबंधन के नेता एनडीए और भाजपा की सीटों के गणित में फंसे है। सभी अपने अपने हिसाब से एक दूसरे की सीटों की भविष्यवाणी कर रहे है। इंडि गठबंधन ने अपना एग्जिट पोल भी जारी कर दिया है। इंडि गठबंधन के नेता इस बात पर एकमत नहीं है कि भाजपा को कितनी सीटें मिलेगी। इंडि के नेता राहुल गाँधी, खरगे, तेजस्वी और अखिलेश यादव, अरविन्द केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी आदि ने अपने अपने हिसाब से एग्ज़िट पोल की घोषणा कर दी है। राहुल गांधी जहाँ एनडीए को 230 सीटों पर सिमटने की भविष्यवाणी कर रहे है वहीं अरविन्द केजरीवाल 100 सीटों से आगे नहीं बढ़ रहे है। लालू यादव और ठाकरे 200 से कम बता रहे है। एनडीए अपने 400 पार के नारे पर कायम है। गृह मंत्री अमित शाह इसे नारा नहीं संकल्प बता कर यह घोषणा भी कर रहे है कि चार चरणों के चुनाव के बाद एनडीए 270 सीट प्राप्त कर रहा है। इसी बीच फलोदी के सट्टा बाजार पर नज़र डाले तो भाजपा देश में सरकार बनाने की ओर बढ़ रही है। बताया जाता है 1952 में कुछ स्थानीय लोगों ने विधान सभा चुनाव को लेकर दांव लगाए तब सट्टा बाजार की शुरुआत हुई थी। फलौदी के कुछ लोग कहते हैं- यह बाजार हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। देशभर के सटोरिये इस बात पर तो एकमत है कि सरकार तो मोदी ही बनाएंगे। मगर 400 पार के दावे पर संशय व्यक्त कर रहे है। गौरतलब है लोकसभा चुनाव से पहले कई ओपिनियन पोल सामने आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी की फिर से सरकार बनती दिख रही है। हालांकि यह तो 4 जून को मतगणना के परिणाम से ही मालूम होगा कि कौन जीत रहा है और किसकी हार होंगी।

(वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर)

सजन रे ! झूठ ही बोलो

– सुनील कुमार महला

बहुत समय पहले वर्ष 1966 में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था- 'तीसरी कसम'। इस फिल्म का एक गाना बहुत प्रसिद्ध हुआ था जिसके बोल थे- 'सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है, न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है...!' आप कहेंगे कि लेखक जी आज आप 'झूठ' की बात क्यों कर रहे हैं? तो बात यह है कि आज दुनिया झूठ के बल पर ही तो चल रही है। झूठ पर झूठ फेंकों और तमाशा देखो। हमारे खासमखास रामलुभाया जी नेता हैं और इस समय देश में चुनावी सीजन भी चल रहा है। रामलुभाया जी चुनावों में जीत हासिल करने के लिए जमकर झूठ बोल रहे हैं। वो जनता के बीच 'झूठ पर झूठ' को हवा में लहराते हैं और स्वयं को ईमानदार छवि वाला बताते हैं। वैसे झूठ बोलना कोई आसान काम नहीं है। झूठ बोलना भी एक कला है। कहते हैं कि एक झूठ को सौ-पचास बार बोलते हैं तो वह सच का अहसास देने लगता है। इसलिए आमजन द्वारा झूठ को ही सच माना जा रहा है। खैर, नेता तो नेता हैं आखिर। हमें लगता है कि ऐसे लोगों को खुदा के पास नहीं जाना। खुदा के पास जाना होता तो वे कभी भी झूठ नहीं बोलते। वे कहते हैं – 'सजन रे झूठ ही बोलो, ये झूठ का ही जमाना है, झूठ में ही हाथी है और झूठ में ही घोड़ा है।' तात्पर्य है कि झूठ बोलकर चुनाव जीत जायेंगे और चुनाव जीतने पर हाथी-घोड़ा, बंगला, नौकर-चाकर सब मिल जायेंगे। इसलिए झूठ बोला जाना चुनावी सीजन का अपरिहार्य तत्व है। अब आप ही बताइए कि झूठ बोलकर सत्ता प्राप्त करेंगे तो खुदा के पास क्यों जायेंगे ? यहीं रहेंगे, इसी जमीन पर। ग़ज करेंगे, राज ! अजी सत्ता की कुर्सी में ही तो खुदा है और जब खुदा यहीं पर इस जमीं पर ही है तो उनके पास क्यों जाना ? ऐसे लोगों को सत्ता की मलाई में खुदा दिखता है। इसलिए झूठ पर झूठ परोसिए और सुर्खियों में रहिए। सच कहें तो झूठ और कुर्सी में सीधा संबंध पाया जाता है। आप जितना झूठ बोलेंगे, कुर्सी आपके उतनी ही नजदीक आती चली जायेगी। अजी ! राजनीति का कारोबार झूठ से ही तो चलता है।अजी ! झूठ बराबर कोई भी तप नहीं है। चुनावी समय में नेताओं के ठेठ झूठे भाषण सुनकर कभी कभी तो हमें लगता है कि झूठ बोलने वाले के हृदय में भगवान स्वयं निवास करते हैं। नेताओं के झूठ को जनता सच मानती है और सिर-आंखों पर बैठाती है। खैर, जो है सो है। वैसे आजकल झूठ बोलने वालों को कौआ भी नहीं काटता। कौए भी आजकल सच बोलने वालों को ही काटते हैं। झूठ बोलने वालों को कौआ काटने की बातें आजकल हवा-हवाई हो चलीं हैं। झूठ बोलने पर कौए काट रहे होते तो सारे हास्पीटल मरीजों से लद-पद हो जाते।

यहीं कारण है कि आज सर्वत्र झूठ का बोलबाला है। झूठ की पावर देखते हुए हम तो यही कह सकते हैं कि 'झूठमेव जयते'। यह भी किसी ने ग़लत ही कहा है कि झूठ के पांव नहीं होते। अजी पांव होते हैं तभी तो झूठ, सत्ता की कुर्सी तक पहुंच पाता है। दाद देनी पड़ेगी रामलुभाया जी की, चुनावों में खड़े होने के बाद इतना सलीके से झूठ बोलते हैं कि बेचारे वोटर ऐतबार न करें तो और क्या करें। इसलिए आप भी जमकर झूठ बोलिए और मजे पर मजे करिए। जय राम जी की। गुस्ताख़ी माफ़।

(फ्रीलांस राइटर, कालमिस्ट व युवा साहित्यकार, उत्तराखंड)

प्रदूषण,तनाव,गलत खानपान,व्यसन,अनिद्रा,मिलावटखोरी,व्यायाम की कमी,संसाधनों पर निर्भरता अर्थात आधुनिक जीवनशैली ने शारीरिक और मानसिक तौर पर हमें बीमार बनाया है। अब हार्ट अटैक या स्ट्रोक उम्र देखकर नहीं बल्कि छोटे बच्चों से लेकर किसी को भी,कभी भी हो सकता है। प्रदूषित वातावरण इस हद तक बढ़ गया है कि गर्भावस्था के दौरान भी गर्भ में पल रहे बच्चों में विकलांगता और जानलेवा बीमारियों में वृद्धि हो रही है।

साइलेंट किलर की भूमिका में हाइपरटेंशन

– डॉ. प्रितम भि. गेडाम

हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप, दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ती जानलेवा बीमारियों की जननी है, जिससे लाखों लोगों की समय से पहले मौत हो जाती है। अनियंत्रित उच्च रक्तचाप से दिल का दौरा या स्ट्रोक, धमनीविस्फार, दिल की धड़कन रुकना, गुर्दे संबंधित समस्याएं, आंखों की समस्या, चयापचयी समस्या, मनोभ्रंश, स्मृतिदोष जैसी जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं। उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि साधारणत इसके लक्षण दिखाई नहीं देते और अचानक शरीर में आघात होता है। हर साल 17 मई को दुनियाभर में 'विश्व उच्च रक्तचाप दिवस' हाइपरटेंशन के बारे में जागरूकता बढ़ाने, स्थिति का शीघ्र पता लगाने को बढ़ावा देने और स्वस्थ भविष्य के लिए उच्च रक्तचाप के प्रभावी प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। सामान्य बीपी अर्थात रक्तचाप 120/80 या उससे कम होता है। हाइपरटेंशन (उच्च रक्तचाप) तब होता है जब रक्त वाहिकाओं में दबाव सामान्य से बहुत अधिक (140/90 या अधिक) होता है, यह शुरुआत होती है, लेकिन अगर इलाज न किया जाए तो यह गंभीर हो सकता है। रक्त पंप करने के लिए हृदय को सामान्य से अधिक दबाव सहन करना पड़ता है। उच्च रक्तचाप का पता लगाने का एकमात्र तरीका अपने रक्तचाप की जांच करवाना है। डब्ल्यूएचओ ने उच्च रक्तचाप के बारे में कुछ मुख्य तथ्य दर्शाए हैं, दुनिया भर में 30-79 वर्ष की आयु के अनुमानित 1.28 अरब वयस्कों को उच्च रक्तचाप है, जिनमें से अधिकांश (दो-तिहाई) निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। अनुमानित 46% वयस्क उच्च रक्तचाप से पीड़ित इस बात से अनजान हैं कि उन्हें यह समस्या है। उच्च रक्तचाप से पीड़ित आधे से भी कम वयस्कों (42%) का निदान और उपचार किया जाता है। उच्च रक्तचाप से पीड़ित लगभग 5 में से केवल 1 वयस्क (21%) में यह स्थिति नियंत्रण में है। उच्च रक्तचाप दुनिया भर में असामयिक मृत्यु का एक प्रमुख कारण है, जिससे प्रति वर्ष 75 लाख मौतें होती है, जो वैश्विक स्तर पर लगभग 30 प्रतिशत मौतों के लिए जिम्मेदार है। उच्च रक्तचाप में वैश्विक प्रभाव की स्थिति पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में कहा गया है कि, यदि उच्च रक्तचाप से पीड़ित आधे लोग भी अपने रक्तचाप को नियंत्रण में रखें तो भारत देश में 2040 तक कम से कम 46 लाख असमय होने वाली मौतों को रोका जा सकता है। उच्च रक्तचाप से पीड़ित केवल 37 प्रतिशत भारतीयों का ही निदान हो पाता है और उनमें से केवल 30 प्रतिशत ही इलाज करा पाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में, देश में उच्च रक्तचाप से पीड़ित केवल 15 प्रतिशत लोगों में ही यह स्थिति नियंत्रण में है। वास्तव में, इसमें कहा गया है, देश में दिल का दौरा जैसी हृदय संबंधी बीमारियों के कारण होने वाली आधी से अधिक मौतों (52 प्रतिशत) का कारण उच्च रक्तचाप हो सकता है। जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन के एक अध्ययन के अनुसार, भारत में उच्च रक्तचाप की समस्या सबसे अधिक है, लगभग 30 प्रतिशत भारतीय आबादी इससे पीड़ित है।

हममें से 90 प्रतिशत से अधिक लोग ऐसे गलत खान-पान का सेवन कर रहे हैं, जो जानवरों के भी खाने लायक नहीं है। तैलीय, मसालेदार, नमकीन, मैदा, मीठा और प्रोसेस्ड भोजन हमारे शरीर में धीमे जहर की तरह काम करते हैं, जो हमें घातक बीमारियों से मौत के मुँह में धकेलते है। आधुनिकता और दिखावा मनुष्य के विनाश का कारण बन गया है, आधुनिकता केवल हमारे विचारों में होनी चाहिए, ये मनुष्य समझ ही नहीं रहा है, कि भौतिक सुख सब कुछ नहीं है। भौतिक सुख-सुविधा पर निर्भरता ने मनुष्य को काफी हद तक मानसिक और शारीरिक तौर पर कमजोर कर दिया है, जिससे मनुष्य की सहनशक्ति, विचारशक्ति क्षीण होकर तनाव, चिड़चिड़ापन, दुर्व्यवहार और स्वार्थीवृत्ति में लगातार वृद्धि हुयी है। इससे सामाजिक समस्याओं में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसका सीधा असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। बड़ी उम्र, आनुवंशिकी, अधिक वजन या मोटापा, शारीरिक रूप से सक्रिय न रहना, अधिक नमक वाला आहार, बहुत अधिक धूम्रपान, शराब पीना जैसी स्थिति उच्च रक्तचाप होने का ख़तरा बढ़ाता है। ग्रामीण आबादी के मुकाबले सुविधा संपन्न शहरी जनसंख्या अधिक बीमारियों का बोझ ढोते है। शहर में विकास के नाम पर शरीर कमजोर हो गए है। प्रदूषण, तनाव, गलत खानपान, व्यसन, अनिद्रा, मिलावटखोरी, व्यायाम की कमी, संसाधनों पर निर्भरता अर्थात आधुनिक जीवनशैली ने शारीरिक और मानसिक तौर पर हमें बीमार बनाया है। अब हार्ट अटैक या स्ट्रोक उम्र देखकर नहीं बल्कि छोटे बच्चों से लेकर किसी को भी, कभी भी हो सकता है। प्रदूषित वातावरण इस हद तक बढ़ गया है कि गर्भावस्था के दौरान भी गर्भ में पल रहे बच्चों में विकलांगता और जानलेवा बीमारियों में वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य सम्बंधित बढ़ती समस्याओं के मूल कारण की ओर लोगों में विशेष जागरूकता नजर नहीं आती है। बीमारियां लगातार क्यों बढ़ रही है, इसके प्रति समाज और देश में बड़े पैमाने पर इतिहास रचने लायक जनजागृति और कड़े नियमों, कानूनों की आवश्यकता है। स्वास्थ्य से खिलवाड़ होने लायक कोई भी गतिविधि देश में नहीं होनी चाहिए, ये पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की है और सरकार को पूरा सहयोग करने की नैतिकता जनता की है। हाइपरटेंशन के रोकथाम में दवा और आधुनिक जीवनशैली में बदलाव के साथ-साथ अधिक हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल खाएं, ज्यादा देर तक लगातार बैठना टाले, शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय रहें, जैसे चलना, दौड़ना, तैरना, नृत्य करना या वजन उठाने जैसी ताकत बढ़ाने वाली गतिविधियां अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने वजन को संतुलित रखें, तनाव को कम करके नियमित रूप से रक्तचाप की जाँच करें, समस्या हो तो योग्य उपचार करना आवश्यक है, चिकित्सक अनुसार देखभाल करें और औषधि लें। सकारात्मक विचारशैली, हेल्दी हॉबी, पोषक आहार, नशे से मुक्ति, स्वच्छता और रोजाना व्यायाम जैसी आदतें हमें बीमारियों से कोसों दूर रखती है। आज के युग की समस्या की सबसे बड़ी जड़ अर्थात झूठा दिखावा और लोगों से ज्यादा अपेक्षाएं है जो इंसान की सोच को कमजोर करती है, अगर हम ऐसे बेमतलब की बातों से दूर रहेंगे तो हम भावनात्मक रूप से मजबूत बनेंगे, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है।

नि:स्वार्थ परोपकार, समाज सेवा, प्रकृति और जानवरों से प्रेम, देश और समाज के प्रति नैतिक जिम्मेदारियों को निभाने से मानसिक शांति और आंतरिक संतुष्टि मिलती है कि हम इंसान बनकर जी रहे हैं, जो आज के समय में बहुत आवश्यक है, यह तनाव मुक्त जीवन जीने का एक आसान तरीका है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

झूठे वायदों एवं वादों से चुनाव को बचाना होगा

-ललित गर्ग

लोकसभा चुनाव के चार चरण पूरे हो गये हैं, पांचवें चरण की ओर बढ़ते हुए चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है। तमाम राजनीतिक दलों में वास्तविकता से दूर झूठे, तथ्य-आधारहीन, भ्रामक एवं बेबुनियाद वादे करने की आपसी होड़ बढ़ती जा रही है। राजनीतिक दल चार चरणों के बाद जिस तरह के जीत के तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं, वह हास्यास्पद एवं अविश्वसनीय है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरा होने के बाद विपक्षी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है और चार जून के बाद सरकार बनाएगा। इसी तरह ममता बनर्जी, अरविन्द केजरीवाल एवं अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की करारी हार की बात कही है। वर्ष 2019 के चुनाव के दौर भी इन नेताओं ने ऐसे ही बयान दिये थे, जो चुनाव परिणाम के बाद झूठे साबित हुए। इस तरह के अतिश्योक्तिपूर्ण, आधे-अधूरे, सत्यता से परे के बयानों से राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता अपने निचले पायदान पर पहुंच चुकी है और तेजी से घट रही है। जिस प्रकार विभिन्न दलों के नेताओं की भाषा, बयान एवं लोकलुभावन वायदे निम्न स्तर पर पहुंच रहे है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि हमारे लोकतंत्र का स्वास्थ्य कहीं-ना-कहीं खराब जरूर हो रहा है।

आम आदमी पार्टी (आप) के वादे और उनके काम के बीच फासला लगातार बढ़ता रहा है, देश की भोली भाली जनता को आपका बेटा, आपकी बेटी कहकर सहानुभूति पाने की उसकी कुचेष्ठाओं का पदार्पाश पहले ही हो गया है। आप ने अपने कामकाज के तरीके में पूरी पारदर्शिता का वादा किया था, लेकिन लोकसभा के लिए उम्मीदवारों के चयन में इसका ख्याल नहीं रखा गया है। हाल ही में पंजाब की चुनावी सभाओं में पार्टी नेता अरविन्द केजरीवाल ने बृजभूषण पर तो गंभीर आरोप लगाते हुए भाजपा को दागगार घोषित किया लेकिन वे अपने ही मुख्यमंत्री निवास पर राज्यसभा सांसद एवं पूर्व दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाती मालीमाल के साथ हुई मारपीट एवं अशिष्टता को भूल गये। निश्चित ही आप की कथनी और करनी में गहरा फासला है। इन्हीं केजरीवाल ने जनता को गुमराह करने एवं ठगने के लिये पिछले गुजरात के विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान एक सादे कागज पर अपने हस्ताक्षर करते हुए गुजरात में आप की सरकार बनने का दावा किया, जबकि उन चुनावों में आप के 4-5 सीटों पर जीत के अलावा सभी सीटों पर आप उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गयी थी। एक बार फिर इन लोकसभा चुनावों में वे ऐसा ही करते

हुए झूठे दावे कर रहे हैं। इससे आप पार्टी की विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता के दावों पर सवालिया निशान लग रहे हैं।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में दावा किया है कि उनकी पार्टी 2009 के आम चुनाव से बेहतर प्रदर्शन करेगी। यह दावा वास्तविकता से कोसों दूर है और राजनीतिक हलकों में उपहास का विषय बन गया है। जब कांग्रेस ने इन चुनावों में कोई लक्ष्य ही तय नहीं किया है तो कौन से लक्ष्य को पाने एवं जीत की बात कांग्रेस कर रही है? जैसे भाजपा ने 400 पार का लक्ष्य बनाया है, क्या कांग्रेस का ऐसा कोई लक्ष्य है? पार्टी के कार्यकर्ता बिना लक्ष्य के किसे अपना मिशन बनाये? कांग्रेस का एक दावा ये भी है कि उसने वो लोकसभा में साफ सुथरी छवि वाले उम्मीदवारों को उतार रही है लेकिन वास्तविकता इसके उलट है। कई उम्मीदवारों को भ्रष्टाचार के उन आरोपों के बाद भी टिकट दिए गए हैं जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। हाल के दिनों में, प्रत्येक राजनीतिक दल के घोषणापत्र में वादों की लंबी चौड़ी फेहरिस्त सामने आयी है। जबकि अतीत में किए उनके काम बताते हैं कि सत्ता में आने के बाद वे अपने घोषणा पत्र के कुछ ही हिस्सों को लागू कर पाते हैं। जो सत्ता में नहीं आ पाते वो अपने घोषणापत्र को कूड़े के डब्बे में डाल देते हैं। विडम्बना तो यह भी है कि जिन दलों को चुनाव जीतने की आशा नहीं है, वे बेतुके वायदे एवं घोषणाएं करके आम मतदाता को भ्रमित करते हैं। शुरुआत से ही राजनीतिक दल वादे इसलिए करते हैं कि लोग उन्हें सत्ता की चाबी सौंपे। लेकिन चुनावी मौसम में राजनीतिक दल और राजनेता अपने अपने कामों के बारे में बढ़ चढ़कर दावे करते हैं और उन्हें भरोसा रहता है कि मासूम और भोली जनता उनके दावों पर यकीन कर लेगी, इसलिए वे लुभावने वादों की झड़ी लगा देते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने उत्तरप्रदेश की एक सभा में चार चरण पूरे होने के बाद भाजपा के 5 किलो मुफ्त अनाज की जगह 10 किलो मुफ्त अनाज की घोषणा कर दी है। बेवक्त पर की गयी यह घोषणा भी पार्टी की अपरिपक्वता को उजागर कर रही है। हालांकि ऐसे वादे हमेशा खाली जाते हैं या अधूरे रहते हैं और वादे करने का मतलब उसे पूरा करना ही नहीं होता। अतीत में, कांग्रेस की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे के साथ 1971 का चुनाव जरूर जीता था। लेकिन लगातार दो बार सत्ता में आने के बाद भी देश से गरीबी नहीं हटी क्योंकि ज्यादातर सरकारी योजनाएं आम गरीबों तक पहुंची ही नहीं। अतीत गवाह है विगत दावों और वादों का हकीकत का। हालांकि यह देखना बाकी है कि किसने सबक लिया और कौन अपने वादों और दावों को प्रति गंभीर रहेगा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राजधानी लखनऊ में एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा प्रमुख ने दावा किया कि विपक्षी इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 लोकसभा सीटें जीतेगा, और सिर्फ एक सीट पर ही मुकाबला है। ऐसे अतिश्योक्तिपूर्ण बयान कभी सच होते हुए नहीं देखे गये है। निश्चित ही चुनाव परिणाम भविष्य के गर्भ में है एवं इसकी 4 जून को घोषणा सभी के लिये आश्चर्यकारी एवं चमत्कृत करने वाली होगी। देश का अगला प्रधानमंत्री चुनने के लिए चार चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। लोकसभा की कुल 543 सीटों में 380 सीटों के लिए वोट डाले चुके हैं। इन चार चरणों की वोटिंग के बाद हर राजनीतिक दल हवा का रुख भांपने की कोशिश कर रहा है लेकिन उनका यह आकलन सत्य से परे हो, बिल्कुल ही आधारहीन हो, इसे लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिये अनुकूल नहीं माना जा सकता। यहां सत्ताधारी भाजपा से लेकर विपक्षी कांग्रेस सभी अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन चार चरणों में 270 सीटें जीतने का दावा करते हुए 400 का टार्गेट आसानी से पूरा करने की बात कही, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का दावा किया है। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जो वायदे किये, उन्हें पूरा किया। 1990 के दशक और 21वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाने के वादे के साथ सत्ता में आई एवं उसने मन्दिर बना दिया। भाजपा ने खुद को पार्टी विद डिफरेंस कहकर भी प्रचारित किया और जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को खत्म करने का वादा भी किया। उसे भी पूरा किया। पिछले 10 वर्षों में देश ने विकास की जो रफ्तार पकड़ी है, उसे देश एवं दुनिया खुली आंखों से देख रही है। फिर भी चुनाव का समय मतदाताओं के जागने एवं विवेक से अपना मतदान करने की अपेक्षा करता है। लोकतंत्र में मतदाताओं की यह जिम्मेदारी बनती है कि वे चुनाव के अवसर पर राजनीतिक दलों की परख करें। झूठों एवं झूठी की एकजुटता ही जगत में कष्टों की वजह है एवं लोकतंत्र को कमजोर करने का बड़ा कारण है। जब तक ईमानदार एकजुट नहीं होंगे, तब तक जगत की कोई समस्या हल नहीं होगी। और ईमानदारों का एकजुट न होना झूठों एवं झूठों का असली बल है। कभी-कभी ऊंचा उठने, सत्ता पाने और भौतिक उपलब्धियों की महत्वाकांक्षा राष्ट्र को यह सोचने-समझने का मौका ही नहीं देती कि कुछ पाने के लिए उसने कितना खो दिया? और जब यह सोचने का मौका मिलता है तब पता चलता है कि वक्त बहुत आगे निकल गया और तब राष्ट्र अनिर्णय के ऊहापोह में दिग्भ्रमित हो जाता है। इस चुनाव को इस विम्बना से बचाना होगा।

सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई हरकत के बाद उजागर हो रहा है आम आदमी पार्टी का असली चेहरा

अशोक भाटिया

आम आदमी पार्टी की तरफ से महिला सम्मान पर डबल स्टैंडर्ड का एक नया रिकॉर्ड कायम किया गया। एक तरफ हरियाणा में अरविंद केजरीवाल पहलवान बेटियों के सम्मान पर वोट मांग रहे थे। दूसरी तरफ दिल्ली में 32 घंटे की चुप्पी के बाद उनकी ही पार्टी ने कबूल कर लिया कि उनकी ही पार्टी की महिला सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास में बदसलूकी हुई। बाहर भले ही केजरीवाल की तरफ से महिला सुरक्षा, महिला सम्मान को लेकर नई गारंटी दी जा रही हो। लेकिन सीएम आवास में ही महिला सुरक्षित नजर नहीं आ रही हैं। वो भी किसी और ने नहीं बल्कि खुद अरविंद केजरीवाल के करीबी और उनके पीए पर महिला सांसद के साथ बदसलूकी के आरोप लगे हैं। घंटे दर घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली आम आदमी पार्टी ने ये मानने में 32 घंटे लगा दिए कि केजरीवाल के शीशमहल में उनकी ही पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है। घंटों इंतजार के बाद आम आदमी पार्टी मीडिया को ये बता पाई कि केजरीवाल के पीए विभव ने ही बदतमीजी की थी। इसके साथ ही आप ये भी मान रही है कि केजरीवाल के आवास पर स्वाति मालीवाल ने पुलिस तक बुलाई थी।

इस घटना के बाद बताया जा था कि बिभव कुमार गुम है पर हाल ही में बिभव कुमार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ दिखे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट से बुधवार की रात को एक तस्वीर आई, जिसमें अरविंद केजरीवाल के साथ उनके पीए बिभव कुमार नजर आए। भाजपा ने इस तस्वीर को सोशल मीडिया मंच एक्स पर शेयर किया है और इसे लेकर हमला बोला है। इस तस्वीर को लेकर भाजपा का कहना है कि अब सबकुछ स्पष्ट हो गया है। इस फोटो में अरविंद केजरीवाल के साथ-साथ संजय सिंह भी नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार की यह तस्वीर ऐसे वक्त में आई है, जब दो दिन पहले ही संजय सिंह ने कहा था कि स्वाति मालीवाल के साथ बिभव ने बदसलूकी की थी और अरविंद केजरीवाल एक्शन लेंगे।

इस तस्वीर को हथियार बनाकर भाजपा ने आम आदमी पार्टी को घेरा है। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "लखनऊ एयरपोर्ट की कल रात की ये फोटो। काली शर्ट में बिभव हैं जिसने स्वाति मालीवाल को मारा। साथ में संजय सिंह जिन्होंने बताया कि बिभव ने बहुत गलत किया, केजरीवाल नाराज हैं। तीसरे खुद केजरीवाल जिन पर स्वाति को पिटवाने का आरोप। दावा है कि यह तस्वीर बुधवार रात लखनऊ एयरपोर्ट की है, जहां सपा मुखिया अखिलेश संग पीसी करने अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं। कपिल मिश्रा के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने एक वीडियो संदेश में कहा, "अब यह स्पष्ट हो गया है कि आप की महिला सांसद स्वाति मालीवाल पर हमले के पीछे अरविंद केजरीवाल थे, क्योंकि पार्टी ने संजय सिंह के बयान के 72 घंटे बाद भी बिभव के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की थी। उन्होंने कहा कि बिभव अभी भी आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ घूम रहे हैं, इसलिए यह स्पष्ट है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल के इशारे पर स्वाति मालीवाल पर हमला किया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने मंगलवार को माना था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार ने मुख्यमंत्री आवास पर पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ "बदसलूकी" की और अरविंद केजरीवाल इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेंगे।

स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के पीए बिभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मांग की है कि संजय सिंह के बयान के आधार पर पुलिस को तत्काल प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए और दोषियों पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए।वहीं, पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्हें अभी तक औपचारिक शिकायत नहीं मिली है लेकिन उन्होंने डीडी (दैनिक डायरी) प्रविष्टि बंद नहीं की है क्योंकि मालीवाल सोमवार को थाने आई थीं और उन्होंने कहा था कि वह शिकायत दर्ज कराने के लिए आएंगी। स्वाति मालीवाल ने कॉल और संदेशों का कोई जवाब नहीं दिया। मालीवाल दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) की प्रमुख रह चुकी हैं। वहीं, राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की प्रमुख रेखा शर्मा ने "एक्स" पर एक पोस्ट में मालीवाल की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें आवाज उठानी चाहिए।

बताया जाता है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से दो बार स्वाति मालीवाल को बुलाया गया है। स्वाति मालीवाल ने पुलिस से बातचीत भी की है। संजय सिंह ने ये भले कहा कि विभव कुमार के खिलाफ कार्रवाई होगी क्योंकि उन्होंने बदतमीजी की है। लेकिन ये नहीं बताया कि क्यों बदतमीजी की और इसका आधार क्या है? सीएम के आवास में ड्राइंग रूम के अंदर वो बैठकर अरविंद केजरीवाल का इंतजार कर रही थी। स्वाति मालीवाल केजरीवाल के साथ पिछले 15 सालों से जुड़ी हैं। उन्होंने केजरीवाल के साथ कई प्रदर्शन में हिस्सा लिया है। आप की तरफ से उन्हें पहले दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष और फिर राज्यसभा भी भेजा गया। स्वाति मालीवाल ने जल्दबाजी में पुलिस को फोन तो कर दिया। लेकिन फिर कोई शिकायत नहीं दर्ज करवाई। वैसे बदसलूकी की बात की जाए तो आपको याद होगा कि योगेंद्र यादव और कई नेताओं ने मीटिंग से धक्के मारकर बाहर करने के आरोप लगाए गए थे।

दिल्ली में अरविन्द की आम आदमी पार्टी का जब गठन नहीं हुआ था, उस समय यह राजनीतिक पार्टी एक आंदोलन बनकर पूरे देश में अपनी पहचान हासिल कर चुकी थी। एक आंदोलन जिसे देश में अन्ना आंदोलन के नाम से पहचाना गया। अन्ना को बहुत बाद में यह समझ में आया कि अरविन्द केजरीवाल ने उनका इस्तेमाल किया था। आंदोलन के बहाने से अरविन्द अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहते थे। आम आदमी पार्टी के चाल और चरित्र की बात करें तो अन्ना हजारे ने जब अरविन्द की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए तैयार हुई राजनीतिक पार्टी से जब अपने आप को पूरी तरह अलग कर लिया। उस समय किसी ने जहर देकर उनकी हत्या का प्रयास किया था। इस बात की चर्चा मीडिया में बहुत कम हुई। वरिष्ठ पत्रकार पूण्य प्रसून वाजपेयी ने अपने ब्लॉग में लिखा और उनकी चिकित्सा से जुड़े एक व्यक्ति ने बातचीत में इस बात को कन्फर्म किया था। चिकित्सा से जुड़े व्यक्ति ने बातचीत के क्रम में बताया था कि उनके नाम के खुलासे से उनके व्यवसाय और उनकी जान को खतरा हो सकता है। अन्ना की चिकित्सा से जुड़े उस व्यक्ति ने बताया था कि कैसे गुड़गांव के एक अस्पताल के मालिक ने उन्हें फोन करके कहा कि अन्ना हजारे उनके यहां भर्ती हैं। पूरे शरीर में जहर का असर है। इसका सबसे अच्छा उपचार प्राकृतिक चिकित्सा से ही हो सकता है। यह सुनने के बाद अन्ना को गुड़गांव से उन्होंने अपने पास बुला लिया। पद्म भूषण अन्ना हजारे की हत्या के इस प्रयास की कोई जांच नहीं हुई। कौन अन्ना की हत्या चाहता था, किसने उन्हें जहर देकर मारने का प्रयास किया। यह सारी बातें अब तक रहस्य हैं।

आज भी अन्ना हजारे भी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। वे लोगों से अपील कर रहे हैं कि सभी इस लोकसभा चुनाव में सही उम्मीदवार चुनें क्योंकि देश की चाबी गलत हाथों में नहीं जानी चाहिए। अन्ना के अनुसार, ऐसे लोगों को कभी नहीं चुनें, जिसके पीछे ईडी पड़ी हो। अन्ना ने मतदान करके लौटते समय मीडिया से यह बात कही।अन्ना हजारे ने केजरीवाल पर शराब घोटाले को लेकर कटाक्ष किया कि हमेशा याद रखें सही उम्मीदवारों को चुनें जो सही छवि वाला राजनेता हो। जेल से लौटने के बाद, शराब माफिया वाली आम आदमी पार्टी के नेताओं की छवि को सही नहीं कहा जा सकता है। अन्ना दिल्ली की जनता को अपना साफ संदेश दे रहे हैं कि शराब के धंधे में लिप्त केजरीवाल की पार्टी से दूर रहें। अन्ना हजारे ने इसी बात को कुछ इस तरह से कहा कि मैं दिल्ली शराब घोटाला मामले में नाम आने के लिए अरविंद केजरीवाल की कड़ी आलोचना करता हूं, क्योंकि उन्होंने यह भ्रष्टाचार किया है। अन्ना ने कहा कि ऐसे लोगों को दोबारा नहीं चुना जाना चाहिए।दिल्ली में आम आदमी पार्टी का गठन 26 नवंबर 2012 को हुआ था। पहले पार्टी बनी और फिर दिल्ली में इनकी सरकार बन गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली वालों के सामने अपनी बेटी की कसम खाई थी कि वह कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बाद में उन्होंने दिल्ली की कुर्सी को कांग्रेस के समर्थन से हासिल किया। दिल्ली की कुर्सी बड़े-बड़े बादशाहों की नहीं हुई। फिर बेटी की झूठी कसम खाकर दिल्ली की कुर्सी पर बैठने वाले सीएम केजरीवाल के पास कितने दिनों तक यह कुर्सी रहेगी?

उनके कुर्सी का मोह उस वक्त भी दिखाई दिया जब वे जेल में थे। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने के बावजूद कुर्सी ना छोड़ने वाले, वे देश के पहले मुख्यमंत्री बने। दिल्ली वालों के बीच इस बात की खूब चर्चा है कि जो आदमी कुर्सी की खातिर अपनी बेटी की खाई हुई कसम का मान नहीं रख पाया, वह जेल जाने के बाद कुर्सी छोड़कर अपने सम्मान का मान क्या रखेगा?अब सवाल यह है कि दिल्ली की जनता ने बार बार आम आदमी पार्टी को दिल्ली में क्यों चुना? इसकी सबसे बड़ी वजह जो सामने निकल कर आई, वह यह है कि पार्टी का चाल, चेहरा, चरित्र जनता को नहीं पता था। दिल्ली के लोग इसलिए भी धोखा खा गए क्योंकि पार्टी में कोई भी चेहरा ऐसा नहीं था, जिसकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि हो। सब नए चेहरे थे। आंदोलन के समय जुड़े एक एक व्यक्ति को अरविन्द ने पार्टी से बाहर किया। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सतेन्द्र जैन जैसे कुछ पुराने लोग बचे थे तो उनके लिए जेल जाने का रास्ता खुलवाया। अब स्वाति मालिवाल के लिए भी बाहर जाने का रास्ता केजरीवाल ने खोल दिया है। मतलब अरविन्द को आम आदमी पार्टी के अंदर एक तानाशाह की तरह, एक एक चीज अपने नियंत्रण में चाहिए।

अब दिल्ली को लग रहा है कि गलती हुई है। उन्होंने गलत व्यक्ति को चुन लिया। दिल्ली की सोच थी कि यह लोग गैर राजनीति वाले हैं। यह जब राजनीति में आएंगे तो राजनीति का चेहरा बदलेगा। कुछ नहीं बदला। बल्कि "आम आदमी" के मुखौटे में लिपटा एक तानाशाह दिल्ली को मिल गया। जिसे रेफरेंडम का ख्याल सिर्फ जनता को धोखा देने के लिए आता है। आम आदमी पार्टी ने कभी इस बात पर रेफरेंडम नहीं कराया कि उनके मुख्यमंत्री को शीश महल में रहना चाहिए या माडल टाउन के टू-बीएचके में? उन्होंने कभी रेफरेंडम नहीं कराया कि उनके नेताओं को मोहल्ला क्लीनिक में इलाज कराना चाहिए या फिर लंदन जाकर? उन्होंने कभी रेफरेंडम नहीं कराया कि दिल्ली सरकार के नेताओं के बच्चों को कथित तौर पर देश के सर्वश्रेष्ठ दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ना चाहिए या फिर लाखों रुपए का चंदा देकर दाखिला देने वाले पब्लिक स्कूलों में? यह सब दिल्ली की जनता के सवाल थे लेकिन रेफरेंडम नहीं हुआ। धोखा सिर्फ दिल्ली वालों के साथ नहीं हुआ। धोखा तो उन अन्ना हजारे के साथ भी हुआ, जिन्होंने केजरीवाल को विश्वव्यापी पहचान दिलवाई।

स्वाति मालीवाल के अपमान पर यह क्या बोल गये अखिलेश, बीजेपी ने घेरा

-संजय सक्सेना

आम आदमी पार्टी की सांसद नेता और राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के संग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ केजरीवाल के एक स्टाफ द्वारा की गई बदसलूकी का मामला दिल्ली की सरहद पार करके उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी गरमाने लगा है। इस मामले की तपिश में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी झुलसते नजर आ रहे हैं। लखनऊ में प्रेस कांफ्रेस के दौरान जिसमें अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह मौजूद थे, उसमें जब केजरीवाल से स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो अखिलेश यादव माइक संभालते हुए बोलने लगे कि और भी कुछ जरूरी मुद्दे हैं। मीडिया के समाने अखिलेश द्वारा स्वाति मालिवाल को लेकर दिये गये उक्त बयान को बीजेपी ने महिलाओं के अपमान से जोड़ लिया है।

भारतीय जनता पार्टी ने बाकयदा प्रेस कांफ्रेस करके नेता अखिलेश के बयान को पूर्व सपा प्रमुख दिवंगत मुलायम सिंह यादव के उस बयान से जोड़कर उस पर कटाक्ष कर रहे हैं जिसमें उन्होंनें(मुलायम सिंह यादव) कहा था कि लड़के हैं उनसे गलती हो जाती है,कोई फांसी पर थोड़ी लटका दिया जायेगा। बता दें मुलायम का यह बयान तब सामने आया था जब उनसे लड़कियों से बलात्कार के संबंध में एक सवाल पूछा गया था।

बता दें बदसलूकी की घटना के बाद पहली बार अरविंद केजरीवाल लखनऊ में मीडिया से रुबरु हो रहे थे। अखिलेश ने केजरीवाल की तरफ से मोर्चा संभालते हुए मात्र पांच शब्दों ने पूरे मामले को खारिज करने की कोशिश की थी,लेकिन ऐसा हो नहीं सका। उन्होंने जेब से एक कागज निकालते हुए कहा... और भी कुछ जरूरी मुद्दे..। सोशल मीडिया पर अखिलेश का यह वीडियो जमकर साझा किया जा रहा है।पूरे उतर प्रदेश में इसकी तपिश महसूस की जा रही है। दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल 16 मई को लखनऊ पहुंचे थे। यहां वह अखिलेश के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ मोचार्बंदी की रणनीति तैयार कर रहे थे इसी को लेकर मीडिया से आमना सामना हुआ। मगर इस सवाल पर अरविंद केजरीवाल के मुंह से एक शब्द नहीं निकला।

मीडिया की तरफ से स्वाति मालिवाल से हुई बदसलूकी की घटना से जुड़ा सवाल भी दिल्ली सीएम की तरफ उछाला गया लेकिन इस सवाल का जवाब अखिलेश ने यह कहते हुए टाल दिया कि और भी जरूरी मुद्दे हैं। यहां आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह भी मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने मोर्चा संभाला और बीजेपी से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए कहा कि कि मणिपुर में करगिल सेनानी कि पत्नी को निर्वस्त्र किया गया, पीएम चुप रहे। पहलवान बेटियां जब जंतर मंतर पर धरने पर थी तब स्वाति भी धरने पर बैठी थीं, उस वक्त पुलिस ने मालीवाल को मारा पीटा और घसीट कर ले गई। उस समय भाजपा व प्रधानमंत्री मोदी चुप रहे। स्वाति आम आदमी पार्टी परिवार की हैं भाजपा इस पर राजनीति न करे। खास बात यह है थी कि स्वाति मालिवाल के साथ जिस शख्स पर अभद्रता करने का आरोप लग रहा है,वह अरविंद केजरीवाल के साथ लखनऊ भी आया था।

शिक्षा की ठोष वैज्ञानिक पृष्ठ भूमी, राष्ट्र की आवश्यकता

संजीव ठाकुर

हर राष्ट्र के विकास के लिए शिक्षा का अति महत्वपूर्ण किरदार होता है जिस राष्ट्र में शिक्षा,संस्कृति जितनी गहरी और समृद्ध हो वह राष्ट्र उतना ही विकसित,पुष्पित, पल्लवित होता है। इसके साथ आर्थिक तथा वैज्ञानिक सोच भी अत्यंत विचारणीय है। हर देश में राष्ट्र के प्रति और राष्ट्रहित के प्रति चिंतन करने वालों का समूह होना चाहिए,जो प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक तथा राष्ट्रहित के विचारों और विकास के मूल मंत्र को नई ऊर्जा ताजा हवा और आगे बढ़ने की सच्चाई को इंगित कर सकें' बिना संस्कृति ,संस्कार और वैचारिक क्षमता के बिना कोई भी राष्ट्र वैश्विक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय प्रगति करने की सोच भी नहीं सकता' वैचारिक और सैद्धांतिक अंतरधारा, सिद्धांतों को कुचला या नष्ट नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत वैचारिक अभिव्यक्ति भारत के संदर्भ में गणतंत्र की मूल आत्मा है।

विचार और सिद्धांत व्यक्ति की अंतःप्रज्ञा होती है। यह सिद्धांत तथा अंतः विचारधारा जनमानस तक पहुंचने से बाधित किया जाए तो अंतरात्मा को प्रभावित करती है। इसके गहरे प्रभाव से व्यक्ति वह सब कर सकता है, जो बिना मार्गदर्शन के व्यक्ति नहीं कर सकता। प्राचीन काल से अब तक मनीषियों के वैचारिक सिद्धांत और विचारधारा सदैव समाज के दिग्दर्शक मार्गदर्शक रहे हैं। इनकी भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रही है।यदि यही सिद्धांत और अंतः प्रज्ञा जनमानस आत्मसात कर लेता है, तो इसका प्रभाव एक जन आंदोलन का रूप ले लेता है और यहीं से युग परिवर्तन की लहर उत्पादित होती है। प्राचीन यूनान में एक बहुत ही कुरूप किंतु विद्वान व्यक्ति रहते थे,उनके विचारों में मौलिकता,नयापन जनजागृति की अद्भुत क्षमता थी। उनकी विद्वता के कारण आम जनमानस होने राजा से ज्यादा महत्व और बुद्धिमान मानते थे। राजकीय तानाशाही के चलते उनके विचारों के कारण उनको मृत्युदंड दे दिया गया। जहर का प्याला पीने के बाद भी विद्वान, चिंतक, सुकरात अमर हो गए, उनकी विचारधारा आज भी जीवित है, एवं लोग उसे अपनाकर अपना जीवन सुधारने में इसका उपयोग करते हैं। अब्राहम लिंकन ने अमेरिकी स्वतंत्रता के बाद दास प्रथा के बारे में कहा था कि दास भी मनुष्य हैं, उन्हें भी उतना ही जीने का अधिकार है जितना स्वामी को है। अब्राहम लिंकन के आंदोलनकारी विचार से तत्कालीन समय में अमेरिका के लोग घबरा गए थे,और उनकी हत्या कर दी गई थी। पर अब्राहम लिंकन के विचारों ने दास प्रथा के उन्मूलन की अंतर आत्मा को जागृत कर दिया था, और जनमानस ने अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए दास प्रथा से मुक्ति पाई थी।

स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। विचार एवं सिद्धांत ही व्यक्ति का निर्माण करता है। वही दुष्ट होने या महान होने का निर्णायक है। और बिना विचारों सिद्धांतों के व्यक्त व्यक्ति का अस्तित्व ही नहीं । विवेकानंद जी के विचार सर्व कालीन प्रासंगिक है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने उनके जीवित रहते हुए थे। आज हमारे बीच विवेकानंद जी स शरीर मौजूद नहीं है, पर उनके विचारों की महत्ता कायम है।भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने से और भौतिक विचार तथा सिद्धांत उतनी ही तीव्रता रखते हैं, वेग रखते हैं, जो एक समाज में परिवर्तन ला सकती है। विचारों की यह अमरता तथा तीव्रता किसी भी तानाशाह के लिए इतनी खतरनाक है, जितनी की सुप्त शेर की गुफा में रहना। जनता के मध्य शुद्ध विचारधारा के जागृत होने पर क्रांति लाई जा सकती है। फिर चाहे वह फ्रांस के वर्साय के महल का विध्वंस हो अथवा भारत की स्वतंत्रता हेतु वृहद आंदोलन हो। व्यक्ति या व्यक्तियों के दबाव को दबाने के बाद विचारों की पीड़िता ने जनसामान्य को एक गरजते हुए सिंह में तब्दील कर दिया था। यह शाश्वत सत्य है कि व्यक्ति को जरूर आप दबा सकते हैं,पर विचारधारा सिद्धांत अजर अमर होते हैं,और वही युग निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाते हैं।

विचारों के संदर्भ में कहा जाता है कि एक व्यक्ति का विचार तब तक उस व्यक्ति के पास है, जब तक वह अकेला है किंतु जैसे ही विचारधारा एवं सिद्धांत का प्रचार प्रसार होता है, तो वह व्यक्ति अकेला ना रह कर उस जैसे हजारों लाखों लोग उसके साथ हो जाते हैं। तब वह अकेला नहीं रह जाता। वह अपने विचारों के माध्यम से जन सामान्य को प्रभावित कर लोगों को उस लड़ाई में शामिल कर लेता है, जिस लड़ाई के वह कभी अकेले नहीं लड़ सकता था। विचारों सिद्धांतों की तीव्रता आवेश तथा सघनता किसी भी क्रांतिकारी लक्ष्य की प्राप्ति में एक बड़ा साधक हो सकता है। विचार व सिद्धांत एक से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरित होते रहते हैं। जिसमें विचारों को सघनता प्राप्त होती है। ताकि सत्ता के दमन के समय वैचारिक अमरता स्थाई बनी रहे। चीन उत्तर कोरिया जैसे राष्ट्रों में विचारों के इस स्वतंत्र का प्रवाह को बाधित नियंत्रित कर दिया गया। अभिव्यक्ति के तमाम माध्यमों को प्रतिबंधित कर दमन चक्र चलाया गया। वहां विचार और सिद्धांत विद्वान व्यक्ति तक ही सीमित रहे उसका फैलाव या विस्तार नहीं हो पाया। जो मानव समाज तथा मानव अधिकारों की संवेदना तथा धाराओं का उल्लंघन भी है। किसी स्वस्थ स्वतंत्र राष्ट्र के लिए व्यक्ति समाज और राष्ट्र के विचारों की स्वतंत्रता नवीनता तथा उत्कृष्टता अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि विचारधारा और सिद्धांतों को रोक पाना किसी भी सत्ता या निरंकुश राजा के नियंत्रण में नहीं होता। विचारों और सिद्धांत अनादि काल से गतिशील है तथा अनंत तक जगत तक गतिशील रहेंगे,और उसका प्रतिपादक एवं अनुशीलन कर्ता विचारों के साथ अमर हो जाते हैं।

स्वाति मालीवाल को लेकर अखिलेश के बयान पर भड़की मायावती

-अजय कुमार

बसपा सुप्रीमों मायावती ने ने कहा है कि महिलाओं की सुरक्षा, समान और उत्पीड़न पर दोहरा मातदंड नहीं अपनाना चाहिए। एक्स पर एक पोस्ट में बहनजी ने कहा कि स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता के मामले में दोषी पर अब तक कार्रवाई नहीं होना गलत है। ऐसे में राज्यसभा के सभापति और महिला आयोग को भी इस घटना का संज्ञान लेना चाहिए। बीजेपी के बाद जिस तरह से बसपा सुप्रीमों इस मुद्दे को उठा रही हैं उससे लगता है कि आम आदमी पार्टी (आप) सांसद स्वाति

मालीवाल से बदसलूकी मामले में

सियासत अभी और तेजी पकड़ेगी। इस मुद्दे पर बीजेपी पहले से आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, तो अब बसपा सुप्रीमो मायावती भी इस मैदान में उतर आई हैं।

बसपा प्रमुख मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व उत्पीड़न के साथ ही किसी भी नेता द्वारा अन्य कोई भी गलत कार्य करने पर सख्त कार्रवाई के मामले में चाहे कोई भी पार्टी या इंडी व अन्य गठबन्धन हो तो इन्हें दोहरा मापदंड नहीं अपनाना चाहिए अर्थात इन्हें बीएसपी के शीर्ष नेतृत्व से जरूर सबक लेना चाहिए। अतः आप पार्टी की महिला राज्यसभा सांसद के साथ सीएम आवास में अभद्रता के गंभीर मामले पर देश की नजर तथा दोषी के विरुद्ध अब तक कार्रवाई नहीं होना अनुचित। ऐसे में राज्यसभा के सभापति व महिला आयोग को भी इस घटना का समुचित संज्ञान लेने की जरूरत। बता दें, मायावती ने ये पोस्ट दिल्ली के के सीएम अरविन्द केजरीवाल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लिखी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वाति मालीवाल मामले में पत्रकारों के सवाल पर केजरीवाल ने चुप्पी साध ली थी तो वहीं अखिलेश ने कहा था कि इससे और भी कुछ जरूरी मुद्दे हैं। केजरीवाल की चुप्पी और अखिलेश की इस प्रतिक्रिया को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक जलते दीप
जयपुर, शुक्रवार 17 मई 2024

महंगाई से काबू पाना सबसे बड़ी चुनौती

सरकार महंगाई पर काबू पाने के लिए कई वर्ष से प्रयास कर रही है, मगर इसमें स्थिरता नहीं आ पा रही। रिजर्व बैंक ने खुदरा महंगाई पांच फीसद के नीचे रखने की मंशा से कई बार बैंक दरों में बढ़ोतरी की और अभी तक वह उनमें कटौती करने के बारे में सोच भी नहीं पा रहा। खुदरा महंगाई पिछले महीने बढ़ कर 7.74 फीसद पर पहुंच गई। अब थोक महंगाई अपने तेरह महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। पिछले महीने यह 1.26 फीसद दर्ज हुई। पिछले वर्ष मार्च में यह 1.41 फीसद थी। थोक महंगाई पिछले दो महीने से लगातार बढ़ रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का कहना है कि अप्रैल में खाद्य वस्तुओं, बिजली, कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस, खाद्य उत्पाद विनिर्माण और अन्य विनिर्माण क्षेत्रों में उत्पाद की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से थोक महंगाई बढ़ी है। इस स्थिति में कब तक सुधार की संभावना है, इसे लेकर कोई आकलन पेश नहीं किया गया है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में कब नरमी दर्ज होगी, कहना मुश्किल है। विश्व में जिस तरह संघर्ष की स्थितियां और मंदी का दौर है, उसमें कीमतों में कमी को लेकर कोई दावा नहीं किया जा सकता। विनिर्माण और बिजली क्षेत्र में महंगाई बढ़ने की वजहें भी साफ हैं। कोयला उत्पादन क्षेत्र में विकास दर सुस्त बनी हुई है। कोयला आयात बढ़ा है। ऐसे में बिजली उत्पादन पर असर पड़ना स्वाभाविक है। विनिर्माण में लागत पर खुदरा महंगाई का भी असर होता है। कोयला और बिजली की कीमतें बढ़ने से भी इस क्षेत्र में महंगाई बढ़ती है। इससे जाहिर है कि अभी आने वाले समय में जल्दी इस स्थिति में किसी सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती। महंगाई का एक बड़ा कारण विकास दर में असंतुलन भी है। कुछ क्षेत्रों में विकास दर काफी ऊंची है, तो कुछ में नीचे का रुख बना हुआ है। थोक महंगाई बढ़ने का अर्थ है कि खुदरा महंगाई पर उसका सीधा असर पड़ेगा। अगर वस्तुओं के उत्पादन पर लागत बढ़ेगी, तो खुदरा वस्तुओं की कीमतें उसके अनुपात में कहीं अधिक बढ़ी हुई दर्ज होंगी। फिर, चूंकि महंगाई का आकलन थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है, वास्तविक महंगाई उससे कहीं अधिक होती है। इसीलिए अक्सर जब सरकारी आंकड़ों में महंगाई का स्तर घटा हुआ दर्ज होता है, तब भी आम उपभोक्ता कोई राहत महसूस नहीं करता। आम चुनाव की सरगर्मी में विपक्षी दलों ने महंगाई और बेरोजगारी को मुख्य मुद्दा बनाया हुआ है। इसलिए थोक महंगाई के ताजा आंकड़े एक बार फिर उन्हें सत्तापक्ष की आलोचना का अवसर देंगे। यह एक अजीब तरह का असंतुलन है कि देश की अर्थव्यवस्था का रुख ऊपर की तरफ है, जबकि महंगाई एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसकी कुछ वजहें साफ हैं। महंगाई को सहनशील स्तर पर लाने के लिए जरूरी है कि बाजार में पूंजी का प्रवाह बढ़े, मगर बेरोजगारी बढ़ने, प्रति व्यक्ति आय घटने और क्रयशक्ति छीजती जाने की वजह से बाजार में संतुलन नहीं बन पा रहा। जिस मौसम में नई फसल की आवक तेज होती है, उसमें भी खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतें ऊंची रहती हैं। दूसरी तरफ किसान फसलों की वाजिब कीमत न मिल पाने से परेशान दिखते हैं। जब तक अर्थव्यवस्था में कायम असंतुलन दूर करने का प्रयास नहीं होता, महंगाई पर काबू पाना कठिन ही बना रहेगा।

मतदान का गिरता ग्राफ

राजनीतिक दलों और लोकतंत्र के अनुरागियों के लिये यह गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए कि आखिर चरण-दर-चरण मतदान में कमी क्यों देखी जाती रही है। निश्चित रूप से मतदान प्रतिशत में कमी चुनाव आयोग के लिये भी मंथन का विषय होना चाहिए। अब तक हुए चार चरणों में हुए मतदान के प्रतिशत में पिछले आम चुनाव के मुकाबले कमी देखी गई है। इस कमी के रुझान ने सत्ता के आकांक्षी राजनीतिक दलों की नींद उड़ायी है। हालांकि, सत्ता पक्ष व विपक्ष मतदान में कमी की अपनी सुविधा से व्याख्या कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के नेता कह रहे हैं कि वोट विपक्षी दलों के घटे हैं। वहीं विपक्ष इसकी व्याख्या सत्ता पक्ष से मोहभंग के रूप में कर रहा है। कुछ लोग मतदान में कमी की वजह गर्मी व प्रतिकूल मौसम को बता रहे हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं, जब पहले ही कहा जा रहा था कि अबकी बार फलां आंकड़ा पार तो फिर ज्यादा मतदान की क्या आवश्यकता है। बहरहाल, मतदान में कमी को राजनेताओं के प्रति घटते विश्वास के रूप में भी देखा जाना चाहिए। दरअसल, कथनी-करनी के फर्क से जनता राजनेताओं से इतनी खिन्न हो चुकी है कि वह नेताओं के वायदों-इरादों पर विश्वास करने से गुरेज करती है। बार-बार छलने से उसका राजनेताओं से मोहभंग होता जा रहा है। दरअसल, सत्ता केंद्रित राजनीति के चलते सत्ता के दंभ से लेकर दल-बदल और सरकारें बनाने-गिराने के खेल से देश का जनमानस व्यथित है। आये दिन लगने वाले आरोप-प्रत्यारोप व नकारात्मक राजनीतिक हथकंडों ने बार-बार जनता का मोह भंग ही किया है। उसे लगता है कि क्या मेरे मतदान कुछ बदलेगा भी? एक राजनेता एक बार किसी दल से चुनाव लड़ता है और फिर पाला बदलकर दूसरे दल में चला जाता है, उससे क्या लोकतंत्र का भला होगा? ऐसे ही कई सवाल मतदाता को आये दिन हैरान-परेशान करते रहते हैं। जिसका असर कालांतर मतदान प्रतिशत पर भी पड़ता है। बहरहाल, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद हुए पहले मतदान में प्रतिशत का अधिक रहना सुखद ही है। जो घाटी के लोगों के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास बढ़ने को दर्शाता है। कालांतर ये इस केंद्रशासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने और यथाशीघ्र विधानसभा चुनाव करवाने का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। बहरहाल, पूरे देश में चुनाव प्रतिशत में कमी के रुझान पर चुनाव आयोग को भी गंभीर मंथन करना चाहिए कि मतदान बढ़ाने के लिये देशव्यापी अभियान चलाने के बावजूद वोटिंग अपेक्षाओं के अनुरूप क्यों नहीं हो पायी। वहीं राजनीतिक दलों को भी आत्ममंथन करना चाहिए कि मतदाता के मोहभंग की वास्तविक वजह क्या है। उन्हें अपनी रीतियों-नीतियों तथा घोषणापत्रों की हकीकत को महसूस करना होगा। यह भी कि जनता में यह धारणा क्यों बन रही है कि वायदे सिर्फ वायदे बनकर ही रह जाते हैं। कुल मिलाकर देश में राजनीतिक धारा को लेकर जनता में जो अविश्वास गहरा हो रहा है, उसे यदि समय रहते दूर करने का प्रयास न किया गया तो आने वाले समय में उसके नकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। राजनीतिक दलों को एक -दूसरे पर आक्षेप करने का अधिकार है, लेकिन गरिमा बनी रहे। नेताओं को फेक न्यूज का सहारा लेने से बचना चाहिए। आरोपों के स्तर में लगातार आ रही गिरावट भी गंभीर चिंता का विषय है। इससे धीरे-धीरे जनप्रतिनिधियों व जनता के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की प्रतिष्ठा के अनुरूप कदापि नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही यह भी चिंतन करना होगा कि आजादी के साढ़े सात दशक बाद भी क्यों हम आम मतदाता को इतना जागरूक नहीं कर पाये कि वो वोट डालने को अपना नैतिक दायित्व मान सके। आंध्र प्रदेश की वे घटनाएं विचलित करती हैं जिसमें कुछ मतदाताओं ने मतदान की पूर्व संध्या पर हंगामा किया कि उन्हें वोट के बदले मिलने वाले रुपये कम मिले या नहीं मिले। इसी तरह आंध्र प्रदेश में ही एक रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने वोट के बदले कॉलोनी के लिये जनरेटर आदि की मांग की। निस्संदेह, बेशकीमती वोट की ऐसी सौदेबाजी भी हमारी गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए।

प्रसंगतः लड़ाई की जड़

एक बार एक बूढ़ा शहद से भरी मटकी लेकर जा रहा था। रास्ते में उसका पांव एक छोटे से पत्थर पर पड़ा तो वह लड़खड़ाया और थोड़ा शहद जमीन पर टपक गया। बूढ़ा तो संभल कर आगे चल दिया, मगर शहद पर कई मक्खियां आकर बैठ गई। मक्खियों को एक गिलहरी ने देखा तो वह फौरन उन पर झपटी। मक्खियां उड़ गईं। तभी एक बिल्ली ने गिलहरी पर झपट्टा मारा। गिलहरी भी भाग गई। उसी समय एक कुत्ता गुर्राता हुआ बिल्ली की तरफ बढ़ा। बिल्ली तो भाग गई मगर अचानक एक और कुत्ता वहां आ गया। दोनों आपस में लड़ने लगे। इतने में इन कुत्तों के मालिक भी आ गए। वे अपने कुत्तों को बचाने में लग गए। जब कुत्ते शांत नहीं हुए तो वे एक दूसरे के कुत्ते को पीटने लगे, फिर आपस में ही झगड़ पड़े। बात बढ़ गई तो उनके घर वाले और दोस्त भी आ पहुंच। कुछ देर बाद दोनों तरफ के मोहल्ले वाले भी लाठियां लेकर मैदान में आ डटे। दोनों गुटों में जमकर मारपीट होने लगी। कई लोग जख्मी हो गए। एक साधु ने उधर से गुजर रही एक बुढ़िया से पूछा, 'यह लड़ाई किसलिए हो रही है?' बुढ़िया कोई उत्तर नहीं दे सकी। साधु ने एक लड़के से पूछा तो उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। खैर किसी तरह साधु को लड़ाई की असली वजह का पता चला तो उसने भीड़ को शांत होने का इशारा किया। लड़ाई रुक गई। साधु ने पूछा, 'बिना बात समझे लड़ने वाले को आप क्या कहेंगे?' सभी मौन थे। साधु ने फिर कहा, 'हमारे यहां लड़ाई की जड़ ही यही है कि लोग जानते ही नहीं कि वे किस बात पर झगड़ रहे हैं। जिस दिन लोगों में यह समझ आ जाएगी कि लड़ने के पहले लड़ाई की जड़ जान लें तो कभी झगड़ा-फसाद होंगे ही।

झूठे वायदों एवं वादों से चुनाव को बचाना होगा

लोकसभा चुनाव के चार चरण पूरे हो गये हैं, पांचवें चरण की ओर बढ़ते हुए चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है। तमाम राजनीतिक दलों में वास्तविकता से दूर झूठे, तथ्य-आधारहीन, भ्रामक एवं बेबुनियाद वादे करने की आपसी होड़ बढ़ती जा रही है। राजनीतिक दल चार चरणों के बाद जिस तरह के जीत के तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं, वह हास्यास्पद एवं अविश्वसनीय है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरा होने के बाद विपक्षी 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' यानी इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है और चार जून के बाद सरकार बनाएगा। इसी तरह ममता बनर्जी, अरविन्द केजरीवाल एवं अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की करारी हार की बात कही है। वर्ष 2019 के चुनाव के दौर भी इन नेताओं ने ऐसे ही बयान दिये थे, जो चुनाव परिणाम के बाद झूठे साबित हुए। इस तरह के अतिश्योक्तिपूर्ण, आधे-अधूरे, सत्यता से परे के बयानों से राजनीतिक दलों की विश्वसनीयता अपने निचले पायदान पर पहुंच चुकी है और तेज़ी से घट रही है। जिस प्रकार विभिन्न दलों के नेताओं की भाषा, बयान एवं लोकलुभावन वायदे निम्न स्तर पर पहुंच रहे है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि हमारे लोकतंत्र का स्वास्थ्य कहीं-ना-कहीं खराब जरूर हो रहा है।

आम आदमी पार्टी (आप) के वादे और उनके काम के बीच फ़ासला लगातार बढ़ता रहा है, देश की भोली भाली जनता को आपका बेटा, आपकी बेटी कहकर सहानुभूति पाने की उसकी कुचेष्ठाओं का पर्दापाश पहले ही हो गया है। 'आप' ने अपने कामकाज के तरीक़े में पूरी पारदर्शिता का वादा किया था, लेकिन लोकसभा के लिए उम्मीदवारों के चयन में इसका ख्याल नहीं रखा गया है। हाल ही में पंजाब की चुनावी सभाओं में पार्टी नेता अरविन्द केजरीवाल ने बृजभूषण पर तो गंभीर आरोप लगाते हुए भाजपा को दागगार घोषित किया लेकिन वे अपने ही मुख्यमंत्री निवास पर राज्यसभा सांसद एवं पूर्व दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाती मालीमाल के साथ हुई मारपीट एवं अशिष्टता को भूल गये। निश्चित ही आप की कथनी और करनी में गहरा फासला है। इन्हीं केजरीवाल ने जनता को गुमराह करने एवं ठगने के लिये पिछले गुजरात के विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान एक सादे कागज पर अपने हस्ताक्षर करते हुए गुजरात में आप की सरकार बनने का दावा किया, जबकि उन चुनावों में आप के 4-5 सीटों पर जीत के अलावा सभी सीटों पर आप उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गयी थी। एक बार फिर इन लोकसभा चुनावों में वे ऐसा ही करते हुए झूठे दावे कर रहे हैं। इससे आप पार्टी की विश्वसनीयता एवं पारदर्शिता के दावों पर सवालिया निशान लग रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में दावा किया है कि उनकी पार्टी 2009 के आम चुनाव से बेहतर प्रदर्शन करेगी। यह दावा वास्तविकता से कोसों दूर है और राजनीतिक हलकों में उपहास का विषय बन गया है। जब कांग्रेस ने इन चुनावों में कोई लक्ष्य ही तय नहीं किया है तो कौन से लक्ष्य को पाने एवं जीत की बात कांग्रेस कर रही है? जैसे भाजपा ने 400 पार का लक्ष्य बनाया है, क्या कांग्रेस का ऐसा कोई लक्ष्य है? पार्टी के कार्यकर्ता बिना लक्ष्य के किसे अपना मिशन बनाये? कांग्रेस का एक दावा ये भी है कि वो लोकसभा में साफ सुथरी छवि वाले उम्मीदवारों को उतार रही है लेकिन वास्तविकता इसके उलट है। कई उम्मीदवारों को भ्रष्टाचार के उन आरोपों के बाद भी टिकट दिए गए हैं जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। हाल के दिनों में, प्रत्येक राजनीतिक दल के घोषणापत्र में वादों की लंबी चौड़ी फेहरिस्त सामने आयी है। जबकि अतीत में किए उनके काम बताते हैं कि सत्ता में आने के बाद वे अपने घोषणा पत्र के कुछ ही हिस्सों को लागू कर पाते हैं। जो सत्ता में नहीं आ पाते वो अपने घोषणापत्र को कूड़े के डब्बे में डाल देते हैं। विडम्बना तो यह भी है कि जिन दलों को चुनाव जीतने की आशा नहीं है, वे बेतूके वायदे एवं घोषणाएं करके आम मतदाता को भ्रमित करते हैं। शुरुआत से ही राजनीतिक दल वादे इसलिए करते हैं कि लोग उन्हें सत्ता की चाभी सौंपें।

– ललित गर्ग

तेलंगाना की राजनीति में 'मिनी पूर्वांचल' अहम फैक्टर

सरकार बनाने में रखते हैं दखल, दलों के सामने इन्हें साधने की चुनौती

तेलंगाना में एक मिनी पूर्वांचल भी बसता है जोकि वहां की राजनीति में अच्छी खासी दखल रखता है। साथ ही सरकार चुनने में भी बड़ी भागीदारी निभाता है। इसी वजह से चुनाव में हर दल इन्हें साधने का प्रयास करते हैं। जानिए किसे कहते हैं मिनी पूर्वांचल और क्या हैं यहां के लोगों के मुद्दे। पूर्वांचल (उत्तर प्रदेश-बिहार-झारखंड) के लोगों के बारे में आम धारणा है कि जहां होते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन हैदराबाद और उसके आसपास के क्षेत्रों में सरकार चुनने में भी उनकी बड़ी भागीदारी होती है। ग्रेटर हैदराबाद में भी 'मिनी पूर्वांचल' बसता है, जो दक्षिण भारत के राजनीतिक चालों और नारों से दूर अपने श्रम की ताकत से उस राज्य की हैसियत को आगे बढ़ाता है। सैकड़ों फैक्ट्रियों के मजदूर से लेकर उद्योगपति और सुरक्षा गार्ड से लेकर शीर्ष पदाधिकारी तक करीब 15 लाख पूर्वांचली मतदाता तेलंगाना के सैकड़ों बूथों पर जाते हैं और चुपचाप प्रत्याशियों की किस्मत तय करते हैं। हैदराबाद समेत आसपास के क्षेत्रों में बिखरे ये मतदाता अपने गृह राज्यों की तरह जात-पात में बंटे नहीं होते। किसी पार्टी विशेष या प्रत्याशी के प्रति आग्रह-दुराग्रह भी नहीं रखते हैं।

विकास है मुद्दा– तरक्की की तलाश में अपने गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर पलायन करके आए हैं, इसलिए विकास इनके एजेंडे में है। हाथ की जगह विकास ने ले ली है। तेलंगाना की राजनीति भी इनकी अहमियत को अच्छी तरह से समझने लगी है। बाहरी लोगों के श्रम के साथ ही वोटों की कीमत भी पहचानने लगी है। यही कारण है कि समर्थन पाने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाए जाने लगे हैं। उत्तर भारतीय नेताओं और भोजपुरी कलाकारों से रोड-शो कराए जाते हैं। पांच महीने पहले तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान भोजपुरी गायक पवन सिंह एवं अक्षरा सिंह जैसे कलाकारों को हैदराबाद की सड़कों पर घुमाया जा चुका है। इस बार प्रत्याशी उत्तर भारतीय विभिन्न संगठनों के साथ बैठकें करने में जुटे हैं। भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव आठ मई को बीआरएस के समर्थन में प्रचार करेंगे।

अर्थव्यवस्था को भी दे रहे गति– दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा पूर्वांचल के लोग तेलंगाना में ही हैं। मुंबई-सूरत के बाद हैदराबाद उत्तर भारतीयों का बड़ा ठिकाना है। गृह राज्यों से सैकड़ों किलोमीटर दूर इस हाईटेक सिटी में आकर पूर्वांचल के लोग सिर्फ मजदूरी ही नहीं करते हैं, बल्कि तेलंगाना की अर्थव्यवस्था को भी गति दे रहे हैं। केसीआर की सरकार में राज्य के मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी जैसे शीर्ष पद भी पूर्वांचलियों के हाथ में थे। वरिष्ठ पत्रकार देव कुमार पुखराज पूर्वांचलियों को हैदराबाद की लाइफ-लाइन बताते हैं। कहते हैं-बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कामगार अगर काम करना बंद कर दें तो हैदराबाद संकट में आ जाएगा। इसीलिए कोरोना के समय केसीआर की सरकार ने बिहारी कामगारों का भरपूर ख्याल रखा था।

पूर्वांचलियों के कई संगठन– हैदराबाद में पूर्वांचलियों ने अलग-अलग कई संगठन बना रखे हैं। बिहार एसोसिएशन मुख्य और मातृ संगठन है, जिससे सारे अन्य संगठन जुड़े हैं। उत्तर भारतीयों के तेलंगाना में रच-बस जाने की झलक पांच मई को मलकाजगिरी संसदीय क्षेत्र के सफीलगुडा रेलवे गेट के पास देखा गया। हैदराबाद में केंद्रीय गृहमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह की जनसभा से तीन-चार घंटे पहले दोपहर की 49 डिग्री तापमान में झुलसते आम यात्रियों को राहत पहुंचाने के लिए बिहार सहयोग समिति और नार्थ पीपुल्स एसोसिएशन के लोग बटर मिल्क लेकर खड़े थे। पटना के पास दानापुर के मूलनिवासी विनय कुमार यादव बिहार सहयोग समिति के अध्यक्ष हैं। उनके कर्मों में तेलंगाना है, लेकिन रगों में खाटी बिहारीपन है। तेलंगाना (तब अविभाजित आंध्रप्रदेश) में करीब सात दशक पहले उनके दादा के कदम पड़े थे। तीन पीढ़ियों के बाद भी विनय खुद को असली बिहारी बताते हैं और राजनीति में उसी तरह सक्रिय रहते हैं, जैसे बिहार-उत्तर प्रदेश के आम लोग।

दर्जनों फैक्ट्रियों के मालिक हैं पूर्वांचली– सीतामढ़ी से 1991 में खाली हाथ आए राम गोपाल चौधरी की हैदराबाद में तीन फैक्ट्रियां हैं। सैकड़ों लोगों को नौकरी और हजारों को रोजगार दे रखा है। लगभग छह दशक पहले सीतामढ़ी से रामदेव मिश्रा आए थे। श्रम किया, संसाधन जुटाए, फैक्ट्री खोली और देखते-देखते कामगार से नियोक्ता बन गए। आज हैदराबाद में सिर्फ सीतामढ़ी के श्रम-साधकों की दर्जनभर कंपनियां हैं, जिनसे हजारों पूर्वांचलियों को आर्थिक ताकत मिल रही है। रामदेव मिश्र नहीं रहे, पर उनके बेटे मानवेंद्र मिश्र खनन कारोबार में अच्छा दखल रखते हैं। उनकी मां डॉ. अहिल्या मिश्रा दक्षिण की प्रख्यात हिंदी सेवी के तौर पर राष्ट्रपति तक से सम्मानित हो चुकी हैं। इसी तरह रामजी मिश्रा के बेटे संजीव मिश्रा भी पिता की औद्योगिक विरासत को विस्तार दे रहे हैं। गया जिले के परमानंद शर्मा नौकरी करने आए थे। आज पाइप फैक्ट्री के मालिक हैं। औरंगाबाद जिले के एसएन शर्मा की सुरक्षा एजेंसी में पूर्वांचलियों के साथ स्थानीय लोग भी काम कर रहे हैं।

पिछले चुनाव में किसे मिले कितने मत– गत चुनावा में 41.7 प्रतिशत टीआरएस, 19.7 प्रतिशत भाजपा, 29.8 प्रतिशत कांग्रेस, 2.8 प्रतिशत एआइएमआइएम व 0.5 प्रतिशत मत जेएनपी को मिले।

नई दिल्ली : भाजपा प्रचार में काफी आगे निकली, कांग्रेस और आप में से पीछे कौन?

लोकसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा विज्ञापन मंजूरी के लिए चुनाव कार्यालय में जमा करवाए हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचिन अधिकारी के दफ्तर के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। दिल्ली में लोकसभा चुनावों के सिलसिले में निर्वाचन कार्यालय में करीब 2,084 राजनीतिक विज्ञापन मंजूरी के लिए जमा हुए हैं, उनमें से लगभग 517 आवेदन बीजेपी की ओर से आए हैं।

कांग्रेस पार्टी की ओर से 349 राजनीतिक विज्ञापनों के लिए 118 आवेदन जमा कराए गए हैं। वहीं दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनावों के सिलसिले में मात्र 6 विज्ञापनों के लिए इतने ही आवेदन डाले हैं। दिल्ली में कुल 2,423 विज्ञापनों को दी गई मंजूरी मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कुल 638 आवेदनों में से कुल 2,423 विज्ञापनों को मंजूरी दे दी है। वहीं चुनाव आयोग के पास बीजेपी के 16 विज्ञापन अभी मंजूरी के लिए पेंडिंग हैं। एक अधिकारी ने कहा, कि राजनीतिक दल चुनाव के दौरान शॉर्ट फिल्में, क्रिएटिव, विज्ञापन के लिए आवेदन डालते हैं। एक आवेदन में कई तरह के विज्ञापनों और शॉर्ट फिल्मों के लिए अनुरोध किया जा सकता है।

बिना मंजूरी वाले विज्ञापनों को हटाने की जिम्मेदारी एमसीडी की– आम चुनावों के लिए अभी चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और राजनीतिक दलों को किसी भी तरह के राजनीतिक विज्ञापनों के लिए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के दफ्तर से मंजूरी लेना आवश्यक है। 8.84 लाख से ज्यादा विज्ञापन हटाए गए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को यह जिम्मेदारी दी गई है कि राजनीतिक दलों के जो भी विज्ञापन बिना सीईओ की मंजूरी के दिल्ली सभी 12 जोन में से कहीं भी लगाए गए हों, उन्हें हटा दे। दिल्ली में लोकसभा की सात सीटें हैं। यहां बीजेपी सभी सात सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जबकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन है। इसके तहत कांग्रेस 3 सीटों पर और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव मैदान में है। पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और नई दिल्ली से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। जबकि, कांग्रेस के उम्मीदवार चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली और उत्तर पश्चिमी दिल्ली से भाग्य आजमा रहे हैं। दिल्ली में 25 मई को छठे चरण में चुनाव होगा और परिणाम 4 जून को निकलेंगे।

साइलेंट किलर की भूमिका में हाइपरटेंशन

हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप, दुनिया भर में सबसे तेजी से बढ़ती जानलेवा बीमारियों की जननी है, जिससे लाखों लोगों की समय से पहले मौत हो जाती है। अनियंत्रित उच्च रक्तचाप से दिल का दौरा या स्ट्रोक, धमनीविस्फार, दिल की धड़कन रुकना, गुर्दे संबंधित समस्याएं, आंखों की समस्या, चयापचयी समस्या, मनोभ्रंश, स्मृतिदोष जैसी जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं। उच्च रक्तचाप को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि साधारणत इसके लक्षण दिखाई नहीं देते और अचानक शरीर में आघात होता है। हर साल 17 मई को दुनियाभर में ÷विश्व उच्च रक्तचाप दिवस÷ हाइपरटेंशन के बारे में जागरूकता बढ़ाने, स्थिति का शीघ्र पता लगाने को बढ़ावा देने और स्वस्थ भविष्य के लिए उच्च रक्तचाप के प्रभावी प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। सामान्य बीपी अर्थात रक्तचाप 120/80 या उससे कम होता है। हाइपरटेंशन (उच्च रक्तचाप) तब होता है जब रक्त वाहिकाओं में दबाव सामान्य से बहुत अधिक (140/90 या अधिक) होता है, यह शुरुआत होती है, लेकिन अगर इलाज न किया जाए तो यह गंभीर हो सकता है। रक्त पंप करने के लिए हृदय को सामान्य से अधिक दबाव सहन करना पड़ता है। उच्च रक्तचाप का पता लगाने का एकमात्र तरीका अपने रक्तचाप की जांच करवाना है।

डब्ल्यूएचओ ने उच्च रक्तचाप के बारे में कुछ मुख्य तथ्य दर्शाए हैं, दुनिया भर में 30-79 वर्ष की आयु के अनुमानित 1.28 अरब वयस्कों को उच्च रक्तचाप है, जिनमें से अधिकांश (दो-तिहाई) निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं। अनुमानित 46त्न वयस्क उच्च रक्तचाप से पीड़ित इस बात से अनजान हैं कि उन्हें यह समस्या है। उच्च रक्तचाप से पीड़ित आधे से भी कम वयस्कों (42त्न) का निदान और उपचार किया जाता है। उच्च रक्तचाप से पीड़ित लगभग 5 में से केवल 1 वयस्क (21त्न) में यह स्थिति नियंत्रण में है। उच्च रक्तचाप दुनिया भर में असामयिक मृत्यु का एक प्रमुख कारण है, जिससे प्रति वर्ष 75 लाख मौतें होती है, जो वैश्विक स्तर पर लगभग 30 प्रतिशत मौतों के लिए जिम्मेदार है।

उच्च रक्तचाप में वैश्विक प्रभाव की स्थिति पर विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में कहा गया है कि, यदि उच्च रक्तचाप से पीड़ित आधे लोग भी अपने रक्तचाप को नियंत्रण में रखें तो भारत देश में 2040 तक कम से कम 46 लाख असमय होने वाली मौतों को रोका जा सकता है। उच्च रक्तचाप से पीड़ित केवल 37 प्रतिशत भारतीयों का ही निदान हो पाता है और उनमें से केवल 30 प्रतिशत ही इलाज करा पाते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में, देश में उच्च रक्तचाप से पीड़ित केवल 15 प्रतिशत लोगों में ही यह स्थिति नियंत्रण में है। वास्तव में, इसमें कहा गया है, देश में दिल का दौरा जैसी हृदय संबंधी बीमारियों के कारण होने वाली आधी से अधिक मौतों (52 प्रतिशत) का कारण उच्च रक्तचाप हो सकता है। जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन के एक अध्ययन के अनुसार, भारत में उच्च रक्तचाप

विश्व उच्च रक्तचाप दिवस विशेष

की समस्या सबसे अधिक है, लगभग 30 प्रतिशत भारतीय आबादी इससे पीड़ित है। हममें से 90 प्रतिशत से अधिक लोग ऐसे गलत खान-पान का सेवन कर रहे हैं, जो जानवरों के भी खाने लायक नहीं है। तैलीय, मसालेदार, नमकीन, मैदा, मीठा और प्रोसेस्ड भोजन हमारे शरीर में धीमे जहर की तरह काम करते हैं, जो हमें घातक बीमारियों से मौत के मुँह में धकेलते है। आधुनिकता और दिखावा मनुष्य के विनाश का कारण बन गया है, आधुनिकता केवल हमारे विचारों में होनी चाहिए, ये मनुष्य समझ ही नहीं रहा है, कि भौतिक सुख सब कुछ नहीं है। भौतिक सुख-सुविधा पर निर्भरता ने मनुष्य को काफी हद तक मानसिक और शारीरिक तौर पर कमजोर कर दिया है, जिससे मनुष्य की सहनशक्ति, विचारशक्ति क्षीण होकर तनाव, चिड़चिड़ापन, दुर्व्यवहार और स्वार्थीवृत्ति में लगातार वृद्धि हुयी है। इससे सामाजिक समस्याओं में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसका सीधा असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। बड़ी उम्र, आनुवंशिकी, अधिक वजन या मोटापा, शारीरिक रूप से सक्रिय न रहना, अधिक नमक वाला आहार, बहुत अधिक धूम्रपान, शराब पीना जैसी स्थिति उच्च रक्तचाप होने का ख़तरा बढ़ाता है।

ग्रामीण आबादी के मुकाबले सुविधा संपन्न शहरी जनसंख्या अधिक बीमारियों का बोझ ढोते है। शहर में विकास के नाम पर शरीर कमजोर हो गए है। प्रदूषण, तनाव, गलत खानपान, व्यसन, अनिद्रा, मिलावटखोरी, व्यायाम की कमी, संसाधनों पर निर्भरता अर्थात आधुनिक जीवनशैली ने शारीरिक और मानसिक तौर पर हमें बीमार बनाया है। अब हार्ट अटैक या स्ट्रोक उम्र देखकर नहीं बल्कि छोटे बच्चों से लेकर किसी को भी, कभी भी हो सकता है। प्रदूषित वातावरण इस हद तक बढ़ गया है कि गर्भावस्था के दौरान भी गर्भ में पल रहे बच्चों में विकलांगता और जानलेवा बीमारियों में वृद्धि हो रही है। स्वास्थ्य सम्बंधित बढ़ती समस्याओं के मूल कारण की ओर लोगों में विशेष जागरूकता नजर नहीं आती है। बीमारियां लगातार क्यों बढ़ रही है, इसके प्रति समाज और देश में बड़े पैमाने पर इतिहास रचने लायक जनजागृति और कड़े नियमों, कानूनों की आवश्यकता है। स्वास्थ्य से खिलवाड़ होने लायक कोई भी गतिविधि देश में नहीं होनी चाहिए, ये पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की है और सरकार को पूरा सहयोग करने की नैतिकता जनता की है।

हाइपरटेंशन के रोकथाम में दवा और आधुनिक जीवनशैली में बदलाव के साथ-साथ अधिक हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल खाएं, ज्यादा देर तक लगातार बैठना टाले, शारीरिक रूप से अधिक सक्रिय रहें, जैसे चलना, दौड़ना, तैरना, नृत्य करना या वजन उठाने जैसी ताकत बढ़ाने वाली गतिविधियां अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने वजन को संतुलित रखें, तनाव को कम करके नियमित रूप से रक्तचाप की जाँच करें, समस्या हो तो योग्य उपचार करना आवश्यक है, चिकित्सक अनुसार देखभाल करें और औषधि लें। सकारात्मक विचारशैली, हेल्दी हॉबी, पोषक आहार, नशे से मुक्ति, स्वच्छता और रोजाना व्यायाम जैसी आदतें हमें बीमारियों से कोसों दूर रखती है। आज के युग की समस्या की सबसे बड़ी जड़ अर्थात झूठा दिखावा और लोगों से ज्यादा अपेक्षाएं है जो इंसान की सोच को कमजोर करती है, अगर हम ऐसे बेमतलब की बातों से दूर रहेंगे तो हम भावनात्मक रूप से मजबूत बनेंगे, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। निस्वार्थ परोपकार, समाज सेवा, प्रकृति और जानवरों से प्रेम, देश और समाज के प्रति नैतिक जिम्मेदारियों को निभाने से मानसिक शांति और आंतरिक संतुष्टि मिलती है कि हम इंसान बनकर जी रहे हैं, जो आज के समय में बहुत आवश्यक है, यह तनाव मुक्त जीवन जीने का एक आसान तरीका है।

– डॉ. प्रितम भि. गेडाम

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

शरणार्थियों को मिली नागरिकता

पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश में दशकों से प्रताड़ित होते आ रहे गैर मुस्लिम भारतीयों को राहत देने हेतू भारत सरकार द्वारा बनाया नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का बेशक विपक्षी दलों द्वारा विरोध किया गया हो लेकिन 15.5.24 का दिन भारत में आये उपरोक्त देशों के शरणार्थियों के लिए राहत देने वाला एक ऐतिहासिक दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। गत बुधवार को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने नार्थ ब्लाक स्थित अपने कार्यालय में 14 शरणार्थियों को भारत की नागरिकता का सर्टिफिकेट सौंपकर इसकी शुरुआत की। वैसे देशभर में कुल 300 शरणार्थियों को सीएए के तहत नागरिकता प्रदान की गई। अन्य लोगों को ईमेल के जरिये नागरिकता के सर्टिफिकेट भेजे गए। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि आखिर शरणार्थियों का दशकों का इंतजार खत्म हुआ। उन्होंने इसे मोदी की गारंटी यानी वादा पूरा होने की गारंटी बताया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि मोदी सरकार हर एक शरणार्थी को भारत की नागरिकता देकर रहेगी। सीएए बंगाल में बड़ा चुनावी मुद्दा है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसके खिलाफ बयान दे रही है। वहीं, शाह ने ममता पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। वैसे तो दिसंबर 2019 में संसद में सीएए पास हुआ था, लेकिन विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर इस पर अमल नहीं हो पाया था। लगभग साढ़े चार साल बाद 11 मार्च को गृह मंत्रालय ने सीएए के नियमों को अधिसूचित कर इसे अमलीजामा पहनाने का काम शुरू किया। इसमें 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान व अफगानिस्तान से आने वाले छह धार्मिक अल्पसंख्यकों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता देने का प्रावधान है। नागरिकता के आवेदन के लिए आनलाइन पोर्टल, पूरी प्रक्रिया डिजिटल: सीएए के तहत नागरिकता के लिए सरकार ने Indiancitizenshiponline.nic.in नामक पोर्टल लांच कर आनलाइन आवेदन की सुविधा दी और शरणार्थियों को आवेदन में मदद करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। नागरिकता देने का काम तीव्र गति से पूरा करने के लिए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाया गया। इन नियमों के तहत सभी जिलों में वरिष्ठ डाक अधीक्षक की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन किया है। जिला स्तरीय समितियां आवेदन के साथ दिए दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आवेदकों को भारत के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाती हैं। इसके बाद राज्य स्तर पर निदेशक (जनगणना संचालन) की अध्यक्षता में गठित समिति इन आवेदनों पर विचार करती है और उन्हें भारत की नागरिकता के सर्टिफिकेट जारी करती है। अभी तक 14,000 निवेदन आ चुके हैं। जिन 14 शरणार्थियों को गृह सचिव ने नागरिकता का सर्टिफिकेट दिया, वे दिल्ली के हैं और दिल्ली की राज्य स्तरीय समिति ने उन्हें भारत की नागरिकता के लिए उपयुक्त पाया है।

शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने के साथ ही जहां शरणार्थियों को नई पहचान मिली वहीं भारतीय इतिहास में एक अध्याय भी जुड़ गया है। भारत सरकार का यह कदम पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बांग्लादेश में प्रताड़ित हो रहे गैर मुस्लिम भारतीयों के लिए एक राहत व आशाभरी नई सुबह की तरह है। वहीं वर्षों से भारत में रह रहे शणार्थियों को नई पहचान देने के साथ राहत भी देगा।

-इरविन

अडानी-अंबानी पर राहुल गांधी खामोश तो हैं

आचार्य विष्णु हरि

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वयं अडानी-अंबानी के खिलाफ बोलेंगे, इन पर अविश्वास जतायेंगे, राहुल गांधी से कथित दोस्ती करने पर अडानी-अंबानी को कोसेंगे, लोकसभा चुनावों को प्रभावित करने का अप्रत्यक्ष आरोप अडानी-अंबानी पर लगायेंगे, इसकी उम्मीद नहीं थी। लेकिन राजनीति ऐसी ही चीज है, कब क्या घटित हो जायेगा, कब कौन सा प्रश्न उफन पर आ जायेगा, कब कौन सा उफान वाला प्रश्न अचानक गायब हो जायेगा, यह नहीं कहा जा सकता है, शाम में किसी के साथ और सुबह किसी के साथ खड़ा हो जाना भी भारतीय राजनीति की स'चाई है। उद्योगपति तो अवसरवादी होते ही हैं, उन्हें तो सिर्फ सरकार से दोस्ती भाती है, इन्हें तो विपक्ष कीडे-मकौड़े जैसे लगते हैं। मोदी का बयान जितना सनसनीखेज है उससे कहीं ज्यादा राहुल गांधी की अडानी और अंबानी के खिलाफ खामोशी है। क्या चुनाव प्रचार के दौरान धनराशि की कमजोरी ने राहुल गांधी और कांग्रेस को अंबनाी-अडानी से पर्दे के पीछे से दोस्ती करने के लिए प्रेरित किया है? कांग्रेस आर्थिक तंगी से जूझती रही है, कांग्रेस के बैंक एकाउंट इनकम टैक्स की परिधि में है। चुनाव प्रचार के दौरान खर्च होने वाले अरबों-खरबों रूपये भी तो इन्हें नामी और बदनामी उद्योगपतियों और कारपोरेट घरानों से आते हें। इसलिए नरेन्द्र मोदी के अडानी-अंबानी विचार भी स्वभाविक ही है। सच्चाई तो है, बिना सच्चाई नरेन्द्र मोदी इतनी सनसनी खेज आरोप तो लगा ही नहीं सकते हैं? अब यहां यह प्रश्न उठता है कि नरेन्द्र मोदी के चुनाव के समर क्षेत्र में अडानी और अंबानी पर विचार क्या है? जिसके लपेटे में खुद राहुल गांधी आ गए हैं? नरेन्द्र मोदी ने एक चुनाव प्रचार के दौरान सीधे तौर पर कहा कि अडानी और अंबानी से राहुल गांधी की सिर्फ दोस्ती ही नहीं हैं, बल्कि पर्दे के पीछे समझौते हुए हैं, बडे डील हुए हैं, डील क्या है, पैसे कितने मिले हैं? मोदी का सीधा कहना है कि चुनाव के दौरान अडानी और अंबानी से राहुल गांधी को पैसे मिले हैं। पैसे की कसौटी पर राहुल गांधी ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस चुनावों के दौरान अडानी-अंबानी पर खामोश हैं। चुनावी इतिहास पर हम ध्यान केन्द्रित करेंगे तो पायेंगे कि पिछले कई चुनावों में अडानी और अंबानी एक मजबूत चुनावी मुद्दा बने रहे हैं, खासकर कांग्रेस पूरी तरह से इनके पीछे पडी रहती थी और कहती थी कि नरेन्द्र मोदी सिर्फ दिखावे के लिए प्रधानमंत्री हैं, ये तो अडानी और अंबानी के गुलाम हैं, अडानी-अंबानी की तिजोरी भरते हैं, गरीब जनता को लूटने की पूरी छूट अडानी और अंबानी को नरेन्द्र मोदी की सरकार में है। राहुल गांधी की छवि अडानी-अंबानी विरोधी है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों सहित अन्य प्रादेशिक चुनावों में इन्होंने अडानी-अंबानी विरोध का मुद्दा बनाया था। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले राहुल गांधी हमेशा अडानी-अंबानी के खिलाफ आग उगलते थे। ऐसे एक सत्य यह है कि अडानी-अंबानी जैसे जितने भी नामी और बदनामी उद्योगपति हैं, ये सबके सब कांग्रेस की ही पैदाइश है। अडानी और अंबानी का उदभव और विकास कोई नरेन्द्र मोदी के दस साल के शासनकाल में नहीं हुआ था। अडानी और अंबानी का उदभव और विकास कांग्रेस के केन्द्रीय शासन के दौरान हुआ। नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक की दोस्ती अडानी-अंबानी जैसे उद्योगपतियों से रही है। इंदिरा गांधी और अंबानी घराने के संस्थापक धीरू अंबानी की दोस्ती के किस्से राजनीतिक परिधि धूमते-फिरते रहते हैं। इंदिरा गांधी और धीरू भाई अंबानी साथ-साथ डिनर करने वाले एक फोटो भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय रहा है। ध्यान यह दिया जाना चाहिए कि धीरू भाई अंबानी का विकास इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान ही हुआ था। पहले तो देश में सिर्फ टाटा-विडला का ही नाम जाना जाता था।

यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य साधती 'मोदी-योगी' की जोड़ी

आर.के. सिन्हा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विगत मंगलवार को पवित्र वाराणसी में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपना पर्चा भरने से एक दिन पहले जब काशी में रोड शो निकाला तो उनकी साये की तरह साथ रहने वाले उत्तर प्रदेश (यूपी) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। रोड शो के सारे मार्ग में काशी की जनता ने मोदी-योगी का जिस उत्साह से अभूतपूर्व स्वागत किया उसने स्वतः कई ठोस संकेत दे दिए। वैसे भी लोकसभा चुनाव के समर में सारे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश पर लगी हुई हैं। सब जानने को उत्सुक हैं कि यूपी किस पार्टी की झोली को आगामी 4 जून को भरकर दिल्ली की सत्ता की चाबी सौंपेगा। सियासी गलियारे में वैसे भी यह कहावत पुरानी है कि दिल्ली के सिंहासन का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। यानी जिस पार्टी के पास यूपी में सबसे अधिक सीटें होंगी, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का उसका रास्ता उतना ही आसान होगा। यही वजह है कि यूपी की 80 सीटों पर जीत हासिल करने के लिए राजनीतिक दल 2024 लोकसभा चुनावों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे।

अलबत्ता सियासी पैंतरेबाजी से उलट राजनीतिक विश्लेषक यही मान रहे हैं कि इस बार यूपी में लोकसभा चुनाव के परिणाम अप्रत्याशित नहीं होंगे। भाजपा 2019 लोकसभा चुनावों का प्रदर्शन बखूबी दोहराएगी। मोदी और योगी की जोड़ी एक बार फिर करिश्माई प्रदर्शन करेगी। दरअसल,मोदी-योगी की जोड़ी जीत की गारंटी बन चुकी है, जिसके आगे विपक्षी तेवर भी ढीले नजर आते हैं। विपक्ष के पास इस जोड़ी की कोई काट नहीं।

भाजपा अगर यूपी में लोकसभा की सभी 80 सीटों पर जीत के लक्ष्य के साथ चुनावी मैदान में ताल ठोंक रही है, तो उसके पीछे भी इसी जोड़ी का भरोसा है। प्रधानमंत्री कई बार सार्वजनिक मंचों से योगी के विकास मॉडल की तारीफ कर चुके हैं। प्रधानमंत्री इसी मॉडल के जरिए यूपी की सभी सीटों पर जीत का दावा भी कर रहे हैं। जैसा कि अमरोहा की अपनी चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा भी कि 'लिखकर ले लीजिए। सात साल से यूपी में योगी की सरकार है। 2019 लोकसभा चुनाव के समय उन्हें दो ही साल काम करने का मौका मिला था। अब तो सात साल हो गए हैं। योगी ने दिखा दिया है कि गर्वनेंस क्या होता है। कानून व्यवस्था क्या होती है। विकास क्या होता है और इसलिए योगी के नेतृत्व में इस बार रिकॉर्ड टूटेगा। इस बार 2014 और 2019 का रिकॉर्ड टूटेगा और यूपी इतिहास रचेगा।'

यूपी के चुनावी सफर में 2014 का लोकसभा चुनाव मील का पत्थर साबित हुआ। इसी साल यूपी में भाजपा का सियासी वनवास पूरा हुआ। उस समय भाजपा के सामने कोई गठबंधन नहीं था। भाजपा ने करीब 43 फीसदी वोट हासिल करते हुए 80 में से 71 सीटों पर जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी ने पांच सीटें जीती ।जबकि, कांग्रेस मात्र 2 सीटों पर ही सिमटकर रह गई थी। बसपा का तो खाता भी नहीं खुला था। 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी लहर और योगी के कार्यों के दम पर बीजेपी ने चुनावी दंगल में पुनः ताल ठोंकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो साल का कार्यकाल पूरा कर चुके थे। नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी और बसपा साथ आए। रालोद ने भी साथ दिया। हालांकि चुनाव परिणाम पुनः भाजपा के पक्ष में ही रहा। भाजपा ने करीब 50 फीसदी वोट शेयर के साथ 61 सीट जीती। बसपा 10 सीट, सपा 5 सीट और कांग्रेस के खाते में महज एक सीट आई। योगी ने 2019 के बाद एक मजबूत और कड़े फैसले लेने वाले मुख्यमंत्री की छवि बनाई और जिसकी परिणिति उत्तरप्रदेश में बुलडोजर के रूप में सामने आई। जो कहीं न कहीं 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा का चुनावी सिंबल सा बन गया। मुख्यमंत्री ने राज्य में कानून व्यवस्था के मोर्चे पर अपने प्रदर्शन के चलते चुनाव को आभासी जनमत संग्रह बना दिया था। भाजपा ने चुनावों में ऐतिहासिक वापसी की और तीन दशकों से चल रहा समाजवादी पार्टी की साइकिल का पहिया पूरी तरह रुक गया। यूपी में भाजपा का वोट प्रतिशत भी 2014 के बाद से लगातार 40 फीसद के ऊपर ही बना हुआ है। विगत दो लोकसभा चुनावों के मुकाबले 2024 चुनाव में स्थिति बिल्कुल अलग है। सपा ने इस बार कांग्रेस से हाथ मिला लिया है जबकि बसपा अकेले ताल ठोंक रही है। रालोद भी इस बार भाजपा के साथ है। एनडीए ने जातीय समीकरण बैठाने के लिए अपना दल (एस), निषाद पार्टी और सुभासपा जैसे क्षेत्रीय दलों के साथ भी गठबंधन किया है। भाजपा इस लोकसभा चुनाव में यूपी में बेहतर स्थिति में है तो इसमें केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ योगी मॉडल का अहम योगदान है। केंद्र में जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारा। जिस तरह गरीब, युवा, महिला और किसानों के जीवन में खुशहाली लेकर आए उसी तरह योगी ने यूपी में सुशासन का राज कायम काम किया। योगी के सुशासन को अगर आंकड़ों के पैरामीटर पर देखें तो यह जानकर संतुष्टि होती है कि सात साल के कार्यकाल में एक भी दंगे नहीं हुए। जबकि पहले के मुख्यमंत्रियों के समय औसतन हर तीसरे-चौथे दिन एक दंगा होता था। यह किसी से छिपा नहीं है कि पहले पेशेवर माफिया और अपराधी सत्ते ता के संरक्षण में दहशत फैलाते थे। योगी राज में माफियाओं पर लगाम लगी। यूपी में जनता अब भयमुक्त है, अपराधियों के मन में कानून का खौफ है। पुलिस अपराधियों, माफियों और दंगाइयों पर कहर बनकर टूटी है। उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त, भयमुक्त एवं दंगामुक्त हुआ है। प्रदेश में पुलिस के डर से बड़े-बड़े अपराधी और माफिया प्रदेश छोड़कर या तो भाग गए या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिए हैं। यूपी में विकास योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में केंद्र सरकार ने भी भरपूर साथ दिया। यही वजह है कि केंद्र की योजनाओं यूपी में खूब फलीभूत हुई। जिस कारण यूपी की अर्थव्यवस्था में गुणात्मक सुधार हुए। वर्ष 2016-17 के मुकाबले राज्य का सकल घरेलू उत्पाद(जीएसडीपी) दोगुनी होकर 25 लाख करोड़ तक पहुंच गया। राज्य सरकार ने 2027 तक प्रदेश की अर्थ व्यवस्था को वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश का बजट 2016-17 में जहां 3.46 लाख करोड़ रुपये का था वहीं 2024-25 में यह दोगुने से भी अधिक 7.36 लाख करोड़ रुपये का हो गया। विकास के इन्हीं आंकड़ों की बदौलत भाजपा यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य हासिल करने का दावा कर रही है। लोकसभा चुनावों में कौन बाजी मारेगा यह तो भविष्य के गर्भ में छिपा है , लेकिन; इतना तो तय है कि मोदी-योगी की जोड़ी पर यूपी की जनता का विश्वास बना हुआ दिख रहा है।

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं)

बिना स्वतंत्र मीडिया के स्वस्थ लोकतंत्र को सुनिश्चित कर पाना संभव नहीं

प्रियंका सौरभ

महात्मा गांधी का यह कथन कि प्रेस की स्वतंत्रता एक अनमोल विशेषाधिकार है जिसे कोई भी देश त्याग नहीं सकता आज के वैश्विक संदर्भ में दृढ़ता से प्रतिध्वनित होता है। भारत में, एक जीवंत और स्वतंत्र प्रेस न केवल संविधान में निहित एक मौलिक अधिकार है, बल्कि लोकतंत्र की आधारशिला भी है, जो एक प्रहरी, सूचना का प्रसारक और विविध आवाज़ों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। हालाँकि, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की वर्तमान स्थिति विभिन्न चुनौतियों के कारण जांच के अधीन है। भारत में प्रेस स्वतंत्रता की वर्तमान स्थिति पर नज़र डाले तो भारत में एक विविध मीडिया परिदृश्य है जिसमें प्रिंट, प्रसारण और डिजिटल प्लेटफॉर्म शामिल हैं। हालांकि यहां काफी हद तक स्वतंत्रता है, फिर भी प्रेस की स्वतंत्रता और अखंडता के संबंध में चिंताएँ उठाई गई हैं। सेंसरशिप, स्व-सेंसरशिप, राजनीतिक हस्तक्षेप और पत्रकारों पर हमलों की घटनाओं ने प्रेस की स्वतंत्रता के क्षरण के बारे में चिंता बढ़ा दी है।

राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते राजनेताओं और मीडिया घरानों के बीच सांठगांठ के परिणामस्वरूप अक्सर पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग होती है और असहमति की आवाज़ों का दमन होता है। धमकियाँ और हमले- पत्रकारों को शारीरिक हिंसा, उत्पीड़न और धमकी का सामना करना पड़ता है, खासकर जब वे भ्रष्टाचार, मानवाधिकार उल्लंघन या सांप्रदायिक तनाव जैसे संवेदनशील मुद्दों को कवर करते हैं। कभी-कभी पत्रकारों को चुप कराने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए राजद्रोह, मानहानि और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जैसे कानूनों का दुरुपयोग किया जाता है। मीडिया संगठन, विशेष रूप से छोटे संगठन, वित्तीय बाधाओं का सामना करते हैं, जिसके कारण पत्रकारिता मानकों से समझौता होता है और कॉर्पोरेट या राजनीतिक फंडिंग पर निर्भरता होती है। इंटरनेट ने मीडिया की पहुंच का विस्तार किया है, इसने गलत सूचना और फर्जी खबरों के प्रसार को भी बढ़ावा दिया है, जिससे पारंपरिक मीडिया आउटलेट्स की विश्वसनीयता कम हो गई है।

यह बहुत शर्मनाक बात है कि हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रेस की आजादी की स्थिति पर कोई खतरा मंडराए। इस स्थिति के लिए किसी एक व्यक्ति या एक संस्था को जिम्मेवार मानना बहुत गलत होगा। लेकिन, इसके साथ ही यह भी सत्य है कि यह हमारे लिए आत्मचिंतन का समय है। यह आत्मचिंतन सरकारों को करनी है, नेताओं को करनी है, पत्रकार बंधुओं को करनी है, रिपोर्टरों को करनी है और खास तौर पर पत्रकारिता संस्थानों के मालिकों को करनी है, कि हम किस तरह की पत्रकारिता चाहते हैं। आज यह आत्मचिंतन का विषय है कि हम क्यों पत्रकार बने या आनेवाली पीढ़ियों में कोई क्यों पत्रकार बने। आज ये सवाल हमें अपने आप से पूछने हैं। साथ ही, किसी रैंकिंग आदि को देख कर यह समझना भी गलत है कि हम (प्रेस) बिल्कुल भी आजाद नहीं है। लेकिन, इतना सच जरूर है कि मीडिया में- खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में- आजकल खबरें कम, एजेंडा ज्यादा चलाया जा रहा है। यहीं आकर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, क्योंकि खबरों को इकट्ठा करनेवालों पर संस्थान मालिकों का दबाव होता है। ज्यादातर तो मालिक ही संपादक होते हैं, जो एजेंडा चलाये जाने के जाल में फंस जाते हैं।

दरअसल, एजेंडा चलाना आज के दौर में मीडिया का बिजनेस मॉडल है और यह मॉडल जब तक रहेगा, तब तक तो प्रेस पर सवाल उठते रहेंगे कि आखिर वह कितना आजाद है और उस पूंजी कितनी हावी है।यहां पर एक बात बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। वह यह कि मौजूदा दौर की वेब पत्रकारिता यानी डिजिटल मीडया इस बिजनेस मॉडल से थोड़ी अप्रभावित है, क्योंकि इसे चलाने में कम खर्च होने के चलते इस पर दबाव कम रहता है। प्रेस की स्वतंत्रता को कायम रखने के संभावित उपाय देखें तो कानूनी सुधार से उन कानूनों को संशोधित या निरस्त करें जिनका उपयोग प्रेस की स्वतंत्रता को कम करने के लिए किया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी के साथ संरेखित हों। पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए धमकियों या हमलों का सामना करने वाले पत्रकारों को पर्याप्त सुरक्षा और कानूनी सहायता प्रदान करना तथा अपराधियों को जवाबदेह ठहराना होगा।

मीडिया साक्षरता के माध्यम से प्रचार और गलत सूचना से विश्वसनीय जानकारी को पहचानने के लिए जनता को शिक्षित करने के लिए मीडिया साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा देना होगा।

नैतिक पत्रकारिता हेतु मीडिया संस्थानों को पेशेवर नैतिकता और मानकों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना, तथा ईमानदारी और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देना और स्वतंत्र मीडिया के लिए बाहरी प्रभावों पर निर्भरता कम करने के लिए स्वतंत्र मीडिया संगठनों को वित्तीय सहायता और नियामक समर्थन प्रदान करना कारगर उपाय होगा। महात्मा गांधी द्वारा मान्यता प्राप्त स्वस्थ लोकतंत्र के कामकाज के लिए स्वतंत्र प्रेस का अधिकार आवश्यक है। जबकि भारत में एक जीवंत मीडिया परिदृश्य है, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार, मीडिया संगठनों, नागरिक समाज और जनता के ठोस प्रयासों की आवश्यकता है। प्रेस की स्वतंत्रता को कायम रखकर, भारत अपने लोकतांत्रिक ताने-बाने को मजबूत कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसके नागरिकों की आवाज़ बिना किसी डर या पक्षपात के सुनी जाए।

शिक्षा का मतलब

मंथन

शिक्षा को कभी भी बच्चों पर थोपना नहीं चाहिए। बच्चों की मानसिक क्षमता, उम्र और उनकी रुचि के अनुरूप शिक्षा मिलनी चाहिए। मान लीजिए, कोई बच्चा संगीत में रुचि रखता हो तो उसे जबरन गणित मत पढ़ाइए। इससे उसकी निपुणता नष्ट होगी और रुचि भंग होगी। शिक्षक का काम केवल सूचनाओं के बोझ से बच्चे को बोझिल करना नहीं, बल्कि बच्चों की निहित संभावनाओं की पहचान कर उन्हें योग्य और तेजस्वी नागरिक बनाना है। एक बार बचपन में रवींद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर उन्हें एक स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए ले गए। स्कूल के प्रिंसिपल ने गणित के कई सवाल रवींद्रनाथ से पूछे, परंतु, रवींद्रनाथ ने एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया। अंत में प्रिंसिपल ने कहा कि आपका बेटा तो बिल्कुल कमजोर है। यह लड़का हमारे स्कूल में एडमिशन के योग्य नहीं है। भले ही गणित के आधार पर रवींद्रनाथ पीछे रहे हों, परंतु दर्शन, काव्य और संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह थे। कहने का मतबल इतना है कि एक खास विषय के आधार पर समग्र व्यक्तित्व की पहचान करना असंभव है। समग्र व्यक्ति का निर्माण केवल गणित के आधार पर नहीं होता है। इसके लिए चरित्र, आचरण, व्यवहार, संस्कार और संयम की भी जरूरत पड़ती है। सच्ची शिक्षा की बुनियाद मानवीय संवेदना और नैतिकता है। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में जो शिक्षा दी जाती है, उसमें ज्ञान–विज्ञान की जानकारियां तो है, लेकिन उसमें आत्मज्ञान और नैतिक मूल्यों को जाग्रत करने से संबंधित जानकारियों का काफी अभाव है। वस्तुतः व्यक्तित्व में आत्मज्ञान का बीजारोपण नैतिक शिक्षा और अच्छे संस्कारों पर अमल करने से होता है। अनेक ऐसें महापुरुष व संत हुए है, जिन्होंने किसी शिक्षण संस्थान में या किसी पाठशाला या विश्वविद्यालय में शिक्षा हासिल नहीं की, लेकिन नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा ने उन्हें महानता की श्रेणी में ला दिया। स्कूल और विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा के साथ आत्म– ज्ञान और नैतिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा का भी अपना महत्व है और ऐसी शिक्षा का उद्गम आध्यात्मिक मूल्यों से ही होता है।

-आचार्य सुदर्शन

इंद्रधनुष

फिटनेस मंत्रा

खरबूजे में छिपे हैं कई औषधीय गुण

गर्मियों के मौसम में मिलने वाले रसदार फल खरबूजे में 90 प्रतिशत तक पानी होता है। खरबूजे में विटामिन और मिनरल्स के साथ-साथ कई औषधीय गुण छुपे होते हैं। यह कई तरीके के रोगों की रोकथाम

के लिए कारगर होता है। खरबूजे का फल के अलावा इसके बीज भी बेहद गुणकारी होते हैं, जिनका इस्तेमाल करने से हड्डियों, बालों और नाखूनों को मजबूती मिलती है। कृषि विज्ञान केंद्र नियामतपुर में पिछले 20 वर्षों से तैनात गृह विज्ञान की एक्सपर्ट डॉ. विद्या गुप्ता ने बताया कि खरबूजा में कैल्शियम, आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी, सोडियम, पोटेशियम और फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसके बीजों में भी कई पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कई तरीके की बीमारियों से हमको राहत दिलाते हैं। खरबूजे में फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें शुगर और कैलोरी की मात्रा भी बेहद कम होती है, जिसकी वजह से यह मोटापे की समस्या से निजात दिलाता है। वजन को नियंत्रित करने में बेहद कारगर है। खरबूजे का सेवन करने से तनाव को कम करने में मदद मिलती है। यह अनिद्रा में भी राहत दिलाता है, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में खरबूजे का सेवन किया जाए, तो यह पाचन तंत्र को खराब कर सकता है। डायरिया, उल्टी और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खरबूजे के फल के अलावा इसमें मिलने वाले बीजों में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। खरबूजे के बीज को घी में भूनकर मिश्री के साथ मिलाकर खाने से सिर दर्द की समस्या से निजात मिलती है। इसके अलावा इसके बीजों का काढ़ा बनाकर गरारा करने से गले की खराश दूर होती है। खरबूजे के बीज और फल के छिलकों को पीसकर चेहरे पर लगाने से दाग धब्बों से छुटकारा मिलता है। चेहरे की त्वचा कोमल और चमकदार होती है।

ट्रैंड में

ब्रिटिश फैशन कंपनी एएसओएस के प्रोडक्ट भारत में बेचेगा रिलायंस रिटेल

ब्रिटेन की मशहूर ऑनलाइन फैशन कंपनी एएसओएस के प्रोडक्ट

भारत में बेचने के लिए रिलायंस रिटेल ने एक दीर्घकालीन साझेदारी की है। लाइसेंसिंग समझौते के तहत, रिलायंस रिटेल भारत में सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनलों पर एएसओएस के प्रोडक्ट्स ग्राहकों को उपलब्ध कराएगा। एएसओएस दुनिया भर के युवा फैशन-प्रेमियों के बीच खासा लोकप्रिय है। कंपनी के प्रोडक्ट 200 से अधिक बाजारों में उपलब्ध हैं। साझेदारी पर खुशी जाहिर करते हुए रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की निदेशक ईशा अंबानी ने कहा, 'हम अपने फैशन परिवार में एएसओएस का स्वागत करते हैं, वैश्विक फैशन रुझानों को भारत के बाजारों तक लाने के हमारे समर्पण में यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह साझेदारी भारत के प्रमुख खुदरा बाजारों में हमारी मजबूत स्थिति को दिखाती है, साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि हमारे ग्राहकों की पहुंच अत्याधुनिक फैशन तक हो, वो फैशन जो वे चाहते हैं।' एएसओएस के सीईओ जोस एंटोनियो रामोस ने कहा, 'रिलायंस रिटेल के साथ मिलकर, हम भारत में ग्राहकों के लिए अपने कुछ फैशन-आधारित ब्रांड लाने के लिए उत्साहित हैं - जिसमें एएसओएस डिज़ाइन भी शामिल है, जो इस पूरी दुनिया में सबसे बड़े ब्रिटिश फैशन ब्रांडों में से एक है।' रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (रिलायंस रिटेल), आरआईएल (रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड) समूह के तहत सभी खुदरा कंपनियों की होल्डिंग कंपनी है। रिलायंस रिटेल कुल 18,836 से अधिक स्टोर और डिजिटल ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों का एक एकीकृत ओमनी-चैनल नेटवर्क संचालित करती हैं। रिलायंस रिटेल ने अपनी न्यू कॉमर्स पहल के माध्यम से 30 लाख से अधिक व्यापारियों के साथ साझेदारी की है।

प्रेरक प्रसंग

दिव्य प्रेम के सामने दुनिया के समस्त आकर्षण फीके होते हैं

प्रत्येक मनुष्य की मूल आवश्यकता है कि वह प्रेम कर सके और प्रेम पा सके। जब मनोवैज्ञानिक मनुष्य की मूल आवश्यकताओं की बात करते हैं तो भोजन, मकान व सुरक्षा के साथ–साथ वे प्रेम को भी इसमें शामिल करते हैं। साधारणतया, व्यक्ति बाहरी दुनिया में अपने माता पिता, भाई–बहनों और रिश्तेदारों से प्रेम की उम्मीद करते हैं। बड़े होने के साथ ही वे अपने मित्रों, पति या पत्नी और अपने बच्चों से प्रेम की उम्मीद करते हैं। दुर्भाग्य से, जीवन में कभी–कभी हम यह सीखते हैं कि ये प्रेम अस्थायी होते हैं। संबंध बदलते रहते हैं। बच्चे दूर चले जाते हैं और माता–पिता गुजर जाते हैं। किसी न किसी समय पर, इस दुनिया से प्रेम खो जाने पर हमें दुख का अहसास होता है। अक्सर, दुनियावी प्रेम के खो जाने पर हम प्रभु की ओर मुड़ते हैं। जब प्रभु हमारी पुकार सुनते हैं, वे हमें किसी ऐसे व्यक्ति के पास भेज देते हैं जो हमें दिखा सकता है कि हमारे भीतर शाश्वत प्रेम सदा विद्यमान रहता है। एक सद्गुरु हमें प्रभु के प्रेम से जोड़ देता है। युगों–युगों से सद्गुरु हमें शाश्वत प्रेम पाने का तरीका बताते आए हैं। सद्गुरु हमें ध्यान का अभ्यास करना सिखाते हैं। जब हम अध्यात्म पथ पर अग्रसर होते हैं तो हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करते हैं। प्रभु को बुद्धि के माध्यम से अनुभव नहीं किया जा सकता। प्रभु प्रेम है और हमारे भीतर बसती आत्मा भी प्रेम है। प्रभु का अनुभव करने के लिए हमें उन परतों को उतारना है जो हमें दिव्य प्रेम का अनुभव करने से दूर रखती हैं। सद्गुरु प्रभु के प्रेम को हमारी ओर प्रसारित करते हैं। जब हम किसी वक्ता का व्याख्यान सुनते हैं, हम बौद्धिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब हम एक आध्यात्मिक गुरु के पास जाते हैं तो वहां हम बौद्धिक ज्ञान से कहीं अधिक पाते हैं। ज्ञान के साथ ही हम अपनी आत्मा के उत्थान का भी अनुभव करते हैं। सद्गुरु की संगत में शरीर से ऊपर उठने का अनुभव प्राकृतिक रूप से मिलता है। वह दयाधारा एक ऊर्जा है, जो हमारे विचार को शरीर से दिव्य चक्षु पर खींच लाती है। एक सद्गुरु की तवज्जो से हमारी आत्मा आत्मिक मंडलों का अनुभव करने लगती है। इस दिव्य अनुभव से हम उत्कृष्ट प्रेम में सराबोर हो जाते हैं। जब हम उस परमानंद को चख लेते हैं तो हमेशा उसी में डूबे रहना चाहते हैं। दिव्य प्रेम के सामने दुनिया के समस्त आकर्षण फीके होते हैं।

हंसगुल्ले

- सिपाही, 'चलो भाई तेरी फांसी का समय हो गया।' कैदी, 'पर मुझे तो फांसी 20 दिन बाद होने वाली थी।' सिपाही, 'जेलर साहिब कह गए हैं कि तू उनके गांव का है इसलिए तेरा काम पहले।'
- पत्नी सुबह-सुबह उठ कर सीधे मेकअप करने लगी, पति की आंख खुली। पति, 'पागल हो गई हो जो सुबह-सुबह मेकअप कर रही हो?'

पत्नी, 'चुप रहो, मैंने अपने फोन पर चेहरा देखकर खुलने वाला लॉक लगाया था, अब फोन मुझे पहचान नहीं रहा।'

उत्तम हिन्दू में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक लेख और अन्य साहित्य सामग्री प्रकाशित करवाने के इच्छुक लोग कृपया इस मेल आईडी lekhuttamhindu@gmail.com पर अपनी प्रकाशन सामग्री भेजें।

संपादकीय

आलोचना को स्वीकार करना कब सीखेंगे हम

हाल की तीन घटनाएं देखें। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को जंगल में लगी आग पर कोर्ट को सत्य न बताने और आग पर काबू पाने में लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए चीफ सेक्रेटरी को तलब किया है। बेंच ने केंद्र से भी इस आपदा पर काबू पाने के लिए राज्य को कम आर्थिक मदद देने पर सवाल किए हैं। दूसरी घटना में, केंद्र की एजेंसी ने एक न्यूज वेबसाइट के मालिक को बिना कारण बताए गिरफ्तार करने, गिरफ्तारी संबंधी और अन्य दस्तावेजों में फर्जी समय डालने और रिमांड आदेश में दो लाइनें बाद में जोड़ने का दोषी पाते हुए अदालत ने पत्रकार को तत्काल छोड़ने के आदेश दिए। यूएपीए के तहत बंद इस पत्रकार पर चीन से पैसे लेने जैसे संगीन आरोप सरकारी तंत्र ने लगाए। लेकिन कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर ही सवाल उठाकर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया। तीसरी घटना में उत्तराखंड में इस अखबार के एक संवाददाता पर अधिकारियों ने मुकदमा किया है। संवाददाता ने तीर्थयात्रियों के जाम में फंसने, ठिठुरती ठंड में भोजन, चिकित्सा और यातायात अवरुद्ध होने के कारण विभिन्न जगहों पर मौत की खबर दी थी। अहंकारी अफसर और राजनीतिज्ञों द्वारा अपनी आलोचना पर गैर-कानूनी और असंवैधानिक कदम उठाने की घटनाएं बढ़ी हैं। सरकारी दावों और हकीकत में भारी अंतर कई बार पाठकों के प्रति समर्पित मीडिया का एक वर्ग उजागर करता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता प्रजातंत्र का मूल है।

प्रेरणा

अच्छे को 'न' कहना सीखें ताकि आप सर्वश्रेष्ठ को 'हां' कह सकें। - **जॉन सी. मैक्सवेल**

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
ptvijayshankarmehta.com

बच्चों की परवरिश को चुनौती मानें, समस्या नहीं

एक समय था, जब अपने बच्चों को बड़ा होता देखकर मां का मुखड़ा खिल जाता था। पिता की छाती चौड़ी हो जाती थी। एक समय अब ऐसा आया कि अपने ही बच्चों को जवान होता देखकर पिता की कमर झुक गई और मां की आंख के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ गए। लालन-पालन समस्या बनता जा रहा है। जबकि इसे चुनौती मानें। समस्या और चुनौती में फर्क है। समस्या को चुनौती मानेंगे तो समाधान जल्दी निकल आएगा। लेकिन चुनौती को समस्या मानेंगे तो उलझ जाएंगे। इसलिए आर्ट ऑफ पैरेंटिंग में एक प्रयोग करते रहिए। अपने बच्चों को घर के धार्मिक रीति-रिवाज से जरूर जोड़िए। अब ये रिसर्च से पक्का हो गया है कि मंत्र और उसके जरिए किया गया ध्यान बच्चों में धैर्य पैदा करेगा। इसलिए बच्चों के साथ सामूहिक ध्यान भी करें। उन्हें पूजा-पाठ का हिस्सा बनाएं। ध्यान में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें तो उनके रचनात्मक गुण बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। और आप इसे समस्या न मानकर चुनौती मानेंगे तो इससे पार लग जाएंगे। क्योंकि लालन-पालन की चुनौती में यदि आप चूक गए तो नुकसान कई पीढ़ियों तक उतरेगा।

• Facebook: Pt. Vijayshankar Mehta

विश्लेषण • जाति-धर्म के परे एक वोट बैंक यह भी

चुनावों के नतीजे तय कर सकती है 'नारी शक्ति'

राजदीप सरदेसाई
वरिष्ठ पत्रकार
rajdeepsardesai52@gmail.com

2024 के चुनावी महासमर में 'एम' फैक्टर केंद्र में आ गया है। एम यानी मोदी, मुस्लिम, मंगलसूत्र, यहां तक कि मटन और मछली भी चुनावी शब्दावली का हिस्सा बन गए हैं। वहीं विपक्ष अपनी दुर्दशा के लिए मीडिया, मार्केटिंग और मनी को दोषी ठहरा सकता है। लेकिन जो 'एम' इस बार निर्णायक साबित हो सकता है, वह है- महिला। भारतीय चुनावी इतिहास में इससे पहले कभी भी महिला वोट का इतना महत्व नहीं रहा था। यह 'पॉवर ऑफ 49' वोट बैंक ही है, जो 'लहर-रहित' चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को बड़ा फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि महिलाओं का झुकाव अभी भी सत्ताधारी दल के पक्ष में अधिक है।

आइए, थोड़ा गणित करते हैं। 2019 के चुनावों में पहली बार ऐसा हुआ था, जब महिलाओं का मतदान-प्रतिशत पुरुषों की तुलना में अधिक था, चाहे थोड़ा-सा ही : 67.02 प्रतिशत की तुलना में 67.18 प्रतिशत। लेकिन मौजूदा चुनाव में, पंजीकृत महिला मतदाताओं में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो पुरुषों (5 प्रतिशत) से अधिक है। अब लगभग 47.1 करोड़ महिलाएं पंजीकृत मतदाता हैं और 12 राज्यों में लैंगिक-अनुपात 2019 के 8 राज्यों की तुलना में महिलाओं के पक्ष में हो गया है। 2019 में एक्सिस माय इंडिया पोल सर्वेक्षण से पता चला था कि 44 प्रतिशत पुरुषों की तुलना में 46 प्रतिशत महिलाओं ने भाजपा को वोट दिया था। वहीं लोकनीति-सीएसडीएस के 2019 के अध्ययन से पता चला था कि 59 प्रतिशत महिलाएं अब परिवार में पुरुष सदस्यों से स्वतंत्र होकर अपने मतदान-निर्णय स्वयं ले रही हैं।

महिला मतदाताओं का उभार सिर्फ 2014 के बाद की परिघटना नहीं है। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में जयललिता महिलाओं को कई प्रकार की छूट और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करती थीं, जिससे वे बड़ी आसानी से सत्ता विरोधी लहर से निपटने में सक्षम हो जाती थीं। बिहार में नीतीश कुमार अति पिछड़ा जातियों के साथ ही महिलाओं के बीच अपना अलग वोट बैंक बनाकर लालू यादव के जातिगत गणित को तोड़ने में सक्षम हुए थे। 2006 में बिहार देश का पहला राज्य बन गया, जहां स्थानीय निकायों और पंचायतों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। बंगाल में अगर ममता बनर्जी 2021 में भाजपा को दूर रखने में सफल हुईं, तो यह काफी हद तक कन्याश्री जैसी उनकी सफल महिला-केंद्रित योजनाओं का ही परिणाम था। भाजपा भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लाडली बहना और महतारी वंदना योजनाओं की मदद से जीती। इन दोनों योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को सीधे नकद लाभ सुनिश्चित करना था। और अगर कांग्रेस ने पिछले साल कर्नाटक में जीत हासिल की, तो इसके लिए जिम्मेदार उसकी 'गारंटियों' में गृह-लक्ष्मी योजना भी शामिल थी, जो परिवार की महिला मुखियाओं को प्रतिमाह 2000 रु. प्रदान करती है। वहीं शक्ति योजना के तहत राज्य द्वारा संचालित बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान की जाती है।

नरेंद्र मोदी ने भी महिला मतदाताओं का समर्थन जीतने की भरसक कोशिशें की हैं। चाहे वह उज्ज्वला योजना हो, जन-धन योजना हो, आवास योजना (जहां परिवार की महिला सदस्य के नाम पर घर बनाए जाते हैं) या हाल की लखपति दीदी योजना- ये सभी महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए बनाई गई हैं। हालांकि ये सभी परियोजनाएं समान रूप से सफल नहीं रही हैं। उज्ज्वला योजना का उद्देश्य ग्रामीण और गरीब परिवारों को एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना था, लेकिन उसमें रिफिल-दर खराब देखी गई है। पिछले साल सूचना का अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में पाया गया कि हर चार लाभार्थियों में से एक ने वित्त वर्ष 2022-23 में कोई सिलेंडर नहीं लिया या सिर्फ एक रिफिल लिया, जिसका मुख्य कारण सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी था। इरादा स्पष्ट है : महिलाओं को खुद को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की प्रमुख 'लाभार्थी' के रूप में देखना चाहिए।

महंगाई से त्रस्त गृहणियों के लिए प्रतिमाह पांच किलो मुफ्त खाद्यान्न एक बड़ी राहत है। महाराष्ट्र में- जहां कृषि संकट गंभीर है- ग्रामीण परिवारों में मुफ्त राशन एक उपहार है। यूपी में महिलाएं कानून-व्यवस्था की बेहतर स्थिति से संतुष्ट हैं।

ऐसे में सवाल उठाता है कि यह महिला मतदाता वास्तव में कौन हैं और क्या चीज उन्हें किसी पार्टी या नेता को वोट देने के लिए प्रेरित करती है? भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में कोई भी सामान्यीकरण जोखिम से भरा होता है, फिर भी एक निश्चित पैटर्न उभर रहा है, जिसमें मुख्यत: कम आय वर्ग वाली महिला मतदाता दोहरी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करती हैं : आजीविका और सुरक्षा। जबकि उनसे अधिक महत्वाकांक्षी महिलाएं कार्यस्थल और उससे परे समान अवसरों के लिए पहचान की लड़ाई लड़ रही हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

दूरदृष्टि • मध्य-पूर्व की दो ताकतों ने भूमिकाएं बदलीं

इजराइल कट्टर होता जा रहा है और सऊदी अरब उदार

थॉमस एल. फ्रीडमैन
तीन बार पुलित्ज़र अवॉर्ड विजेता एवं 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' में स्तंभकार

सऊदी अरब और इजराइल मध्य-पूर्व में अमेरिका के दो सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। बाइडन प्रशासन आज दोनों से गहराई से जुड़ा हुआ है। अमेरिका, सऊदी अरब के साथ एक परस्पर रक्षा-संधि बनाने की कोशिश कर रहा है तो हमास और ईरान के साथ संघर्ष में इजराइल की मदद भी कर रहा है। लेकिन बाइडन की टीम को इन दो पुराने सहयोगियों के साथ एक अभूतपूर्व स्थिति का सामना करना पड़ा है, जिससे अमेरिका की आंतरिक राजनीति में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। जहां एक तरफ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) ने अपने देश के सबसे कट्टर धार्मिक चरमपंथियों को जेल में डाल दिया है, वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चरमपंथियों को मंत्रिमंडल में तैनात कर रहे हैं। और यहीं से इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट आता है।

एमबीएस का फोकस आर्थिक विकास पर है। उनका कहना है कि सऊदी अरब कई दशकों से गहरी नींद में सोया था। उन्होंने अपने देश में अब तक की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक क्रांति को जन्म दिया है- और इसकी लहरें दूसरे अरब-देशों तक भी पहुंच रही हैं। बात अब उस बिंदु पर पहुंच गई है, जहां अमेरिका और सऊदी अरब एक औपचारिक गठबंधन को अंतिम रूप देने पर विचार कर रहे हैं। यह गठजोड़ ईरान को अलग-थलग कर सकता है, मध्य-पूर्व में चीन के दखल को रोक सकता है और शांतिपूर्ण तरीके से इस क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव को प्रेरित कर सकता है, जो इराक और अफगानिस्तान पर सैन्य कार्रवाइयों के जरिए अमेरिका कभी नहीं कर पाया था।

ऐसा नहीं है कि एमबीएस की सरकार ने भूलें नहीं की हैं। 2018 में उनकी हुकूमत में इस्ताम्बुल में अमेरिका निवासी उदारवादी सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या करवा दी थी। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा भी किया है, जिसकी हिम्मत उनके पूर्ववर्तियों में से किसी ने नहीं की थी। यह है, 1979 के बाद से सऊदी सामाजिक और धार्मिक नीतियों पर रूढ़िवादियों की मजबूत हो चुकी पकड़ को तोड़ना। यह बदलाव सऊदी महिलाओं और युवाओं में इतना लोकप्रिय साबित हुआ है कि कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ गई है। अकेले 2018 और 2022 के बीच ही महिला कर्मचारियों की संख्या 20 प्रतिशत से बढ़कर 35 प्रतिशत हो गई थी, और आज तो यह और अधिक है।

यह दुनिया के किसी भी हिस्से में सबसे तेज गति से होने वाले सामाजिक परिवर्तनों में से एक है। रियाद में आप इसका प्रभाव शहर की सड़कों, कॉफी हाउसों और सरकारी-व्यावसायिक कार्यालयों में देख सकते हैं। आज सऊदी महिलाएं सिर्फ कार ही नहीं चला रही हैं; वे डिप्लोमेसी में हैं, बैंकों में हैं और अब सऊदी महिला प्रीमियर फुटबॉल लीग भी सामने आ चुकी है। एमबीएस का विजन सबसे ज्यादा इस बात में दिखता है कि अमेरिका के साथ नए समझौते के हिस्से के रूप में वे इजराइल से कूटनीतिक-आर्थिक संबंधों को सामान्य बनाने की इच्छा सार्वजनिक रूप से जता चुके हैं।

कभी इजराइल भी ऐसा ही हुआ करता था, लेकिन अफसोस कि नेतन्याहू के नेतृत्व में इजराइल की त्रासदी यह है कि सत्ता पर कब्जा कायम रखने की अपनी बेताबी में उन्होंने यहूदी वर्चस्ववादियों को अभूतपूर्व शक्ति दे दी है। आज इजराइल के रक्षा, वित्त और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मंत्रालयों में यहूदी वर्चस्ववादी तैनात हैं। उन्होंने न्यायिक तख्तापलट को प्राथमिकता दी है। वे अति-रूढ़िवादी धर्मगुरुओं को रियायतें देते हैं और उनके स्कूलों में भारी मात्रा में धन हस्तांतरित करते हैं, जहां अमूमन गणित, अंग्रेजी या नागरिक शास्त्र की शिक्षा नहीं दी जाती। ये सच है कि सऊदी अरब आज भी एक पूर्ण राजशाही है, वहीं इजराइल एक लोकतंत्र है। दोनों देशों के नेताओं को यह आकलन करना होता है कि कौन-सी चीज उन्हें सत्ता में बनाए रखेगी। इसी प्रवृत्ति के चलते नेतन्याहू इजराइल को पहले के सऊदी अरब जैसा बनाने पर आमादा हैं। वहीं एमबीएस सऊदी अरब को पहले के इजराइल जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। धुर दक्षिणपंथियों के साथ गठबंधन बनाने का दुष्परिणाम नेतन्याहू के सामने यह है कि इजराइल सऊदी अरब में हो रहे व्यापक बदलावों का लाभ नहीं उठा पा रहा है। एमबीएस इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने और शेष मुस्लिम दुनिया के साथ रिश्तों के नए रास्ते खोजने की पेशकश कर रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू अनसुनी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से इजराइल को 'टू स्टेट सोल्यूशन' के लिए फिलिस्तीनियों के साथ मिलकर रास्ता तलाशना होगा।

सऊदी अरब एक पूर्ण राजशाही है, वहीं इजराइल एक लोकतंत्र है। इसके बावजूद आज नेतन्याहू इजराइल को पहले के सऊदी अरब जैसा बनाने पर आमादा हैं। वहीं सऊदी अरब पहले के इजराइल जैसा बनने की कोशिश कर रहा है।

(द न्यूयॉर्क टाइम्स से)

भास्कर खास

ब्रांड सक्सेस स्टोरी

यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप | म्यूजिक कंपनी, **कब बनी**- 1934, **मार्केट कैप**- 4.27 लाख करोड़ रु.

दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी, 38% मार्केट शेयर, अब भारतीय बाजार पर नजर

टेलर स्विफ्ट हो या जस्टिन बीबर जैसे कई नामचीन सिंगर...इनके अधिकांश एल्बम का कॉपीराइट यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप (यूएमजी) के पास है। ये सिंगर्स जितने लोकप्रिय होते हैं, यूएमजी की कमाई भी उतनी ही ज्यादा होती है। दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनी यूएमजी का वैश्विक संगीत बाजार के 38 फीसदी हिस्से पर कब्जा है। इसके बाद सोनी म्यूजिक है। हालांकि भारत में इसकी उपस्थिति बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन कंपनी अब भारत में भी विस्तार की योजना बना रही है। जिस बिजनेस मॉडल से टी-सीरीज और सारेगामा भारत में पैसा कमाती हैं, उसी मॉडल से यूएमजी दुनियाभर में कमाई करता है। टिकटॉक और यूएमजी विवादों के बीच कंपनी चर्चा में है। इस हफ्ते की ब्रांड स्टोरी में इस म्यूजिक कंपनी के बारे में जानते हैं।

यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप का लोगो और इसका नाम यूनिवर्सल पिक्चर्स से लिया गया है। दोनों कभी एक ही कंपनी थे।

यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप का वैश्विक कारोबार

- **38.23%** मार्केट पर यूएमजी का कब्जा है, दूसरे नंबर पर सोनी है
- **32** लाख से ज्यादा रिकॉर्डिंग्स हैं इसके पास, इस मामले में नंबर 1 है
- **45** लाख से ज्यादा म्यूजिक टाइटल्स के राइट्स कंपनी के पास हैं
- **1,350** से ज्यादा आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं यूएमजी के साथ
- **11** हजार अरब से ज्यादा म्यूजिक ट्रैक सोशल मीडिया पर चले यूएमजी के
- **76%** कमाई रिकॉर्डेड म्यूजिक से रही कंपनी की साल 2023 में
- **17%** कमाई म्यूजिक पब्लिशिंग से हुई, बाकी मर्चेंडाइज बेचकर
- **7.2%** कमाई के साथ अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है यूएमजी का

स्रोत- यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप की एनुअल रिपोर्ट 2023

शुरुआत : अब तक कुल 9 मालिक बदल चुके, नीदरलैंड मुख्यालय है

यूएमजी के बीज साल 1934 में पड़े। फिर 60 के दशक में मनोरंजन कंपनी एमसीए का अमेरिकन डेक्का में विलय हुआ। 90 के दशक में एमसीए का मालिकाना हक बदला और 1995 में सीग्राम कंपनी ने एमसीए को खरीदा। 1996 में कंपनी का नाम बदलकर हुआ यूनिवर्सल स्टूडियोज और इसके म्यूजिकल डिवीजन का नाम हुआ यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप। इस बीच फ्रेंच कंपनी विवेंडी की एंट्री हुई, विवेंडी ने जल्द ही यूनिवर्सल पिक्चर्स का कारोबार एनबीसी को बेच दिया। लेकन म्यूजिक डिवीजन अपने पास रखा और 31 मार्च 2020 को कंपनी ने अपने शेयर्स, चीनी कंपनी टेन्सेंट के नेतृत्व वाली एक कंसोर्टियम को बेच दिए। इन सालों में यूनिवर्सल म्यूजिक के 9 मालिक बदल चुके हैं। कंपनी का मुख्यालय नीदरलैंड में है।

- यूएमजी के 19.92% शेयर इन्हीं पार्टनर्स कंसोर्टियम के पास हैं। 18% शेयर फ्रांसीसी कंपनी बोल्लोरे के पास, 10-10% शेयर फंड मैनेजर विलियम अल्बर्ट एकमैन और विवेंडी के पास हैं।

बिजनेस : दिग्गज कलाकारों से करार, सब्स्क्रिप्शन से सबसे ज्यादा कमाई

20वीं सदी में हॉलीवुड में धूम मचाने वाले वाले कलाकार जैसे बॉब मार्ले, जेम्स ब्राउन या फिर बीटल्स जैसे रॉक बैंड हों या मौजूदा दौर में युवाओं की पसंद टेलर स्विफ्ट, कैरी अंडरवुड हों, यूनिवर्सिल म्यूजिक ग्रुप की कलाकारों की डायरेक्ट्री में दुनिया के दिग्गज कलाकार हैं। कंपनी मुख्य तौर पर तीन तरीके से पैसा कमाती है। म्यूजिक पब्लिश करके, रिकॉर्डेड म्यूजिक के जरिए और मर्चेंडाइज बेचकर। कंपनी कलाकारों, गीतकारों की पहचान करके कंटेंट निर्माण में उनकी मदद करती है। इसके अलावा अच्छा बिजनेस करने वाले या अच्छे रिव्यू पाने वाले एलबम्स का फिर से उत्पादन करने के अलावा उनका डिस्ट्रीब्यूशन आदि करती है। कलाकारों से कॉपीराइट खरीदकर कंपनी अच्छा-खासा पैसा कमाती है।

- सब्स्क्रिप्शन सर्विस से कंपनी को सबसे ज्यादा मुनाफा हो रहा है। टिकटॉक से हुआ विवाद और उसकी डील के बाद से सब्स्क्रिप्शन बढ़ा है। 2023 में 1 लाख करोड़ रु. कमाई हुई।

भारत में बिजनेस : फिल्मी गीत-संगीत से दूरी, गैर-फिल्मी गीतों से रेवेन्यू आ रहा

भारत में फिल्मों में इस्तेमाल गीत-संगीत ही ज्यादा लोकप्रिय रहा है। यहां संगीत सुनने वालों में 64 फीसदी लोग फिल्मी म्यूजिक ही सुनते हैं और इस बाजार पर भारतीय कंपनियों जैसे टी-सीरिज या सारेगामा का ही कब्जा है। लेकिन अब कलाकार केंद्रित संगीत और एलबम्स का चलन भी बढ़ रहा है। 2023 में म्यूजिक की जितनी खपत हुई, इसमें 27 फीसदी आर्टिस्ट म्यूजिक रहा। इसलिए यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप के लिए भारत उभरता हुआ बाजार बन रहा है। कंपनी की यहां विस्तार की योजना है। कंपनी को वित्त वर्ष 2023 में भारत से 555 करोड़ रुपए की कमाई हुई, इसमें 72 करोड़ रुपए का मुनाफा रहा। यूएमजी ने भारत में संगीत निर्माण के लिए डेफ जेम रिकॉर्डिंग्स, फाउंड आउट रिकॉर्ड्स, यूनिवर्सल म्यूजिक इंडिया, वायवीआरएल भोजपुरी, हरियाणवी, पंजाबी और ओरिजिनल्स ब्रांड्स से करार किया है।

पीपुल भास्कर

चर्चा में | **सुनील छेत्री**, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान ने संन्यास की घोषणा की है

कभी क्रिकेटर बनना चाहते थे छेत्री, फीफा ने इन पर फिल्म बनाई है 'कैप्टन फैंटास्टिक'

जन्म: 3 अगस्त 1984, सिकंदराबाद
शिक्षा: आशुतोष कॉलेज, कोलकाता से ग्रेजुएशन
परिवार: पत्नी-सोनम भट्टाचार्य, बेटा-ध्रुव
संपत्ति : करीब 8-10 करोड़
(विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के अनुसार)

फुटबॉल की अंतरराष्ट्रीय संस्था फीफा ने गुरुवार को अपने अधिकृत सोशल मीडिया हैंडल से क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी और सुनील छेत्री की तस्वीर शेयर की है। जिस पर लिखा है 'रिटायरिंग एज ए लीजेंड'। फीफा ने यह तस्वीर भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री के सम्मान में जारी की है। छेत्री ने गुरुवार को घोषणा की है कि वे अगले माह अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लेंगे।

छेत्री भले ही आज देश के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर हों, लेकिन बचपन में वे क्रिकेटर बनना चाहते थे। हालांकि परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण पिता ने महंगी क्रिकेट किट दिलाने में असमर्थता जता दी। इसलिए उन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। खराब आर्थिक स्थिति का आलम यह था कि उन्हें फटे हुए फुटबॉल शूज सिलकर पहनने पड़ते थे। खेल के प्रति जुनूनी छेत्री ने इसका तोड़ भी खेल से ही निकाल लिया। दिल्ली के धौलाकुआं स्थिति आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाई के दौरान माइलो टूर्नामेंट प्रतियोगिता शुरू हुई। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को 1500 रुपए कीमत के स्पोर्ट्स शूज दिए गए। प्रतियोगिता तीन साल चली। सुनील हर बार श्रेष्ठ खिलाड़ी रहे। पर हर साल 750-750 के दो जोड़ी शूज लिए, जिसमें से हर साल एक जोड़ी शूज पिता को गिफ्ट कर दिए।

धारा प्रवाह पांच भाषाएं बोल लेते हैं सुनील

पत्नी सोनम भट्टाचार्य और बेटे के साथ सुनील छेत्री

शुरुआत : विरासत में फुटबॉल, माता-पिता दोनों रहे फुटबॉलर

सुनील छेत्री का जन्म तत्कालीन आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद में केबी छेत्री और सुशीला छेत्री के घर हुआ था। उनके पिता आर्मी की इंजीनियरिंग शाखा में थे जबकि मां गृहणी थीं। सुनील को फुटबॉल विरासत में मिली है। दरअसल पिता फुटबॉल खिलाड़ी थे और सेना की फुटबॉल टीम के लिए खेलते थे जबकि उनकी मां नेपाल की महिला राष्ट्रीय टीम में फुटबॉल खेल चुकी थीं। छेत्री के पांच मामा थे और सभी फुटबॉलर थे। यानी फुटबॉल खेलना उनके खून में था। उनके बारे में एक रोचक किस्सा है। एक बार उनकी मां ने कुछ गुब्बारे लेकर घर पर रखे थे। छेत्री ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते थे बावजूद उसके उन्होंने खड़े होकर गुब्बारे को किक किया था। यह देख माता-पिता दोनों आश्चर्य चकित हो गए। उनकी एक बहन भी है, जिसका नाम बंदना छेत्री है। उन्होंने अपने कोच की बेटी से शादी की है।

करियर : सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाले दुनिया के चौथे खिलाड़ी

सुनील छेत्री ने 2001-02 में दिल्ली के स्थानीय क्लब सिटी क्लब से करियर शुरू किया। यहीं कोलकाता के मोहन बागान एथलेटिक क्लब की नजर उन पर पड़ी। इसके बाद 2002 में मात्र 17 साल की उम्र में मोहन बागान के साथ प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की। 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ राष्ट्रीय टीम के लिए डेब्यू किया। उनका पहला अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट 2007 में नेहरू क्लब था। इसमें भारत ने कंबोडिया को 6-0 से हराया। वर्तमान में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय गोल के मामले में वे दुनिया चौथे खिलाड़ी हैं जबकि सक्रिय खिलाड़ियों के मामले में उनसे आगे केवल पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो (128 गोल) और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी (106 गोल) ही हैं। सुनील छेत्री के 94 गोल हैं। अंतरराष्ट्रीय मंच पर वह 2008 में एएफसी चैलेंज कप, 2011 और 2015 में एसएएफएफ चैंपियनशिप, 2007, 2009 और 2012 में नेहरू कप के साथ-साथ 2017 में इंटरकांटिनेंटल कप में खिताब जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं।

रोचक/उपलब्धि : खेल रत्न पाने वाले एकमात्र फुटबॉलर

- फीफा ने पिछले साल उन पर 'कैप्टन फैंटास्टिक' नामक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया था, जो फीफा+ चैनल पर उपलब्ध है।
- एक मात्र भारतीय फुटबॉलर हैं जिन्हें खेल रत्न प्रदान किया गया है। यह सम्मान 2021 में मिला था।
- उन्होंने रिकॉर्ड 7 बार 2007, 2011, 2013, 2014, 2017, 2019 और 2022 में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (एआईएफएफ) का प्लेयर ऑफ द ईयर अवॉर्ड जीता है।
- सुनील छेत्री अंग्रेजी, हिंदी, नेपाली, बंगाली और कन्नड़ भाषा धारा प्रवाह बोल लेते हैं। इसके अलावा वे तेलगू, मराठी और कोंकणी भाषा भी कुछ-कुछ समझ लेते हैं।
- अंतरराष्ट्रीय 86 गोल पूरा करने के बाद उन्होंने गोद में फुटबॉल को छिपाकर पत्नी के गर्भवती होने की जानकारी दर्शकों को रोचक अंदाज में दी थी।
- मेजर लीग सॉकर के अमेरिकी क्लब कैनसस सिटी विजार्ट के लिए खेलने वाले पहले भारतीय हैं।

पटना **आज** शुक्रवार १७ मई, २०२४ सौर ३ जेष्ठ सं. २०८१ वि.

सुभाषित

यदि दानको सर्वश्रेष्ठ बनाना है तो क्षमादान करना सीखना होगा।

❐ चार्ल्स बक्सन

खाद्य पदार्थोंकी गुणवत्ता आवश्यक

स्ले इंडियाके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सुरेश नारायणन द्वारा बेबी फूड फार्मूलेशनमें चीनीकी अधिक मात्राके आरोपोंको नस्लीय तौरपर रुढ़बिद्ध धारणा और असत्यके रूपमें नकारनेको संदेहास्पदके तौरपर ही लिया जाना चाहिए। मीडियामें उनके हवालेसे कहा गया कि पोषण पर्याप्तता अध्ययन करनेके लिए कोई स्थानीय दृष्टिकोण नहीं है।

❐ देविंदर शर्मा

बालपनमें भूखके मुकाबले मोटापा बड़ी समस्या बनने जा रहा है। दूसरी ओर भारत पहलेसे ही वयस्कोंमें मोटापेके मामलेमें शीर्ष पांच देशोंमें शामिल है। रिपोर्टोंमें कहा गया है कि अनुमानित रूपसे १३५ मिलियन भारतीय या तो मोटे हैं या फिर अधिक वजनवाले हैं। बेशक इसके लिए पूरी तरहसे खानपान संबंधी आदतें और उपभोग जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन भोजनकी गुणवत्ताको निर्यंत्रित करनेका 'चलता है' वाला रवैया अधिकसे अधिक लोगोंको इस जंजालमें धकेल रहा है। तत्काल आवश्यकता एफएसएसएआईको एक ऐसी संस्थामें बदलने की है जिसपर देश भरोसा कर सके।

स्ले इंडियाके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सुरेश नारायणन द्वारा बेबी फूड फॉर्मूलेशनमें चीनीकी अधिक मात्राके आरोपोंपर कहा है कि विश्व स्तरपर उम्रके हिसाबसे व्यंजन तैयार किये गये हैं जहां बढ़ते बच्चोंको ऊर्जा सघन उत्पादोंकी आवश्यकता होती है। इसलिए यूरोपीय बच्चे और भारत या दुनियाके किसी अन्य हिस्सेमें एक बच्चेके बीच भेद नहीं किया जाता है। नारायणन स्विटजरलैंड स्थित एनजीओ थर्ड आई और इंटरनेशनल बेबी फूड एक्शन नेटवर्क (आईबीएफएएन) की रिपोर्टमें कम्पनीपर दोहरे मानदंड अपनाने संबंधी आरोपोंके बारेमें प्रकाशित समाचारोंपर प्रतिक्रिया दे रहे थे। जिसके मुताबिक यूरोपमें बेचे जानेवाले उत्पादोंकी तुलनामें भारत एवं विकासशील देशोंमें बेचे जानेवाले शिशु-आहार अनाजों (सेरेलैक) में चीनीकी उच्च मात्रा विद्यमान है। भारतमें हमें आवश्यकता है, यही कारण है कि हमने इसे शामिल किया है, लेकिन उन स्तरोंपर जो स्थानीय नियामक द्वारा निर्दिष्टकी तुलनामें भी बहुत कम हैं और मुझे लगता है कि किसीको भरोसा रखना होगा कि स्थानीय नियामक जानता है कि क्या है जो हम वहां डाल रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि मानकोंमें यह कोई नाटकीय बदलाव किया गया है। वे कहते हैं कि मातृ आहारकी कुछ आदतों, कच्चे मालकी स्थानीय उपलब्धता एवं स्थानीय नियामककी जरूरतों जैसी अलग-अलग धारणाओंके आधारपर फॉर्मूलेशनको स्थानीय रूपसे उत्पादमें ढाला जाता है। इस बयानके जरिये जो कुछ भी कहा गया है यदि वह सच है तो कोई कारण नहीं दिखता कि उपभोक्ता मामलोंके मंत्रालयको नियामक एजेंसी-भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) को नेस्लेके खिलाफ उचित काररवाईका निर्देश देना चाहिए था। निर्देशके बाद एफएसएसएआईने नेस्ले बेबी फूड उत्पादोंकी संरचनासे संबंधित विवादकी जांच पहले ही शुरू कर दी है और मैं यहां यह भी जोड़ना चाहूंगा, आरोपोंकी जांचके लिए सख्त निर्देशके बावजूद यकीन नहीं है कि वादेके मुताबिक जांच अपने तार्किक निष्कर्षतक पहुंचेगी। यदि एफएसएसएआईने पहले तो अपने कड़े मानक तय करनेमें सख्तीसे काम लिया होता, फिर इसके साथ ही कड़ाईसे इनको लागू किया होता तो कोई भी विशाल खाद्य कम्पनी भारतीय बाजारको इतने हल्के रूपमें न लेती। मैं यहां उस बयानको दोहरा रहा हूं। आरोपोंके खंडन संबंधी नेस्लेका वह बयान स्वयं ही स्पष्ट तौरपर दोषोंको उजागर करता है जब वह कहता है, भारतमें हमें आवश्यकता है, यही कारण है कि हमने इसे मिलाया है, लेकिन उन स्तरोंपर जो यहांतक कि स्थानीय नियामक द्वारा निर्दिष्ट स्तरसे भी बहुत कम हैं। यदि आप इस कथनको देखें तो यह सवाल तुरन्त उठता है कि भारतमें ऐसी आवश्यकता कहां है जिसने कम्पनीको शिशु आहारमें चीनीकी ज्यादा मात्रा डालनेके लिए प्रेरित किया। बेबी फूड कम्पनियोंको भारतमें बेचे जानेवाले अपने उत्पादोंमें अधिक चीनी मिलानेके लिए आखिर कहा किसने है। मैंने भारतमें पोषण संबंधी संस्थाओंका कोई अध्ययन या रिपोर्ट ऐसी नहीं देखी जो शिशु आहारमें ऊर्जा प्रदाताके तौरपर ज्यादा मात्रामें चीनी मिलानेकी जरूरत बताता हो। वहीं, नेस्लेका कहना है कि उसने प्रति सौ ग्राम फीडमें केवल ७.१ ग्राम चीनी डाली है और वह भी एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित १३.६ ग्रामकी स्वीकार्य सीमाके मुकाबले बहुत कम, यह बयान मामलेका एक और गम्भीर पहलू उजागर करता है। इससे पता चलता है कि एफएसएसएआईके मानक कितने ढीले हैं, जिससे एक हाथीको भी गुजरनेकी इजाजत मिल जाती है। एफएसएसएआईको वह डेटा जारी करनेके लिए कहा जाना चाहिए जिसके आधारपर उसने शिशु आहारमें चीनीकी स्वीकार्य सीमा निर्धारित की है। एफएसएसएआईको इससे बच निकलने नहीं दिया जा सकता है। एफएसएसएआईने मानक तय करनेके लिए २६ वैज्ञानिक समितियां गठित की हैं और फिर भी यदि मानदंडोंमें इतनी ढील दी गयी है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि हितोंका टकराव अकसर चर्चाकी तुलनामें कहीं अधिक बड़ा है। जैसा कि वरिष्ठ विज्ञान टिप्पणीकार दिनेश सी. शर्मा कहते हैं, वर्षोंसे उपभोक्ता समूह और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ उच्च नमक, चीनी और वसावाले खाद्य उत्पादोंके लिए एक अलग हेल्थ लेबलकी मांग कर रहे हैं, लेकिन खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण और उद्योगने लगातार इसका विरोध किया है। दूसरी ओर नियामक अकसर उद्योगकी मांगोंको पूरा करने और यहांतक कि उनके उत्पादोंका समर्थन करनेमें भी तत्पर रहता है, जो कि उसके लिए अनिवार्य नहीं है। इससे पता चल जाता है कि कार्पोरेशंस सार्वजनिक नीतिको कैसे प्रभावित करते हैं।

हालांकि हरेक व्यक्तिको चीनीके सेवनके प्रति सचेत रहना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थोंमें छिपा रहता है। यहांतक कि एक सजग उपभोक्ताके लिए भी अतिरिक्त चीनीकी पहचान करना मुश्किल होगा। चूंकि कई अध्ययनोंसे पता चला है कि चीनीके लिए कमसे कम ५६ अलग-अलग नाम हैं जो आम तौरपर उपभोक्ताओंको धोखा देनेके लिए उपयोग किये जाते हैं, लेकिन कमसे कम एफएसएसएआईको इन्हें पढ़नेमें सक्षम होना चाहिए और इससे होनेवाले नुकसानको जानते हुए इसके उपयोगको काफी हदतक प्रतिबंधित करना चाहिए। यहां मैं केवल मधुमेहके बारेमें बात नहीं कर रहा हूं जिसके होनेके जोखिम कारकोंमें बहुत अधिक चीनीका सेवन जुड़ा है, बल्कि जैसा कि जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजीमें प्रकाशित एक अध्ययनसे पता चला है कि आनुवंशिक कारकोंके अलावाए यहांतक कि चीनी आधारित मीठे पेय भी पुरुषोंमें बालोंके झड़नेकी वजह बन सकते हैं। यह सब किस दिशामें लेकर जायेगा खासकर तब जब पिछले कुछ सालोंसे जंक फूडकी खपतमें भारी उछाल देखा जा रहा है। यदि एफएसएसएआई एक सख्त नियामकके रूपमें उभर सकता है तो औसत उपभोक्ता सुपरमार्केटसे जो कुछ भी खरीद रहा है उसके प्रति संतुष्ट हो जायगा, यह जाननेके चलते कि यह सुरक्षित और हेल्दी है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उपभोक्ताओंका एक प्रमुख वर्ग जानता है कि वह जो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ खरीद रहा है वह स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, लेकिन उसके पास विकल्प बहुत कम हैं। वैश्विक अध्ययनोंसे हमें पता चला है कि भारत और छह अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओंमें उपलब्ध ८९ प्रतिशत प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ स्वास्थ्यके हिसाबसे सही नहीं हैं।

हम पहले ही ऐसी स्थितिमें हैं जहां बालपनमें भूखके मुकाबले इस उम्रका मोटापा बड़ी समस्या बनने जा रहा है। दूसरी ओर भारत पहलेसे ही वयस्कोंमें मोटापेके मामलेमें शीर्ष पांच देशोंमें शामिल है। रिपोर्टोंमें कहा गया है कि अनुमानित रूपसे १३५ मिलियन भारतीय या तो मोटे हैं या फिर अधिक वजनवाले हैं। बेशक इसके लिए पूरी तरहसे खान-पान संबंधी आदतें और उपभोग जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन भोजनकी गुणवत्ताको निर्यंत्रित करनेका 'चलता है' वाला रवैया अधिकसे अधिक लोगोंको इस जंजालमें धकेल रहा है। तत्काल आवश्यकता एफएसएसएआईको एक ऐसी संस्थामें बदलनेकी है जिसपर देश भरोसा कर सके। इसके लिए भले ही मौजूदा ढांचेमें बदलावकी बात आये तो हमें यह करना ही होगा। देशको इसी गारंटीकी आवश्यकता है।

केजरीवालके जमानतसे उपजे सवाल

बीते दिनों सुप्रीम कोर्टने दिल्लीके मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवालको जमानत दे दी। आम आदमी पार्टी प्रमुख केजरीवालको कथित शराब घोटाला कांडसे जुड़े मनी लाण्ड्रिंग केसमें केजरीवालको गत दिनों गिरफ्तार किया गया था।

❐ राजेश माहेश्वरी

शीर्ष अदालतने केजरीवालको आम आदमी पार्टीके चुनाव अभियानको गति देने हेतु एक जूनतकके लिए अंतरिम जमानत दी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ताकी पीठने अरविंद केजरीवालको सशर्त यह जमानत दी। इससे पहले शीर्ष अदालतने सुनवाईके दौरान कहा था कि केजरीवाल दिल्लीके निर्वाचित मुख्य मंत्री हैं। वे कोई आदतन अपराधी नहीं हैं। सुप्रीम कोर्टके फैसलेको लेकर सोशल मीडियामें सन्देशोंकी बाढ़-सी आ गयी। सोशल मीडियामें अधिकतर मैसेज सुप्रीम कोर्टके फैसलेकी आलोचना करते ही दिखे। व्यापक तौरपर लोगोंका यह मानना है कि इस फैसलेसे गलत परम्परा पढ़ेगी। आनेवाले समयमें इस फैसलेके आधारपर अन्य लोग भी जमानतकी मांग करेंगे। इससे कानूनका राज स्थापित करनेमें कठिनाइयोंका सामना करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवालको जमानत देते समय अदालतका यह भी मानना था कि लोकसभाके चुनाव पांच सालमें एक बार आते हैं। ऐसेमें केजरीवालको जमानत देनेमें कोई हर्ज नहीं है। केजरीवालको २१ दिनकी राहत देकर शीर्ष अदालतने अपरोक्ष रूपसे यही संदेश दिया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थामें चुनावी मुकाबलेमें हर दल एवं नेताको बराबरीका मौका मिलना चाहिए। इसी सोचके अनुरूप दिल्लीके मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवालको एक जूनतकके लिए अंतरिम जमानत मिली है। केजरीवालको दो जूनको आत्मसमर्पण करनेको कहा गया है। इस फैसलेके विरोधमें बोलनेवालोंका यह भी तर्क है अदालतके फैसलेसे यह भी साबित हुआ है कि नेता और आम आदमीके अधिकार अलग-अलग हैं। यह संविधानकी मूल भावना के विपरीत है। हेमंत सोरेन भी झारखंडके पूर्व मुख्य मंत्री और झामुमोके कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उन्हें चुनाव प्रचारके लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गयी। बहसके दौरान यह तर्क भी न्यायिक पीठके सामने दिया गया कि चुनाव प्रचार करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है। संभवत: किसी भी राजनेताको चुनाव प्रचार करनेको जमानतपर जेलसे रिहा नहीं किया गया। केजरीवालपर जो फैसला अदालतका है, वह भी उसका विशेषाधिकार है।

कोर्टने केजरीवालको अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि माना उनपर लगाये गये आरोप गम्भीर हैं, लेकिन उनपर लगाये गये आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं। वहीं जमानत देनेके साथ अदालतने कुछ शर्तें भी लगायी हैं। इस दौरान केजरीवाल न तो मुख्य मंत्री कार्यालय और न ही सचिवालय जा पायंगे। वे अपने केससे जुड़े किसी गवाहसे कोई सम्पर्क करनेकी कोशिश भी नहीं करेंगे। उन्हें जेलसे रिहाईके लिये पचास हजार रुपयेकी जमानत भरनेको भी कहा गया। साथ ही इस दौरान वे किसी फाइलपर साइन नहीं करेंगे। यदि बहुत जरूरी हुआ तो उप राज्यपालकी अनुमतिसे ऐसा कर पायंगे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्टने केजरीवालको निर्देश दिया कि वह शराब घोटालेसे संबंधित मनी लाण्ड्रिंग मामलेमें अपनी भूमिकाके बारेमें कोई बयानबाजी न करें। फिलहाल शीर्ष अदालतके इस फैसलेके बाद आम आदमी पार्टी तथा इंडिया गठबंधनके लिए चुनाव प्रचार अभियानमें तेजी आनेकी उम्मीद जतायी जा रही है। हालांकि इससे पहले ईडीने केजरीवालको अंतरिम जमानत देनेका पुरजोर विरोध किया था। प्रवर्तन निदेशालयका तर्क था कि चुनाव प्रचार किसी व्यक्तिका मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्टने इस तर्कको स्वीकार नहीं किया। केजरीवालकी रिहाईके बाद इंडिया गठबंधनके खेमेमें खासा उत्साह देखा जा रहा है। गठबंधनके स्टार प्रचारक केजरीवालका यूं तो दिल्लीमें ही ज्यादा बोलबाला रहा है, जहां वे कांग्रेसके साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। यहां गठबंधनके तहत चुनाव लड़नेके लिए आपके हिस्सेमें चार एवं कांग्रेसको तीन सीटें आयी हैं। इस गठबंधनके तहत हरियाणाकी कुरुक्षेत्र सीट आपके हिस्सेमें आयी है। जहां २५ मईको वोट पड़ने हैं। वहीं पंजाबमें सीटोंको लेकर आप एवं कांग्रेसमें कोई समझौता नहीं हो सका है। राज्यकी तेरह सीटोंपर आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ रही है। पंजाबमें अंतिम चरणमें एक जूनको वोटिंग होनी है। आपको दिल्ली एवं पंजाबमें ज्यादा उम्मीदें हैं। अबतक दिल्लीमें अरविंद केजरीवालकी पत्नी चुनाव प्रचारकी बागडोर सम्भाले हुए थीं। उन्होंने रामलीला मैदान रैलीके अलावा कुछ रोड शो भी किये थे। साथ ही वे संकल्प सभा व जेलका जवाब वोटसे अभियानमें भी सक्रिय रहीं। वहीं पंजाबमें मुख्य मंत्री भगवंत मान ही चुनाव अभियानकी बागडोर संभाले हुए थे। फिलहाल केजरीवालकी रिहाईसे इंडिया गठबंधनका उत्साह खासा बढ़ा है। पिछले दिनों जेलसे रिहा हुए आप नेता संजय सिंह भी उत्तर प्रदेश समेत कई राज्योंमें इंडिया गठबंधनकी रैलियोंमें शिरकत करते रहे हैं। ऐसी ही उम्मीद गठबंधनके नेता केजरीवालसे भी कर रहे हैं ताकि पूरे देशमें राजग गठबंधनके खिलाफ आक्रामक प्रचार किया जा सके।

केजरीवालकी रिहाईपर आम आदमी पार्टी जो जश्न मना रही है और तानाशाहीपर लोकतंत्रकी जीत बता रही है, वह सब बेमानी है, क्योंकि देशमें तानाशाही होती तो केजरीवाल जेलसे कभी छूट ही नहीं पाते। राजनीतिमें सब कुछ जायज है। अपने पहले संबोधनमें ही केजरीवालने यहांतक भ्रम और अफवाह फैला दी कि प्रधान मंत्री मोदी अमित शाहको प्रधान मंत्री बनानेके लिए वोट मांग रहे हैं तो मोदीकी गारंटीका क्या होगा। प्रधान मंत्री मोदी सितंबर, २०२५ में ७५ सालके हो जायंगे। उन्होंने ही २०१४ में सत्तारूढ़ होनेके बाद यह नियम घोषित किया था कि ७५ साल और उससे अधिक उम्रके नेता चुनाव नहीं लड़ सकेंगे और न ही किसी पदपर आसीन होंगे। यह एक नैतिक व्यवस्था बनायी गयी थी, अलबत्ता भाजपाके संविधानमें कोई संशोधन नहीं किया गया। केजरीवालके सन्दर्भमें सर्वोच्च न्यायालयने जो टिप्पणी की है वह एक तरफा आधी-अधूरी है और अमान्य है, क्योंकि केजरीवालने लगातार नौ बार सम्मन ठुकराये हैं, जबकि सरकारके मुखियाके तौरपर उन्हें कानूनका सम्मान करना चाहिए था। वही जब वे गिरफ्तार हो गये तो उन्हें मुख्य मंत्रीके पदसे त्यागपत्र देना चाहिए था, यह एक सामान्य नैतिकता है कि सरकारका एक सामान्य कर्मचारी भी २४ घंटेसे ज्यादा जेलमें बंद रह जाता है तो उसे पदसे हटा दिया जाता है किन्तु एक मुख्य मंत्री लगातार कई कई दिनोंतक जेलमें बंद रहा और वह जबरिया अपने पदपर बना रहना चाहता है।

इस तरहकी अनैतिकता नहीं थोपी जा सकती, इस सन्दर्भमें भी सर्वोच्च न्यायालयको गंभीरतासे देखना चाहिए था। भाजपामें ७५ प्लसके १७ सांसद अब भी हैं और ८० सालसे अधिकवाले दो सांसद हैं। केजरीवाल पतंगबाजीमें माहिर हैं और उन्होंने गप्पी राजनीति कर कुछ हासिल करनेकी कोशिश की, लेकिन स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाहने उसे ध्वस्त कर दिया और हैदराबादमें सार्वजनिक तौरपर स्पष्ट किया कि प्रधान मंत्री मोदी अपना तीसरा कार्यकाल भी पूरा करेंगे। केजरीवालकी पतंगबाजी यह भी है कि चुनाव नतीजेके दो माह बाद उत्तर प्रदेशके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथको भी निबटा दिया जायगा। प्रधान मंत्री एक खतरनाक मिशनपर काम कर रहे हैं-एक देश, एक ही नेता। लिहाजा साफ है कि जेलसे बाहर आते ही केजरीवाल आक्रामक दिख रहे हैं।

आत्मबोध

जीवनशैली

❐ जे.पी.शर्मा

मनुष्य समाजकी एक इकाई है, जिनके समूह से ही समाजकी रचना होती है। अर्थात् व्यक्ति और समाजका एक अंतरंग रिश्ता है। सामाजिकता व्यक्तिकी जीवनशैलीकी एक महत्वपूर्ण विशिष्टता है। आरम्भसे अंततक उसे समाजमें ही जीवनयापन करना होता है। सुख, दुख, गमी, खुशी सभी आवेगों एवं संवेगोंमें उसे सामाजिक कर्तव्य निभाने पड़ते हैं। सामाजिक रस्मों-रिवाज, प्राथमिकताएं, निषेधाज्ञाएं, संस्कार, परंपराएं, डूज एंड डोंटस सभी अनिवार्यताएं ही उसकी प्राथमिकता होती हैं। प्रकृति प्रदत्त पारिवारिक अंतरंग रिश्तोंके अलावा उसे पड़ोस, निकटतम मित्र सभीके चयन एवं चुनावमें स्वतंत्रता हासिल रहती है। वह अपनी सुविधानुसार सामाजिक संबंधोंको परिवर्तन भी करता रहता है। अनचाहे, स्वार्थी, मतलबपरस्त, समयपर साथ न देनेवाले संबंधोंको त्याग नये सामाजिक रिश्ते बनाना भी उसकी अपनी प्राथमिकता एवं अधिकार क्षेत्रमें रहता है। लबोलुआब यह है कि विशाल समाजमेंसे अपने अनुरूप अपने लिए एक मुट्ठी आसमान बनाना, चुनना, निभाना, त्यागना अथवा पुन: निर्मित करना उसके वशमें रहता है। परन्तु दुर्भाग्यपूर्ण विडंबना है कि इसी वैचारिक स्वतंत्रताके अधिकारका राजनीतिके वर्तमान दौरने हनन कर दिया है। राजनीति कुछ इस कद्र जीवनके हर क्षेत्रमें रच, बस गयी है या यूं कहें कि एक लत और व्यसन-सी बन गयी है कि छूटती नहीं है काफिर मुंहसे लगी हुई जैसी कहावत चरितार्थ हो रही है। व्यक्तिकी मानसिकतापर घरके अंतरंग संबंध हो, शिक्षा संस्थान हो, व्यावसायिक प्रतिष्ठान हो, उद्योगिक क्षेत्र हो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो या कोई अन्य कार्य क्षेत्र सभीमें राजनीति और कूटनीति प्रवेश कर मानस पटलपर हावी हो गयी है। राजनीति करनेकी प्रवृत्ति सामाजिक संबंधोंको लील रही है। समाचार-पत्रोंकी सुर्खियों, टीवीकी अवांछित राजनीतिक डिबेटों, सोशल मीडिया चैनलोंमें दिखाई जानेवाली राजनीतिक अर्नगल बहसवाजीने व्यक्तिकी सोच इस सीमातक कुप्रभावित कर दी है कि उसकी वास्तविक शखसियत गुम हो गयी है। वर्तमान राजनीतिमें निहित बेइमानी, भ्रष्टता, हिसंक साम्प्रदायिक असंवेदनशीलता, स्वार्थकी चरमसीमा, वतनफरामोशीका जहरीला वायरस सामाजिक संबंधोंको संक्रमित करके मासूम व्यक्तिसे उसकी प्रकृति प्रदत्त सामाजिक सोच एवं संबंधोंको छीननेका अमानवीय कृत्य कर रहा है। यही आजकी दूषित राजनीतिकी देन है। जिसने सामाजिक सद्भावना एवं सौहार्दको तार-तार करके व्यक्तिसे मानो उसकी सामाजिकता ही छीन ली है।

डेंगूके जोखिमकी न हो अनदेखी

❐ योगेश कुमार गोयल

डेंगू वैसे तो प्रतिवर्ष कहर बनकर टूटता है लेकिन कुछ राज्योंमें इसके कारण महामारी जैसे हालात नजर आने लगे हैं और सैकड़ों लोगोंकी मौत भी होती है। हालांकि डेंगूकी दस्तक तो हर साल सुनायी पड़ती है किन्तु हर तीन-चार वर्षके अंतरालपर डेंगू एक महामारीके रूपमें उभरकर सामने आता है। डेंगूकी दस्तकके बाद डाक्टरों एवं प्रशासन द्वारा आम जनताको कुछ हिदायतें दी जाती हैं लेकिन डाक्टर एवं प्रशासन इस मामलेमें खुद कितने लापरवाह रहे हैं, इसका उदाहरण डेंगू फैलनेके बाद भी कमोवेश सभी राज्योंमें जगह-जगहपर फैले कचरे और गंदगीके ढेर तथा विभिन्न अस्पतालोंमें सही तरीकेसे साफ-सफाई न होने और अस्पतालोंमें भी मच्छरोंका प्रकोप हर साल देखकर स्पष्ट रूपसे मिलता रहा है। डेंगू बुखार एक वायरल संक्रमण है। यह एक खतरनाक बीमारी है, जो ऐडीस मच्छरके काटनेसे होती है, जो हमारे घरोंके आसपास खड़े पानीमें ही पनपता है। ऐडीस मच्छर काले रंगका स्पॉटेड मच्छर होता है, जो प्राय: दिनमें ही काटता है। डेंगूका वायरस शरीरमें प्रविष्ट होनेके बाद सीधे शरीरके प्रतिरोधी तंत्रपर हमला करता है। इस मच्छरका सफाया करके ही इस बीमारीसे पूरी तरहसे बचा जा सकता है। प्राय: मानसूनके बाद ही डेंगूके ज्यादा मामले देखनेको मिलते हैं। डेंगू प्राय: दोसे पांच दिनोंके भीतर गम्भीर रूप धारण कर लेता है। ऐसी स्थितिमें प्रभावित व्यक्तिको बुखार आना बंद हो सकता है और रोगी समझने लगता है कि वह ठीक हो गया है लेकिन वास्तवमें ऐसा होता नहीं है, बल्कि यह स्थिति और भी खतरनाक होती है। अत: बेहद जरूरी है कि आपको पता हो कि डेंगू बुखार होनेपर शरीरमें क्या-क्या प्रमुख लक्षण उभरते हैं। डेंगूके अधिकांश लक्षण मलेरियासे मिलते-जुलते होते हैं लेकिन कुछ लक्षण अलग भी होते हैं। तेज बुखार, गलेमें खराश, ठंड लगना, बहुत तेज सिरदर्द, थकावट, कमर एवं आंखोंकी पुतलियोंमें दर्द, मसूडों, नाक, गुदा एवं मूत्र नलिकासे खून आना, मितली एवं उल्टी आना, मांसपेशियों एवं जोड़ोंमें असहनीय दर्द, हीमोग्लोबिनके स्तरमें वृद्धि, शरीरपर लाल चकते (खासकर छातीपर लाल-लाल दाने उभर आना), रक्त प्लेटलेट (बिम्बाणुओं) की संख्यामें भारी गिरावट इत्यादि डेंगूके प्रमुख लक्षण हैं। बीमारी कोई भी हो, उसके उपचारसे बेहतर उससे बचाव ही होता है और डेंगूके मामलेमें तो बचाव ही सबसे बड़ा हथियार माना गया है। इसीलिए बारिशके मौसमसे पहले ही लोगोंको इसके बारेमें जागरूक करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि उचित सावधानियां और सतर्कता बरतकर ही इस जानलेवा बीमारीसे बचा जा सकता है। घरकी साफ-सफाईका ध्यान रखा जाना बेहद जरूरी है। आपके घर या आसपासके क्षेत्रमें डेंगूका प्रकोप न हो, इसके लिए जरूरी है कि मच्छरोंके उन्मूलनका विशेष प्रयास हो। डेंगू फैलाने वाले मच्छरोंका पनपना रोकें। कुछ अन्य जरूरी बातोंपर ध्यान देना भी बेहद जरूरी है। जैसे, अपने घरमें या आसपास पानी जमा न होने दें। जमा पानीके ऐसे स्रोत ही डेंगू मच्छरोंकी उत्पत्तिके प्रमुख कारक होते हैं। इस बातका विशेष ध्यान रखें कि कहीं भी पानी जमा होकर सड़ न रहा हो। घरके दरवाजों, खिड़कियों तथा रोशनदानोंपर जाली लगवायें ताकि घरमें मच्छरोंका प्रवेश बाधित किया जा सके। पूरी बाजूके कपड़े पहनें। सोते समय मच्छरदानीका प्रयोग करना मच्छरोंसे बचावका सस्ता है। डेंगूके लक्षण उभरनेपर तुरन्त योग्य चिकित्सककी सलाह अवश्य लें। डेंगू हो जानेपर रोगीको हर हालमें पौष्टिक और संतुलित आहार देते रहना बेहद जरूरी है। डेंगू होनेपर तुलसीका उपयोग बेहद लाभकरी है। आठ-दस तुलसीके पत्तोंका रस शहदके साथ मिलाकर लें या तुलसीके १०-१५ पत्तोंको एक गिलास पानीमें उबाल लें और जब पानी आधा रह जाय, तब पी लें। नारियल पानी पीयें, जिसमें काफी मात्रामें इलैक्ट्रोलाइट्स होते हैं, साथ ही यह मिनरल्सका भी अच्छा स्रोत है, जो शरीरमें ब्लड सेल्सकी कमीको पूरा करनेमें मदद करते हैं। विटामिन सी शरीरके इम्यून सिस्टमको सही रखनेमें मददगार होता है। इसलिए आंवला, संतरा, मौसमी जैसे विटामिन सीसे भरपूर फलोंका सेवन करें। बुखार होनेपर पैरासिटामोलका इस्तेमाल करें और ध्यान रखें कि बुखार किसी भी हालतमें ज्यादा न बढ़ने पाये लेकिन ऐसे मरीजोंको एस्प्रिन, ब्रूफिन इत्यादि दर्दनाशक दवाएं बिल्कुल न दें, क्योंकि इनका विपरीत प्रभाव हो सकता है। उल्टियां होनेपर रोगीको नसों द्वारा ग्लूकोज चढ़ाना अनिवार्य है। स्थिति बिगड़ती देख तुरन्त चिकित्सकसे सम्पर्क करें।

शरणार्थियोंको नया जीवन

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) यद्यपि दिसम्बर २०१९ में संसदमें पारित हो गया था लेकिन विरोध प्रदर्शन यह लागू नहीं हो पाया था। अन्तत: साढ़े चार वर्षोंके अन्तरालके बाद इस कानूनको अमलीजामा पहना दिया गया और ११ मार्च, २०२४ को सीएए देशभरमें लागू कर दिया गया। देशभरमें कुल तीन सौ शरणार्थियोंको भारतकी नागरिकता प्रदान कर उन्हें बुधवारको प्रमाण-पत्र देना भी शुरू कर दिया गया। स्वराष्ट्र सचिव अजय कुमार भल्लाने एक विशेष समारोहमें १४ लोगोंको प्रतीकात्मक तौरपर नागरिकता प्रमाण-पत्र सौंप कर इसे ऐतिहासिक दिवस बना दिया। अन्य लोगोंको डिजिटल प्रमाण-पत्र ई-मेलके माध्यमसे भेजे जा रहे हैं। इस कानूनके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बंगलादेशमें प्रताड़नाके शिकार हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदायके लोगोंको भारतकी नागरिकता प्रदान करनेका प्रावधान है। यह नागरिकता ३१ दिसम्बर २०१४ तक भारत आये लोगोंको ही दी जायगी। केन्द्र सरकारका यह अत्यन्त ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कदम है। लम्बे अरसेसे इसकी प्रतीक्षा की जा रही थी लेकिन राजनीतिक कारणोंके चलते इसमें काफी विलम्ब हो गया। सीएएको लेकर जो विरोध प्रदर्शन हुए वह भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। २०१९ में कानून पारित होनेके बाद देशके विभिन्न हिस्सोंमें विरोध प्रदर्शन हुए और पुलिसकी काररवाईके दौरान सौसे अधिक लोगोंकी मृत्यु भी हुई। राजधानी दिल्लीमें लम्बे समयतक सड़क जाम कर प्रदर्शन किये गये जिससे आम नागरिकोंको काफी परेशानी भी उठानी पड़ी। आन्दोलन समाप्त करानेके लिए सर्वोच्च न्यायालयको भी कड़ा रुख अपनाना पड़ा। सीएए विरोधी आन्दोलनके लिए देशके अतिरिक्त विदेशोंसे भी आर्थिक समर्थन मिले जिसके चलते ही आन्दोलन लम्बे समयतक चला। यह सन्तोषकी बात है कि केन्द्र सरकारने व्यावहारिक धरातलपर इस कानूनको अमलीजामा पहना दिया लेकिन कुछ राज्य अब भी इस कानूनका विरोध कर रहे हैं, जिसके पीछे उनके राजनीतिक स्वार्थ हैं। स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाहने कहा है कि आजादीके समय किये गये वादेको प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीने पूरा करके दिखाया है। अमित शाहने यह भी आश्वस्त किया है कि केन्द्र सरकार हर एक पात्र शरणार्थीको भारतकी नागरिकता देकर रहेगी। यह इसलिए भी जरूरी माना जायगा, क्योंकि बंगलादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तानमें रहनेवाले हिन्दुओं, सिखों, बौद्धों, जैन, पारसी और इसाई समुदायके अल्पसंख्यकोंका काफी उत्पीड़न किया गया है। भारतकी नागरिकता मिलनेसे इन्हें नया जीवन मिलेगा।

मौलिक अधिकारपर फैसला

जीवन और निजी आजादीके अधिकारके हननपर सर्वोच्च न्यायालयकी यह सख्त टिप्पणी पूरी तरह न्यायसंगत है कि किसी व्यक्तिको अपनी गिरफ्तारीका आधार जाननेका मौलिक एवं वैधानिक अधिकार है। ऐसे लिखित आधारोंकी एक प्रति गिरफ्तार व्यक्तिको बिना किसी अपवादके जल्दसे जल्द दी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहताकी पीठने बुधवारको न्यूजक्लिक वेबसाइटके सम्पादक प्रबीर पुरकायस्थकी गिररफ्तारीको चुनौती देनेवाली याचिकापर सुनवाईके दौरान संविधानके अनुच्छेद २२(१) एवं २२ (५) को रेखांकित करते हुए कहा कि ये अनुच्छेद पवित्र है। इनका किसी भी स्थितिमें उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। पुरकायस्थको रिमाण्ड अर्जीकी प्रति आवेदनके बावजूद नहीं दी गयी जिससे प्राकृतिक न्यायके सिद्धान्तोंका उल्लंघन हुआ। इसीके साथ पीठने पुरकायस्थकी गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तारी और उसके बाद रिमाण्डको अवैध करार देते हुए तत्काल रिहाईके आदेश दिये, जिन्हें उसी दिन देर शाम रिहा कर दिया गया। कोर्टका फैसला अत्यन्त महत्वपूर्ण है, क्योंकि गिरफ्तारीके आधारकी जानकारी गिरफ्तार व्यक्तिके लिए वकीलसे परामर्शका एकमात्र प्रभावी साधन हो सकती है। संविधानके तहत मिले जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रताके अधिकार सबसे पवित्र मौलिक अधिकार हैं। इनके उल्लंघनके किसी भी प्रयाससे सख्तीसे निबटनेकी जरूरत है। इसपर किसी भी प्रकारका अतिक्रमण संविधानकी अनदेखी है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पुरकायस्थकी गिरफ्तारी और रिमाण्डकी पूरी कवायद गुप्त तरीकेसे की गयी थी जो कानूनकी उचित प्रक्रियाको दरकिनार करनेका जोरदार प्रयास था। यह कानूनकी शुचिताको प्रभावी करनेवाला है। ऐसे मामलोंमें अदालतोंको कड़ा रुख अपनाना होगा, जिससे लोगोंका न्यायपर भरोसा बना रहे।

लोक संवाद

थोरियम घोटाला

महोदय,-पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयीके कार्यकालमें भारतके न्यूक्लियर ऊर्जाके क्षेत्रमें अग्रणी देशोंकी पांतमें आनेसे राष्ट्रीय टैक्नोलॉजी दिवसकी शुरुआत हुई। अटल जीने अंतरराष्ट्रीय शक्तियोंके दबावके बावजूद पोखरणमें न्यूक्लियर परीक्षणको सफल बनानेमें वैज्ञानिकोंके कंधेपर हाथ रखकर ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि दुनिया देखती रह गयी। विज्ञान और टैक्नोलॉजी पसंदीदा विषय होनेसे और इस क्षेत्रमें लेखन और फिल्म निर्माण करनेसे सोचका वैज्ञानिक होना स्वाभाविक है। ध्यान आया कि यह भी घोटालोंसे अछूता नहीं रह पाया। २४२ लाख करोड़का थोरियम घोटाला हो गया और किसीके माथेपर शिकनतक नहीं। सत्य यह है कि यदि यह न हुआ होता तो देश अबतक सुपरपावर बन चुका होता। जब डाक्टर भाभा जैसे वैज्ञानिककी दुर्घटनामें मृत्यु नहीं, हत्या हो सकती है तो वैज्ञानिकोंकी अवहेलना मामूली बात है। यूपीए सरकार अपने कार्यकालमें घोटालोंके नामसे जानी जाती थी। इन्हींमें एक था थोरियम घोटाला। उसे कैसे, किसने और क्यों बाहर नहीं आने दिया, यह जांचका विषय होना चाहिए था। इस तकनीकी विषयको सामान्य नागरिक समझ नहीं पाया और सब कुछ गहरी गर्तमें दब गया। थोरियम एक ऐसा खनिज भंडार है, जो न्यूक्लियर संसारकी जरूरतें पूरी करता है। हमारे सभी रिएक्टर, संयंत्र, अंतरिक्ष यान और बहुतसे दूसरे कामोंमें ऊर्जा यानी शक्ति या ईंधनका इस्तेमाल होता है जो थोरियमसे आसानीसे मिल जाता है। हम दुनियाके एक-तिहाईसे भी अधिक स्रोतके मालिक हैं। नागरिकोंके लाभकी बात करें तो इससे प्रति वर्ष ५०० गीगावॉट बिजली अगले ४०० वर्षोंतक पैदा की जा सकती है। इससे संचालित होनेवाले प्लांटसे निरन्तर बिजली मिल सकती है, चाहे वह कोई भी इलाका हो। थोरियम कहीं और नहीं, हमारे जो समुद्री तट हैं, बीचेज हैं, जहां हम सैर-सपाटेके लिए जाते रहते हैं, वहां जो रेत है, यह उसमेंसे निकलता है। हरेक जगह नहीं, तमिलनाडु और केरलमें सबसे अधिक और उसके बाद आंध्र, कर्नाटक और ओडिशामें मिलता है। इसका नियंत्रण भारत सरकारका संस्थान एटॉमिक एनर्जी विभाग करता है। इसकी रखवाली और प्राप्त करनेकी व्यवस्था करता है। निजी कम्पनियोंसे करार होता है कि वे इस रेतको विभागके पास जमा करायंगी, वे न इसे बेच सकती हैं, न कहीं किसी औरको दे सकती हैं तथा दूसरे देशोंको तो किसी भी कीमतपर नहीं। तमिलनाडुके शहर तिरुनेलवेलीके एक व्यापारी और उससे जुड़े लोगोंको यह ठेका दिया जाता है। इस कम्पनीने एक कण जितना भी थोरियम मिला रेत विभागमें जमा नहीं कराया और बंदरगाहों, विशेषकर तूतीकोरिनसे विदेशोंको स्मगल कर दिया। २००२-२०१२ के बीच २.१ मिलियन टन मोनटाइजर नामक खनिज गायब हो जाता है, जिसमेंसे थोरियम निकलता है। यह २,३५,००० टन थोरियमके बराबर है। एटॉमिक एनर्जी विभाग आंखें बंद कर लेता है और खरबों रुपयेका भंडार तस्करीके जरिये चीन, जापान, कोरिया, फ्रांस पहुंच जाता है। तस्कर अरबपति और देश कंगाल, नागरिक उज्जवल भविष्यकी आस लगाये बैठे रह जाते हैं। उल्लेखनीय है कि पंडित नेहरू, जो देशको विज्ञानके आधारपर विकसित करना चाहते थे, जिन्होंने औद्योगिक प्रगतिके लिए सीएसआईआर तथा अन्य वैज्ञानिक संस्थाओंका गठन किया और जो भारतकी खनिज संपदाके बारेमें जानते थे, उन्होंने इस खनिजके निर्यातपर बैन लगा दिया था। विडंबना है कि केन्द्रकी यूपीए सरकार और कांग्रेसी नेतृत्व इस खनिजके निर्यातसे पाबंदी हटा देता है। सीएसआईआरके कहनेपर भाभा एटॉमिक संस्थानके निदेशक इस तस्करीके बारेमें पता करने व्यापारीके ठिकानोंपर जाते हैं तो उन्हें अन्दर घुसनेतक नहीं दिया जाता, क्योंकि उसका ग्लोबल नैटवर्क है। एनडीए सरकार व्यापारी और उसके एक साथी तथा पर्यावरण मंत्रालयके एक भ्रष्ट अधिकारीपर मुकद्दमा चला पाती है। जिन लोगोंको देशद्रोहके जुर्ममें फांसी होनी चाहिए थी, उन्हें तीन वर्ष और सरकारी अफसरको पांच वर्षकी जेल होती है। वास्तविकता यह कि यदि यही थोरियम देशमें होता तो न ऊर्जाकी कमी होती, न औद्योगिक क्षेत्रमें पिछड़ते, शिक्षा संस्थान आधुनिक, किसान और कारीगर, मतलब सभीका जीवन संवर जाता। आज राष्ट्रीय टैक्नोलॉजी दिवसके सरकारी आयोजनोंके बीच इस घोटालेपर भी नजर पड़ जाय तो देश कृतज्ञ होगा। -**पूरन चंद, वाया ईमेल।**

https://t.me/AllNewsPaperPaid

संपादकीय

घटते मतदान का सिलसिला जारी

लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में भी मतदान 2019 के मुकाबले कम ही रहा। चुनाव और राजनीतिक दलों के तमाम प्रयासों के बाद भी वोटर अपेक्षित संख्या में वोट देने नहीं निकल रहे हैं, यह सभी की चिंता का विषय है। लेकिन इसका असली कारण यही है कि चुनाव में कोई ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं है कि जिससे यह माहौल बने कि देश में कोई सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। ऐसे में सत्तारूढ़ दल के समर्थक वोटर तथा विरोधी दलों के समर्थक मतदाता भी बहुत ज्यादा उत्साह से घरों से नहीं निकल रहे हैं। राहत की बात इतनी है कि चुनाव के शुरूआती दो चरणों के मुकाबले तीसरे और चौथे चरण में स्थिति कुछ बेहतर है। अगर मप्र की बात करें तो तीसरे चरण में दो तीन सीटों पर मतदान पिछले चुनाव की तुलना में कुछ ज्यादा दर्ज हुआ था जैसे कि राजगढ़। लेकिन ये बढ़ा हुआ मतदान के किसके पक्ष में है, यह नहीं कहा जा सकता। अच्छी बात यह है कि चौथे चरण में 8 सीटों पर भी मतदान ज्यादा भले न हुआ हो, लेकिन बहुत कम भी नहीं हुआ है। चौथे चरण के अंतिम आंकड़े आने के बाद पूरी स्थिति साफ होगी। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बम्पर वोटिंग हुई थी, वह अपने आप में अभूतपूर्व और 17 लोकसभा चुनावों में सर्वाधिक था। इस चुनाव में भाजपा और एनडीए के अधिकांश प्रत्याशी बम्पर मार्जिन से जीते थे, जबकि विपक्षी कांग्रेस के उम्मीदवार बहुत अंतर से जीत पाए थे। इस बार मप्र की 29 सीटों पर लोकसभा चुनाव का औसत प्रतिशत 2014 से ज्यादा और 2019 से कम रह सकता है। यह मतदान प्रतिशत औसतन 65 प्रतिशत हो सकता है। ध्यान रहे कि 2014 में राज्य में लोकसभा चुनाव में 61 फीसदी से अधिक मतदान हुआ था, जो 2019 में 10 फीसदी बढ़कर 71 फीसदी से ज्यादा हो गया था और भाजपा ने 29 में से 28 सीटें जीत ली थीं। मतदान में 10 फीसदी की यह वृद्धि अभूतपूर्व थी और लोग मोदी सरकार को वापस लाने के लिए घर से निकले थे। लेकिन इस बार तो मोदी सरकार को खतरा किसी से महसूस ही नहीं हो रहा है। इस बार भी लगभग वही स्थिति बनती दिख रही है। कांग्रेस दो तीन सीटों पर जीत सकती है। यह भी संभव है कि कांग्रेस को एक भी सीट न मिले। क्योंकि भाजपा लंबे समय से मिशन 29 पर काम कर रही है। इस चुनाव में आदिवासी इलाकों में उतनी ज्यादा वोटिंग नहीं हुई, जिसकी कि उम्मीद की जा रही थी। इसका मुख्य कारण विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा न होना तथा समूचा चुनाव कैम्पेन मोदी विरोध और बेरोजगारी, महंगाई पर केन्द्रित होना है। मप्र में तो राहुल गांधी को छोड़कर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता प्रचार के लिए नहीं आया। राहुल गांधी मोदी सरकार को घेर रहे हैं तो आम नेता अरविंद केजरीवाल ने यह भविष्यवाणी करके सभी को चौंका दिया था कि अगले पीएम मोदी नहीं बल्कि अमित शाह होंगे। बेशक चुनाव में भी स्थायी और स्थानीय मुद्दे हैं, लेकिन उन सब पर मोदी और राममंदिर का मुद्दा भारी पड़ सकता है। चुनाव नतीजों को यह सर्वाधिक प्रभावित करेगा। यह मुद्दे इस चुनाव में अंडर करंट की तरह से हैं, जो बाहर से भले न दिखाई दे, लेकिन जो मतदाता के दिल से जुड़े हैं। समूचे देश में लोकसभा चुनाव के तीन चरण अभी बाकी हैं। उनमें भी मतदान का वही ट्रेंड रहता है तो नतीजे 2014 के लोकसभा चुनाव के आसपास ही रह सकते हैं।

धर्म आधारित जनसंख्या का बढ़ता असंतुलन

धर्म आधारित जनसंख्या असंतुलन को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जनसंख्या का यह 'असंतुलन' ही अंत में भौगोलिक सीमा में बदलाव का कारक होता है, यह हम 1947 में देख चुके हैं जब देश का विभाजन जनसंख्या के 'असंतुलन' के कारण ही हुआ था। दुनिया में भी जनसंख्या 'असंतुलन' से हुए बदलावों के कई उदाहरण हैं जैसे कि ईस्ट तिमोर, दक्षिण सूडान और कोसोवो आदि जनसंख्या में असंतुलन के कारण ही नए देश बने हैं। लेबनान जैसे अति समृद्ध देश जनसंख्या असंतुलन के कारण तबाह हो गए। समय आ गया है कि केंद्र में आने वाली एन.डी.ए. की सरकार कुछ सख्त फैसले ले और देश में जनसंख्या नियंत्रण, समान अचार संहिता जैसे कानून लाए। इससे आबादी बढ़ा कर राजनीतिक सत्ता हासिल करने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। जनसंख्या नियंत्रित होने से देश के हर नागरिक, चाहे वह किसी मजहब को मानने वाला हो, के कल्याण के लिए देश के संसाधनों के सम्यक उपयोग का रास्ता प्रशस्त होगा।

श्याम जाजू

18वीं लोकसभा के चुनावों की गहमा-गहमी के बीच एक ऐसी रिपोर्ट आई है, जिसे देश पहले से ही जानता था पर आधिकारिक तौर पर मोहर अब लगी है। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ई.ए.सी.पी.एम.) द्वारा जारी 'धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी- एक क्रॉस कंट्री विश्लेषण (1950-2015)' शीर्षक से एक अध्ययन से पता चला है कि भारत में बहुसंख्यकों (हिंदुओं) की जनसंख्या हिस्सेदारी में गिरावट आई है।

अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत में 1950 और 2015 के बीच बहुसंख्यक ड्क्षहदू आबादी की हिस्सेदारी 1950 में 84.68 प्रतिशत से घटकर 2015 में 78.06 प्रतिशत हो गई है, अर्थात इसमें 7.82 प्रतिशत की कमी आई है जबकि इसी अवधि (65 वर्ष) में मुसलमानों की हिस्सेदारी 9.84 प्रतिशत से बढ़कर 14.09 प्रतिशत हो गई है अर्थात 43.15 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि। इसी अवधि में ईसाइयों में 5.38 प्रतिशत की वृद्धि, सिखों में 6.58 प्रतिशत की और बौद्धों में मामूली वृद्धि देखी गई, जबकि जैन और पारसियों की संख्या में कमी देखी गई। आजादी के समय देश का धर्म के आधार पर विभाजन हुआ - मुसलमानों और सैक्युलरों के बीच क्योंकि जहां पाकिस्तान केवल मुसलमानों के लिए बना, वहीं हिन्दुस्तान सभी धर्मों और सम्प्रदायों को साथ लेकर चलने वाला देश बन गया। जहां पाकिस्तान से चुन-चुन कर हिन्दुओं को भेजा गया या मार दिया गया, वहीं हिंदुस्तान में बड़ी संख्या में मुसलमान रह गए, जिनको समानता के साथ देश का नागरिक बने रहने का अधिकार मिला। कालखंड में इनकी संख्या बढ़ती गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारत सैक्युलर है और यहां के बहुसंख्यक हिंदू सैक्युलर हैं। यही वजह है कि यहां और धर्मों तथा सम्प्रदायों को मानने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। शोर के विपरीत, इस रिपोर्ट के विश्लेषण से पता चलता है कि अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित हैं, बल्कि वास्तव में भारत में फल-फूल रहे हैं।

पर इस रिपोर्ट का एक दूसरा भी पहलू है। वह यह कि जैसे-जैसे हिन्दुओं की संख्या घटेगी, देश में सैक्युलरिज्म की अवधारणा पर चोट पहुंचेगी। हाल के दिनों में यह स्पष्टता से देखने में आया है। जहां-जहां हिन्दू अल्पसंख्यक हुए हैं, वहां इनटॉलरैंस बढऩे, शरिया लागू करने की मांग उभर कर आ रही है। देश के अनेक राज्यों और जिलों में जहां-जहां हिन्दू अल्पसंख्यक हुए हैं, वहां हिन्दुओं के धार्मिक जलूसों पर पथराव, हिंदू मान्यताओं का विरोध आदि शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल और केरल इसके मुख्य उदाहरण हैं।

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हिन्दू अल्पसंख्यक हो गए हैं (ये हैं- लद्दाख, जम्मू - कश्मीर, लक्षद्वीप, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, और अरुणाचल प्रदेश)। कुछ लोग पंजाब का भी नाम लेते हैं, पर वहां के बहुसंख्यक सिख हिन्दुओं का ही बृहत्तर हिस्सा हैं। इसके अलावा देश में ऐसे कई राज्य हैं, जहां हिन्दुओं की जनसंख्या तेजी से घट रही है और मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे कि पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तराखंड, जहां पर 2001 से 2011 के दशक में ही यह वृद्धि 2 प्रतिशत की थी। 2011 के बाद निस्संदेह यह संख्या बढ़ ही रही है। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वीकली में छपी एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, केवल प्रदेशों में ही नहीं, देश के अनेकों जिलों में जनसंख्या का असंतुलन चिंताजनक तरीके से बढ़ता जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, देश के 458 जिलों में 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम आबादी की वृद्धि 24.4 प्रतिशत की थी। कई जिले तो ऐसे हैं, जो पूरी तरह से मुस्लिम बहुल हो गए हैं। उदाहरण के तौर पर बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है। यहां पर 66.8 प्रतिशत और इसके बाद नंबर आता है मालदा जिले का, जहां 51.27 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है।

दरअसल मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या दर वोटबैंक की राजनीति का परिणाम है। कांग्रेस और तृणमूल तथा समाजवादी पार्टी सरीखे कई क्षेत्रीय दलों ने मुसलमानों को एक वोटबैंक की तरह इस्तेमाल किया है। कांग्रेस ने तो आजादी के समय से ही सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए मुस्लिम कार्ड खेला है। याद कीजिए, यह कांग्रेस ही थी, जो सत्ता के लिए धर्म के आधार पर देश का विभाजन करने को तैयार हो गई थी और यह वही कांग्रेस थी, जो एक ओर तो हिन्दुओं से 'हम दो, हमारे दो' का आह्वान करती रही, वहीं दूसरी ओर आज मुसलमानों के लिए 'जितनी आबादी, उतना हक' जैसे नारे देती है।

पश्चिम बंगाल में तो राजनीतिक लाभ और वोटों की चाह में जनसंख्या विद्रूपता अपने चरम पर है। वहां पर सत्तारूढ़ तृणमूल पर वोट बैंक के लिए बंगलादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देकर मुस्लिम जनसंख्या बढ़ाने का आरोप है। बंगाल सरकार की शह पर घुसपैठियों ने कथित तौर पर वोटर कार्ड से लेकर राशन, आधार कार्ड व पासपोर्ट जैसे दस्तावेज तक बना लिए हैं, जिससे मुस्लिम संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो चुनाव में अहम रोल निभाते हैं। आज पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बड़ा फैक्टर बन गया है। ये लोकसभा की 42 में से 13 सीटों और विधानसभा की 294 में से करीब 100 सीटों पर हार-जीत करते हैं। बंगलादेश की सीमा से लगने वाले जिलों उत्तर दिनाजपुर में 49.92 प्रतिशत, बीरभूम में 37.06 प्रतिशत, दक्षिण 24 परगना में 35.57 प्रतिशत और उत्तर 24 परगना में 30 प्रतिशत मुस्लिम आबादी है, जो तृणमूल का वोट बैंक बन गई है। सी.एस.डी.एस.-लोकनीति पोस्ट पोल विश्लेषण के अनुसार, 2021 के चुनावों में 10 में से लगभग 8 मुसलमानों ने टी.एम.सी. को वोट दिया था, जो उसकी जीत का कारण बना। आज भारत को एक व्यापक जनसंख्या नीति की जरूरत है।

धर्म आधारित जनसंख्या असंतुलन को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जनसंख्या का यह 'असंतुलन' ही अंत में भौगोलिक सीमा में बदलाव का कारक होता है, यह हम 1947 में देख चुके हैं जब देश का विभाजन जनसंख्या के 'असंतुलन' के कारण ही हुआ था। दुनिया में भी जनसंख्या 'असंतुलन' से हुए बदलावों के कई उदाहरण हैं जैसे कि ईस्ट तिमोर, दक्षिण सूडान और कोसोवो आदि जनसंख्या में असंतुलन के कारण ही नए देश बने हैं। लेबनान जैसे अति समृद्ध देश जनसंख्या असंतुलन के कारण तबाह हो गए। समय आ गया है कि केंद्र में आने वाली एन.डी.ए. की सरकार कुछ सख्त फैसले ले और देश में जनसंख्या नियंत्रण, समान अचार संहिता जैसे कानून लाए। इससे आबादी बढ़ा कर राजनीतिक सत्ता हासिल करने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। जनसंख्या नियंत्रित होने से देश के हर नागरिक, चाहे वह किसी मजहब को मानने वाला हो, के कल्याण के लिए देश के संसाधनों के सम्यक उपयोग का रास्ता प्रशस्त होगा।

अध्यात्म

निंदा से सदैव बचना चाहिए

एक बार एक राजा ने यह फैसला लिया कि वह प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर खिलाया करेगा। एक दिन खीर वाले दूध में सांप ने मुंह डाला और दूध में विष डाल दिया और ज़हरीली खीर को खाकर 100 के 100 अंधे व्यक्ति मर गए। राजा बहुत परेशान हुआ कि मुझे 100 आदमियों की हत्या का पाप लगेगा। राजा परेशानी की हालत में अपने राज्य को छोड़कर जंगलों में भक्ति करने के लिए चल पड़ा, ताकि इस पाप की माफी मिल सके। रास्ते में एक गांव आया। राजा ने चौपाल में बैठे लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला परिवार है? ताकि उसके घर रात काटी जा सके। चौपाल में बैठे लोगों ने बताया कि इस गांव में दो बहन भाई रहते हैं जो खूब बंदगी करते हैं। राजा उनके घर रात ठहर गया। सुबह जब राजा उठा तो लड़की ध्यान पर बैठी हुई थी। इससे पहले लड़की का रूटीन था कि वह दिन निकलने से पहले ही ध्यान से उठ जाती थी और नाश्ता तैयार करती थी। लेकिन उस दिन वह लड़की बहुत देर तक ध्यान पर बैठी रही। जब लड़की ध्यान से उठी तो उसके भाई ने कहा की बहन तू इतना लेट उठी है ,अपने घर मुसाफिर आया हुआ है। इसने नाश्ता करके दूर जाना है। तुझे ध्यान से जल्दी उठना चाहिए था। तो लड़की ने जवाब दिया कि भैया ऊपर एक ऐसा मामला उलझा हुआ था। धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति पर कोई फैसला लेना था और मैं वो फैसला सुनने के लिए रुक गयी थी, इस लिए देर तक बैठी रही ध्यान पर। तो उसके भाई ने पूछा ऐसी क्या बात थी। तो लड़की ने बताया कि फलां राज्य का राजा अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था। लेकिन सांप के दूध में विष डालने से 100 अंधे व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज को समझ नहीं आ रही कि अंधे व्यक्तियों की मौत का पाप राजा को लगे, सांप को लगे या दूध नंगा छोड़ने वाले रसोईए को लगे। राजा भी सुन रहा था। राजा को अपने से संबंधित बात सुन कर दिलचस्पी हो गई और उसने लड़की से पूछा कि फिर क्या फैसला हुआ? लड़की ने बताया कि अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया था। तो राजा ने पूछा कि क्या मैं आपके घर एक रात के लिए और रुक सकता हूं? दोनों बहन भाइयों ने खुशी से उसको हां कर दी। राजा अगले दिन के लिए रुक गया, लेकिन चौपाल में बैठे लोग दिन भर यही चर्चा करते रहे कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव में एक रात रुकने के लिए आया था और कोई भक्ति भाव वाला घर पूछ रहा था। उस की भक्ति का नाटक तो सामने आ गया है। रात काटने के बाद वो इस लिए नही गया क्योंकि जवान लड़की को देखकर उस व्यक्ति की नियत खोटी हो गई। इसलिए वह उस सुन्दर और जवान लड़की के घर पक्के तौर पर ही ठहरेगा या फिर लड़की को लेकर भागेगा। दिनभर चौपाल में उस राजा की निंदा होती रही। अगली सुबह लड़की फिर ध्यान पर बैठी और रूटीन के टाइम अनुसार ध्यान से उठ गई। तो राजा ने पूछा- बेटी अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसको लगा? तो लड़की ने बताया- वह पाप तो हमारे गांव के चौपाल में बैठने वाले लोग बांट के ले गए। निंदक हमेशा दुसरों के पाप अपने सर पर ढोता रहता है। और दूसरों द्वारा किये गए उन पाप-कर्मों के फल को भी भोगता है। अत : हमें सदैव निंदा से बचना चाहिए।

भारतीय संस्कृति का सत्व

20 नवम्बर 1988 को भारत-चीन मैत्री संघ के तत्कालीन अध्यक्ष ठाकुर सेन नेगी ने कहा था कि भारतीय संस्कृति की पवित्रता गंगा नदी की सुगम्य धारा में निहित है जिसमें मिलकर सम्पूर्ण जल प्रवाह गंगा की जल धारा ही बन जाती है, भारतीय संस्कृति के पवित्र आदर्श इन्हीं मूल आदर्शों पर आधारित है। भारतीय संस्कृति में परोपकार की भावना निहित है जिसका तादात्म्य व्यास जी के वचनों से स्थापित होता है जो परोपकार का भाव लिए हुए है, 'अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनदयम, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम' के श्रेष्ठ आदर्शों वाली संस्कृति को आधात पहुंचाने के लिए आर्य एवं अनार्य की भ्रामक विचारधारा कार्य कर रही है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रभावित करने के लिए पंजाब में खालीस्तानी, पूर्वोत्तर में माओवादी आदि संगठनों द्वारा भारतीय संस्कृति और समाजिक संरचना को प्रभावित करने के लिए भ्रामक जानकारी आज युवा पीढ़ी को दी जा रही है, राजनीति के नापाक विचारों से देश और समाज आहत हुआ है, भारतीय संस्कृति और संस्कारों से जुड़कर हमें समाज एवं राष्ट्र दोनों को सशक्त बनाना है।

डॉ. रामेश्वर मिश्र

आज वर्तमान में युवाओं की भारतीय संस्कृति में निहित मानवीय मूल्य पर केंद्रित संस्कारों से अनभिज्ञता राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए कड़ी चुनौती है। इस अपरिपक्व ज्ञान और विचारधारा का उन्नयन एक सोची समझी विचारधारा का द्योतक है, इन्हीं नापाक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एवं समाज को समाज से तोड़ने के लिए अनेक भ्रामक विचारों का निष्पादन किया जाता है।

इस दौर में तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद एवं नकल आधारित जीवन जीने की होड़ ने समाज की रीढ़ कहे जाने वाले युवा पीढ़ी और समाजिक संस्कृति की गतिशीलता के लिए उत्तरदायी नारी शक्ति को भारतीय संस्कृति के सत्व को पहचाना होगा। सोशल मीडिया के इस युग में समाज औ राष्ट्र को कमजोर करने के लिए कभी जाति के आधार पर तो कभी उत्तर-दक्षिण का भेद-भाव फैलाकर तो कभी पूर्वोत्तर में हिंसा फैला कर भारतीय राष्ट्र को कमजोर करने की कोशिश की जाती है और जब इन सब नापाक हरकतों से काम नहीं बनता है तब हिन्दू-मुस्लिम वाद और भारतीय संस्कृति के लिए भ्रामक जानकारी फैला कर राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने का प्रयास किया जाता है। भारतीय संस्कृति में निहित त्याग, परोपकार, समरसता, दया, करुणा, मैत्री, सहानुभूति, सहिष्णुता, सहृदयता, सहयोग, समन्वय एवं सत्कर्मों आदि ऐसे मानवीय मूल्यों हैं जो भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता को विश्व पटल पर स्थापित करते हैं। भारतीय संस्कृति कभी भी ऊंच-नीच, अगड़ा-पछड़ा या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करती है। भारतीय संस्कृति में सम्पूर्ण मानव मात्र के कल्याण का भाव निहित है। उपनिषद में निहित अद्वैतवाद मानव मात्र मे ही नहीं वरन प्राणी मात्र में एक ही तत्व के दर्शन कराता है। भारतीय संस्कृति की महत्ता एवं उसकी विशालता तो उसके सम्पूर्ण मानव से तादात्म्य स्थापित करने मे निहित है जिसका मूल वसुधैव कुटुम्बकम की पवित्र भावना है। भारतीय संस्कृति में सम्पूर्ण विश्व को एक परिवार माना गया है। इतने ऊंचे आदर्शों वाली भारतीय संस्कृति के लिए भ्रामक विचारों का उन्नयन अल्प ज्ञान का प्रदर्शन मात्र है। मन की समता, समरसता, त्याग और करुणा के भाव, भारतीय संस्कृति में निहित उच्च मानवीय आदर्श है।

20 नवम्बर 1988 को भारत-चीन मैत्री संघ के तत्कालीन अध्यक्ष ठाकुर सेन नेगी ने कहा था कि भारतीय संस्कृति की पवित्रता गंगा नदी की सुगम्य धारा में निहित है जिसमें मिलकर सम्पूर्ण जल प्रवाह गंगा की जल धारा ही बन जाती है, भारतीय संस्कृति के पवित्र आदर्श इन्हीं मूल आदर्शों पर आधारित है। भारतीय संस्कृति में परोपकार की भावना निहित है जिसका तादात्म्य व्यास जी के वचनों से स्थापित होता है जो परोपकार का भाव लिए हुए है, 'अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनदयम, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम' के श्रेष्ठ आदर्शों वाली संस्कृति को आधात पहुंचाने के लिए आर्य एवं अनार्य की भ्रामक विचारधारा कार्य कर रही है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को प्रभावित करने के लिए पंजाब में खालीस्तानी, पूर्वोत्तर में माओवादी आदि संगठनों द्वारा भारतीय संस्कृति और समाजिक संरचना को प्रभावित करने के लिए भ्रामक जानकारी आज युवा पीढ़ी को दी जा रही है, राजनीति के नापाक विचारों से देश और समाज आहत हुआ है, भारतीय संस्कृति और संस्कारों से जुड़कर हमें समाज एवं राष्ट्र दोनों को सशक्त बनाना है।

संस्कृति बोध से व्यक्ति हजारों हजार साल से परम्पराओं के जरिये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भारतीय संस्कृति के मूल्यों से जुड़ता आ रहा है। भारतीय संस्कृति के सत्व को पहचानने के लिए हमें विवेकानन्द जी, गांधी जी, धरमपाल जी के विचारों के चिन्तन को समझना चाहिए। गांधी जी भारतीय संस्कृति के सत्व को पहचानते थे और अपने सपनों के भारत में देशवासियों के अटूट प्रेम और राष्ट्र की एकता पर बल देते हुए देशज संस्कृति से जुड़ने की बात की है। गांधी जी के इन्हीं विचारों को लेकर धर्मपाल जी ने कार्य किया है और साक्ष्यों एवं प्रमाणों के आधार पर यह साबित किया कि ब्रिटिश शासन ने भारत की शिक्षा पद्धति का अपहरण करते हुए भारतीय संस्कृति का अपहरण किया, इसका एक उदहारण देते हुए धर्मपाल जी लिखते हैं कि '1830 में ब्रिटिश गवर्नर जर्नल बेंटिक ने इस बात पर संतोष व्यक्त करते हुए कहते हैं कि-'सम्पन्न और प्रतिष्ठित भारतीय अब पश्चिमी शिष्टाचार तथा व्यवहार की विधियां अपनाने लगे हैं और भिक्षुकों, सन्यासियों और ब्राह्मणों को दान देना छोड़ रहे हैं। अब उसकी जगह वह धन यूरोपियों का आडम्बर पूर्ण ढ़ंग से मनोरंजन करने में लगाया जाने लगा है।' 'रमणीय वृक्ष' में धर्मपाल जी भारतीय शिक्षा प्रणाली में आये परिवर्तनों के कारणों को बताते हुए लिखते हैं कि- भारतीय भाषाओं में पढ़ाई में कमी का मुख्य कारण पूरे देश में चलाई जा रही ब्रिटिश नीति ही होगी।

भारतीय संस्कृति में हुए इस परिवर्तन के लिए धर्मपाल जी आगे लिखते हैं कि प्रत्येक भाषा का एक विशद अर्थ होता है, उसमे परम्परा, दर्शन-परम्परा और विचार की अभिव्यक्ति होती है। जब हम विदेशी भाषा को अपनाते हैं तो प्रायः स्वयं को, विश्व को, व्यक्ति, समाज संस्थाओं, मान्यताओं, लक्ष्यों, रुचियों तथा आदर्शों आदि को भी हम उसी भाषा-परम्परा और संस्कृति-परम्परा से देखने लगते हैं। धर्मपाल जी ने भारतीय संस्कृति और परम्परा से लोगों को जुड़ने के लिए कहा जिस संस्कृति में लोगों का लोगों के प्रति निजता जुड़ी थी और जिसका पतन भारतीय संस्कारों एवं सभ्यता का पतन था। स्वत्व एवं भारतीयता की जो संकल्पना धर्मपाल जी द्वारा प्रयोग की जाती थी वह मानवीय प्रेरक थी।

भारतीय संस्कृति का बोध यह है कि राष्ट्र एवं विश्व के समस्त प्राणियों के बीच प्रेम और एकता का भाव हो जिसके फलस्वरूप विश्व कल्याण की कामना को मूर्त किया जा सके। भारतीय संस्कृति में निहित समर्पण और शान्ति की कामना से विश्व में शान्ति स्थापित की जा सकती है। इन मालवीय मूल्यों से निहित मंगल कामना से समूल राष्ट्र और विश्व को एकता के सूत्र में पिरोया जा सकता है। भारतीय संस्कृति के मूल '? द्यौः शांति' के मंत्र है, जो कि यजुर्वेद से लिया गया है, इस मंत्र में परमपिता से विश्व कल्याण और शान्ति के लिए प्रार्थना की गयी है। भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता की संस्कृति है परन्तु इन सब विविधताओं को जो एक साथ जोड़ता है वह संस्कृति के मूल में निहित शान्ति और विश्व के कण-कण की शान्ति की कामना है। भारत में रहने वाले समूल निवासी उसी परम्परा के वाहक है जो मिश्रित रूप से राष्ट्र कल्याण का भाव रखते हैं।

आज का कार्टून

राशिफल

मेष

किसी महत्वपूर्ण बैठक में आम सम्मिलित हो सकते हैं। प्रेम सम्बन्धों में प्रगाढ़ता बढ़ने के योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में मित्रों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा।

वृषभ

नौकरीपेशा लोगों को घर पर भी बहुत कुछ काम करना पड़ेगा। विद्यार्थी अपने करियर को लेकर कुछ बौद्धिक लोगों से परामर्श ले सकते हैं।

मिथुन

बड़े आर्थिक निवेश के लिये समय अनुकूल नहीं है। अपने किसी शौक को करियर के रूप में चुन सकते हैं। अधिकारी वर्ग आपके प्रति नकारात्मक हो सकता है।

कर्क

व्यापार में स्थितियाँ सम्भलती हुयी प्रतीत होंगी। समय अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करें। परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा।

सिंह

कोई बड़ा खर्च अचानक सामने आ सकता है। पार्टनरशिप से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ज्यादा आदर्शवादी होने से आपको बचना चाहिये।

कन्या

सहकर्मी आपकी काफी मदद करेंगे। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ मीटिंग कर सकते हैं। निजी रिश्तों में मधुरता बनाये रखने में आपकी बड़ी भूमिका होगी।

तुला

आपको शरीर में सुस्ती महसूस हो सकती है। आप किसी समस्या को सुलझाने के लिये काफी तनाव ले रहे हैं। चुस्ती फुर्ती के लिये व्यायाम अवश्य करें।

वृश्चिक

ऐसे मुद्दों से दूर रहें जिसके विषय में आपके पास कम जानकारी है। दूसरे लोगों की काफी मदद करेंगे। अपनी गुप्त बातें किसी से शेयर न करें।

धनु

धन को लेकर थोड़े परेशान रहेंगे। दिनचर्या अव्यवस्थित हो सकती है। अनजानी जगहों पर अकेले यात्रा करने से बचें। हमेशा अपने दिमाग का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें।

मकर

व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आयेगी। अटकी हुयी पेमेन्ट आपको वापस मिल सकती है। अविवाहितों को विवाह के उत्तम प्रस्ताव मिल सकते हैं। पारिवारिक वातावरण मधुर रहेगा।

कुंभ

समय का सदुपयोग करने की प्रवृत्ति के कारण आज आप काफी सक्रिय रहेंगे। सन्तान के प्रति अपना व्यवहार अच्छा रखें। घर का माहौल सुखद रहेगा।

मीन

आपको भागदौड़ काफी ज्यादा करनी पड़ेगी। आप दूसरों के झगड़ों को सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं। कानूनी मामलों को लेकर सावधान रहें।

https://t.me/Newspaper

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 78

अपवादों से बचें

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने बुधवार को शेयर बाजार को जानकारी दी कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने उसे 10 फीसदी सार्वजनिक अंशधारिता की अनिवार्यता पूरी करने के लिए तीन साल की मोहलत और दे दी है। अब उसे 16 मई, 2027 तक इसे पूरा करना होगा। एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के बाजार पूंजीकरण वाली कंपनियों से सरकार की अपेक्षा है कि वे पांच साल में 25 फीसदी सार्वजनिक अंशधारिता की व्यवस्था करें। बहरहाल, एलआईसी की बात करें तो उसके लिए पहले ही इसे 10 वर्ष किया जा चुका है। एलआईसी के शेयरों ने जहां अवधि विस्तार की इस घोषणा पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, वहीं इससे बचे जाने की आवश्यकता थी। ऐसे कदम बाजार नियामक और सरकार दोनों की विश्वसनीयता को प्रभावित करते हैं।

आर्थिक सुधारों के बाद की अवधि में देश के नीतिगत प्रतिष्ठान की एक बड़ी कमजोरी रही है अच्छी पहलों को बरकरार नहीं रख पाना। विनिवेश कार्यक्रम भी ऐसा ही एक उदाहरण है। बुनियादी विचार यह था कि सरकारी उपक्रमों की हिस्सेदारी बेचने या उनका पूरी तरह निजीकरण करने से इनके प्रदर्शन में सुधार होगा तथा सरकार को भी संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी। सेबी के सार्वजनिक हिस्सेदारी के मानकों का उद्देश्य था सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार नकदीकरण करना तथा उनके लिए बेहतर मूल्यांकन की तलाश करना। बहरहाल एलआईसी के मामले में विनिवेश और सार्वजनिक अंशधारिता दोनों ही सिद्धांतों के साथ समझौता हुआ। एलआईसी को करीब दो वर्ष पहले यानी मई 2022 में सूचीबद्ध किया गया था और उसकी 3.5 फीसदी हिस्सेदारी का निजीकरण किया गया था। उम्मीद थी कि आगे चलकर सरकार और हिस्सेदारी बेचेगी तथा सूचीबद्धता के उल्लिखित मानक हासिल करेगी। बहरहाल अब तक ऐसा नहीं हुआ है।

सरकार के अनिच्छुक होने की एक वजह एलआईसी के शेयरों का प्रदर्शन भी है। 949 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर जारी होने के बाद मार्च 2023 में ये घटकर 540 रुपये प्रति शेयर पर आ गए थे। ऐसे में अगर बाद में दोबारा सार्वजनिक पेशकश की जाती तो उसे काफी कम कीमत मिलती। वास्तव में बाजार में और शेयरों के आने के अनुमान से कीमतों में और गिरावट आ सकती थी। परंतु इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि शुरुआती पेशकश को अधिक अनुकूल कीमत मिली। चूंकि झटके के बाद शेयर उबर गया इसलिए सरकार सार्वजनिक अंशधारिता के मानक का पालन करने के लिए अपने शेयर बेच सकती थी। एलआईसी के 6 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कुल बाजार पूंजीकरण को देखते हुए सरकार अपने पूंजीगत व्यय कार्यक्रम के लिए अच्छी खासी राशि जुटा सकती थी और अपना राजकोषीय घाटा कम कर सकती थी। परंतु ऐसा नहीं किया गया। शायद सरकारी उपक्रम होने के कारण एलआईसी को यकीन था कि उसे नियामकीय राहत मिल जाएगी।

बहरहाल, कीमतों में कमी और संभावित राजनीतिक अनिवार्यता से परे ऐसी घटनाएं कुछ इस प्रकार की नजीर पेश करती हैं जिनसे बचा जाना चाहिए। यह बात ध्यान देने लायक है कि एलआईसी कोई अनूठा मामला नहीं है। बाजार के आंकड़े दिखाते हैं कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों समेत 20 से अधिक ऐसी सूचीबद्ध कंपनियां हैं जहां सरकार की हिस्सेदारी 75 फीसदी से अधिक है। सरकार 12 कंपनियों में तो 90 फीसदी से अधिक की हिस्सेदार है। विशुद्ध आर्थिक नजरिये से देखें तो यह समझना मुश्किल है कि जब सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ा हुआ है और वह पूंजीगत व्यय बढ़ाना चाहती है तब भी वह विनिवेश पर आक्रामक ढंग से जोर नहीं दे रही है। हाल के दिनों में शेयर बाजार भी सहयोगी भूमिका में रहे हैं। ऐसे में सरकारी उपक्रमों में शेयरों की बिक्री करके मानकों का पालन करने से सरकार को पर्याप्त संसाधन भी मिल जाते। इससे भी अहम बात, सरकार सार्वजनिक उपक्रमों के लिए अपवाद तैयार करने से बच जाती।

नई सरकार की क्या हों प्राथमिकताएं

केंद्र में बनने वाली नई सरकार को कुछ ऐसी नीतियों का निर्माण और उन पर अमल करना चाहिए जो देश को समतापूर्ण वृद्धि प्राप्त करने में मददगार साबित हों, बता रहे हैं नितिन देसाई

चुनाव में चाहे जिसकी जीत हो, नई सरकार का प्राथमिक ध्यान इस बात पर केंद्रित होगा कि चुनाव घोषणापत्र में किए गए वादों पर किस तरह अमल किया जाए। इसमें बजट में घोषित कल्याण योजनाओं के लिए फंडिग भी शामिल होगी जिसे वर्ष के मध्य में पेश किया जाएगा। बहरहाल, वास्तविक जरूरत होगी विकास नीति को नए सिरे से तैयार करना ताकि हम समतापूर्ण वृद्धि के करीब आ सकें।

विकास से जुड़े हमारे प्रदर्शन में कुछ दीर्घकालिक खामियां हैं और हालिया आंकड़े बताते हैं कि कुछ कमियां भी हैं जिन्हें हल करना होगाः

1. निजी खपत और कारोबारी निवेश बढ़ाने के प्रयास
2. उत्पादक रोजगार में वृद्धि को बढ़ावा देना और छोटे और मझोले उपक्रमों के लिए ऐसी नीतियां बनाना जो उन्हें बढ़ने को प्रोत्साहित करें।
3. शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य सेवा में अहम सुधार ताकि श्रम शक्ति को नए पेशों के लिए उपयुक्त बनाया जा सके।
4. इन सबके साथ प्रभावी संघवाद के लिए लाभ और जरूरत को लेकर अधिक सम्मान की भावना।

पहले निजी खपत बढ़ाने की बात करते हैं। नैशनल अकाउंट्स स्टैटिसटिक्स (एनएएस) के ताजा आंकड़े बताते हैं कि खपत में वृद्धि की सालाना दर 2011-12 से 2018-19 तक सात फीसदी रहने के बाद गत पांच वर्षों से चार फीसदी से थोड़ी अधिक रह गई है।

2023-24 के दूसरे अग्रिम अनुमान बताते हैं कि निजी खपत में केवल तीन फीसदी वृद्धि हुई है। भारत जैसे बड़े देश में निजी खपत वृद्धि में मंदी कॉर्पोरेट निवेश को प्रभावित करेगी। यही वजह है कि ताजा एनएएस दिखाता है कि निजी कारोबारी निवेश की सालाना दर 2011-12 और 2015-16 के बीच 10 फीसदी से अधिक रहने के बाद अब घटकर पांच फीसदी से कम रह गई है।

ऐसा आंशिक रूप से वस्तु एवं सेवा निर्यात में कमी की वजह से हो सकता है। कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो कारोबारी निवेश घरेलू मांग वृद्धि से संचालित है जिसे निजी खपत आकार देती है। निजी खपत वृद्धि में कमी की वजह क्या हो सकती है? यह घरेलू बचत में इजाफा तो नहीं है क्योंकि एनएएस के मुताबिक पारिवारिक आय में घरेलू बचत का प्रतिशत 2011-12 के 29 फीसदी से कम होकर 2022-23 में 23 फीसदी रह गया है। मेरी नजर में ऐसा इसलिए हुआ कि उच्च आय वाले समूहों की आय बढ़ी। यह महंगी टिकाऊ वस्तुओं और उपभोक्ता उत्पादों की बढ़ती मांग में भी नजर आता है। कम आय वाले समूहों में धीमी आय वृद्धि शायद धीमी खपत वृद्धि की मुख्य वजह है।

देश में आय की असमानता का आकलन बहुत विभाजित है। खासतौर पर हाल के वर्षों में ऐसा राजनीतिक वजहों तथा डेटा की कमी की वजह से हुआ। सावधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण 2022-23 के मुताबिक करीब 46 फीसदी श्रमिक कृषि क्षेत्र में हैं जबकि राष्ट्रीय स्तर पर सकल मूल्यवर्द्धन में कृषि की हिस्सेदारी 18 फीसदी है। इसका बड़ा हिस्सा भू-स्वामित्व के प्रतिफल के रूप में है।

इसके अलावा श्रमिकों का ऐसा समूह भी है जो बहुत अधिक शोषण का शिकार है। उदाहरण के लिए विनिर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक जो मार्च 2020 में लगे कोविड लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित हुए थे। श्रम शक्ति में इनकी हिस्सेदारी 13 फीसदी है। उपरोक्त सर्वे का एक तथ्य यह भी है कि केवल 21 फीसदी रोजगार शुदा श्रमिकों के पास नियमित वेतन आय है और 18 फीसदी केवल घरेलू उपक्रमों में सहायक का काम करते हैं।

यह भी ध्यान देने वाली बात है कि गैर कृषि क्षेत्र में 74 फीसदी श्रमिक प्रोपराइटर और पार्टनरशिप उपक्रमों में काम करते हैं। इनमें से अनेक ऐसे हैं जो श्रम कानूनों के दायरे से बाहर हैं। श्रमिकों के अधिकारों के कानून लागू करना मायने रखता है और ऐसा किया जाना चाहिए। परंतु अहम जवाब एक ऐसी विकास नीति है जो करीब एक दशक तक श्रम आयु वाली आबादी की वृद्धि दर की तुलना में तेजी से उत्पादक रोजगार बढ़ाए।

इससे श्रमिक कृषि क्षेत्र से बाहर आएंगे और बड़ी तादाद में उनके मेहनताने में सुधार होगा। उन क्षेत्रों के कामगारों के मेहनताने में ऐसा सुधार देखा जा सकता है जहां उत्पादक रोजगार वहां की स्थानीय कामगार आबादी में वृद्धि से अधिक हैं या जहां सामाजिक कारक श्रम की सौदेबाजी की ताकत बढ़ाते हैं।

इसका एक उदाहरण है तमिलनाडु के गैर कृषि कामगारों की दैनिक मजदूरी और राष्ट्रीय औसत में अंतर। उन्हें रोज 482 रुपये मेहनताना मिलता है जबकि राष्ट्रीय औसत 348 रुपये का है। दक्षिण और पश्चिमोत्तर के अन्य प्रवासी निर्भर प्रांतों में भी यह अंतर काफी अधिक है। प्रवास से मदद मिलती है और जनगणना के मुताबिक 2001 के 3.3 करोड़ कामगारों की तुलना में 2011 में 5.1 करोड़ प्रवासी कामगार थे। परंतु प्रवास कामगार आबादी की आयु में अनुमानित वृद्धि का समुचित जवाब नहीं है। खासकर उत्तर भारत में। इसका जवाब उत्तर भारत में उत्पादक रोजगार बढ़ाने में निहित है।

मेरा मानना है कि छोटे उपक्रमों की गतिशीलता एक प्रमुख कारक है। बहरहाल, इन्हें दिया जाने वाला नीतिगत प्रोत्साहन, खासतौर पर नियंत्रित नियमन से राहत के रूप में किया जाने वाला नीतिगत हस्तक्षेप उन पर यह दबाव बनाता है कि वे अपना स्तर छोटा बनाएं रखें। इससे बचने की जरूरत है। उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे छोटे से मध्यम आकार में अपना विस्तार करें और मझोले आकार से बड़े आकार की ओर बढ़ें।

उत्पादक रोजगार निर्माण का एक और पहलू है राष्ट्रीय मूल्य श्रृंखला पर नियमित ध्यान देना। यह भौतिक और डिजिटल अधोसंरचना में व्यवस्थित सुधार के साथ उत्तरी राज्यों को उच्च वृद्धि वाले दक्षिण और पश्चिम के राज्यों से जोड़ सकता है। गौरतलब है कि उत्तर के राज्यों में रोजगार तैयार करने की सख्त आवश्यकता है। ई-कॉमर्स और डिजिटल भुगतान व्यवस्था का तेज उभार भी इसमें मदद कर सकता है।

प्रभावी रोजगार तैयार करने के लिए पर्याप्त कुशल कर्मियों की आवश्यकता है। इसके लिए कौशल विकास पर काम करना होगा। इससे भी एक कदम आगे बढ़कर शिक्षा और स्वास्थ्य की गुणवत्ता बढ़ाने पर भी काम किया जा सकता है। इससे न केवल समता बढ़ाने में मदद मिलेगी बल्कि प्रभावी श्रम शक्ति के लिए बेहतर आधार भी तैयार होगा।

इन उपायों से उत्पादक रोजगार तैयार करने की दर के कारण आय में इजाफा हो सकता है। खासकर उन इलाकों में जहां कृषि से विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की ओर बदलाव की अधिक आवश्यकता है। इससे खपत की मांग बढ़ेगी और इस प्रकार निवेश तथा वृद्धि हासिल होगी जो सभी राज्यों के लिए मददगार साबित होगी। परंतु इसके लिए एक योग्यता जरूरी है। अधिकांश उपाय अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होंगे। ऐसे में राष्ट्रीय नीतियां इस प्रकार बनानी होंगी ताकि राज्यों के पास पर्याप्त वित्तीय और निर्णय लेने की क्षमता हो और वे चुनिंदा उपायों को लागू कर सकें।

ऐसे में केंद्र में बनने वाली नई सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह अपने वादे पूरे करे लेकिन साथ ही ऐसे उपाय भी अपनाए जो समतापूर्ण वृद्धि को गति देने वाले हों। ऐसा करते समय देश की भौगोलिक विविधता तथा जरूरतों और संभावनाओं का ध्यान रखा जाए।

आर्थिक बदलाव और चुनावी नतीजे

आम चुनावों के परिणाम से भारत का आर्थिक भविष्य, खासकर राजनीतिक अर्थव्यवस्था की वजह से महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित होगा। अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है और यह बढ़ती असमानता, घटती आमदनी और कमजोर बुनियादी ढांचे की तिहरी मार झेल रही है। कोरोना महामारी ने भी ग्रामीण क्षेत्रों की परेशानी को और बढ़ा दिया है।

देश की कुल कामकाजी आबादी में 45 फीसदी का हिस्सा रखने वाले कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर पिछले साल सिर्फ 1.8 फीसदी रही। नतीजा यह हुआ कि देश के 40 प्रतिशत लोगों को सब्सिडी वाले मुफ्त भोजन का सहारा लेना पड़ रहा है। शहरों में भी रोजगार की स्थिति खराब है। करीब 10 करोड़ से ज्यादा युवा न तो पढ़ाई और न ही नौकरी कर रहे हैं। युवाओं को कम वेतन वाली सरकारी नौकरियों के लिए आपस में कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, वहीं दूसरी तरफ विनिर्माण (उत्पादन) का क्षेत्र भी सिमटकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का सिर्फ 13 फीसदी रह गया है।

फ्रांस के शाही घराने के राजाओं की तरह ही अभिजात्य वर्ग अपने एक सीमित समुदाय वाले दायरे में ऐशो-आराम की जिंदगी जी रहे हैं। दूसरी ओर शेयर बाजारों में तेजी दिख रही है और पूंजी लगाने से मुनाफा बढ़ रहा है और इन सबका फायदा सिर्फ उन्हें ही मिल रहा है। आमलोगों की तनख्वाह वहीं की वहीं ठहरी हुई है जबकि पूंजीपति खूब खर्च कर रहे हैं, अपनी पूंजी विदेश भेज रहे हैं और अपने बच्चों को भी विदेश पढ़ने भेज रहे हैं।

अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कोई ठोस और दीर्घकालिक रणनीति भी नजर नहीं आ रही है। देश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों के बीच बढ़ती असमानता वास्तव में गंभीर राजनीतिक और आर्थिक सवाल खड़े कर रही है। लेकिन इन सवालों का अब तक कोई समाधान नहीं मिला है। इन सभी चुनौतियों के सामने, सत्तारूढ़ पार्टी के घोषणा पत्र में कुछ दिखावे और सब्सिडी देने की बातें शामिल हैं। इसमें बेरोजगारी की समस्या या ग्रामीण क्षेत्रों की परेशानियों को भी नहीं स्वीकारा गया है। गृह मंत्रालय की ओर से भी 2019 के घोषणा पत्र में किए गए वादों को लागू करने के लिए बल प्रयोग करने की रणनीति साफ दिखाई देती है।

पिछले दिनों एक साक्षात्कार में गृह मंत्री ने यह बताया कि अगली सरकार के लिए शेयर बाजार का अच्छा प्रदर्शन और रुपये में अंतरराष्ट्रीय कारोबार अहम लक्ष्य होंगे। इस तरह यह अंदाजा हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है।

रथिन रॉय

इन रिकॉर्ड के अनुसार, वर्ष 2024 में दीर्घकालिक या अल्पकालिक आर्थिक समस्याओं को ध्यान में रखकर वोट देने वाला कोई भी मतदाता 2019 जैसा (या उससे बेहतर) जनादेश 2024 में नहीं देगा।

अगर मौजूदा सरकार को पूर्ण बहुमत या उससे ज्यादा सीटें मिल जाती हैं तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि लोगों के लिए अर्थव्यवस्था की स्थिति शायद उतना अहम मुद्दा नहीं है। इसके विपरीत, अगर किसी भी तरह की गठबंधन सरकार सत्ता में आती है तब यह बात अहम हो जाएगी कि 'अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा मायने रखती है।'

इसके बाद क्या होगा? वर्ष 2019 में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने संरचनात्मक बदलाव से जुड़े विचार को खारिज कर दिया और मुझसे 'छोटे आर्थिक सुधारों' का सुझाव देने के लिए कहा था। लेकिन ऐसा लगता है कि अब इसमें बदलाव आया है। कांग्रेस का घोषणापत्र देश के सामने मौजूद ढांचागत चुनौतियों को स्वीकार करने और उनका विश्लेषण करने के साथ-साथ असमानता कम करने, समृद्धि लाने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए साहसिक कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित करता है। इसकी पुष्टि निर्वाचित पार्टी नेताओं के सार्वजनिक बयानों द्वारा और मजबूती से होती है।

कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दोनों के घोषणापत्रों में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों के लिए सब्सिडी और आरक्षण के वादे शामिल हैं। ये उपाय जरूर आवश्यक हैं लेकिन ये संरचनात्मक चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। कृषि के मुद्दे पर कांग्रेस ने एक अहम प्रस्ताव दिया है कि कृषि वित्त में सुधार किया जाए और एक बेहतर कृषि आयात-निर्यात नीति को मजबूत बनाने और न्यूनतम समर्थन मूल्य के सवालों का समाधान भी निकालने की कोशिश की जाए।

कांग्रेस यह भी मानती है कि भूमि का सवाल अहम है और घटती हुई वास्तविक मजदूरी और बढ़ते मुनाफे के बीच श्रम और पूंजी के संतुलन को बहाल करने की जरूरत है। सबसे अच्छा प्रस्ताव यह है कि कार्यबल की गुणवत्ता, उसके दायरे और रोजगार क्षमता को बेहतर बनाने के लिए हर डिप्लोमा धारक और कॉलेज ग्रैजुएट को मांग के आधार पर एक साल के लिए सशुल्क प्रशिक्षण दिया जाए।

एक अन्य पार्टी द्रमुक मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) ने एक सुसंगत सामाजिक न्याय घोषणापत्र की पेशकश की है जो विनिर्माण और उच्च-मूल्य सेवाओं की नौकरियों को बेहतर बनाने के विशेष प्रस्तावों के साथ यह अतीत के मानव विकास और विकास की उपलब्धियों पर आधारित है। यदि प्रशिक्षण के प्रस्ताव पर 1 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाने से भी नौकरियों के लिए कुशल लोग तैयार होंगे और इससे बड़े पैमाने पर प्रतिफल मिलेगा।

यह तो अच्छी शुरुआत है, लेकिन और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। जैसा कि मशहूर अर्थशास्त्री कीन्स ने कहा था, 'अगर आप इसे कर सकते हैं, तो आप इसका खर्च भी उठा सकते हैं।' पैसा असल समस्या नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि एक प्रशिक्षण कार्यक्रम पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपये खर्च करने से रोजगार के लिए कुशल लोग तैयार होंगे तो यह भविष्य में बहुत अधिक लाभ देगा।

इसी तरह, एक स्थिर और अधिक उत्पादक कृषि क्षेत्र न सिर्फ गरीबी कम करने में मदद करेगा बल्कि समावेशी विकास के लिए महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही, सामाजिक न्याय के उपाय भी बहुतजरूरी हैं जो मानव विकास और उनकी भागीदारी में आने वाली बाधाओं को दूर करेंगे। मुख्य बात यह सुनिश्चित करना है कि इन उपायों को बड़े पैमाने पर लागू किया जाए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) और सर्व शिक्षा अभियान जैसी योजनाओं में देखी गई धीमी प्रगति, आगे बढ़ने के लिए न तो स्वीकार्य होगी और न ही यह वहन करने योग्य होगी।

बड़े पैमाने की अन्य नीतिगत योजनाओं की भी कमी नहीं है। मैंने भी 'जहां घर वहीं नौकरी' का प्रस्ताव दिया था जिससे पलायन की समस्या के साथ ही उत्तर-दक्षिण के विभाजन की समस्या का हल होगा और यह एक नए राष्ट्रीय राजनीतिक समझौते का आधार बन सकता है।

शहरी क्षेत्र के लिए नरेगा जैसी योजनाओं के साथ ही भारत को झुग्गियों से मुक्त करने के लिए सरकारी जमीन का उपयोग, घरेलू बाजार की मांग को पूरा करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र पर नए सिरे से ध्यान देना, वियतनाम और बांग्लादेश से 200 रुपये की शर्ट के आयात को रोकना, गरीब समर्थक बुनियादी ढांचे (एयरपोर्ट के बजाय बस स्टेशन, फुटपाथ आदि) पर जोर देना विभिन्न राजनीतिक दलों के जमीनी कार्यकर्ताओं को अच्छा लग सकता है।

चुनाव महत्त्वपूर्ण है। आज के मतदाता यह फैसला कर रहे हैं कि देश का आर्थिक बदलाव उनके चुनावी फैसले को निर्धारित करेगा या नहीं। फैसला 4 जून को होगा जिसमें हमारे सामूहिक वोट के नतीजे सामने दिखेंगे।

(लेखक ओडीआई, लंदन में विजिटिंग सीनियर फेलो हैं और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य रह चुके हैं)

आपका पक्ष

देश के श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी

देश की श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी कम है जिसे बढ़ाने की जरूरत है। देश के विभिन्न उद्योगों में महिला कर्मचारियों की संख्या अलग-अलग है। आमतौर पर महिला रोजगार के लिए शिक्षक, बैंक में नौकरी या सॉफ्ट स्किल के बारे में ही अधिक विचार किया जाता है। लेकिन आज देश विकसित होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में जरूरी लगने लगी है। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद सेना में भी महिलाओं की नियुक्ति होने लगी है। पिछले दिनों रिलायंस इंडस्ट्रीज की निदेशक ईशा अंबानी ने भी हर कार्य क्षेत्र में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने आईटी और इंजीनियरिंग क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की वकालत की। आज महिलाएं हर क्षेत्र में बेहतर काम कर रही हैं। उन्हें शिक्षिका, परिचारिका, नर्स आदि जैसे तय

ऑटोमोबाइल कंपनियों में महिलाएं वाहन विनिर्माण में भी अपना बेहतर योगदान दे रहीं हैं

कार्य क्षेत्रों में सीमित नहीं किया जा सकता है। आज सेना से लेकर पुलिस बलों में और अंतरिक्ष से लेकर कृषि क्षेत्र में महिलाएं अपना बेहतर योगदान दे रही हैं। मेट्रो चालक हो या कैब चालक यहां तक कि बसों में भी महिला ड्राइवर काम कर रही हैं। हमें अपनी रूढ़िवादी सोच को बदल कर महिलाओं को हर क्षेत्र में कार्य करते हुए देखने की आदत डालनी होगी। देश तभी विकसित होगा जब तक विकास कार्य में महिलाओं की हिस्सेदारी आधी नहीं हो जाती है। महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए रोजगार में आरक्षण के अलावा महिला आरक्षण के बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है। जब तक रोजगार में महिला आरक्षण नहीं दिया जाता तब तक महिलाओं को उचित मौका नहीं मिल सकेगा।

मोहित कुमार, नई दिल्ली

पहाड़ी तीर्थ स्थल पर भीड़ नियंत्रित हो

उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में यात्रियों का सैलाब उमड़ रहा है। 10 मई से यात्रा शुरू होने के बाद से 14 मई तक करीब पौने तीन लाख तीर्थयात्री यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, और बदरीनाथ का दौरा कर चुके हैं। अभी तक 27 लाख लोग चार धाम यात्रा के लिए पंजीयन करा चुके हैं। इस वर्ष 80 लाख लोगों के चार धाम यात्रा के लिए जाने की संभावना है। बेशक लोगों का धार्मिक पर्यटन के प्रति रुझान बढ़ा है क्योंकि पहाड़ों पर सड़कें अच्छी बन गई है। नई सुरंगें बनाने से मार्ग सुगम, छोटे और जल्दी पहुंचाने वाले हो गए हैं। देशभर में कई ट्रैवल एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं और हेलीकॉप्टर के सभी टिकट बुक हो चुके हैं। विगत वर्षों से हमने पहाड़ों पर भारी प्राकृतिक आपदाएं देखी हैं जिनका सबसे बड़ा कारण पर्यटकों की सुविधाओं के लिए किए जा रहे निर्माण कार्य और अधिक भीड़ भी बताया जाता है। अब वक्त आ गया है कि सरकार को पहाड़ों पर जाने वाले पर्यटकों की संख्या को नियंत्रित करना चाहिए। अधिक कमाई के लालच में यदि ऐसे ही पहाड़ बिखरते रहे तो भविष्य में पूरे देश के लिए पर्यावरण का बड़ा संकट हो सकता है और पहाड़ी तीर्थ स्थलों को भारी क्षति पहुंच सकती है।

मधु सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो – पीटीआई

उत्तराखंड में नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने की कोशिश करते दमकल कर्मी। राज्य के जंगलों में इन दिनों कई जगह भीषण आग लगी हुई है और यह मामला उच्चतम न्यायालय भी पहुंचा, जहां न्यायालय ने आग को काबू नहीं कर पाने पर अपनी नाराजगी जताई।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

ईशावास्यमिदं सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

पंजाब केसरी संपादकीय

संस्थापक: शहीद शिरोमणि लाला जगतनारायण जी, अमर शहीद रमेश चन्द्र जी एवं कलम के योद्धा अश्विनी कुमार जी

युद्ध में भारतीय कर्नल की मौत

इजराइल और हमास के बीच पिछले सात महीनों से जंग जारी है। इस जंग में 30 हजार फिलिस्तीनी और लगभग 2000 इजराइली मारे जा चुके हैं। गाजा पट्टी और राफा में जिस तरह से इजराइल ने हमले किए हैं उससे बहुत बड़ा मानवीय संकट पैदा हो चुका है। इस भयानक युद्ध को रोकने के लिए बातें तो बहुत होती रही हैं लेकिन युद्ध रुक नहीं रहा है। युद्ध में अब तक कुल 190 सहायता कर्मी मारे गए हैं। भारत के लिए यह दुख भरी खबर रही कि इजराइली हमले में भारत के रिटायर्ड कर्नल वैभव काले की मौत हो गई। इस युद्ध में यह पहली बार है जब संयुक्त राष्ट्र के किसी अन्तर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता की मौत हुई है।

46 साल के कर्नल वैभव अनिल काले दो महीने पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा विभाग में सुरक्षा समन्वय अधिकारी के रूप में शामिल हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वैभव काले 13 मई की सुबह अपने सहयोगी के साथ संयुक्त राष्ट्र के वाहन में राफा स्थित यूरोपियन हॉस्पिटल जा रहे थे। जब हमला हुआ वैभव संयुक्त राष्ट्र के स्टिकर वाली कार में बैठे थे। उनकी कार पर संयुक्त राष्ट्र का झंडा भी लगा हुआ था। इसके बावजूद उनकी कार पर हमला किया गया। 11 जम्मू-कश्मीर राइफल्स में तैनात रहे काले ने 2022 में समय से पहले सेवानिवृत्ति ले ली थी। सेना में अपने 22 साल लंबे करियर के दौरान वो संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भी रहे। उनकी तैनाती कॉंगो में थी। काले जम्मू-कश्मीर में आतंक रोधी कार्रवाई में भी तैनात रहे थे। प्री-मैच्योर रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कुछ वक्त एमेज़ॉन के लिए भी काम किया था। वो अपने पीछे पत्नी और दो बच्चे छोड़ गए हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने कर्नल वैभव काले की मौत पर भारत से माफी मांगी है। गाजा के राफा में लाखों की संख्या में फिलिस्तीनियों ने शरण ली हुई है। शरणार्थी शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जिनकी देखरेख संयुक्त राष्ट्र कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के सैंकड़ों अधिकारी और कर्मचारी मानव सेवा के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कर्नल वैभव काले भी मानवता की सेवा के लिए गाजा गए थे। संयुक्त राष्ट्र एक दंत विहीन संस्था बनकर रह गई है। अक्सर वह ऐसे युद्धों को रोकने में हमेशा नाकाम ही रहा है। जिस तरह से इजराइल ने युद्ध नियमों और मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है उस पर दुनिया का तमाशबीन बने रहना बहुत दुखद है।

दुनिया भर में शांति-शांति का राग अलापने वाले अमेरिका की दोगली चालों से सारी दुनिया वाकिफ है। अमेरिका खुद युद्ध उन्मादी रहा है। कौन नहीं जानता कि अमेरिका ने अफगानिस्तान, ईराक और लीबिया में विध्वंस का खेल खेला था। रूस-यूक्रेन युद्ध में भी अमेरिकी रवैये को लेकर न केवल अमेरिकी जनता बल्कि डैमोक्रेटिक पार्टी के नेता भी बाइडन से नाराज हैं। इजराइल यह चाहता है कि युद्ध बढ़े और अमेरिका सीधा उसके साथ आ खड़ा हो। ऐसा करने के लिए नेतन्याहू की अपनी घरेलू राजनीतिक मजबूरियां भी हैं।

अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति चुनाव है और ऐसे मौके पर उससे उम्मीद लगाना कि वह पश्चिम एशिया में निष्पक्ष भूमिका निभाएगा अर्थहीन है। समस्या यह है कि युद्ध अब ऐसे नाजुक मोड़ पर है जहां युद्ध विराम तक पहुंचने के लिए समझदारी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अमेरिका को समझ ही नहीं आ रहा कि वह करे तो क्या करे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को गाजा में हमले रोकने के लिए कई बार सख्ती से कहा लेकिन नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं। अमेरिका ने इजराइल को राफा पर हमले करने पर हथियारों की सप्लाई बंद करने का फैसला किया था। अमेरिका ने दोगली चाल चलते हुए यू टर्न मार लिया है और उसने एक अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक कीमत के हथियार और गोला बारूद इजराइल को भेजने का फैसला कर लिया है। इन हथियारों के पैकेज में टैंक से लेकर गोला बारूद तक शामिल है। इसके लिए लगभग 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर, सामरिक वाहनों के लिए 50 करोड़ डॉलर और मोर्टार राउंड के लिए 6 करोड़ डॉलर रकम निर्धारित है।

दुनिया भर में शांति-शांति का राग अलापने वाले अमेरिका की दोगली चालों से सारी दुनिया वाकिफ है। अमेरिका खुद युद्ध उन्मादी रहा है। कौन नहीं जानता कि अमेरिका ने अफगानिस्तान, ईराक और लीबिया में विध्वंस का खेल खेला था। रूस-यूक्रेन युद्ध में भी अमेरिकी रवैये को लेकर न केवल अमेरिकी जनता बल्कि डैमोक्रेटिक पार्टी के नेता भी बाइडन से नाराज हैं। इजराइल यह चाहता है कि युद्ध बढ़े और अमेरिका सीधा उसके साथ आ खड़ा हो। ऐसा करने के लिए नेतन्याहू की अपनी घरेलू राजनीतिक मजबूरियां भी हैं। ईरान ने जिस तरह से पिछले दिनों इजराइल पर सीधे हमले किए थे और उसके बाद इजराइल ने भी उस पर जवाबी हमले किए थे। इससे स्पष्ट है कि पश्चिम एशिया का तनाव कभी भी पूर्ण युद्ध में बदल सकता है।

पिछले सात अक्तूबर को जब इजराइल पर वीभत्स हमला हुआ तो दुनिया ने इस यहूदी राष्ट्र के साथ एकजुटता दिखाई लेकिन इजराइल ने तब से जिस तरीके से गाजा के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है वह हमास द्वारा इजराइलियों के साथ की गई करतूतों से अलग नहीं है। अपने ताकतवर पश्चिमी सहयोगियों की मदद से नेतन्याहू की सरकार ने गाजा की पूरी आबादी को सामूहिक दंड देना शुरू कर दिया लेकिन फिलिस्तीनियों के खिलाफ बेहिसाब ताकत के इस्तेमाल के बावजूद इजराइल का सैन्य प्रदर्शन उससे कोसों दूर है जिसके लिए उसे दशकों पहले जाना जाता था। इजराइल न तो हमास को हरा पाने में कामयाब हुआ है, न ही बंधकों को रिहा करा पाने में। अगर नेतन्याहू राफा पर आक्रमण की योजना के साथ आगे बढ़ते हैं तो वह भयानक गलती करेंगे। वैश्विक शक्तियों को युद्ध रोकने के लिए हर सम्भव प्रयास करने ही होंगे।

आदित्य नारायण चोपड़ा
Adityachopra@punjabkesari.com

जब भारत में...

गीता पाढा

"जब भारत में फलते-फूलते कालेधन के व्यापार दिखते होंगे,
हम दुनिया के आगे कितने शर्मशार दिखते होंगे,,
बेरोजगार भटके युवा के हाथों में चाकू, तलवार दिखते होंगे,
और जनप्रतिनिधियों के बयानबाजियों में जातिगत प्रचार दिखते होंगे...।।

परिवार वालों का एयर इंडिया पर फूटा गुस्सा, कार्यालय के बाहर शव रखकर प्रदर्शन

तिरुवनंतपुरम, (पंजाब केसरी): एयर इंडिया केबिन क्रू के अचानक हड़ताल पर जाने से केरल की एक महिला अपने पति को आखिरी बार नहीं देख सकी। गुरुवार सुबह तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर महिला के पति राजेश (39) का शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं इस घटना से गुस्साए परिवार वालों ने एयर इंडिया के कार्यालय पर शव रखकर प्रदर्शन किया। अमृता 8 मई को अपने बीमार पति एन. राजेश से मिलने के लिए यहां हवाई अड्डे पर पहुंची थीं। उनके पति दिल का दौरा पड़ने के बाद मस्कट के एक अस्पताल में भर्ती थे। एयर इंडिया एक्सप्रेस के केबिन क्रू की हड़ताल शुरू होने के बाद वह अपने पति से आखिरी बार नहीं मिल पाईं।

चुनावों में राहुल गांधी को कितना फायदा?

राकेश कपूर
संसद से सड़क तक
kapurakesh@gmail.com

लोकतंत्र में वही राजनीतिज्ञ नेता बन पाता है जो जनता से शक्ति लेकर उसकी आवाज को अपनी आवाज देता है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने यह कला बहुत देर से सीखी। वास्तव में यह कला उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुए अनुभवों से सीखी। राहुल गांधी की पांच महीने से अधिक चली 4000 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पैदल यात्रा उनके जीवन में एक मील का पत्थर साबित हुई। श्री राहुल गांधी को यह देखना होगा कि उनका मुकाबला उस नरेंद्र मोदी से है जिसने भारत के लोगों के दिलों में उतरकर अपनी लोकप्रियता बनाई और उनके दैनिक जीवन को भीतर तक प्रभावित किया।

नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अभी तक बरकरार मानी जाती है और राहुल गांधी के लिए यह कोई छोटी चुनौती नहीं है। राहुल गांधी की सबसे बड़ी ताकत इस देश की युवा शक्ति है। जिस प्रकार से उन्होंने सेना में भर्ती की अग्नि वीर योजना को निरस्त करते हुए देश के नौजवानों में यह चेतना भरी है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए उनका अधिकार और उनकी भावनाएं कभी भी टुकड़ों में बांट कर नहीं देखी जा सकती हैं, उन्हें युवा वर्ग में वर्तमान राजनीतिक माहौल में लोकप्रियता प्रदान कर रही है। परंतु इतना निश्चित है कि राहुल गांधी ने जो मुद्दे चुनावी विमर्श में खड़े किए हैं वह ठीक वैसे ही हैं जैसे कभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया खड़े किया करते थे। भारतीय चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी को एक केंद्रीय मुद्दा बना देना कोई छोटी बात नहीं कहीं जा सकती क्योंकि 5 साल बाद होने वाले हर चुनाव में महंगाई व बेरोजगारी एक मुद्दा तो रहे मगर कभी केंद्र में नहीं आ पाए थे। राहुल गांधी ने इन मुद्दों को केंद्र में लाकर पूरे राजनीतिक विमर्श को आर्थिक नीतियों के खांचे में खड़ा कर दिया है।

यदि हम गौर से देखें और भारत के चुनावी इतिहास का विश्लेषण करें तो 1952 से लेकर 2024 तक अभी तक केवल 1971 के लोकसभा चुनाव ऐसे हुए जिनके केंद्र में आर्थिक मुद्दे रहे। 1971 के चुनाव में स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने जब गरीबी हटाओ का नारा दिया था तो निश्चित रूप से उनका मंतव्य भारत की आर्थिक नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन का था। निश्चित रूप से वह समाजवादी नीतियों का दौर था और इंदिरा जी का समाजवाद तब लोगों के सिर चढ़कर बोला। वर्तमान राजनीतिक दौर में राहुल गांधी ठीक अपनी दादी की भूमिका में आए लगते हैं जो लोगों का ध्यान आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित करना चाहते हैं। राहुल गांधी का राजनीतिक ग्राफ बढ़ने का मुख्य कारण यही लगता है कि उन्होंने न केवल देश के युवा वर्ग का ध्यान बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर केंद्रित किया है बल्कि आम जनता का ध्यान भी उन आर्थिक मुद्दों की तरफ खींचा है जो आजादी के बाद से इस देश का राजनीतिक धर्म माना जाता है। यह राजनीतिक धर्म भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था रही है। यह अर्थव्यवस्था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का आर्थिक मॉडल था। इसी मॉडल के चलते भारत ने अपना बहुमुखी विकास इस प्रकार किया कि एक तरफ देश में सार्वजनिक संपत्ति का सृजन हुआ और निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ा तथा दूसरी तरफ राष्ट्रीय संपत्ति का समेकित बंटवारा हुआ। गरीबों को आर्थिक मदद देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने की इस नीति के तहत 1991 के आते-आते भारत में मध्यम वर्ग का इतना बड़ा बाजार सृजित हुआ की पूरी दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियों की लालची आंखें भारत की तरफ उठने लगी और उन्हें यह आकर्षक बाजार के रूप में दिखाई देने लगा। इस वर्ष से शुरू हुआ आर्थिक उदारीकरण का दौर भारत को एक बाजार के रूप में देखने का दौर ही कहा जाएगा। तब से लेकर अब तक भारत बाजार मूलक व्यवस्था के दौर में आ चुका है जिसमें सर्वाधिक अपेक्षा कृषि क्षेत्र की हुई है। इसी वजह से हम इस क्षेत्र में बेचैनी का आलम देखते हैं। राहुल गांधी ने इस बेचैनी को पड़कर भारत के किसानों की चिंता करने की कोशिश की है और कृषि उत्पादन पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का कानून बनाने का वादा भी वह कर रहे हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी देश के युवा वर्ग को रोजगार देने के लिए जिस प्रशिक्षु योजना को लागू करना चाहते हैं उसे भी कानूनी जामा पहनाने की बात कर रहे हैं। यहां वह डॉक्टर लोहिया के बहुत करीब नज़र आते हैं।

हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत में बाजार मूलक अर्थव्यवस्था के जनक कहे जाते हैं परंतु उन्हीं के प्रधानमंत्रित्व काल के दौरान कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रहते हुए राहुल गांधी की मां श्रीमती सोनिया गांधी ने उन्हीं की सरकार से भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार जैसे कानून बनवाने में सफलता प्राप्त की। लोकतंत्र की यह भी विशेषता होती है कि इसमें लोगों के अधिकार मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है परंतु जो भी अधिकार मिलते हैं वह स्थाई होते हैं। यह विचारधारा डॉक्टर लोहिया की ही नहीं बल्कि मूल रूप से महात्मा गांधी की है। राहुल गांधी को इस बात से मतलब नहीं है कि उनके बारे में राजनीतिक वर्ग क्या राय बनाता है बल्कि इस बात से मतलब ज्यादा है कि भारत में रहने वाले जो लोग स्वयं को पीड़ित और वंचित समझते हैं उनके बीच उनकी हैसियत क्या बनती है। भारतीय संविधान को एक चुनावी मुद्दा बना देना यह राहुल गांधी की सफलता मानी जा सकती है। हालांकि भारत में संविधान बचाओ आंदोलन पिछले लगभग 6 वर्षों से चल रहा था। जनता दल (यू) के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय श्री शरद यादव तो इस संविधान बचाओ आंदोलन की कमान थामें ही चल बसे। संविधान बचाओ की बात करके राहुल गांधी ने यह तो आम जनता तक संदेश पहुंचा ही दिया है कि देश की वर्तमान सरकार का रवैया संविधान के प्रति उस सार्थकता का नहीं है जिसकी अपेक्षा लोकतंत्र में की जाती है। उनके राजनीतिक ग्राफ बढ़ने का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि वह लोकतंत्र में मिले लोगों के अधिकारों को इससे जोड़ रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि यदि संविधान का ढांचा बदल दिया जाता है तो भारत की सामाजिक व्यवस्था तहस-नहस हो जाएगी। विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ों आदि को मिला आरक्षण का अधिकार बट्टे खाते में जा सकता है। इस संदर्भ में राहुल गांधी का यह कहना कि वह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुच्य आरक्षण पर लगाई गई 50% सीमा को हटा देंगे और इसे आगे बढ़ा देंगे अगर जातिगत जनगणना में इन वर्गों की जनसंख्या अधिक निकलती है। इस मुद्दे पर उनकी तुलना चौधरी चरण सिंह से की जा सकती है। चौधरी चरण सिंह हालांकि जाति के स्थान पर व्यवसाय की बात करते थे और इसमें भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े व्यवसायों की विशेषतौर पर। राहुल गांधी को समझ आ गया है कि लंबी राजनीति भविष्य की दृष्टि के साथ ही की जा सकती है। इसमें उन पर पंडित नेहरू की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। परंतु श्री राहुल गांधी का मुकाबला इन चुनावों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से होगा।

आम लोगों के मनोविज्ञान को समझने में मोदी माहिर माने जाते हैं और उनके लोकप्रिय होने की असली वजह यही मानी जाती है। आम लोगों के साथ संवाद स्थापित करना मोदी की विशेषता कही जाती है क्या यही विशेषता राहुल गांधी ने हासिल कर ली है जो उनकी जनसभा में लोग अब प्रतिक्रियाएं देते नजर आने लगे हैं। राहुल गांधी को यह कला सीखने में निश्चित रूप से बहुत लंबा समय लगा है। उनकी दूसरी मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा जिसे न्याय यात्रा कहा गया उसमें भी यही पक्ष उभर कर के सामने आया कि लोगों के दुख और वेदना को किस प्रकार नेता पहचान कर अपनी आवाज देते हैं।

पर्यावरण, ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति जरूरी

लक्ष्मीकांता चावला
(पूर्व मंत्री पंजाब)

यह सुखद, स्वस्थ समाचार है कि दो दिन पूर्व भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली व आसपास ठोस कचरे का समुचित निस्तारण नहीं होने पर केवल नाराजगी ही नहीं, अपितु चिंता भी जताई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए. एएस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा कि हम ठोस कचरे के शोधित न होने के कारण बहुत चिंतित हैं, क्योंकि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का यह उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया क्या कहेगी, 2024 में भारत की राजधानी में प्रतिदिन 3800 टन ठोस कचरा अशोधित रह जा रहा है। 2025, 2026 और इसके बाद क्या होगा हर जगह भयानक स्थिति है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा जैसे क्षेत्रों में प्रतिदिन ठोस कचरा निकलने और उसे शोधित करने की क्षमता पर आंकड़ों का जिक्र करते हुए शीर्ष कोर्ट ने कहा कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हो रहे विकास कार्यों पर विचार करें तो यह स्वभाविक है कि इस कचरे में वृद्धि होगी, पर शहरी विकास सचिव को अधिकारियों के साथ बैठक कर समस्या का समाधान खोजने को कहा और यह भी चेतावनी दी कि अगर अधिकारी कोई ठोस प्रस्ताव खोजने में असमर्थ रहे तो अदालत कठोर आदेश जारी करने पर विचार करेगी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय से हम देशवासियों की एक अपील है— बड़े—बड़े अधिवक्ताओं की मदद लेकर हम लोग अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते, पर जब अदालत ने स्वयं ही यह अनुभव कर लिया कि प्रदूषण मुक्त वातावरण हर नागरिक का मौलिक अधिकार है तो देश के नब्बे प्रतिशत से ज्यादा नागरिक इस अधिकार से वंचित क्यों? क्या कभी किसी ने आकर देखा कि दिल्ली से दूर भी पूरे देश में कचरे का प्रकोप है। यह कचरा सब जगह ठोस तो नहीं है, पर कूड़े के बड़े—बड़े ढेर, गंदगी, बदबू, उस पर मक्खियों के झुंड, आसपास सीवरेज का गंदा पानी यह हम लोगों की किस्मत है। जो स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपये अपने देश में खर्च किए जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी की घोषणा एक फैशन बन गया है उसमें अपने देश के आम नागरिक कहीं स्थान नहीं पा रहे। केवल सिविल लाइन क्षेत्र, अमीरों के मोहल्ले, उन्हीं का विकास हो रहा है। वैसे प्रदूषण तो शोर का भी होता है श्रीमान। उस शोर की अभी चर्चा नहीं की जा रही जो दिन रात मोटर गाड़ियां के हार्न से पैदा हो रहा है, हमारे तो गली मोहल्लों में भी रात रात भर कुत्तों की चीख पुकार रहती है। एक नहीं अनेक आवारा कुत्ते हमारी सड़कों पर लोगों का जीवन दूभर कर रहे हैं। लोग कटते हैं, कुछ मरते हैं, कुत्तों की गंदगी गली बाजारों में फैली रहती है, पर सरकार की योजना कि इनका नलबंदी और नसबंदी करवाएंगे तब शायद दस बीस वर्ष बाद संख्या कम होगी और उस समय तक जो लोग दुनिया में रहेंगे उन्हें कुत्तों से राहत मिलेगी, यह आम जनता के साथ क्रूर सरकारी मजाक है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश यह जानते होंगे कि सरकारें इन चौपायों के लिए प्यार तो प्रदर्शित करती हैं, पर जनता को इनके प्रहारों से बचाने का कोई प्रयास नहीं करती। जनता को यह कहा गया है कि नलबंदी नसबंदी के बाद भी कुत्ते लोगों के आसपास ही छोड़े जाएंगे, पर यह नहीं बताया कि क्या ये कुत्ते बाद में भोंकना और काटना बंद कर देंगे। एक बार माननीय अदालत ने यह भी कहा था कि नींद लेना भी मानवीय अधिकार है। पुलिस जब किसी अपराधी को रात रात भर सोने नहीं देती उस घटना का संज्ञान लेते हुए देश की किसी बड़ी अदालत ने यह निर्णय दिया था, पर जो हमारे घरों के आसपास, गली बाजारों में रात-रात भर कुत्ते चीखते हैं वह भी तो हमें सोने नहीं देते। हमारा अधिकार कहां गया?

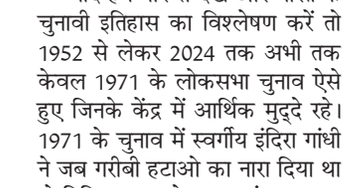

इसके साथ ही भीड़ भरे मोहल्लों में श्मशानघाट बने हैं। जो बड़े बड़े राजनेता स्वयं शहरों से दूर विशाल भवनों में, वृक्षों के झुरमुट में रहते हैं वे राजनीतिक दबाव से इन श्मशानघाटों को शहरों से दूर नहीं जाने देते, पर स्वयं जहां रहते हैं वहां श्मशानघाट का धुआं पहुंचने की भी संभावना नहीं। अपने शहरों की घनी आबादियों में बने श्मशानघाटों को शहर से दूर ले जाने के लिए लंबा संघर्ष करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती, क्योंकि राजनेता अधिक हावी प्रभावी हो जाते हैं। जिस युग में मानव चंद्रमा पर जाने की तैयारी में है, हर हाथ में मोबाइल और खान पान विदेशी ढंग का हो गया है वहां पर ये सरकारें आज तक अंतिम संस्कार के लिए आधुनिक ढंग के विद्युत शवदाह गृह आधुनिक पद्धति से अंतिम संस्कार जैसे साधन जनता को नहीं दे सकी। दिन रात विदेश यात्राएं करने वाले ये नेता यूरोप अमेरिका आदि देशों से यह नहीं देखकर आए कि वहां कैसे जनता अंतिम संस्कार के प्रदूषण से भी बची हुई है। सही बात यह है कि हमें पूरी पूरी रात लाउडस्पीकरों का शोर भी सहना पड़ता है। जिस कार्यक्रम में नेताजी आएंगे वहां क्षेत्र के पुलिस अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी की सारी शक्तियां जवाब दे जाती हैं और वे लाउडस्पीकरों का शोर नियंत्रित नहीं कर पाते। शोर का प्रदूषण, नींद न मिलना, गंदगी और कूड़े और इसके साथ ही शहर की सड़कों पर चूहों का दौड़ना घरों में अन्न दूषित करना यह हमारे स्मार्ट शहरों का हाल है। अंतर इतना है कि घायल की गति घायल जाने और हमारे शासक, प्रशासक, यहां तक कि बड़े बड़े कानूनविद् भी आम घायल जनों की पीड़ा नहीं जानते। इसलिए मेरी एक विनम्र अपील जनहित में देश के नब्बे प्रतिशत से भी ज्यादा जनता के हित में देश की न्यायपालिका से है कि हमें भी प्रदूषण मुक्त वातावरण दिलवाइए। हमें नींद का अधिकार मिलना ही चाहिए।

प्रवासी भारतीयों का कमाल : देश मालामाल

आकाश चोपड़ा

यह वास्तविकता है कि भारतीयों में विदेशों में जाकर अच्छा रोजगार पाने और धन कमाने की लालसा बहुत ज्यादा है। अच्छी शिक्षा के लिए विदेशों में जाकर पढ़ने वाले छात्र भी वहीं रहना पसंद कर रहे हैं। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं जहां भारतीयों की मौजूदगी न हो। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत के लोग विदेशों में रह रहे हैं। भारतीयों में एक विशेष गुण है कि वह विदेशों में रहकर भी अपने देश की जड़ों से जुड़े हुए हैं। अगर कोई वहां श्रमिक है तो उसकी इच्छा अपने परिवार को धन भेजकर गांव में पक्का घर बनाने की है। अगर भारतीय उच्च पदों पर हैं तो उन्हें इस बात की चिंता रहती है कि भारत में प्रगति किस तरह से हो। अनेक प्रवासी भारतीयों ने अपने-अपने गांव में स्कूल, कालेज, कम्प्यूटर सैंटर खोलने के लिए न केवल अपनी पुश्तैनी जमीन दान में दी है बल्कि दिल खोलकर धन भी दिया है।

पिछले हफ्ते दो खबरों से स्पष्ट हो गया कि भारतीयों ने विदेशों में रहकर न केवल अपना भविष्य संवारा है बल्कि देश को भी मालामाल किया है। भारत को इस बात पर गर्व है कि प्रवासी भारतीय भले ही वह किसी भी देश में हों वहां के संविधान और संस्कृति को आत्मसात करके वहां की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान ही नहीं दे रहे हैं बल्कि अपने देश में भी वह कमाई भेज रहे हैं।

प्रवासियों द्वारा अपनी कमाई देश वापस भेजने के मामले में भारत फिर पहले स्थान पर आ गया है। संयुक्त राष्ट्र के अन्तर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में विदेशों में कार्यरत भारतीयों ने 111 अरब डॉलर से अधिक रकम देश को भेजी थी। विप्रेषित धन का सौ अरब का आंकड़ा छूने और पार करने वाला भारत पहला देश बन गया है। यह उपलब्धि प्रवासी भारतीयों की दक्षता और उनकी बढ़ती कमाई को इंगित करती है। इससे पहले 2010, 2015 और 2020 में भी भारत में सबसे अधिक कमाई आयी थी।

भारत के अलावा मेक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस इस मामले में शीर्ष के देशों में हैं। देश में आने वाली कमाई विदेशी मुद्रा भंडार में उल्लेखनीय योगदान करती है तथा प्रवासियों के परिवार के जीवन-स्तर को बेहतर करने में बड़ी भूमिका निभाती है। साल 2020 में देश में 83.15 अरब डॉलर की राशि आई थी जो 2022 में 111.22 अरब डॉलर हो गयी। इसका अर्थ है कि भारत से अधिक संख्या में लोग काम करने भी जा रहे हैं और उनकी आमदनी भी बढ़ रही है। रिपोर्ट का आंकलन है कि भारत के 1.80 करोड़ लोग दूसरे देशों में काम करते हैं जो हमारी कुल आबादी का 1.3 प्रतिशत है।

दुनिया में भारतीय श्रम एवं कौशल की बड़ी मांग है। क्योंकि भारतीय मजबूर मेहनती, ईमानदार एवं कार्यनिष्ठ होते हैं। विकसित देशों में श्रमिकों की भारी कमी के बीच खेती, निर्माण और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में काम करने के वास्ते भारतीय कामगारों को विदेश भेजने के लिए विकसित देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते करने का भारत सरकार का इरादा है। भारत सरकार उन देशों के साथ एग्रीमेंट करने जा रही है जहां आबादी तेजी से घट रही है। वैसे हम पहले ही जापान और फ्रांस के साथ लेबर सप्लाई एग्रीमेंट कर चुके हैं। इजराइल के साथ भी एक करार है जिसके तहत हजारों भारतीय वहां खेती और मजदूरी के लिए भेजे जा रहे हैं।

दुनिया की चोटी की आईटी सैक्टर की कम्पनियों में आज उच्च पदों पर भारतीय ही बैठे हैं। इतना ही नहीं मॉरिशस, अमेरिका, पुतर्गाल, ब्रिटेन और कनाडा की राजनीति में भी प्रवासी भारतीय काफी प्रभावशाली हैं। दूसरी खबर यह है कि दुबई में सम्पत्ति खरीदने वाले भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है।

दुनियाभर के अमीरों में दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने का क्रेज लगातार बढ़ रहा है। भारत के 29 हजार 700 लोगों के पास दुबई में 35 हजार प्रॉपर्टीज हैं। इनकी कीमत 1.42 लाख करोड़ रुपए है। सेंटर फॉर एडवांस डिफेंस स्टडीज को मिले डेटा के आधार पर 58 देशों के 74 मीडिया हाउस ने यह रिपोर्ट तैयार की है।

रिपोर्ट को 'दुबई अनलॉक्ड' नाम दिया गया है। इसमें 2020-22 तक दुबई में विदेशियों की संपत्ति की डीटेल साझा की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस लिस्ट में सबसे ऊपर भारतीयों का नाम है। संपत्ति के मामले में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान है। यहां के 17 हजार लोग करीब 23 हजार प्रॉपर्टीज के मालिक हैं। इनकी कुल कीमत 91.8 हजार करोड़ है।

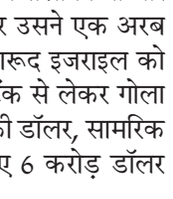

रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के पास दुबई में 2 हजार करोड़ की संपत्ति है। वहीं लुलु ग्रुप के चेयमैन एमए यूसुफ अली और उनके परिवार के पास 585 करोड़ की प्रॉपर्टी है। इस लिस्ट में अरबपति गौतम अडाणी के भाई का भी नाम है। इसके अलावा बॉलीवुड स्टार्स जैसे शाहरुख खान, अनिल कपूर और शिल्पा शेट्टी भी दुबई में करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के आंकड़ों के हिसाब से दुबई में विदेशियों के पास कुल 160 अरब डॉलर की संपत्ति है। भारत के पास विदेशी मुद्रा तो आ रही है लेकिन हम देश की प्रतिभाओं का अपने देश के लिए इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। बेहतर होता अगर देश की प्रतिभाओं को देश में ही अपनी शिक्षा के मुताबिक रोजगार मिलता। यद्यपि भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है लेकिन हमें बहुत लम्बा रास्ता तय करना है।

एयर इंडिया नहीं रही सरकार की इकाईः उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक फैसले में कहा कि जनवरी, 2022 में टाटा समूह के हाथों अधिग्रहीत होने के बाद एयर इंडिया संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत सरकार या इसकी इकाई नहीं रही है और इसके खिलाफ मौलिक अधिकार के कथित उल्लंघन का कोई मामला नहीं बनता है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने बंबई उच्च न्यायालय के 20 सितंबर, 2022 के फैसले के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय में एयर इंडिया के कुछ कर्मचारियों की तरफ से वेतन बढ़ोतरी और पदोन्नति जैसे मसलों को उठाया गया था। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि उच्च न्यायालय ने एयर इंडिया के निजीकरण को आधार बनाते हुए इन रिट याचिकाओं को सुनवाई के लायक न मानते हुए उनका निपटारा कर दिया था।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। शुक्रवार, 17 मई 2024

दोस्ती अनलिमिटेड

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पूतिन एक बार फिर चीन के दौरे पर हैं। चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ उनकी मुलाकात ने दुनिया की बेचैनी बढ़ा दी है कि यूक्रेन में अब क्या होने जा रहा है। युद्ध के मोर्चे पर क्रेमलिन को अगर किसी एक देश से बिना शर्त समर्थन मिल रहा है, तो वह चीन ही है। ऐसे में बाकी मुल्कों की चिंता समझ में आती है।

बदली भूमिका | पूतिन अपनी यात्रा के दौरान चीन के उत्तर-पूर्व में मौजूद शहर Harbin भी जाएंगे। कभी इस शहर को लेकर कहा जाता था कि यह चीन से ज्यादा रूसी है। रूस की संस्कृति की कुछ छाप यहां अब भी बची है। दोनों देशों के रिश्तों में भी ऐसा ही बदलाव आया है। कभी इस रिलेशन में रूस बड़ा भाई था, लेकिन अब रोल बदल चुके हैं।

पूतिन के चीन दौरे पर निगाहें

युद्ध में मददगार | यूक्रेन युद्ध शुरू होने के पहले साल 2021 में चीन और रूस के बीच का कुल व्यापार करीब 150 बिलियन डॉलर था, जो 2023 में 240 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया। आरोप है कि व्यापार की आड़ में चीन दरअसल रूस की युद्ध में मदद कर रहा है, चीनी कंपनियां रूस की डिफेंस इंडस्ट्री को जरूरी सहायता मुहैया करा रही हैं। अमेरिका और पश्चिमी देश कई दफा इस बारे में चिंता भी जाहिर कर चुके हैं। उनका मानना है कि चीनी समर्थन के बिना पूतिन शायद ही इतनी लंबी लड़ाई जारी रख पाते।

अमेरिका से दुश्मनी | रूस और चीन की दोस्ती को पूतिन सीमाओं के परे बताते हैं। उन्हें शी पर कितना भरोसा है यह इससे जाहिर होता है कि युद्ध अपराधी घोषित होने के बाद उन्होंने भारत तक का दौरा टाल दिया, लेकिन चीन जाने से गुरेज नहीं। इस भरोसे की बुनियाद साझा है, अमेरिका के प्रति अविश्वास। दोनों ही देशों को लगता है कि पश्चिमी जगत उनकी प्रगति के आड़े आ रहा है। दोनों को ही कई तरह की बंदिशों का सामना करना पड़ रहा है।

भारत की सीमा | पश्चिमी प्रतिबंधों ने रूस को बहुत हद तक चीन पर निर्भर कर दिया है। भारत से जारी व्यापार ने भी उसकी मदद की है, लेकिन नई दिल्ली उस तरह से खुलकर युद्ध में रूस का साथ नहीं दे सकती, जैसा चीन दे रहा है। माना जा रहा है कि पूतिन का यह दौरा भी रक्षा सहयोग को लेकर है। उनके साथ नए और पुराने, दोनों रक्षा मंत्री गए हैं। चीन यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए मध्यस्थता की कोशिश भी कर चुका है। हालांकि इस पर बहस हो सकती है कि वह मध्यस्थता थी या रूस की पैरवी।

नई दिल्ली क्या करे | रूस भारत का पुराना दोस्त है, जबकि चीन के साथ उसके रिश्ते नरम-गरम वाले रहे हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत का रुख स्पष्ट है कि वह युद्ध के खिलाफ है, लेकिन किसी गुट का हिस्सा नहीं बनेगा। यह सही रास्ता भी है क्योंकि भारत खुद को ग्लोबल साउथ की आवाज के रूप में पेश करता रहा है और उसके इस रुख की सराहना भी हुई है।

क्रॉस-वर्ल्ड

नागरिकों का हक

शैलेंद्र पांडेय

भारत में चुनाव चल रहे हैं और अमेरिका में तैयारी। बांग्लादेश में खूब शोर मचा, जबकि रूस में सब शांति से हो गया। उधर, पाकिस्तान को पता भी नहीं चला कि आखिर चुनाव में हुआ क्या है। यूक्रेन, ब्राजील, इंडोनेशिया... अफ्रीका से लेकर यूरोप और एशिया तक - यह साल दुनिया की लगभग आधी आबादी के लिए चुनावी है। करीब 64 देशों की जनता अपने यहां जनप्रतिनिधि चुनने वाली है। इनमें से कुछ देशों में इलेक्शन बस नाम का होगा। वहीं, कुछ देशों में लोकतंत्र की असली ताकत देखने को मिलेगी। चुनावों का यह अलग-अलग चेहरा दरअसल उस मुल्क का भी चेहरा है, पहचान है वहां की। वहां के राष्ट्रवाद का एक रूप, Civic Nationalism। जब जाति, धर्म या संस्कृति के बजाय साझा राजनीतिक मूल्यों और नागरिक अधिकारों को राष्ट्रीय पहचान का आधार बनाया जाए तो उसे नागरिक राष्ट्रवाद कहते हैं। इसमें देश की पहचान राजनीतिक सिद्धांतों, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून जैसे मूल्यों पर आधारित होती है।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका सबसे पुराना। इन दोनों ही देशों के चुनाव अपने आप में मिसाल हैं। भारत में पहला लोकसभा चुनाव साल 1951-52 में हुआ। पहली ही बार में कई रेकॉर्ड बना दिए थे इसने। मुल्क को आजाद हुए तब चार साल हुए थे और दुनिया में किसी को उम्मीद नहीं थी कि 17 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार की अहमियत समझते हुए उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन, भारतीयों ने सभी को गलत साबित कर दिया। तब से आज तक, हिंदुस्तान का हर चुनाव पहले से ज्यादा विशाल और भव्य होता गया है। हर मतदान के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। इसी तरह, अमेरिका में इलेक्शन कैंपेन चलता है दो नेताओं के बीच, लेकिन उसकी धमक पूरी दुनिया महसूस करती है। US ने काफी निवेश किया है मानवाधिकारों, नागरिक आजादी और नैतिक मूल्यों में। भारत और अमेरिका, दोनों को अपनी चुनावी प्रक्रिया और नागरिक व्यवस्था पर नाज है। हालांकि, सीरिया, माली, उत्तर कोरिया, ईरान, सूडान, अजरबैजान जैसे मुल्क भी हैं, जहां जनता को पसंद जाहिर करने की पूरी स्वतंत्रता नहीं मिलती। कुछ देश कोशिश करते हैं अपने को उदार दिखाने की, जबकि कई दिखावे तक की जहमत नहीं उठाते। फिर भी, चुनाव civic nationalism का चमकदार चेहरा है। जिस तरह खेल, व्यापार और तकरार ने दुनिया को जोड़ रखा है, वैसा ही कुछ काम किया है चुनावों ने भी।

एकदा

संगीत जिनकी आत्मा

भारतीय शास्त्रीय संगीत के महान गायक कुमार गंधर्व की बाल्यकाल से ही संगीत में बेहद रुचि थी। उनके घर में संगीत का माहौल था, लिहाजा प्रारंभिक संगीत शिक्षा घर में ही मिली। बाद में गुरु बी.डी. देवधर के सान्निध्य में उन्होंने संगीत की कड़ी साधना की। सब कुछ ठीक चल रहा था कि 1947 में उनके जीवन में एक निराशाजनक मोड़ आ गया। वह केवल 21 वर्ष के थे तभी उन्हें टीबी की बीमारी हो गई। तब टीबी का बढ़िया इलाज नहीं था। डॉक्टरों ने उन्हें गाने से मना कर दिया, क्योंकि इससे उनके फेफड़ों पर बहुत जोर पड़ता। यह उनके लिए अत्यंत कठिन समय था, क्योंकि संगीत उनकी आत्मा था। इलाज के दौरान कुमार गंधर्व को देवास, मध्य प्रदेश में रहने की सलाह दी गई। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। देवास में उन्होंने प्रकृति और आसपास की लोक संस्कृति से गहन प्रेरणा ली। स्वास्थ्य को सुधारने के साथ-सात संगीत की नई धाराओं और शैलियों को भी आत्मसात किया। उन्होंने मालवा के लोक संगीत को अपने शास्त्रीय गायन में शामिल किया। स्वास्थ्य में सुधार के बाद कुमार गंधर्व ने एक बार फिर से मंच पर वापसी की। उनकी आवाज पहले जैसी नहीं थी, पर उनकी गायकी में नई ऊर्जा और नवाचार की झलक थी। उन्होंने शास्त्रीय संगीत में नई रागों और बंदिशों को जोड़ा और लोक संगीत को शास्त्रीय संगीत के साथ मिलाकर एक नया आयाम दिया। कुमार गंधर्व का जीवन हमें सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद जुनून और समर्पण हो, तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं।

Subrata Dhar

संकलन : **दीनदयाल मुरारका**

रील्स अच्छे हैं या नहीं, क्यों छिड़ी बहस

अपनी रील्स को वायरल करने के लिए लोग किसी हद तक जा रहे

Reels

शैलेंद्र पांडेय

फेसबुक और इंस्टाग्राम मिलाकर हर दिन करीब 200 अरब रील्स। केवल इंस्टाग्राम पर ही प्रतिदिन लगभग 1.8 करोड़ घंटे। 50% से ज्यादा की एनुअल ग्रोथ। मोबाइल पर बिताने वाले वक्त में से आधा केवल इसी के नाम। ये डेटा लगातार बदल रहा है, बढ़ रहा है। रील्स की रफ्तार अब किसी भी आंकड़े में कैद होने वाली नहीं रही। जब तक कोई डेटा तैयार होकर आप तक पहुंचता है, तब तक रील्स आगे बढ़ चुकी होती हैं। और उसे यह ताकत मिल रही है हमारी-आपकी वजह से ही। इधर, मोबाइल स्क्रीन पर अंगुलियां फिसलती हैं, उधर रील्स की हैसियत बढ़ती है। स्थिति अब वहां तक पहुंच चुकी है, जहां हम रील्स के गुलाम लगने लगे हैं।

समाज से दूरी | रील्स ने हमारे जीवन पर ऐसा कब्जा जमा लिया है कि अब हमारा अपना कोई प्राइवेट टाइम ही नहीं रहा। दिन में जो भी वक्त बचता है, वह रील्स के नाम हो जाता है। घर में, ऑफिस में, सफर पर - जहां कहीं भी दो-चार मिनट का समय मिला लोग उसे रील्स में खपा देते हैं। बस-ट्रेन में बहुत कम चेहरे मिलते हैं, जो खिड़की से बाहर देख रहे हों, जो सहयात्री को देख मुस्कुराएं, क्योंकि सभी तो रील्स की दुनिया में खोए हैं। ऐसा तिलिस्म है इसका कि परिवार तक में साथ होते हुए लोग साथ नहीं होते। वे होते हैं रील्स के साथ। सामाजिकता खत्म कर दी है इसने। लेकिन, संकट बस इतना नहीं है।

कम नहीं हैं खतरे

- आसपास की दुनिया से कटते जा रहे
- शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का है जोखिम
- लाइक्स को मानने लगे हैं असलियत

दिमाग पर असर | रील्स ने हमारे दिमाग के साथ खेलना शुरू कर दिया है। कुछ रिसर्च का कहना है कि रील्स की आदत दिमागी सेहत पर असर छोड़ती जाती है। हर स्वाइप के साथ मस्तिष्क हैपी हार्मोन डोपामाइन रिलीज करता है। यह हार्मोन दूसरी एक्टिविटी से भी रिलीज होता है, लेकिन रील्स के मामले में अंतर यह है कि इसकी कोई लिमिट नहीं। यहां खुश रहने की चाहत अनलिमिटेड है। रील्स से कभी मन ही नहीं भरता। आंखों को और देखना है। स्क्रीन पर खुशी पाने के लिए भागदौड़ बढ़ती जाती है। ऐसी स्थिति आ सकती है, जहां फिर खुशी के लिए रील्स जरूरी हो जाएं। इससे तनाव, चिंता और डिप्रेशन जैसी शिकायतें हो सकती हैं।

कम होता concentration | एक रील होती है अधिकतम 90 सेकंड की। तमाम तो इससे भी कम। लेकिन, अब इतना भी नहीं देखा जाता। चंद सेकंड बाद ही मन करता है स्वाइप करने का। रील्स ने बेसब्र बना दिया है हमें। एक जगह देर तक दिमाग टिकता ही नहीं। Concentration कम होता जा रहा है।

यादों पर हमला | कभी गौर किया आपने कि एक बार में जो दर्जनों रील्स आप देख मारते हैं, उसमें से कितनों का कंटेंट याद रहता है? कितनों का छोड़ दीजिए, 8-10 रील के बाद से ही पिछले सारे देखे हुए की याद धूमिल पड़ने लगती है, जैसे किसी ने ब्लैकबोर्ड पर डस्टर चला दिया हो। 'गजनी' फिल्म के नायक की तरह रील्स हमें शॉर्ट टर्म मेमरी लैप्स का शिकार बना रही है।

कंटेंट का जाल | रील्स और शॉर्ट विडियो को आपको उलझाने के लिए डिजाइन किया गया है। कॉमिडी, डांस, स्पोर्ट्स, ब्यूटी टिप्स, इतिहास का कोई किस्सा, राजनीति की बात - एक के बाद एक नए टॉपिक पर स्लाइड आती जाती है। ऐसा लगता है जैसे एक अंतहीन सिलसिला हो और जिसे हमने शुरू किया है। हर रील इस तरह से बनी, जो आगे और देखने के लिए मजबूर कर दे, उकसाए और बाहर न निकलने दे। कुल मिलाकर swiping का यह खेल जाल है एक, जिसमें हम जानते-बूझते फंसते जा रहे हैं।

वजह तलाशिए | कहते हैं कि हर चीज के होने की एक वजह होती है। लेकिन, रील्स की क्या है? अगर कहेंगे कि मनोरंजन तो जवाब सही नहीं होगा, क्योंकि जो लत बन जाए, उसे मनोरंजन नहीं कह सकते। हकीकत में रील्स के होने की कोई वजह नहीं है सिवाय सोशल मीडिया कंपनियों के मुनाफे के। यह आप खुद पर भी आजमा सकते हैं। रील्स पर एक घंटा बिताइए और फिर सोचिए कि आपने इस दौरान क्या पाया, क्या सीखा, उसमें से क्या याद रहा? आप पाएंगे कि यह एक घंटा सोशल मीडिया पर बस भटकना रहा और कुछ नहीं। इसका जमा हासिल शून्य। हां, आपके खाते से कीमती एक घंटा जरूर कम हो गया।

वास्तविकता से दूर | रील्स एक पूरी पीढ़ी को सचाई से दूर कर रही है। इसने अपनी एक दुनिया बना दी है, जहां लोग लाइक्स और शेयर को ही असलियत मानने लगे हैं। उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है वायरल होना और इसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्हें ट्रैफिक जाम कर नाचने, लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या खुद का भी जीवन खतरे में डालने से जरा भी संकोच नहीं। यहां तक कि भाषा की मर्यादा लांघने में कोई गुरेज नहीं। और यह तो अभी शुरुआत है। रील्स को पैदा हुए चार बरस भी नहीं हुए और इसने हजारों साल की इंसानी सभ्यता को बदलना शुरू कर दिया है। इससे पहले कि यह बदलाव उस पॉइंट तक पहुंच जाए, जहां से वापसी मुमकिन न हो, नींद से जागना होगा।

आमने-सामने

महज़ टाइमपास नहीं, एक प्रफेशन भी है रील्स बनाना, अवसरों की कमी नहीं

Profession

गौरव खरे

सोशल मीडिया पर आज करोड़ों लोग रील्स बना रहे हैं। इनमें से किसी की रील को कभी कुछेक लाइक्स मिलते हैं तो किसी का बनाया कंटेंट रातो रात वायरल हो जाता है। ऐसे में अगर आप प्रफेशनली इस फील्ड में आगे बढ़ने की सोचते हैं तो जाहिर है, इसके लिए जी तोड़ मेहनत करने में भी किसी से पीछे नहीं रहेंगे।

माइंड होता है क्रिएटिव | यहीं से रील्स बनाने वाले का टैलंट निखरना शुरू होता है। वह अपने कंटेंट में ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना प्रारंभ कर देता है।

टीम वर्क सीखते हैं | रील्स बनाने वाले शुरू में खुद ही अपना कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन जैसे-जैसे उनकी रीच (Reach) बढ़ती है, वैसे-वैसे उनकी टीम भी बढ़ने लगती है। आज बहुत से बड़े क्रिएटर के पास एक बड़ी टीम मौजूद होती है। ऐसे में कैमरामैन से लेकर स्क्रिप्ट राइटर तक के साथ काम करना और उनके साथ तालमेल भी बनाना होता है।

डिजिटल मीडिया | रील्स बनाना एक काम जरूर है लेकिन इसके लिए आपको तकनीक के भरोसे रहना होता है। कैमरा, लाइट, माइक, म्यूजिक आदि कई चीजों से आपका वास्ता पड़ता है। इनका सही इस्तेमाल करना आप सीखते हैं। इन सब चीजों का प्रयोग करके ही एक अच्छी रील बन पाती है। जब आप ये कर रहे होते हैं, तो इसके साथ ही आपका तकनीकी ज्ञान भी बढ़ रहा होता है। मसलन, कौन सा माइक अच्छा होता है, किस माइक की कहां जरूरत है, कैसा कैमरा चाहिए, कंटेंट के हिसाब से लाइट कैसी होनी चाहिए वगैरह वगैरह।

विडियो एडिटिंग | आज विडियो एडिटिंग करना खुद एक बड़ा प्रफेशन बन चुका है। वहीं जब आप रील को अपलोड करते हैं तो उसके लिए सही विवरण, टैग, हैशटैग, की-वर्ड्स आदि भी देने होते हैं। एक रील को वायरल करने के लिए पूरी रिसर्च करनी होती है। इस सबसे डिजिटल मीडिया के बारे में जानकारी बढ़ती है। आज का दौर डिजिटल मीडिया का है तो जिसको इस बारे में ज्यादा जानकारी होती है, उसका करियर भी उतना ही ब्राइट होता है।

रिश्तों में आती है मजबूती | हम ऐसी कई रील्स देखते हैं, जिसमें एक ही परिवार के कई लोग शामिल होते हैं। बहुत से लोग बच्चों, पत्नी और पैरंट्स के साथ मिलकर कंटेंट बना रहे हैं। परिवार के सदस्यों या फिर किसी दोस्त के साथ मिलकर रील्स बनाते हैं, तो एक-दूसरे के आइडिया पर भी काम करते हैं, एक-दूसरे के साथ नए-नए ट्रेंड शेयर करते हैं। इससे परिवार या दोस्तों के साथ बॉन्डिंग अच्छी होती है और रिश्तों में मजबूती आती है।

दुनिया को जानने का मौका | अगर आप रील्स की दुनिया में अपनी जगह बना लेते हैं, तो कई कंपनियां आपके साथ मिलकर काम करने में रुचि जताने लगती हैं। वह आपकी रील को स्पॉन्सर करती हैं, कई कंपनियां देश-विदेश में होने वाले इवेंट में या अपने प्रॉडक्ट के लिए भी रील्स बनाने वालों को हायर करती हैं। ऐसे में क्रिएटर को देश-विदेश जाने का, वहां के कल्चर को समझने का और बदलते दौर के साथ कंटेंट में कुछ नया करने का मौका मिलता है।

आगे बढ़ने के हैं बहुतेरे मौके

- रील्स पॉप्युलर हों तो फॉलोअर्स बढ़ते हैं
- ज्यादा फॉलोअर्स हों तो पैसे भी बनते हैं
- प्रॉडक्ट प्रमोशन भी कराती हैं कंपनियां

पैसा भी खूब है | इसमें दो राय नहीं कि आज जितने भी लोग रील्स बनाने में रुचि दिखाते हैं, उनका एक बड़ा लक्ष्य ये भी होता है कि वे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आप क्रिएटिव और ट्रेंडी रील बना रहे हैं, तो इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी बनाई रील पहुंचती है। समय के साथ-साथ आपके फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं। जैसे ही आप सारे नियमों को पूरा कर लेते हैं, वैसे ही आप अपने अकाउंट को मॉनेटाइज कराकर अपनी इनकम शुरू कर पाते हैं। जितने ज्यादा व्यूज और फॉलोअर्स मिलते हैं, उतनी ही इनकम भी बढ़ती जाती है।

प्रॉडक्ट का प्रमोशन | इसके साथ ही अगर आप किसी खास कैटिगरी जैसे ट्रैवेल, फैशन, फूड आदि पर रील्स बनाते हैं, तो उससे संबंधित कंपनियां भी आपसे अपने प्रॉडक्ट का प्रमोशन कराती हैं, जिसकी एवज में क्रिएटर को अच्छा-खासा पैसा मिलता है। इसके अलावा भी आज रील्स बनाने वालों के पास पैसे कमाने के कई तरीके हैं, जिनका वह भरपूर प्रयोग कर रहे हैं।

रील्स के आगे दुनिया और भी है | ऐसा नहीं कि सारे क्रिएटर्स सिर्फ रील्स बनाने तक ही सीमित हैं। जब आप रील्स की दुनिया में अपने पैर जमा लेते हैं, तो कई लोग इसी क्षेत्र से जुड़े दूसरे कार्यों में भी अपना हाथ आजमाने लगते हैं। कुछ लोग पैसा लगाकर अपना प्रॉडक्शन हाउस बना लेते हैं, तो कुछ स्टूडियो सेटअप कर लेते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग का भी बिजनेस शुरू कर देते हैं। ये सभी काम वे रील्स बनाने के साथ करते रहते हैं, जिससे वे इंडस्ट्री में बड़ा नाम बन जाते हैं।

सबको चाहिए साउथ की मेहरबानी

मंजरी चतुर्वेदी

आंध्र प्रदेश विभाजन को दस साल हो चुके हैं। इस बीच आंध्र और तेलंगाना की तासीर ही नहीं, जमीनी मुद्दे भी बदले हुए दिख रहे हैं। दोनों राज्यों में क्षेत्रीय दलों की पकड़ मजबूत रही है, लेकिन इधर कांग्रेस और BJP जैसे राष्ट्रीय दल अपनी पकड़ मजबूत करने की पूरी कोशिश में हैं। विभाजन के बाद कांग्रेस के प्रति इतना आक्रोश उपजा कि आंध्र ही नहीं, तेलंगाना भी अपने गठन की जिम्मेदार पार्टी को अपना आशीर्वाद नहीं दे पाया। खैर तेलंगाना में दस साल बाद कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली, पर इन राज्यों में BJP के लिए स्वीकार्यता हासिल करना आसान नहीं है। यहां अधिकांश लोग BJP को आज भी उत्तर भारतीयों की पार्टी के तौर पर देखते हैं। इसके अलावा कहीं न कहीं द्रविड़ बनाम आर्य का पुराना टकराव भी दिखता है। ऐसे में कर्नाटक छोड़ बाकी के राज्यों में BJP को जगह बनाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसके लिए कई जगह वह क्षेत्रीय दलों का सहारा भी ले रही है। तेलंगाना में वह तेजी से जगह बना रही है तो आंध्र में TDP के भरोसे अपने पैर जमाने की कोशिश में जुटी है।

विशुद्ध राजनीति

कसौटी

AI Image

तेलंगाना की टक्कर

तेलंगाना में BJP अपनी सीधी टक्कर कांग्रेस से मान रही है। BJP ने यहां मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा छेड़ा तो ग्रेटर हैदराबाद में राम मंदिर के बहाने माहौल बनाने की तैयारी की। ग्रेटर हैदराबाद में बड़ी तादाद में उत्तर भारत से आए लोग भी रहते हैं। मल्कानगिरी, चेवल्ला, सिकंदराबाद और हैदराबाद में राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा के मौके पर हुए आयोजन इसकी बानगी हैं। वहीं BJP ने बंडी संजय, माधवी लता, डीके अरुणा जैसे उम्मीदवारों के जरिए अपनी हिंदुत्व की राजनीति को नई धार देने की कोशिश की। 2011 की जनगणना के मुताबिक, तेलंगाना की कुल आबादी में मुस्लिम भागीदारी 12.75% है। वहीं हैदराबाद, आदिलाबाद, निजामाबाद और महबूबनगर जैसे इलाकों में यह संख्या 30% से ज्यादा है। हालांकि सदियों से हिंदु-मुस्लिमों की साझी विरासत में BJP के लिए छेद कर पाना आसान नहीं है। जमीन पर आज भी बहुत से लोग आपको कहते मिलेंगे कि हमारे यहां हिंदु-मुस्लिम कोई मुद्दा नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस यहां विकास और गारंटी की बात कर राज्य को नई दिशा में ले जाने का दावा कर रही है। सीएम रेवंत रेड्डी आगामी 15 अगस्त तक किसानों को दी गारंटी पूरा करने का दावा करते दिख रहे हैं।

आंध्र प्रदेश का मैदान

आंध्र में असली लड़ाई TDP-BJP-जनसेना पार्टी नीत गठबंधन और YSR कांग्रेस के बीच ही है, हालांकि कुछ सीटों पर कांग्रेस ने लड़ाई को तिकोना बनाने की कोशिश जरूर की। वैसे, इन दस सालों में जमीन पर कांग्रेस के प्रति नफरत व नाराजगी का भाव काफी कम हुआ है। आंध्र में मुस्लिम आबादी लगभग 7.50% है। ऐसे में BJP के लिए यहां अपना जमीनी आधार बना पाना उतना आसान नहीं होगा। आंध्र में सियासत की लड़ाई विकास के इर्द-गिर्द घूमती दिख रही है। जहां YSR कांग्रेस जनहित कार्यक्रमों के भरोसे सत्ता में लौटने की कोशिश कर रही है, वहीं TDP विकास के मुद्दे पर जीत की जुगत में है। राज्य में ग्रामीण आबादी जहां YSR के प्रति नरम रुख रखती है, वहीं शहरी आबादी TDP के पक्ष में है। ऐसा नहीं है कि BJP ने यहां राम मंदिर और हिंदुत्व का मुद्दा उठाने की कोशिश नहीं की, लेकिन धार्मिक स्थलों, तीर्थ स्थलों व बड़े मंदिरों के केंद्र आंध्र में जमीनी स्तर पर लोगों में मेलजोल इतना है कि वहां BJP के हिंदुत्व के लिए ज्यादा उत्साह नजर नहीं आता। यही वजह रही कि पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर BJP के बड़े-बड़े राष्ट्रीय नेताओं की रैलियों और भाषणों में भी विकास सहित असली मुद्दों की गूंज ज्यादा सुनाई दी।

भावनाओं को समझ लिया तो निर्णय भी सही होगा

संजय तेवतिया

व्यक्ति के जीवन में भावनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। भावना से ही जीवन में सकारात्मकता आती है और कहीं इन भावनाओं की दिशा ठीक न हो तो पूरा जीवन नकारात्मकता से भर उठता है। इसलिए इन पर नियंत्रण होना जरूरी है। दुनिया में जो कुछ भी हम सुनते हैं, देखते हैं या समझते हैं, उनमें इन भावनाओं का बहुत बड़ा रोल होता है। तभी तो तुलसीदास जी भी कह गए हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जब भावना और कल्पना आपस में एकाकार हो जाते हैं तो इनकी ताकत बढ़कर दुगनी हो जाती है।

हम सभी निर्वाण पाना चाहते हैं। लेकिन इसकी एक बेहद जरूरी शर्त होती है। निर्वाण प्राप्ति के लिए भी मन की झोली को भी उसके लायक होना होता है, या फिर बनाना पड़ता है। इसके लिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। कल्पना मन की अंतर्मुखी साहसिकता होती है। यह इतनी शक्तिशाली होती है कि यह हमसे बड़े से बड़ा, अच्छा से अच्छा और गलत से गलत काम करा देती है। यह एक शक्ति है, जो हमारे जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह हमें आत्मा के आध्यात्मिक संचार की दिशा में ले जाती है और आत्म साक्षात्कार कराती है। जो असाधारण और अद्भुत होती है। लेकिन अगर कल्पनाओं में नकारात्मक भावनाएं भरी हैं तो यह हमें गलत दिशा में ले जाती है। गलत कल्पना और नकारात्मक भावनाएं मिलकर हमें ऐसी चीजों से साक्षात्कार कराती है, जो न सिर्फ हमारा नुकसान करती हैं, बल्कि हमारे आसपास मौजूद लोगों का और फिर पूरे समाज का भी नुकसान करने लगती हैं।

भावना एक ऐसी अद्वितीय ताकत है जो हमें इस सांसारिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। भावनाएं अक्सर चिंतन से जन्म लेती हैं। चिंतन की शक्ति को समझने के लिए हमें समर्पित होने की आवश्यकता होती है। यह ऐसी शक्ति है जो हमें हमारे उद्देश्य की दिशा में प्रेरित करती है, जो हमें हमारी अद्वितीय प्रकृति की ओर ले जाती है। हमें एक सांत्वना की अनुभूति प्रदान करती है, जो हमें हमारे आत्मिक स्वरूप के साथ जोड़ती है। भावना का अर्थ होता है मन की गहराई में उत्कृष्ट भावों को अनुभव करना। यह हमें अपने स्वयं के भावों को समझने और संजोने की क्षमता प्रदान करती है। भावना अगर गलत हुई तो हम अपने आप से ही दूर होते चलते जाते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है, जब हम अपने आप से इतने दूर चले जाते हैं कि चाहकर फिर स्वयं को नहीं पा सकते, ईश्वर का प्रेम पाना तो बहुत दूर की बात है।

अक्सर कहा जाता है कि व्यक्ति को भावना में बहकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है, क्योंकि भावनाओं के कई रूप होते हैं। हमें इनको पहचानना आना चाहिए। कोई भी निर्णय तब नहीं लेना चाहिए, जब हम बहुत ज्यादा खुश या दुखी हों। खुशी यदि स्थाई है, यानी आनंद लगातार बना हुआ है, तब तो अलग बात है, क्योंकि तब तो उसे ठोस मानना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। संतुलित दिमाग से हम इनमें फर्क कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कई निर्णय लेने पड़ते हैं। ये निर्णय हमारे जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं। सही निर्णय हमें सफलता की बुलंदियों तक सहजता से पहुंचा सकते हैं।

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

hindi.speakingtree.in

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

■ **उम्मीद से ज्यादा भीड़**

16 मई का लेख 'हिमालय इतनी भीड़ के लिए नहीं है तैयार' पढ़ा। 2013 की केदारनाथ की आपदा को हमें भूलना नहीं चाहिए। चारधाम यात्रा में हर वर्ष हादसों में जान-माल का नुकसान होता है। वहां लोगों की इतनी भीड़ देखकर यही लगता है कि सिस्टम कैसे काम करेगा। 25-25 किलोमीटर लंबी लाइन में यात्री प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या उत्तराखंड प्रशासन इतने बड़े जन सैलाब को संभालने में सक्षम है? इसका उत्तर ना में ही होगा। जब हर साल यात्रियों की बेतहाशा भीड़ उमड़ती है, तो उसका इंतजाम और एक्शन प्लान पहले बना लेना चाहिए। ऐसा होने से हादसे कम होंगे।

बाल गोविंद, नोएडा

■ **भारत की पहुंच**

यह पत्र 15 मई के संपादकीय 'दूरगामी समझौता' से संबंधित है। भारत और ईरान के बीच हुए चाबहार बंदरगाह समझौते के तहत भारत अगले 10 साल तक इस बंदरगाह के रखरखाव का काम संभालेगा। यह समझौता न सिर्फ दोनों देशों के आपसी संबंधों के लिहाज से अहम है, बल्कि समझौते के तहत भारत अन्य देशों के साथ अपनी कनेक्टिविटी को भी विस्तार दे पाएगा। पाकिस्तान को बाईपास करते हुए भारत अब अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच बना पाएगा। यही नहीं इस समझौते से चीन के BRI को भी बैलेंस करने में मदद मिलेगी।

पैंथर तोमर, किशन गंज

■ **आरक्षण का मुद्दा**

2024 लोकसभा के चुनाव में देश के दो सबसे बड़े दल कांग्रेस और BJP ने आरक्षण को राष्ट्रव्यापी मुद्दा बना दिया है। दोनों दलों के नेताओं में आरक्षण की तरफदारी करने और उसके प्रति समर्पण दिखाने की होड़ मची हुई है। यह विडंबना है कि आज आरक्षण का विरोध करने वाले चुप बैठे हुए हैं। आरक्षण के विरोध में न जाने कितनी दलीलें दी जाती थीं। पर चुनावी हितों को देखते हुए कोई इस बारे में कुछ नहीं बोल रहा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आरक्षण के मुद्दे पर ही कटघरे में खड़ा कर दिया है।

विरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

nbtedit@timesgroup.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

CUET के पहले दिन कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन - एक खबर - स्टूडेंट्स को कितनी 'परीक्षाओं' से गुजरना पड़ेगा सर जी!

सुमन जायसवाल

आर.एन.आई. नं. 510/57@ सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्स: 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • शुक्रवार • 17 मई • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

आप नियमों का पालन करके चलना नहीं सीख सकते। आप गिर कर ही चलना सीखते हैं।
-रिचर्ड ब्रैनसन

मिलने लगी नागरिकता

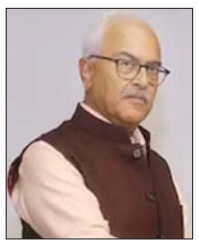

नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के तहत चौदह लोगों को भारत की नागरिकता दी गई। पड़ोसी देशों में प्रताड़ना का शिकार रहे गैर-मुस्लिम प्रवासियों को यह नागरिकता प्रदान की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2014 तक या उसके पूर्व भारत आए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए दिसम्बर, 2019 में लाया गया था। इसमें हिन्दू, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग शामिल हैं। पोर्टल के माध्यम से लिए गए आवेदनों के दस्तावज के सत्यापन के बाद आवेदकों को निष्ठा की शपथ भी दिलाई गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे एतिहासिक बताते हुए एक्स पर लिखा मोदी की गारंटी, वादा

पूरा होने की गारंटी। विवादों में घिरा रहा यह कदम आम चुनाव के दरम्यान उठाकर केंद्र सरकार ने मतदाताओं को स्पष्ट तौर पर यही दर्शाने का प्रयास किया है। विपक्ष ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसका भारी विरोध हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि इसका कार्यान्वयन समानता और धार्मिक गैर-भेदभाव के भारतीय संवैधानिक मूल्यों के लिए झटका है। सीएए को देश के अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दायित्वों के साथ असंगत बताया गया। आलोचकों की दलील कि यह देश के मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव दर्शा रहा है, अनुचित नहीं कही जा सकती। दुनिया भर में तीसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है जिनमें वे भी शामिल हैं, जिन्हें किन्हीं-न-किन्हीं कारणों से प्रताड़ित किया जाता है। धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर स्पष्ट रूप से खास समुदाय को शरण न देने की बात करना कतई उचित नहीं हैं। परंतु धर्म के आधार पर राजनीति करने वाले इस संवेदनशील बात को गले उतारने को कतई राजी नहीं नजर आते। संवैधानिक सिद्धांतों का सम्मान करते हुए विशाल हृदयता का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। यह कहना गलत नहीं है कि आवेदकों द्वारा उपलब्ध दस्तावेज और उनके प्रताड़ित होने के कारणों की जांच बेहद सतर्कतापूर्वक किए जाने की जरूरत है। इसमें कोई संदेह नहीं कि दुनिया भर में शरणार्थियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अभी तो आवेदकों में नाममात्र के प्रवासियों को नागरिकता प्राप्त हो पाई है। राजनीति से हटकर आवेदनकर्ताओं के कष्टों का अहसास करते हुए प्रक्रिया को तेज करने की जरूरत है।

सुधरें जांच एजेंसियां

सर्वोच्च न्यायालय ने प्रबीर पुरकायस्थ को रिहा कर दिया। प्रबीर समाचार वेबसाइट 'न्यूजक्लिक' के संस्थापक संपादक हैं, जिन्हें 3 अक्टूबर, 2023 इस आरोप में गिरफ्तार किया गया था कि वह चीन से पैसे लेकर भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार करते हैं। उनकी गिरफ्तारी गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत की गई थी। जाहिर है कि उनके ऊपर लगाया गया आरोप निहायत ही गंभीर था, लेकिन जांच एजेंसियों ने वह गंभीरता नहीं दिखाई जो उन्हें दिखानी चाहिए थी। न्यायालय के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 20, 21 और 22 व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये अधिकार संविधान के तहत व्यक्ति को प्राप्त सर्वाधिक

पवित्र एवं महत्त्वपूर्ण अधिकार हैं, लेकिन पुरकायस्थ की गिरफ्तारी की प्रक्रिया में उनके इसी अधिकार का मनमाने ढंग से अतिक्रमण किया गया। विधिक प्रक्रिया यह है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए उससे पहले पूरी जांच-पड़ताल करके उसे लिखित तौर पर बताया जाए कि आखिर, उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी तरह रिमांड देने वाले न्यायिक अधिकारी का भी दायित्व बनता है कि वह सुनिश्चित करे कि जिस व्यक्ति को रिमांड पर भेजा जा रहा है, उसे लिखित में बताया जाए कि उसे रिमांड पर क्यों भेजा जा रहा है। लेकिन जांच एजेंसी ने प्रबीर के मामले में इस बेहद महत्त्वपूर्ण निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। प्रबीर को बेहद हड़बड़ी में गिरफ्तार किया गया और इस तरह न्याय की मूल अवधारणा के विरुद्ध कार्य किया गया। इसीलिए न्यायालय ने इसी आधार पर कि अभियुक्त को उसकी गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया गया, उसकी गिरफ्तारी और रिमांड को अवैध करार दिया और रिहा करने का आदेश दिया। यह आदेश उन सभी जांच एजेंसियों के लिए एक तमाचा भी है, और सबक भी है कि वे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार तो कर लेती हैं, लेकिन गिरफ्तारी से पहले की जो कार्यवाहीजन्य प्रक्रियाएं होती हैं, उन्हें पूरा नहीं करतीं। परिणामस्वरूप गंभीर आरोपों के अभियुक्तों को भी रिहाई मिल जाती है और जांच एजेंसियों की किरकिरी होती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय को आगे इस तरह की टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

साहित्य/के. विक्रम राव

एलिस का जाना

साहित्य के प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार की विजेता एलिस मुनरो का कल (15 मई, 2024) कनाडाई नगर ओंतारियो में निधन हो गया। वे 92 वर्ष की थीं। मतिभ्रम से पीड़ित थीं। लघु-कथा लेखिका के रूप में मशहूर एलिस की समता भारतीय लघु कथाकार मुल्कराज आनंद और आरके नारायण से की जाती है। रूसी कथाकार एंटोन चेखोव और एलिस में काफी सादृश्य देखा गया।

एलिस की लघु कथाओं के अधिकांश पात्र महिलाएं होती थीं। समालोचकों ने कहा, 'एलिस को पढ़ने से लगता है कि आपने वैसा कभी पहले नहीं पढ़ा था।' एलिस की चंद मशहूर रचनाओं के शीर्षक रहे : 'सुखद छाया का नृत्य' (1998), 'युवतियों और महिलाओं का जीवन' (1971), 'क्या समझते हैं? आप कौन हैं?' (1978), 'मूंस का जूपिटर' (1982) आदि। एलिस ने उपन्यास नहीं लिखे क्योंकि 'रुचि नहीं थी।' नोबेल पुरस्कार प्रदानकर्ताओं ने लिखा : 'एलिस को पढ़ने के बाद महसूस होता है कि नया पढ़ रहे हैं।' उनकी कहानियां सरल गद्य शैली में मानवीय जटिलताओं का पता लगाती हैं। नोबेल पुरस्कार के अलावा मुनरो को 2009 में प्रतिष्ठित मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार भी मिला। वह कनाडा के गवर्नर जनरल पुरस्कार की तीन बार विजेता भी रहीं और उन्हें राइटर्स ट्रस्ट ऑफ कनाडा का 1996 मैरियन एंगेल पुरस्कार और रनवे के लिए 2004 रोजर्स राइटर्स ट्रस्ट फिक्शन पुरस्कार मिला। मगर 2013 के आसपास उन्होंने लिखना लगभग बंद कर दिया था। एलिस ने एक किशोरी के रूप में लिखना शुरू किया था और 1950 में दो साल की छात्रवृत्ति पर वेस्टर्न ओंटारियो विश्वविद्यालय में अंग्रेजी और पत्रकारिता का अध्ययन करते हुए अपनी पहली कहानी 'द डाइमेंशन ऑफ अ शैडो' प्रकाशित की। इस अवधि के दौरान उन्होंने होटल परिचायिका, तंबाकू बीनने वाली और पुस्तकालय क्लर्क के रूप में काम किया। उन्होंने 1951 में साथी छात्र जेम्स मुनरो से शादी करने के लिए विश्वविद्यालय छोड़ दिया, जहां वह 1949 से अंग्रेजी में पढ़ाई कर रही थीं। वे एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जेम्स की नौकरी के लिए डंडारेव, वेस्ट वैंकूवर चले गए। 1963 में, दंपति विक्टोरिया चला गया जहां उन्होंने मुनरो बुक्स खोली, जो अभी भी संचालित होती है। अपना उपनाम एलिस ने 'मल्लिका' रखा था यानी बेलवाला, सुगंधित पुष्प, कुटज वृक्ष, करुण पेड़ आदि। भारतीय शब्दों से कितना सामीप्य और साम्य!

चुनावी मुद्दा क्यों नहीं

मौलिक अधिकार
अखिलेश आर्येन्दु

लोकसभा का आम चुनाव कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा लेकिन देश की राजधानी में वह मुद्दा चर्चा का विषय नहीं बनता दिखाई दे रहा है जो दिल्ली के लिए सबसे अहम है। आम तौर पर माना जाता है कि राष्ट्रीय मुद्दों, स्थानीय समस्याओं और समाधानों के लिए पार्टियों के घोषणापत्रों में किए गए वादों पर चुनाव लड़े और जीते जाते हैं, लेकिन इस बार भी राजधानी में वे मुद्दे गायब हैं, जो वर्षों से देश और राजधानी के लिए कई तरह की समस्याओं के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा राजधानी और एनसीआर में अत्यंत खराब या गंभीर पर्यावरण प्रदूषण का है।

सुप्रीम कोर्ट के अनुसार स्वच्छ हवा में सांस लेना लोगों का मौलिक अधिकार है, तो इस अधिकार की लड़ाई के लिए इसे सत्ता पक्ष या विपक्ष कोई मुद्दा क्यों नहीं बना रहा? इस समस्या के प्रति सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों चुप लगाए हैं। सीधा सा सवाल है दिल्ली और एनसीआर वालों को दिल्ली की जहरीली हवा और कचरे की दुर्गंध से छुटकारा दिलाने के लिए कोर्ट की ताजा टिप्पणी को गंभीरता से लेने और इसे सबसे जरूरी मुद्दा मानकर इसे चर्चा में लाने के लिए आम आदमी को जागरूक करने की पहल की जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि संविधान में जाति, नस्ल, मजहब, आर्थिक स्थिति, क्षेत्र और स्त्री-पुरुष के नाम पर किसी तरह का किसी भी हालत में भेदभाव किसी के साथ नहीं किया गया है। लेकिन साथ में यह भी कहा गया है कि मौलिक अधिकारों का दुरुपयोग अपराध माना जाएगा। आजादी के साथ कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य, व्यवहार और विचार रख सकता है, लेकिन किसी के लिए असम्माननीय, नुकसान करने वाला या राष्ट्रविरोधी कार्य, विचार, व्यवहार और गतिविधियों को आगे नहीं बढ़ा सकता। सवाल यह है कि वाहनों, कारखानों, पराली या कोयला जलाने और प्रदूषण फैलाने की कवायदें क्या समाज या राष्ट्रविरोधी कार्य नहीं हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि प्रदूषण में सांस लेना लोगों के मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है। लेकिन प्रदूषण फैला कौन रहा है? कोर्ट और केंद्र सरकार ने प्रदूषण फैलाना अपराध के दायरे में माना है और जो प्रदूषण फैला रहा है उसके खिलाफ आर्थिक दंड और गिरफ्तारी के कानून साथ-साथ लागू हो सकते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के रुख को समझने की जरूरत है।

नवम्बर, 2023 में भी एक याचिका पर सुनाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि प्रदूषण की

वजह से लोगों को मरने नहीं दिया जा सकता। उसके बावजूद दिल्ली सरकार ने आज तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे दिल्ली की जहरीली हवा को साफ करने के दूरगामी असर दिखाई देते। अदालत की टिप्पणी के पीछे इस बात को समझने की जरूरत है कि जनता और शासन के लिए संविधान में महज अधिकार ही नहीं दिए गए हैं, बल्कि कर्त्तव्यों की भी बात की गई है। क्या जनता कभी इस तरफ गौर करती है?

दिल्ली की हवा में प्रदूषण निजी कवायदों से 99 प्रतिशत होता है, और सरकारी वाहनों से शायद एक प्रतिशत भी नहीं। फिर भी जरूरी है कि जनता और शासन, दोनों की आपसी पूरकता के आधार से सहमति बने और ऐसी नीति और नियम बनाए जाने चहिए जो दिल्ली एनसीआर में कचरे और उससे बढ़ते प्रदूषण को कम करने में मददगार साबित हों। इससे सबसे बड़ा फायदा जनता को होगा कि प्रदूषण से फैल रहीं तमाम बीमारियों और समस्याओं पर रोक लगना प्रारंभ होगा। लोगों की उम्र बढ़ जाएगी और प्रदूषण रोकने पर होने वाले अरबों रुपयों की बचत भी हो सकेगी। कोर्ट ने एक हलफनामे के हवाले से कहा कि गुरुग्राम में रोजाना 1200 टन ठोस कचरा पैदा होता है जबकि उसके उपचार की क्षमता महज 150 टन प्रति दिन है। फरीदाबाद में 1000 टन ठोस कचरा पैदा होता है लेकिन उपचार की क्षमता केवल 240 टन प्रति दिन है। हवाला देने का कोर्ट का मतलब यह था कि शासन कचरे के निपटान या उपचारित करने के प्रति कितना लापरवाह है।

मेरे विचार से मामला इतना भर नहीं है, बल्कि कचरे को उपचारित कर उसके बेहतर इस्तेमाल के लिए भी एनसीआर के नगर निगमों को कदम उठाना चाहिए। वाकई में भारत दूसरे देशों की अपेक्षा इस मामले में बहुत पीछे है। सरकारों की न कोई कचरा निपटान नीति है और न नीयत ही प्रदूषण खत्म करने की लगती है। वरना क्या वजह है पिछले दो दशकों से एनसीआर में कचरे के निपटान और बढ़ते प्रदूषण को लेकर अनेक बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश, सलाह और कार्रवाई करने के निर्देश देने के बाद भी कचरा निपटान के प्रति शासन-प्रशासन या स्थानीय निकाय लापरवाह बने रहे हैं? अब तो हालात ये हैं कि रोग बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। शायद इसीलिए झल्ला कर कोर्ट को यहां तक कहना पड़ा कि कचरे के निपटान के मामले में भारत की शाख इससे कम ही होगी क्योंकि आने वाले तीन-चार सालों में एनसीआर के स्थानीय निकायों के पास कचरे के निपटान के लिए कोई व्यवस्था यानी यंत्र लगाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। कोर्ट का कहना कि, लगता है किसी भी अधिकारी ने हर दिन पैदा होने वाले ठोस कचरे के निपटाने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं होने के गंभीर परिणामों पर विचार करने की जहमत ही नहीं उठाई पर कई सवाल खड़े करता है। कोर्ट की सख्त टिप्पणी क्या यह नहीं बताती कि कचरे से प्रदूषित हो रही दिल्ली और एनसीआर में बढ़ रही गंभीर बीमारियों और समस्याओं के प्रति नगर निगम और सरकारें कितनी गैर-जिम्मेदार हैं?

आश्चर्य होता है कि नगर निगमों के जिम्मेदार अधिकारी दिल्ली या एनसीआर में कहीं न कहीं रहते होंगे, बावजूद इस कदर प्रदूषण के प्रति असंवेदनशीलता कि जिस जहरीली हवा में वे श्वास ले रहे हैं, उसके कारणों का समाधान खोजने के लिए ईमानदार कोशिश भी नहीं की? दिल्ली को कचरा और प्रदूषण से मुक्त करने के साथ कूड़े के पहाड़ों को समाप्त करने की बात दिल्ली सरकार सालों से करती रही है, लेकिन न कचरा निपटान की समस्या का कोई कारगर उपाय खोजा गया, न प्रदूषण में कमी लाने में कोई कामयाबी मिलती आज तक दिखाई दी। ऐसे में सवाल लाजिमी है कि कब तक टाल-मटोल होता रहेगा?

> मेरे विचार से मामला इतना भर नहीं है, बल्कि कचरे को उपचारित कर उसके बेहतर इस्तेमाल के लिए भी एनसीआर के स्थानीय निकायों को कदम उठाने चाहिए। वाकई में भारत दूसरे देशों की अपेक्षा इस मामले में बहुत पीछे है। सरकारों की न कोई कचरा निपटान नीति है और न नीयत ही प्रदूषण खत्म करने की लगती है। वरना क्या वजह है पिछले दो दशकों से एनसीआर में कचरे के निपटान और बढ़ते प्रदूषण को लेकर तमाम निर्देशों के बावजूद शासन-प्रशासन लापरवाह बने रहे हैं

भारत के पास कपड़ा कारोबार की पूरी वैल्यू चेन

- भारत का कपड़ा बाजार करीब 150 अरब डॉलर का है। कपड़े का निर्यात बाजार करीब 40 अरब डॉलर का है
- बांग्लादेश और वियतनाम कुछ मामले में भारत को टक्कर दे रहे हैं, लेकिन उनकी सीमा यह है कि वे कुल मिलाकर अपैरल कंट्री ही हैं जबकि भारत के पास पूरी वैल्यू चेन है
- भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्यातक है। कपास जैसे नैचुरल फाइबर के मामले में भारत सबसे आगे है। दुनिया में कपास के कुल रकबे का एक तिहाई से ज्यादा भारत में है

(स्रोत : मीडिया इनपुट्स)

सुप्रीम कोर्ट ने न्यूजक्लिक के एडिटर-इन-चीफ प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया है, जिन्हें दिल्ली पुलिस ने पिछले साल यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आरोप पत्र दाखिल न किए जाने के आलोक में उनकी तत्काल रिहाई के आदेश दिए। लेकिन पुलिस को जवाबदेह कौन ठहराएगा जिसने यूएपीए के कठोर प्रावधानों का इस्तेमाल करके व्यक्तिगत आजादी और जीवन के अधिकार को ही बंधक बना लिया था।

राजदीप सरदेसाई, पत्रकार
@sardesairajdeep

एक ही पक्ष न देखें

वायरल वीडियो **रजनीश कपूर**

जब सोशल मीडिया में किसी मुद्दे पर कोई वीडियो वायरल हो जाता है तो ज्यादातर लोग उसके एक ही पहलू पर ध्यान देते हैं जबकि समझदारी इसी में है कि तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखा जाए। आजकल के 'फेक मीडिया' वाले माहौल में हमें अपना निर्णय लेने से पहले उस वीडियो को गहराई से समझने की आवश्यकता है। हाल में दिल्ली व देश के कुछ भागों में ऐसे वीडियो वायरल हुए जिन्हें देख लोगों ने काफी सहानुभूति जताई और कुछ समय बाद जब उसी वीडियो का दूसरा पक्ष सामने आया तो वीडियो को वायरल करने वालों की असलियत पता चली। परंतु हर व्लॉगर (सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने वाला) एक जैसा नहीं होता। कुछ अपवाद भी होते है जो मुद्दे की तह तक जाते है।

पिछले दिनों दिल्ली के तिलक नगर में दस साल के एक बच्चे का वीडियो इतना वायरल हुआ कि उसके समर्थन में कई जाने-माने लोगों तक ने सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मों पर उसे खुले आम सहयोग देने की बात कर डाली। इनमें सबसे पहले व्यक्ति थे प्रसिद्ध उद्योगपति आनंद महिंद्रा। फिल्म अभिनेता सोनू सूद भी इस बच्चे के समर्थन में उतरे। कहानी दिल्ली में रहने वाले जसप्रीत सिंह की है। दस वर्षीय इस बालक को वीडियो में दिल्ली के तिलक नगर में एक रेहड़ी पर 'एग रोल' बनाते दिखाया गया है। वीडियो बनाने वाले ने जब उस मासूम बालक से पूछा कि वो ये काम क्यों कर रहा है तो उसका जवाब था, 'मुझ पर अपनी बहन की जिम्मेदारी है।' जब उससे पूछा गया कि उसके माता-पिता कहां है तो वो बोला, 'पिता की मृत्यु हो गई और मां छोड़ कर चली गई।' बस फिर क्या था। वीडियो बनाने वाले ने जो शुरुआत की उसे कई अन्य व्लॉगर्स ने भी खूब वायरल कर डाला। जसप्रीत पर बने लगभग हर वीडियो ने यही दर्शाया गया कि 'दस वर्ष की उम्र में घर चलाने को मजबूर', 'पिता की मृत्यु हो गई और मां छोड़ कर चली गई।' जो भी वीडियो को देखे उसका दिल भर आए। जसप्रीत की खुद्दारी ऐसी है कि उसे किसी से भी वित्तीय सहायता नहीं चाहिए। ऐसा सुन कर कुछ लोगों ने उसके स्टॉल से सैकड़ों रोल बनवा कर लंगर में बंटवाए ताकि जसप्रीत के स्वाभिमान को ठेस न पहुंचे। जाने-माने लोगों ने ऐसे वीडियो को देख कर उस बालक का समर्थन किया तो इसे ग़लत नहीं माना जा सकता। बात सच है कि जसप्रीत के पिता की बीमारी के

कारण मृत्यु हुई। यह भी सच है कि जसप्रीत स्कूल जाने के साथ-साथ ठेले पर एग रोल बेचने को मजबूर है। यह भी सच है कि उसकी मां उसके साथ नहीं रहती।

परंतु क्या किसी भी व्लॉगर ने जानने का प्रयास किया कि ऐसी कौन मां होगी जो अपने पति की मृत्यु के चार दिन ही बाद अपने छोटे बच्चों को छोड़ कर अपने मायके चली जाएगी? पर क्या किसी ने उस मां का पक्ष जानने की कोशिश की? दिल्ली में सामाजिक कार्य करने वाले एक शख्स सरदार हरमीत सिंह पिंका ने इस दिशा में पहल की। वे जसप्रीत के स्टॉल पर गए और उससे बातचीत के दौरान उसकी मां का पता लिया। इस बीच, उन्होंने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से जसप्रीत के लिए एक चमचमाता हुआ आधुनिक स्टॉल भी बनवाया। सच की खोज में वे पंजाब के राजपुरा पहुंचे। जहां जसप्रीत की मां सिमरन कौर का मायका था। हरमीत सिंह ने सिमरन कौर के साथ बातचीत का वीडियो भी यूट्यूब पर डाला। उन्होंने इस बिखरे हुए परिवार को जोड़ने का भी प्रयास किया क्योंकि जसप्रीत की मां किसी मजबूरी में ही घर छोड़ कर गई थी। आज हर व्लॉगर को सरदार हरमीत सिंह पिंका से सबक लेना चाहिए।

आपको याद होगा कि किस तरह दक्षिण दिल्ली के एक ढाबा चलाने वाले 'बाबा' का वीडियो वायरल कर कुछ व्लॉगर्स ने पैसे इकट्ठा करने शुरू कर दिए थे। 'बाबा का ढाबा' के नाम से वायरल हुए वीडियो और उससे जुड़े एक व्लॉगर के गोरखधंधे की पोल भी बहुत जल्द खुल गई और उस व्लॉगर को सरेआम सभी से माफी भी मांगनी पड़ी। उस व्लॉगर द्वारा 'बाबा के ढाबा' के नाम पर इकट्ठा किए पैसे भी लौटाने पड़े। दरअसल, बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा प्रसिद्धि पाने की नीयत से कुछ लोग जनता को गुमराह कर देते हैं। बिना सोचे कि ऐसा करने से जो सच्चे और सुपात्र लोग होते हैं, उन्हें भी शक की नजर से देखा जाता है। इसी श्रृंखला में दिल्ली में 'वायरल वड़ा-पाव' के नाम से जाने जाने वाली चंद्रिका दीक्षित हैं। ये भी बहुत जल्द प्रसिद्ध होने वाली एक और सोशल मीडिया शख्सियत हैं। जितनी जल्दी प्रसिद्ध हुईं उतनी ही जल्दी विवाद में भी आईं। इनके दोनों तरह के वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल हैं परंतु सोचने वाली बात यह है कि पहले प्रसिद्ध होने और फिर दूसरा पहलू सामने आने पर आम जनता को ठगने वाले व्लॉगर्स पर लगाम कैसे लगाई जाए? इसलिए जब भी कभी आपके पास कोई वायरल वीडियो पहुंचता है तो इसके दूसरे पहलू की जांच की मांग अवश्य करें। आज वायरल वीडियो का दूसरा पहलू उजागर करने वाले और फैक्ट चेक करने वाले व्लॉगर की संख्या गिनी-चुनी अवश्य है परंतु जब तक ऐसे व्लॉगर समाज में सक्रिय रहेंगे तब तक मासूम जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करना आसान नहीं होगा।

सच्चा सुख **श्रीराम शर्मा आचार्य**

एक बार की बात है। एक गांव में एक महान संत रहते थे। अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे जिसके लिए वे कई लोगों से मुलाकात करते थे। और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह यात्रा के लिए जाना पड़ता था। इसी यात्रा के दौरान एक दिन उनकी मुलाकात एक साधारण सी कन्या विदुषी से हुई। विदुषी ने उनका बड़े हर्ष से स्वागत किया और संत से कुछ समय कुटिया में रुक कर विश्राम करने की याचना की। संत उसके व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार किया। विदुषी ने संत को अपने हाथों से स्वादिष्ट भोज कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी और खुद धरती पर टाट बिछा कर सो गई। विदुषी को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि विदुषी चैन की सुखद नींद ले रही है। उधर संत को खटिया पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे नरम गद्दे की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था। वो रात भर चैन की नींद नहीं सो सके और विदुषी के बारे में ही सोचते रहे। सोच रहे थे कि वो कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो सकती है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने विदुषी से पूछा कि तुम कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो रही थी। तब विदुषी ने बड़ी ही सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव! मेरे लिए मेरी ये छोटी सी कुटिया एक महल के समान ही भव्य है। इसमें मेरे श्रम की महक है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानती हूं। जब दिन भर के कार्यों के बाद मैं इस धरा पर सोती हूं तो मुझे मां की गोद का आत्मीय अहसास होता है। मैं दिन भर के अपने सत्कर्मों का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाती हूं। मुझे अहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धरा पर हूं। यह सब सुनकर संत जाने लगे। तब विदुषी ने पूछा, हे गुरु वर! क्या मैं भी आपके साथ आश्रम के लिए धन एकत्र करने चल सकती हूं? तब संत ने विनम्रता से उत्तर दिया, बालिका! तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है, उससे मुझे पता चला कि मन का सच्चा का सुख कहां है। अब मुझे किसी आश्रम की इच्छा नहीं रह गई। यह कह कर संत वापस अपने गांव लौट गए और एकत्र किया धन को उन्होंने गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बना कर रहने लगे।

रीडर्स मेल

सीएए के तहत नागरिकता

पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ना के शिकार होकर भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के तहत भारतीय नागरिकता देने का काम शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने नॉर्थ ब्लॉक स्थित अपने कार्यालय में 14 शरणार्थियों को भारत की नागरिकता का सर्टिफिकेट सौंप कर इसकी शुरुआत की। वैसे देश भर में कुल 300 शरणार्थियों को सीएए के तहत नागरिकता प्रदान की गई। अन्य लोगों को ईमेल के जरिए सर्टिफिकेट भेजे गए। इस बीच, गृह मंत्री अमित शाह ने इस ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि आखिर, शरणार्थियों का दशकों का इंतजार खत्म हुआ। दिसम्बर, 2019 में संसद में सीएए पास हुआ था, लेकिन विरोध प्रदर्शनों के चलते इस पर अमल नहीं हो पाया था। साढ़े चार साल के इंतजार के बाद 11 मार्च को गृह मंत्रालय ने सीएए के नियम अधिसूचित कर इसे अमलीजामा पहनाने का काम शुरू किया। इसमें 31 दिसम्बर, 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को नागरिकता देने का प्रावधान है।

सदन जी, पटना

जाते रहे हैं प्रकृति के विरुद्ध हम

गर्मी के इस मौसम में उन राज्यों में भी गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ने की संभावना है जहां हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। लू परेशान करती है, और हमें बीमार कर सकती है, इसलिए दोपहर को बाहर निकलते समय सावधानी बरतनी चाहिए। बढ़ती गर्मी का मुख्य कारण प्रकृति के विरुद्ध जाना, पर्यावरण की अनदेखी और वृक्षों का धड़ाधड़ कटान है। जब हम कड़वे नीम के बीज बोएंगे तो मीठे आम की उम्मीद रखना नासमझी नहीं होगी तो ओर क्या होगा? विकास के नाम पर और अपनी सुख-सुविधाओं की अंधी दौड़ में हम इसी तरह प्रकृति के विरुद्ध जाते रहे, पर्यावरण के प्रति लापरवाह रहे तो दिन दूर नहीं जब हमें सर्दी-गर्मी के मौसम तो ज्यादा तंग तो करेंगे ही, साथ ही हमें सांस लेने के लिए शुद्ध और साफ हवा मिलना भी मुहाल हो जाएगा।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

दूर करनी होंगी दिक्कतें

हर साल 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। इसी दिन अंतरराष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना भी इसी दिन की गई थी। करीब एक सदी पहले जब कोविड-19 से कहीं ज्यादा घातक स्पेनिश फ्लू की महामारी फैली थी और लोग एक-दूसरे से दूरी बना रहे थे, तब बहुत से लोगों (मूल रूप से अमेरिकियों) ने दोस्तों, परिजनों और सहकर्मियों से संपर्क में बने रहने के लिए टेलीफोन का इस्तेमाल किया था। उस समय यह नई तकनीक थी। इस रोग ने अहसास कराया कि समाज के लिए यह तकनीक कितनी महत्त्वपूर्ण थी। आज भी दूरसंचार के असंख्य लाभों के बावजूद कुछ चुनौतियां और चिंताएं भी हैं। सबसे गंभीर मुद्दा है डिजिटल डिवाइड। ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी और किफायती संचार सेवाओं तक पहुंच सीमित बनी हुई है, जिससे लाखों लोग डिजिटल अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से भाग नहीं ले पा रहे हैं। ।

देवेन्द्रराज सुथार, जालोर, राजस्थान
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्त्तव्य • समर्पण
वर्ष-33, अंक 273
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित। । समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

जलवायु परिवर्तन एवं मलेरिया

धरती के तापमान में बढ़ोतरी तथा जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक आपदाओं की त्वरा के साथ-साथ स्वास्थ्य से संबंधित जोखिम भी बढ़ रहे हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि मलेरिया की रोकथाम के लिए हो रहे प्रयासों के लिए जलवायु परिवर्तन एक खतरा बनता जा रहा है. भारत समेत दुनिया के अधिकतर देशों में मलेरिया एक बड़ी चुनौती है. वातावरण का तापमान और उमस बढ़ने तथा अनियमित बरसात या अतिवृष्टि आदि से मलेरिया का कारण बनने वाले मच्छरों के व्यवहार और वृद्धि पर असर पड़ रहा है. विशेषज्ञों के अनुसार, अपेक्षाकृत अधिक गर्मी मच्छर के भीतर मलेरिया परजीवी के विकास तथा संचरण की संभावना को बढ़ा सकती है. अनियमित बारिश और नमी से मच्छरों को पैदा होने के अनुकूल वातावरण मिल सकते हैं तथा उन्हें प्रजनन के लिए जगह मिल सकती है. ऐसी स्थिति में मलेरिया के मामले बढ़ने की आशंका बढ़ जायेगी. एक चिंताजनक पहलू यह भी है कि जलवायु परिवर्तन से जहां कई स्थानों पर मलेरिया के मामले बढ़ सकते हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसी जगहों पर यह बीमारी वापस भी आ सकती है, जहां से इसका उन्मूलन हो चुका है. इससे स्वास्थ्य सेवा पर बोझ बहुत बढ़ सकता है और मलेरिया की रोकथाम के लिए अब तक हुए प्रयास एवं उपलब्धियों का मतलब नहीं रह जायेगा. भारत के लिए यह बड़ी चुनौती है. देश की लगभग 95 प्रतिशत आबादी मलेरिया-प्रभावित क्षेत्रों में वास करती है. हमारे यहां 80 प्रतिशत मामले उन जगहों से आते हैं, जहां जनसंख्या का 20 प्रतिशत हिस्सा रहता है. ये जगहें आदिवासी, पहाड़ी, दुर्गम और दूर-दराज के क्षेत्र हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में दुनिया के 96 प्रतिशत मलेरिया के मामले केवल 29 देशों में दर्ज किये गये थे. भारत में 1.7 प्रतिशत मामले थे और मौतों में 1.2 प्रतिशत का हिस्सा था. अगर दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र को देखें, अनुमानित मामलों में 83 प्रतिशत तथा मौतों में 82 प्रतिशत की हिस्सेदारी भारत की थी. दर्ज मामलों में इस क्षेत्र में भारत का हिस्सा 36.4 प्रतिशत था. अनुमानित और दर्ज मामलों के आंकड़ों में इस अंतर का कारण कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थितियां हैं, फिर भी कोशिश की जानी चाहिए कि हर मामला दर्ज किया जाए. निश्चित रूप से दो दशक से मलेरिया की रोकथाम में उल्लेखनीय सफलता मिली है, फिर भी यह गंभीर स्वास्थ्य समस्या है. जलवायु परिवर्तन इसे खतरनाक दिशा मुहैया करा सकता है. हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि मलेरिया की जांच और उपचार की सुविधाओं का विस्तार हो. बहुत सी मौतें समय पर जांच नहीं होने और उपचार न मिलने के कारण होती हैं.

विशेषज्ञों के अनुसार, अपेक्षाकृत अधिक गर्मी मच्छर के भीतर मलेरिया परजीवी के विकास तथा संचरण की संभावना को बढ़ा सकती है.

साइबर हमले को लेकर सजग हों हम

मधुरेंद्र सिन्हा
वरिष्ठ पत्रकार
madhurendra.sinha6@gmail.com

तीन नये आपराधिक कानूनों का उद्देश्य साइबर अपराधियों द्वारा कानून के चंगुल से बचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कानूनी खामियों को दूर करना भी है. बावजूद इसके, अभी बहुत कुछ किये जाने की जरूरत है, परंतु इस क्षेत्र में सक्रिय रहने और 'डिजिटल रूप से सुरक्षित भारत' सुनिश्चित करने के प्रयासों की दिशा में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है. सजग रहना ही समस्या का समाधान है.

इंटरनेट ने दुनिया को एक गांव में तब्दील कर दिया था, पर डिजिटलीकरण ने उस दुनिया को और बदल दिया है. दूरियां खत्म कर दी है. कहीं से भी, कभी भी संवाद स्थापित करना पलक झपकते संभव है. परंतु इसी सरलता ने देशी-विदेशी अपराधियों को मौका दे दिया है और वे सक्रिय हो गये हैं. आज ऐसे लोग मौजूद हैं जो इसका लाभ उठाकर आम आदमी और हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं. साइबर हमलों के माध्यम से ऐसे प्रयास बढ़ रहे हैं, जिनमें से कुछ स्थानीय आपराधिक तत्वों के अलावा सीमाओं के पार से प्रायोजित अपराधी भी शामिल हैं. इन हमलों का उद्देश्य भारत के दूरसंचार, बैंकों, बिजली, अस्पतालों से लेकर सरकारी और निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों तक के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करना और लूट, फिरौती एवं अराजकता के माध्यम से अविश्वास पैदा करना है. इन दिनों साइबर हमलावरों ने दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई नगरों में ईमेल भेजकर स्कूल, स्टेशन, हवाई अड्डों को बम से उड़ाने की धमकी देनी शुरू की है. सुरक्षा एजेंसियों ने पता लगा लिया है कि यह शांति भंग करने की एक साजिश है और एक गिरोह ईमेल भेजकर सभी को डरा रहा है.

सुरक्षा एजेंसियों ने इस अपराध को रोकने के लिए कई उपाय किये हैं, उम्मीद है कि अपराधियों का जल्द ही पता लग जायेगा. जी-20 के दौरान तो भारतीय प्रतिष्ठानों और जी-20 आयोजनकर्ताओं के दफ्तरों पर हजारों नहीं लाखों हमले हुए. परंतु हमारी एजेंसियों ने अपना कौशल दिखाते हुए उन्हें नाकाम कर दिया. जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान हर 60 सेकेंड में 16 लाख साइबर अटैक हुए थे. केंद्रीय एजेंसियों ने अपनी त्वरित कार्रवाई से साइबर अपराधियों को उनके मंसूबों में सफल नहीं होने दिया. केवल देश ही नहीं, आम जन पर भी लगातार ऐसे हमले हो रहे हैं. साइबर अपराधी आम जनता को कॉल करके उनसे ठगी कर रहे हैं. देश में रोजाना साइबर अपराध के चलते 50000 कॉल मिल रही हैं. एक लाख लोगों पर 129 शिकायतें दर्ज हो रही हैं. हजारों साइबर अपराधी पकड़े जा रहे हैं और उन पर कार्रवाइयां हो रही हैं. इन अपराधों को रोकने तथा लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह की टीम द्वारा शुरू की गयी 'साइबर सेफ इंडिया पहल' गृह मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है. केंद्रीय गृह मंत्रालय में साइबर क्राइम से निपटने के लिए स्थापित किये गये 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आईफोरसी) ने अब तक उल्लेखनीय कार्य किया है. विदेशों से हमले करने वाले साइबर अपराधियों के पास आधुनिकतम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है. वे कहीं से भी हमला करते हैं और हमारे देश के महत्वपूर्ण संस्थानों की वेबसाइटों तथा संचार व्यवस्था को ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं या वहां से सूचनाएं चुराने का प्रयास करते हैं. हमारे कई बड़े संस्थानों पर ऐसे हमले हो चुके हैं, पर अधिकतर निष्फल ही हुए है. इस तरह के हमले चीन, पाकिस्तान से तो होते ही हैं, तुर्की और यहां तक की अमेरिका-कनाडा से भी होते हैं.

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आइफोरसी) ने देशभर में 1200 करोड़ रुपये से अधिक की बचत की है और लगभग पांच लाख शिकायतों का निपटारा किया है. यह केंद्र विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों और हितधारकों के बीच समन्वय स्थापित करने के अतिरिक्त, साइबर अपराध से निपटने के लिए देश के भीतर क्षमता निर्माण करने का भी प्रयास कर रहा है. इसने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीआरपी) के लॉन्चिंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी, जिसका उपयोग पहले से ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 31 लाख से अधिक साइबर अपराध शिकायतों, 66,000 एफआईआर के साथ 14 करोड़ बार किया जा चुका है. क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) के माध्यम से 12.30 करोड़ से अधिक मामलों का निपटान किया जा चुका है. राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला (एनसीएफएल) साइबर घटनाओं से संबंधित जांच में सहायता करती है. चूंकि ऐसे अपराध राज्य की सीमाओं से परे होते हैं, इसलिए आइफोरसी ने बेहतर अंतर-राज्य समन्वय के लिए संयुक्त साइबर अपराध समन्वय दल जेसीसीटीएस की स्थापना की है. आइफोरसी के अंतर्गत राष्ट्रीय साइबर अपराध पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन इकाई साइबर स्वच्छता में जागरूकता के लिए 'संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण' अपनाती है. 'साइबर दोस्त' नामक एक सोशल मीडिया हैंडल भी संचालित किया जा रहा है, जो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा से जुड़े टिप्स मुहैया कराता है. गृह मंत्रालय द्वारा 'साइबर जागृति दिवस' नामक एक पहल भी आरंभ हुई है, जिसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और स्कूलों, कॉलेजों द्वारा हर महीने के पहले बुधवार को सुबह 11 बजे शुरू किया जाता है.

गृह मंत्री ने गुरुग्राम में 'एनएफटी, एआइ और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा' विषय पर जी-20 सम्मेलन के दौरान भारत के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों से साइबर स्वयंसेवक दस्ते को हरी झंडी दिखाई थी. डिजिटल रूप से सुरक्षित भारत की जरूरत बन चुका आईफोरसी पहल विकसित भारत के आह्वान को एक मजबूती प्रदान करता है. भविष्य में बड़े पैमाने पर डिजिटल दुनिया में होने वाले अपराधों को रोकने, कम करने और उन पर निगरानी रखने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की देखरेख में एक राष्ट्रव्यापी साइबर अपराध रोकथाम तंत्र कार्यरत है. भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है. परंतु इसके मार्ग में साइबर अपराधी खड़े हैं. कई देश नहीं चाहते कि भारत इतनी तरक्की करे और इसके लिए वे साइबर हमलों का सहारा लेते हैं ताकि उनकी पहचान छुपी रहे, परंतु हमारी एजेंसियां भी इतनी चुस्त-दुरुस्त हैं कि वे पकड़ ही लेती हैं कि हमला कहां से हो रहा है या इसके पीछे कौन-कौन से तत्व हैं. हमलावर भी चुप नहीं बैठते और उनके विरुद्ध हमारी ओर से भी जवाबी हमले किये जाते हैं ताकि उनकी कमर टूटे. गृह मंत्री अमित शाह द्वारा शुरू किये गये तीन नये आपराधिक कानूनों का उद्देश्य साइबर अपराधियों द्वारा कानून के चंगुल से बचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कानूनी खामियों को दूर करना भी है. बावजूद इसके, अभी बहुत कुछ किये जाने की जरूरत है, परंतु इस क्षेत्र में सक्रिय रहने और 'डिजिटल रूप से सुरक्षित भारत' सुनिश्चित करने के प्रयासों की दिशा में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है. सजग रहना ही समस्या का समाधान है.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

उच्च रक्तचाप बीमारी नहीं, लक्षण है

डॉ अंशुमान कुमार
स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ
dranshumankumar@gmail.com

विश्व उच्च रक्तचाप दिवस

हमारी सभ्यता एक जटिल जंजाल में उलझ गयी है. बीमारियों का सीधा संबंध हमारी जीवनशैली और आदतों से हो गया है. सरल और सादा रहन-सहन हमें स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन दे सकता है. यह सही है कि कोई समस्या होने पर जांच करायी जाए और चिकित्सा करायी जाए, पर हमें हाइपरटेंशन के कारणों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है.

हमारी नसों में खून के समुचित प्रवाह के लिए एक दबाव या तनाव की जरूरत होती है, जो सीमा से अधिक होने पर उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन कहा जाता है. आम तौर पर उच्च रक्तचाप को एक बीमारी के रूप में देखा जाता है और चिकित्सक भी उसी का उपचार कर रहे हैं. पहले यह मान्यता थी कि सामान्य ब्लड प्रेशर की सीमा 80 और 120 होनी चाहिए. अमेरिकी हार्ट एसोसिएशन ने इसमें बदलाव करते हुए सीमा को 70 और 110 निर्धारित किया है. एथलीटों और अच्छी जीवनशैली वाले लोगों में ब्लड प्रेशर 60 और 100 पाया जाता है. इसे भी उनके लिए सामान्य माना जाना चाहिए. इस सीमा से अधिक या कम होने पर जांच की आवश्यकता होती है. यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि हाइपरटेंशन एक बीमारी नहीं है, बल्कि कुछ बीमारियों का लक्षण है.

लक्षण के निर्धारण के लिए रक्तचाप को दो प्रकारों में बांटा गया है- प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन. भारत में अधिकतर लोगों को प्राइमरी हाइपरटेंशन की समस्या है. यह वह स्थिति है कि डॉक्टर ने देखा कि व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, पर इसका कोई खास कारण नहीं मिला. इसे एसेंशियल हाइपरटेंशन भी कहा जाता है. सेकेंडरी हाइपरटेंशन में बीमारी, जैसे- किडनी की समस्या, हार्ट की कोई खराबी, कोई ट्यूमर आदि- का पता चलता है. इस श्रेणी में ऐसे लोग भी होते हैं, जो दुकान से दवा, खासकर दर्दनिवारक, खरीद खाते हैं. कई दवाओं में ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले तत्व होते हैं. खाने में नमक की मात्रा अधिक होना भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन का कारण हो सकता है. अक्सर ऐसा होता है कि आपकी जीवनशैली ठीक नहीं है, पर आपका हृदय ठीक काम कर रहा है. वैसे में खून की नालियों में संकुचन आ जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. आधुनिक चिकित्सा में उपाय यह निकाला जाता है कि दवा देकर खून को पतला कर दिया जाए और हाइपरटेंशन कम हो जाए. उस स्थिति में एड्रीनलिन शरीर के अन्य हिस्सों- मस्तिष्क, हार्ट, किडनी आदि- पर असर करेगा. लेकिन देखा तो यह जाना चाहिए कि नसों में संकुचन क्यों हुआ.

अगर व्यक्ति मोटापा का शिकार हो, तो उसे उच्च रक्तचाप की शिकायत हो सकती है. बहुत अधिक कैलोरी के भोजन, जैसे- पिज्जा, बर्गर आदि प्रोसेस्ड फूड, अधिक वसा, नमक और चीनी के सेवन से भी ब्लड प्रेशर की समस्या होती है. ऐसे व्यक्ति को हृदय रोगों, डायबिटीज और कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं. मोटापा बढ़ने से शरीर अधिक इन्सुलिन बनाने लगता है. इन्सुलिन का काम ग्लूकोज कम करना होता है, पर आप उसे बार-बार बढ़ायेंगे, तो वह शरीर में सोडियम और पानी जमा करने लगेगा, जो हाइपरटेंशन का एक कारण बनता है. साठ से अस्सी किलो वजन के व्यक्ति को हर दिन छह ग्राम नमक खाना चाहिए. बहुत अधिक चीनी खाना भी इन्सुलिन स्पाइक करेगा और ब्लड प्रेशर बढ़ेगा. इन आदतों के साथ-साथ लोगों की जीवनशैली सुस्त है. आम तौर पर हमें हर दिन आधे घंटे व्यायाम करना चाहिए. यहां व्यायाम से मतलब जिम नहीं है. सामान्य कसरत, जैसे टहलना, दौड़ना, तैरना, साइकिल चलाना आदि, से उच्च रक्तचाप की स्थिति को पैदा होने से रोका जा सकता है. लोग अगर हर दिन 10-12 हजार कदम पैदल चलें, तो ब्लड प्रेशर ही नहीं, कई घातक रोगों से बचाव हो सकता है.

तनाव हाइपरटेंशन का एक बड़ा कारण है. जैसी शहरी जिंदगी की आपाधापी है, उसमें तनाव होना स्वाभाविक है. इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि तनाव से एड्रीनलिन के साथ-साथ एक हार्मोन और निकलता है, जो सोडियम और पानी जमा करता है तथा मोटापे का कारण बनता है. इसमें भोजन की खराब आदत और सुस्त होने के पहलुओं को जोड़ लें, तो तनाव एक बेहद चिंताजनक कारक बन जाता है. शराब और धूम्रपान भी उच्च रक्तचाप के बड़े कारण हैं. यह समझना आवश्यक है कि उच्च रक्तचाप सभ्यता के अनियोजित विकास का एक अभिशाप है. जैसे जैसे हमारी वर्तमान सभ्यता और लापरवाह जीवनशैली आगे बढ़ेगी, हाइपरटेंशन की समस्या गंभीर होती जायेगी तथा बीमारियों का बोझ बढ़ता जायेगा.

कभी पहले मिट्टी, लोहे, पीतल आदि के बर्तनों में भोजन बनाया जाता था. अब पॉलिश वाले और नॉन-स्टिक बर्तनों का चलन बढ़ता जा रहा है. ऐसे बर्तनों में कुछ तत्व मेटाबॉलिक सिंड्रोम का कारण बनते हैं. इस सिंड्रोम में हाइपरटेंशन के साथ-साथ डायबिटीज आदि को गिना जाता है. प्लास्टिक में पैक किये गर्म खाने की चीजें भी खतरनाक हैं. यही स्थिति फास्ट फूड के साथ है. ऐसी वस्तुओं को संरक्षित करने के लिए उनमें नमक का अधिक इस्तेमाल होता है. स्वाद में नमक का असर कम करने के लिए चीनी डाली जाती है. चीनी धूम्रपान की तरह लत लगने वाली चीज है. ऐसी वस्तुओं को जब हम बासी के रूप में खाते हैं, तो और भी रसायन निकलते हैं. इस प्रकार हमारी सभ्यता एक जटिल जंजाल में उलझ गयी है. बीमारियों का सीधा संबंध हमारी जीवनशैली और आदतों से हो गया है. सरल और सादा रहन-सहन हमें स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन दे सकता है. **(ये लेखक के निजी विचार हैं.)**

देश दुनिया

यह समय वैक्सीन पर चर्चा का है, आख्यान गढ़ने का नहीं

जबकि कोविड-19 अब समाचार नहीं बन रहा है, हाल के महीनों में कोरोना वैक्सीन के दुष्प्रभाव से संबंधित मुकदमों ने सुर्खियां बटोरी हैं. इस संबंध में सबसे हालिया मामला दवा निर्माता कंपनी एस्ट्राजेनेका के विरुद्ध एक वैक्सीन ट्रायल पेशेंट द्वारा दायर मुकदमा है, जिसमें दावा किया गया है कि परीक्षण के दौरान वह वैक्सीन के कारण डिसेबल हो गयी थी, और कंपनी ने उसके मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं किया. एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, दो सप्ताह पहले एक ब्रिटिश व्यक्ति- जिसे टीकाकरण के कुछ दिनों बाद ब्रेन इंजुरी हुई थी- ने एस्ट्राजेनेका पर यह आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया था कि कंपनी ने जोखिमों को कम करके आंका और इसकी प्रभावशीलता को बढ़ा-चढ़ाकर बताया है. अन्य दवा निर्माताओं जैसे बायोएनटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को भी क्रमशः जर्मनी और भारत में मुकदमों का सामना करना पड़ा है. हाल के वर्षों में टीका विरोधी अभियानों के बढ़ते प्रभाव ने टीका बाद के लाभों और जोखिमों के बारे में तर्कसंगत चर्चा को कठिन बना दिया है. चिकित्सा व्यवसायी और सरकारी अधिकारी इस बात से चिंतित हैं कि टीके के जोखिमों या दुष्प्रभावों के बारे में किसी भी तरह की सार्वजनिक चर्चा से लोगों में टीके के प्रति झिझक उत्पन्न हो सकती है या टीकाकरण के विरोधियों द्वारा समर्थित षड्यंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा मिल सकता है. इसके परिणामस्वरूप आख्यानों में द्वंद्व उत्पन्न हो सकता है. एक आख्यान टीकाकरण की संख्या को हर दूसरे सुरक्षात्मक उपाय से ऊपर रखती है तथा इसके दुष्प्रभावों को दुर्लभ मामले बता खारिज कर देती है. वहीं एक दूसरा आख्यान, जो जोर पकड़ रहा है, वह मजबूत टीका विरोधी विचारों को दर्शाता है. इसके अधिकांश दावे बेतुके हैं, जैसे कि टीके एक जैविक हथियार थे. इस तरह की बातें कोविड-19 टीकों की प्रभावशीलता, क्षमता और जोखिमों पर स्वस्थ चर्चा और शोध में बाधा डाल रही हैं.

South China Morning Post

-जोसेफिन मा

बोधि वृक्ष

शरीर और आत्मा

असल में आदमी का शरीर और आदमी की आत्मा एक ही चीज के दो छोर हैं. मेरी दृष्टि में, आत्मा का जो हिस्सा हमारी इंद्रियों की पकड़ में आ जाता है, उसका नाम शरीर है और जो पकड़ से बाहर रह जाता है, उसका नाम आत्मा है. अदृश्य शरीर का नाम आत्मा है, दृश्य आत्मा का नाम शरीर है. ये दो अस्तित्व नहीं है, ये एक ही अस्तित्व की दो तरंग-अवस्थाएं हैं. वास्तव में, दो, द्वैत, डुआलिटी की धारणा ने मनुष्य जाति को बड़ी हानि पहुंचायी है. सदा हम दो की भाषा में सोचते रहे और मुसीबत हुई. पहले हम सोचते थे- मैटर और एनर्जी. अब हम यह नहीं कहते कि पदार्थ अलग है और शक्ति अलग. अब हम कहते हैं, मैटर इज एनर्जी. सच तो यह है कि यह पुरानी भाषा हमें दिक्कत दे रही है. पदार्थ ही शक्ति है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है. कुछ है, एक्स, जो एक छोर पर पदार्थ दिखाई पड़ता है और दूसरे छोर पर शक्ति दिखाई पड़ती है. ये दो नहीं हैं. ये एक ही ऊर्जा हैं, एक ही अस्तित्व के दो छोर हैं. ठीक वैसे ही, मनुष्य का शरीर और उसकी आत्मा एक ही अस्तित्व के दो छोर हैं. बीमारी दोनों छोरों में से किसी भी छोर से शुरू हो सकती है. शरीर के छोर से शुरू हो सकती है और आत्मा के छोर तक पहुंच सकती है. वास्तव में जो भी शरीर पर घटित होता है, उसके संकेत, उसकी तरंगें आत्मा तक सुनी जाती हैं. इसलिए कई बार यह होता है कि शरीर से बीमारी ठीक हो जाती है और आदमी फिर भी बीमार बना रह जाता है. शरीर से बीमारी विदा हो जाती है, डॉक्टर कहता है कि कोई बीमारी नहीं है और आदमी फिर भी बीमार रह जाता है, बीमार मानने को राजी नहीं होता कि मैं बीमार नहीं हूं. इस तरह के बीमारों से डॉक्टर बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि उनके पास जो भी जांच के साधन हैं, वे कह देते हैं कि कोई बीमारी नहीं है. परंतु कोई बीमारी नहीं होने का मतलब स्वस्थ होना नहीं है. स्वास्थ्य की अपनी पॉजिटिविटी है. हम कह सकते हैं कि कोई कांटा नहीं है. परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि फूल है. कांटा नहीं है, इससे केवल इतना ही पता चलता है कि कांटा नहीं है. परंतु फूल का होना कुछ और बात है.

-ओशो

कुछ अलग

युवा नेता की धमक और फोटो सेशन

पुष्पेंद्र दीक्षित
व्यंग्यकार
pushpendra.dixit906@gmail.com

नेता की एक धमक होती है, बड़े नेता की दूसरी धमक होती है, बहुत बड़े नेता की तीसरी धमक होती है. तीसरी धमक वाले बहुत बड़े नेता के जब भी शहर में पधारने की खबर फैलती है तो एक विशेष तरह का उत्सवीय मौसम बेसाख्ता उतर आता है. इसकी भनक सबसे पहले प्रशासन को लगती है और वह बहुत बड़े नेता के उत्तम स्वागत की भारी-भरकम व्यवस्था में लग जाता है. इसे प्रोटो वाला कॉल कहते हैं, पर तैयारी की बड़ी मुहीम एक जगह और छिड़ जाती है. वह है पार्टी की युवा कही जाने वाली विंग. हालांकि इसमें कई भूतपूर्व युवा होते हैं.

इनमें से कुछ फैशन डिजाइनर की सलाह पर पार्टी के रंग जैसा कुर्ता-पायजामा सिलवाने में लग जाते हैं. कुछ भगवा रंग के, तो कुछ सफेद रंग के कुर्ते का चुनाव करते हैं. कुछ का कुर्ता हरा, तो कुछ का पीला होता है. पार्टी की विचारधारा और रंग में रंगी पोशाक पार्टी के सबसे बड़े विश्वसनीय सिपाही के रूप में अपने आपको दिखाने की वर्दी होती है. अपने चार-छह खाली, फुक्के टाइप समर्थकों के साथ, कथित युवा हृदय सम्राट, मांगी हुई गाड़ी में चंदे का पेट्रोल डालकर, सभा स्थल की ओर रवाना हो जाते हैं. वहां पहुंचकर एक और कठिन जोड़-तोड़ उन्हें करनी होती है. रैली के आयोजन से जुड़े लोगों का चरण चुंबन कर वहां खड़े होने की जगह हथियाना, जहां से महान नेता का आगमन होगा. फिर वह घड़ी आती है जब बड़ी धमक वाले बड़े नेता सभा स्थल पर उड़नखटोले से उतरकर कदम धरते हैं. इसके साथ ही चेहरा चमकाने का दौर शुरू हो जाता है. कोई फूल देकर कई कोणों से फोटो खिंचवाता है, कोई पैरों के पास बैठकर, कोई लेटकर, तो कुछ पैरों को चूमने वाली मुद्रा बनाकर, कोई इधर खड़े होकर, कोई उधर खड़े होकर. फोटो सेशन का यह सिलसिला हेलीपैड से शुरू होकर नेता के मंच पर पहुंचने और भाषण देकर उतरने के बाद तक जारी रहता है.

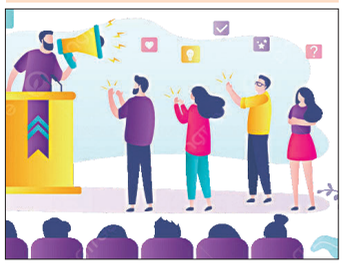

कुछ बहुत करीब से फोटो खिंचाने में सफल हो जाते हैं. ऐसे सफल युवा इसे तत्काल सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देते हैं और कैप्शन लगाते हैं कि मंत्री या मुख्यमंत्री से पार्टी की नीतियों और शहर की स्थिति पर चर्चा करते हुए. वहीं यदि किसी की नेता जी के साथ बैठे हुए फोटो आ गयी, तब फोटो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस संदेश के साथ जाती है कि मंत्री जी के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा करते हुए. ऐसी फोटो ड्राइंग रूम में वहां रखी जाती हैं, जहां से आगंतुक को घुसते ही दिखे. आजकल इसी को बुद्धिमानी वाली राजनीति कहा जाता है.

आपके पत्र

ध्वनि प्रदूषण से बढ़ रही है बीमारी

औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के रास्ते पर तेजी से बढ़ते शहरों में ध्वनि प्रदूषण की स्थिति हर दिन भयावह होती जा रही है. सामान्यत, हमारे कान एक निश्चित ध्वनि की दर को स्वीकार करते हैं, लेकिन नियमित तेज आवाज को सहन नहीं कर पाते. इसके कारण कान के पर्दे बेकार हो जाते हैं. साथ ही ध्वनि प्रदूषण के कारण बहरापन, कान में दर्द, कमजोरी, अनिद्रा, तनाव, उच्च रक्त दाब आदि समस्या भी होती है. सरकार को भी ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है.

हिमांशु शेखर, केसपा (गया)

अनजान कॉल से सावधानी जरूरी

साइबर अपराधी तरह-तरह के हथकंडा अपना कर लोगों से ठगी करने लगे हैं. ऐसे में लोगों के मोबाइल पर अनजाने नंबर से आनेवाले वीडियो कॉल, फोन कॉल या एसएमएस से सावधान रहने की आवश्यकता है. साइबर फ्रॉड पार्सल, नौकरी, झूठा मुकदमा, लॉटरी, आपत्तिजनक वीडियो आदि बहाना बना कर लोगों को ठगी का शिकार बनाते हैं. इसलिए मोबाइल पर आनेवाले अनजान कॉल से प्रलोभन से बचने की जरूरत है. यदि किसी प्रकार की ठगी के शिकार होते हैं, तो साइबर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करें.

बंधु मुन्ना, मरौना (सुपौल)

पोस्ट करें : प्रभात खबर, प्लॉट संख्या डी-9-10, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया, पटना (बिहार) - 800013, ■ **मेल करें :** patna @prabhatkhabar .in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है.

https://t.me/AllNewsPaperPaid

उदारता से नागरिकता

नागरिकता संशोधन अधिनियम अर्थात सीएए के तहत नागरिकता देने की शुरुआत सुखद और स्वागतयोग्य है। देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जो भारतीय नागरिकता के हकदार हैं। ऐसे लोगों को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने के लिए ही सीएए लाया गया है। विगत चार वर्ष से इसका विरोध हो रहा था, तो इसे लागू करने की मांग भी सुनाई पड़ती थी। अंततः केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता प्रमाणपत्र का पहला सेट बुधवार को जारी कर दिया, जिसके तहत नई दिल्ली में 14 आवेदकों को प्रमाण पत्र सौंपे गए। जाहिर है, केंद्र सरकार के इस कदम से नागरिकता की आस लगाए बैठे लोगों को अपार खुशी हुई होगी। अगर यही कवायद पहले शुरू होती, तो अब तक ज्यादा लोग लाभान्वित हुए होते। दरअसल, सीएए का विरोध इतना तीव्र था कि केंद्र सरकार ने कानून तो बना दिए, पर नियम तय न हो सके। इसी साल नियम तय हुए और नागरिकता देने की शुरुआत हुई है।

नागरिकता संशोधन नियम, 2024 के बारे में देशवासियों को पूरी तरह से जागरूक रहना चाहिए। जो विदेशी भारत में बगैर वैधता रह रहे हैं, उनको जरूरत और इंसाफ के आधार पर नागरिकता लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं, जिन लोगों को नागरिकता मिली है, उनकी खुशी पर गौर करना चाहिए। जिनको नागरिकता दी गई है, उनमें से ज्यादातर पाकिस्तान से बहुत कष्ट भोगने के बाद भारत आने को मजबूर हुए थे और दशक भर से ज्यादा समय से नागरिकता का इंतजार कर रहे थे। ध्यान रहे, इस अधिनियम के तहत, सरकार ने बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सताए गए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को आसानी से भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। नागरिकता पहले भी मिलती थी, पर अब उसमें तेजी आ जाएगी। बहरहाल, सीएए के विरोध को भी समझने की जरूरत है। ऐसे लोग हैं, जो हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई के साथ ही मुस्लिमों को भी भारतीय नागरिकता की सुविधा देने के पक्ष में हैं। ऐसे लोग भारत को धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में देखते हैं और पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में सताए जाने वाले मुस्लिमों के लिए भी भारत के दरवाजे खुले रखना चाहते हैं। खांटी सांप्रदायिक आधार पर बने तीन पड़ोसी देशों के बीच धर्मनिरपेक्ष भारत से जैसी विशेष उदारता की उम्मीद की जा रही है, उस पर व्यापक बहस की गुंजाइश से भला कैसे इनकार किया जा सकता है? निस्संदेह, आगामी पांच वर्ष में केंद्र सरकार के लिए यह विचारणीय विषय हो सकता है।

मजबूर होकर भारत आए लोग संवेदना के भूखे हैं। अगर उन्हें वैधता हासिल होती है, तो वह अपने नए देश की तरक्की के लिए ज्यादा मन से काम करेंगे।

एक पहलू यह भी है कि सीएए को रद्द कर देने की भी बात हो रही थी। हालांकि, रद्द करने का फैसला समयानुकूल नहीं होगा, इसमें बहुमत के आधार पर संशोधन की कोशिश पर्याप्त रहेगी। यह कानून विदेशियों नहीं, बल्कि भारतीयों के बीच लोकप्रिय होना चाहिए। इसकी लोकप्रियता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकारी एजेंसियां इसे कैसे लागू करती हैं। नागरिकता अपने आप में बहुत बड़ा व संवेदनशील विषय है। मजबूर होकर भारत आए लोग संवेदना के भूखे हैं। अगर उन्हें वैधता हासिल होती है, तो वे अपने नए देश की तरक्की के लिए ज्यादा मन से काम करेंगे। भारत पहुंचकर किसी भी सताए गए व्यक्ति को प्रेम का अनुभव होना चाहिए, नफरत का नहीं, पर जो लोग अवैधता, अलगाव और द्वेष के साथ यहां रहना चाहते हैं, उनके प्रति कानून की हथेलियां खुरदुरी ही रहें, तो बेहतर है।

चाबहार बंदरगाह पर रिश्तों के जहाज

यहां स्कैन करें

विवेक काटजू | पूर्व राजदूत

भारत के चहुंमुखी हित ईरान की तुलना में अमेरिका से कहीं अधिक जुड़े हैं, फिर भी, इसका यह मतलब नहीं कि तेहरान और नई दिल्ली अपने रिश्ते आगे न बढ़ाएं।

चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत और ईरान के बीच हुआ ताजा समझौता काफी अहम है। यह आपसी रिश्ते को तो नई ऊंचाई देगा ही, 'कनेक्टिविटी' की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा। दोनों देशों के संबंधित मंत्रियों की मौजूदगी में इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आईपीजीएल), जो भारत की एक सार्वजनिक कंपनी है और ईरान के बंदरगाह एवं समुद्री संगठन के बीच यह तय हुआ है कि शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह-चाबहार के आधुनिकीकरण में भारतीय कंपनी अगले 10 साल में लगभग 37 करोड़ डॉलर खर्च करेगी और उसका प्रबंधन व संचालन भी करेगी। इस रकम में से करीब 12 करोड़ डॉलर की धनराशि बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश की जाएगी, जबकि शेष 25 करोड़ डॉलर बतौर कर्ज ईरान को दिया जाएगा।

चाबहार बंदरगाह को विकसित करने की भारतीय मंशा दशकों पुरानी है। यह बंदरगाह ईरान के दक्षिण-पूर्वी तट पर है, जहां से अफगानिस्तान-ईरान सीमा पर स्थित जरांज शहर के जरिये दक्षिणी अफगानिस्तान का पूरा फलक खुल जाता है। आज से 22 साल पहले 2002 में ही वाजपेयी सरकार ने दूरंदेशी दिखाते हुए जरांज से दिलाराम तक सड़क बनाने में अफगानिस्तान की मदद की थी। यह सड़क चाबहार से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के जरिये मध्य एशिया, आगे रूस व यूरोपीय देशों के लिए रास्ता खोलती है। इसके साथ-साथ, ईरान की सहभागिता वाला अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा भी भारत के वाणिज्यिक हितों को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका अदा करेगा। हमें भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान अपने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के जरिये अफगानिस्तान का मार्ग हमारे निर्यात के लिए कभी नहीं खोलेगा, जबकि इस्लामाबाद व बीजिंग की मंशा अफगानिस्तान को चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से जोड़ने की भी है, जिसकी कड़ी ग्वादर बंदरगाह से जुड़ी है। ऐसे में, आर्थिक और वाणिज्यिक नजरिये से स्वाभाविक ही चाबहार बंदरगाह का विकास हमारे हित में है। इससे हमारा सामरिक हित भी जुड़ा हुआ है।

शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह-चाबहार पर समझौते के बाद अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा है कि ईरान से सहयोग करने वालों को वे अमेरिकी प्रतिबंध याद रखने चाहिए, जो वाशिंगटन ने तेहरान पर लगा रखे हैं। अभी हमें यह नहीं पता कि अमेरिकी प्रवक्ता की यह प्रतिक्रिया बस औपचारिक थी या फिर अमेरिकी प्रशासन ने चाबहार की अपनी नीति बदल ली है? दरअसल, 2016 में जब भारत और ईरान के बीच चाबहार को लेकर एक समझौता हुआ था, तब प्रतिबंधों के बावजूद अमेरिका ने यह एलान किया था कि चाबहार के विकास के लिए दिया जाने वाला भारतीय सहयोग प्रतिबंध के दायरे से बाहर रहेगा। लिहाजा, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ठीक ही कहा है कि चाबहार के सहयोग को संकीर्ण नजरिये से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसका सकारात्मक प्रभाव पूरे क्षेत्र पर पड़ेगा। यह भी मुमकिन है कि भारत और अमेरिका की इस मसले पर परदे के पीछे बातचीत हुई हो, क्योंकि अमेरिकी प्रवक्ता के बयान में तल्खी नहीं थी। संभावना यह भी है कि घरेलू दबाव के चलते अमेरिका ने यह बयान दिया हो, क्योंकि इस साल वहां पर राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है और बाइडन प्रशासन ने ईरान के प्रति काफी कड़ा रुख अपनाया है।

बहरहाल, ईरान पश्चिम एशिया का एक बड़ा देश है। भारत के साथ उसके राजनीतिक संबंध और आधुनिक काल में, विशेषकर ऊर्जा के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग दोनों देशों के लिए लाभदायक रहे हैं। हालांकि, सच यह भी है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते कई भारतीय कंपनियों ने ईरान से दूरी बनाए रखी थी। वे वहां निवेश करने से तो बचती ही थीं, ईरानी कंपनियों के साथ साझेदारी से भी हिचकती थीं, क्योंकि उनको डर था कि ऐसा करने से अमेरिकी कंपनियों से उनका रिश्ता या अमेरिका में उनका संचालन प्रभावित हो सकता है। भारत सरकार ने भी ईरान के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने में अमेरिकी प्रतिबंधों को ध्यान में रखा है। हां, चाबहार समझौता एक अपवाद रहा। आज भी भारत-ईरान के आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों में अमेरिकी प्रतिबंधों का नकारात्मक प्रभाव हम आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि भारत के चहुंमुखी हित ईरान की तुलना में अमेरिका से कहीं अधिक जुड़े हैं। फिर भी, इसका यह मतलब नहीं कि तेहरान और नई दिल्ली अपने रिश्ते आगे न बढ़ाएं। कुछ न कुछ रास्ता तो ढूंढ़ना ही पड़ता है और यही कूटनीति की चुनौती भी होती है कि एक बड़ी शक्ति अमेरिका के प्रतिबंधों से कैसे निपटा जाए?

इस पूरे मसले का एक पहलू यह भी है कि भारत के पश्चिम एशियाई देशों से गहरे हित जुड़े हैं। सामरिक और सुरक्षा के नजरिये से इजरायल नई दिल्ली के लिए अहम है, तो खाड़ी के देश हमारी ऊर्जा-सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। अरब देशों के साथ हमारा व्यापारिक संबंध काफी मजबूत है और लाखों भारतीय वहां काम करते हैं, जिनके द्वारा स्वदेश भेजी गई रकम हमारी अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाती है। भारत की पारंपरिक नीति यही थी कि वह पश्चिम एशिया की अंदरूनी राजनीति से दूर रहे। यहां के हरेक देश के साथ वह अपने संबंध आगे बढ़ाता रहा है। मगर बीते कुछ वर्षों से इस नीति में बदलाव देखने को मिल रहा है। जिस तरह से अमेरिका ने खाड़ी के कुछ देशों, खासकर यूएई के साथ इजरायल के रिश्ते बढ़ाने में परदे के पीछे से मदद की, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यूएई के सदर और अबू धाबी के शासक मोहम्मद बिन जायेद से अपने निजी रिश्ते भी मजबूत किए हैं। कुछ महीने पहले प्रधानमंत्री ने अमीरात का सफल दौरा भी किया था, जब वहां एक भव्य मंदिर का उद्घाटन हुआ था। स्वाभाविक है, इन घटनाओं को तेहरान में तीखी नजर से देखा जा रहा हो? ऐसे में, हम यह कह सकते हैं कि ताजा समझौते के जरिये भारत ने ईरान और इस क्षेत्र को एक संकेत दिया है कि वह अपनी पश्चिम एशिया की नीति में संतुलन बनाना चाहता है, जो उचित भी है।

उल्लेखनीय है कि ऐसे समझौते अमूमन चुनाव के बीच नहीं होते हैं। मगर इसका दूसरा पहलू यह है कि ईरान को विश्वास है, भारत और उसके हित को हर भारतीय सरकार आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, वह यह भी जानता है कि भारत की नजर चीन-ईरान-पाकिस्तान रिश्तों पर भी रहती है और ईरान जैसे महत्वपूर्ण देश में चीन और पाकिस्तान को भारत खुली छूट नहीं दे सकता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

भारतीय फुटबॉल मैदान से सुनील छेत्री की विदाई

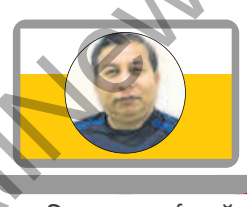

यहां स्कैन करें

अनादि बरुआ | पूर्व फुटबॉलर एवं कोच

भारत के लिए सर्वाधिक 94 गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है और उसके बाद उनके नाम की चर्चा फुटबॉल की दुनिया में ही नहीं, पूरे देश में तेज हो गई है। लंबे समय तक राष्ट्रीय टीम के कप्तान रहे सुनील लगभग दो दशक तक भारतीय फुटबॉल का सबसे चमकदार चेहरा हैं। वह दुनिया में सर्वाधिक गोल करने वाले सर्वश्रेष्ठ चार फुटबॉलर में शुमार हैं। आने वाले दिनों में भारतीय टीम में उनकी कमी बहुत खलेगी और युवाओं के लिए वह आने वाले दशकों में प्रेरणास्रोत बने रहेंगे।

सुनील छेत्री को मैं तब से जानता हूं, जब वह आर्मी पब्लिक स्कूल, धौलाकुआं में पढ़ा करते थे। वहां से वह खेलते-खेलते ममता मॉडल स्कूल गए। तब मैं फुटबॉल टीम चयनकर्ता भी था, सुब्रतो कप के लिए टीम चुनता था। सुनील का खेल देखकर मैं तब दूसरे चयनकर्ताओं से कहता था, यह लड़का बड़ा खिलाड़ी बनेगा। सुनील के मम्मी-पापा भी वहां बैठकर मैच देखते थे और मुझे याद है, मैं उनके सामने भी सुनील की तारीफ करता था। गौर करने की बात है कि सुनील की मम्मी भी कुशल फुटबॉलर रही हैं और गेंद को पैरों पर लगातार घुमाने और नियंत्रित करने में माहिर हुआ करती थीं। ऐसे में, सुनील को संस्कार में ही फुटबॉल नसीब हुई।

वह देश के सबसे सफल फुटबॉलर हैं। अब प्रेरणास्रोत और प्रशिक्षक के रूप में उनसे यह देश निश्चित ही बड़ी उम्मीदें रखेगा।

मैं दिल्ली का भी फुटबॉल कोच रहा हूं, तो मैंने यहां लगभग हर खिलाड़ी को खेलते-बढ़ते देखा है। इन सभी खिलाड़ियों में सुनील छेत्री सबसे खास हैं। मैंने उन्हें प्रशिक्षित भी किया है। इस मेहनती खिलाड़ी में सबसे अच्छा गुण है अनुशासन। वह किसी अच्छी चीज को जल्दी सीख लेते हैं। एक बार हम फरीदाबाद में टूर्नामेंट खेल रहे थे। एक दिन मैच होता था और एक दिन आराम। आराम वाले दिनों में खिलाड़ी गप मारने बैठ जाते थे। एक दिन मैंने सुनील से कहा, ऐसे समय मत खराब करो, आओ, तुम्हें एक खेल सिखाता हूं। तब मैंने उन्हें कमरे के अंदर ही बॉल से 'लेग टेनिस' का अभ्यास करना सिखाया। कमरे के अंदर ही इस खेल में सुनील और बाकी खिलाड़ियों को बहुत आनंद आया। तब संतोष ट्रॉफी खेल रहे सभी खिलाड़ियों ने कहा कि हम अपने घर में भी ऐसे खेलने की कोशिश करेंगे, इससे खेल कौशल व चपलता में भी मदद मिलेगी।

सुनील अनुशासन के पक्के हैं। चीजों को बहुत सहेजकर, करीने से रखते हैं। जब वह अपने खेल में उत्कर्ष पर थे, तब मैं उनसे मिलने बेंगलुरु गया था। उनके कमरे में ही ठहरा हुआ था, तो वहां मैंने देखा, उन्होंने पंद्रह या बीस जोड़ी जूते सजाकर रखे हैं, एकदम साफ-सुथरे। लोकप्रियता के चरम दौर में भी उनका भोजन एकदम समय से होता था और वह तैलीय या मसालेदार खाने से बचते थे। ऐसा मैंने बहुत कम खिलाड़ियों को करते देखा है।

उनके खेल की खासियत अगर देखें, तो कम जगह में, छोटे एंगल में भी वह गोल दागने में सक्षम हैं। ऐसे खेल का दुनिया में कम ही खिलाड़ियों को अभ्यास है। यही वजह है, उनकी गिनती सर्वाधिक गोल करने के मामले में दुनिया के श्रेष्ठ समकालीन दो खिलाड़ियों क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के साथ होती है। वह भारत के सबसे कामयाब फुटबॉलर हैं। ऐसा खिलाड़ी खोजना आसान नहीं होगा। यह मानने में कोई हर्ज नहीं कि अभी उनके स्तर का खिलाड़ी भारत के पास नहीं है।

याद है, एक बार मैंने उन्हें खूब डांटा था। दिल्ली में टीम संतोष ट्रॉफी खेल रही थी। दो खिलाड़ियों के साथ सुनील ने भी घर जाने का समय मांगा। मैंने कहा, 'ठीक है, रात साढ़े नौ बजे आ जाना।' वह साढ़े दस बजे लौटे, तो मैंने उन्हें खूब सुनाया। दूसरे दिन पता चला कि वह अपनी टीम की जर्सी घर छोड़ आए हैं। खैर, उनके लिए मैंने एक जर्सी की व्यवस्था की और उन्होंने गलती के लिए माफी मांगी। विनम्रता उनके स्वभाव में है और तभी वह अपने खेल को ऊंचे मुकाम पर पहुंचा सके हैं।

उनमें अहंकार नहीं है, तो युवाओं के साथ भी उनका अच्छा जुड़ाव है। एक बार वह मेरे फुटबॉल कोचिंग सेंटर, नोएडा में आए, तो बच्चों और उनके माता-पिता से बेहद उत्साह के साथ मिले। ऐसे खिलाड़ी देश की पूंजी हैं, धरोहर हैं। प्रेरणास्रोत और प्रशिक्षक के रूप में उनसे यह देश निश्चित ही बड़ी उम्मीदें रखेगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

आध्यात्मिक क्रांति की प्रतीक्षा

जहां कहीं भी एक महान अंत दिखे, निश्चित जानो कि एक महान प्रारंभ होगा। जब भी तुम्हारे मस्तिष्क को एक भीषण और कष्टकारी विनाश भयभीत करे, उसे एक वृहद् और महान सृजन की निश्चितता से ढाढ़स बंधाओ। याद रखो, ईश्वर न केवल स्थिर तुच्छ आवाज में है, बल्कि वह अग्नि और बवंडर में भी विद्यमान है।

विनाश जितना बड़ा होगा, सृजन के अवसर उतने ही मुक्त होंगे; किंतु विनाश प्रायः लंबा, धीमा और उत्पीड़क होता है, सृजन अपने आगमन में मंदगति और विजय में बाधित होता है। रात्रि बार-बार लौटकर आती है और दिवस उगने में देर लगाता है अथवा ऐसा भी लगता है कि कहीं भोर का मिथ्या आभास तो नहीं। इसलिए निराश मत हो, बल्कि कर्म करो। जो उतावले होकर आशा करते हैं, वे निराश भी जल्दी ही हो जाते हैं : न आशा करो न भय, बल्कि ईश्वर का उद्देश्य और उसे पूरा करने का अपना संकल्प सुनिश्चित कर लो।

ईश्वर अपनी दुनिया पर इतनी कठोरता से प्रहार क्यों करता है, क्यों उसे रौंदता और आटे जैसा गूंधता है, रक्त स्नान व भट्टी के रक्तिम नारकीय ताप में इतनी अधिक बार उसे क्यों झोंकता है? क्योंकि मानवता का पिंड अभी भी एक सख्त, अनगढ़ और मैल भरी कच्ची धातु है, जिसे और किसी तरह गलाया और आकार नहीं दिया जा सकता; जैसा उसका पदार्थ है, वैसा ही उसका तरीका है।

प्रत्येक धर्म ने मानव जाति की सहायता की है। देव पूजन ने मनुष्य में सौंदर्य का प्रकाश फैलाया है, उसके जीवन को विशालता और ऊंचाई दी है, बहुमुखी पूर्णता की ओर उसका लक्ष्य बढ़ाया है; ईसाई धर्म ने उसे दैवी प्रेम और परोपकारिता की कुछ दृष्टि दी; तो बौद्ध धर्म ने उसे अधिक बुद्धिमान, विनम्र और शुद्ध होने का एक गौरवपूर्ण रास्ता दिखाया; यहूदी धर्म और इस्लाम ने यह बताया कि कैसे कर्म में धार्मिक रूप से निष्ठावान और ईश्वर के प्रति प्रचंड रूप से समर्पित रहना है; वहीं हिंदुत्व ने उसके सामने अधिकतम और अगाधतम आध्यात्मिक संभावनाएं खोल दी हैं। यदि ये सभी ईश्वरीय दृष्टियां परस्पर मिलकर एक-दूसरे में अपने को ढाल लें, तो यह एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी; किंतु बौद्धिक रूढ़िवाद और पंथगत अहंकार इसके रास्ते में आड़े आते हैं।

कोई धर्म मानव जाति का अभी तक आध्यात्मीकरण नहीं कर पाया। उसके लिए किसी पंथ या सिद्धांत की नहीं, वरन आत्मविकास के एक सतत और सर्वव्यापी प्रयास की आवश्यकता है।

सभी धर्मों ने अनेक आत्माओं को बचाया है, पर उनमें से कोई भी मानव जाति का आध्यात्मीकरण अब तक नहीं कर पाया। उसके लिए किसी पंथ या सिद्धांत की नहीं, वरन आत्मविकास के एक सतत व सर्वव्यापी प्रयास की जरूरत है। आज विश्व में जो परिवर्तन हम देखते हैं, वे अपने आदर्श व मंतव्य में बौद्धिक, नैतिक व भौतिक हैं। आध्यात्मिक क्रांति अपनी घड़ी की प्रतीक्षा करती है और जब तक वह नहीं आती, तब तक मानव भविष्य के पूर्वानुमान की सारी व्याख्याएं व्यर्थ हैं।

श्री अरविंद

रामचंद्र गुहा | इतिहासकार

अगस्त 1909 में गांधीजी लिखते हैं- तथाकथित बड़े लोगों से हुई हर मुलाकात के बाद मुझे गहरी निराशा हुई। सत्ता के ऊंचे पदों पर बैठे लोग न्याय के प्रति बहुत कम रुचि दिखाते हैं। उनकी एकमात्र चिंता अपने पद पर बने रहने की होती है!

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले | 17 मई, 1949

समाचारों की स्वतंत्रता

संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेम्बली ने समाचारों की स्वतंत्रता के सम्बन्ध में एक विधान स्वीकार किया है। समाचार संग्रह करने और उनको संसार के विभिन्न भागों में भेजने के बारे में कोई अन्तर्राष्ट्रीय विधान बनाने का यह प्रथम प्रयास है। उसकी मुख्य धाराओं का आशय यह है कि विदेशी संवाद एजेंसियों के देशी अथवा विदेशी संवाददाताओं को आवागमन की पूरी स्वतन्त्रता हो और उन्हें समाचार संग्रह करने की समान सुविधायें दी जायें। विधान की एक और धारा में यह कहा गया है कि शांति-काल में राष्ट्र-रक्षा की आवश्यकता के प्रसंग को छोड़कर खबरों की पूर्व जांच-पड़ताल और काट-छांट न की जाये। राष्ट्रों को यह अधिकार दिया गया है कि अगर कोई खबर गलत छप जाये अथवा उस खबर से दूसरे देशों के साथ संबंध बिगड़ने की आशंका हो, तो संबंधित देश उस खबर का खंडन भेज सकता है। यदि यह खंडन प्रकाशित न हो, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम द्वारा उसे प्रकाशित करने की व्यवस्था की जायेगी।

आधुनिक विज्ञान ने दुनिया को बहुत छोटा बना दिया है। दुनिया के विभिन्न देश आज एक-दूसरे के बहुत निकट आ गये हैं। एक देश में होने वाली घटनाओं का दूसरे देशों पर अनिवार्य रूप से असर पड़ता है। दुनिया के विभिन्न देश एक-दूसरे के बारे में जानने को उत्सुक रहते हैं। विश्व में ऐसे आंदोलन चल रहे हैं, जिनका उद्देश्य है कि युद्धों की संभावना को दुनिया से मिटा दिया जाये या कम से कम कर दिया जाये, कारण युद्ध मानव जीवन को सुखी बनाने वाले साधनों का नाश तो करते ही हैं, मनुष्यों में कटुता और द्वेष की भावनाओं को भी जगाते हैं। जब यह होता है, तो भाईचारा और आपसी सहयोग कायम नहीं हो सकता, जिसके लिए आज दुनिया के साधारण-जन प्यासे हैं। भाईचारा और सहयोग तभी कायम हो सकता है, जब दुनिया के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों को एक-दूसरे के बारे में सही जानकारी सुलभ हो। सही जानकारी एक-दूसरे के विचारों और कार्यों को समझने में सहायक होती है। दुनिया के जितने भी पाप होते हैं, वे अंधकार में, पर्दे की ओट में ही होते हैं। अतः विश्व शांति और आपसी सद्भाव की रक्षा के लिए समाचारों की स्वतंत्रता के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो विधान स्वीकार किया है, उसका हम स्वागत करते हैं।

प्रधानमंत्री का अभी कोई विकल्प नहीं

चलो मान ली तुम्हारी बात कि एनडीए नहीं आ रहा है अबकी बार, लेकिन यह तो बता दो कि आ कौन रहा है? किसके प्रधानमंत्री बनने के ख्याल से गुदगुदी हो रही है? राहुल गांधी? ममता बनर्जी? अरविंद केजरीवाल? अखिलेश यादव? तेजस्वी यादव? पी विजयन? या फिर एमके स्टालिन? इनमें से कौन है, जो प्रधानमंत्री बनने के लायक है? अब यह न कहना कि कोई आसमान से टपकेगा? यह सोचकर खुश हो जाना एक बात है कि भाजपा की सरकार नहीं बन रही, लेकिन तब यह भी सोचना होगा कि बनेगी किसकी? और, क्या उस सरकार के मौजूदा नेताओं में देश चलाने की काबिलियत है? सच कहूं, तो भारतीय राजनीति में इस स्तर की विकल्पहीनता शायद पहली बार है, जब एक भी चेहरा नहीं दिखता, जिसकी प्रधानमंत्री के तौर पर कल्पना की जा सके! इसलिए तरस आता है उन लोगों पर, जो मोदी विरोध में लहालोट हो रहे हैं, क्योंकि वे सिर्फ मोदी को हटाने तक सोच पा रहे हैं, बनेगा कौन उनकी जगह- इसका जवाब किसी के पास नहीं है। यही दुर्भाग्य है इस देश का! लोकतंत्र का! भारतीय राजनीति में मौजूदा विकल्पहीनता पर इस टिप्पणी को मेरी 'व्यक्ति और पार्टी भक्ति' के तौर पर मत देखिए। मेरा किसी पार्टी से कोई लगाव या दुराव नहीं है। मगर 'व्यक्ति विरोध' के नाम पर अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर नहीं रह सकता। सच तो यही है कि आज 'ब्रांड मोदी' 'ब्रांड बीजेपी' से बड़ा हो चुका है। अब यह आपकी मर्जी है कि आप इसे मानें या न मानें।

विवेक सत्य मित्रम, टिप्पणीकार

असाधारण कार्यकाल

पिछले दस साल बेमिसाल रहे हैं और पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना है। इन वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अभूतपूर्व विकास का साक्षी बना है। इतना कि 'अब मोदी का कोई विकल्प नहीं' विपक्षी दलों के नेताओं के दिलो-दिमाग पर भी हावी हो चला है। ऐसा विश्वास है देश की जनता का अपने प्रधानमंत्री पर। निराशा से आशा की ओर बढ़ते कदम! आज समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण की चिंता देश कर रहा है। गांधीजी का भी तो यही सपना था। जन-कल्याण की योजनाओं में भ्रष्टाचार रुका है। अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में राशि जा रही है और बीच में कमीशन या कट आदि पर प्रभावशाली तरीके से रोक लगी है। स्पष्ट है, नेतृत्वहीन, दिशाहीन और नीतिहीन नेतृत्व से निकलकर देश अब सशक्त हाथों में है, इसलिए आज नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प ही नहीं दिखता।

सागरिका चौधरी, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

मोदी बनाम कौन?

विकल्पहीनता की स्थिति कभी नहीं रहती

दो दशक पहले की बात है। भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी अपनी सरकार के लिए जनादेश मांग रहे थे। तब 'इंडिया शाइनिंग', यानी भारत उदय एक ऐसा नारा बन चुका था, जो हर कोई दोहराता दिख रहा था। चुनावी हवा वाजपेयी के पक्ष में दिख रही थी। तमाम विमर्शों में यही कहा जा रहा था कि वाजपेयी साहब फिर से सरकार बना रहे हैं, क्योंकि उनके सामने विपक्ष का कोई चेहरा नहीं है। मगर उस कथित विकल्पहीनता की स्थिति में भी भाजपा की हार हुई और सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए गठबंधन सरकार बनाई। उस वक्त प्रधानमंत्री बनाए गए डॉ मनमोहन सिंह, जिनके नाम की कोई चर्चा न तो चुनाव से पहले हो रही थी और न नतीजों के बाद। ऐसी कथित राजनीतिक विकल्पहीनता का गवाह हम आपातकाल के बाद भी बन चुके हैं। यह वह दौर था, जब इंदिरा गांधी का कोई विकल्प नहीं बताया जाता था। 'इंडिया इज इंदिरा ऐंड इंदिरा इज इंडिया' जैसे जुमले गढ़े जा रहे थे। मगर 1977 के चुनाव में अपनी परंपरागत रायबरेली सीट से इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा और राज नारायण जैसे नेता ने उनको चुनावी मात दे दी।

स्पष्ट है, भारतीय राजनीति ऐसी घटनाओं की भी साक्षी है, जब चुनावी विश्लेषकों ने विकल्पहीनता का राग अलापा और जनादेश उनकी सोच के बिल्कुल विपरीत आया। जनता ने किसी न किसी में विकल्प ढूंढ़ ही निकाला। वास्तव में देखा जाए, तो यह दुनिया कभी विकल्पहीन हो ही नहीं सकती। भारतीय मतदाताओं ने भी इसे वक्त-वक्त पर साबित किया है। इसीलिए, अभी जो लोग विकल्पहीनता का राग अलाप रहे हैं, वे जरा भारत का राजनीतिक इतिहास पढ़ने की जहमत उठाएं। बेशक अभी वे राहुल, अखिलेश, ममता या अन्य नेताओं को मोदी का विकल्प न मान रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई दूसरा खड़ा नहीं हो सकता। विकल्पहीनता की बात कहकर दरअसल वे शासकीय विफलताओं को नजरंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वे कुतर्कों और झूठ का भी सहारा लेने से नहीं हिचकिचाते। मेरा यही मानना है कि 'विकल्प' जैसे खूबसूरत-सम्मोहक और भारी भरकम शब्द की ओट में चालाकी या बेवकूफी करने के बजाय लोगों को सच का सामना करना चाहिए। उनको यह समझना चाहिए कि असलियत में बदलाव ही विकल्प है। अगर आप बदलाव के समर्थक हैं, तो आपको विकल्प दिखेगा, और यदि आप यथास्थिति के पक्षधर हैं, तो आप निरंतर विकल्पहीनता का ही विलाप करते रहेंगे।

ज्योत्सना, टिप्पणीकार

https://epaper.livehindustan.com

दैनिक जागरण

विवेक के प्रकाश में ही कर्तव्य का दर्शन होता है

झूठ की पोल खुली

नागरिकता संशोधन कानून के नियमों को अधिसूचित करने के दो माह के अंदर तीन सौ से अधिक लोगों को नागरिकता प्रदान करने के अगले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने आजमगढ़ में एक सभा को संबोधित करते हुए यह बिल्कुल सही कहा कि इस कानून को लेकर झूठ का पहाड़ खड़ा किया गया और दंगे भी कराए गए। चूंकि झूठ का पहाड़ खड़ा करने का काम विपक्षी दलों की ओर से किया गया, इसलिए वे इस आरोप से बच नहीं सकते कि उन्होंने लोगों को गुमराह कर सड़कों पर उतारा। इन्हीं लोगों ने हिंसा और उपद्रव का सहारा लिया। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो हिंसक प्रदर्शन हुए, उनमें सरकारी एवं गैर-सरकारी संपत्ति को तो नुकसान पहुंचाया ही गया, जान माल की क्षति भी हुई। इन हिंसक प्रदर्शनों के कारण लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दुर्भाग्य से दिल्ली के लोगों को कुछ ज्यादा ही, क्योंकि यहां पर शाहीन बाग इलाके में एक व्यस्त सड़क को अवरुद्ध कर महीनों तक यातायात बाधित रखा गया। इसी अराजक धरने के कारण दिल्ली को भीषण दंगों का सामना करना पड़ा, जिनमें 50 से अधिक लोग मारे गए। इससे देश की बदनामी भी हुई, क्योंकि इन दंगों के समय तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति भारत में थे।

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लोगों को किस तरह बरगलाया गया, इसका एक प्रमाण यह है कि दो माह पहले जब इस कानून के नियम अधिसूचित किए गए तो कहीं कोई विरोध देखने को नहीं मिला। विरोध के नाम पर केवल कुछ बयान जारी किए गए और वह भी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले विरोधी दलों के नेताओं की ओर से। स्पष्ट है कि लोग समझ चुके हैं कि इस कानून के विरोध में सचमुच झूठ का पहाड़ खड़ा किया गया था और यह कोरी अफवाह थी कि इस कानून से भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। यह कानून तो तीन पड़ोसी देशों-अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित किए गए वहां के उन अल्पसंख्यकों के लिए है, जो किसी तरह अपनी जान बचाकर भारत आ गए। बुधवार को ऐसे ही कुछ लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इन दीन-हीन लोगों को नागरिकता देने का विरोध क्यों? आखिर इन प्रताड़ित लोगों को नागरिकता देना गलत कैसे है? यह तो भारत का नैतिक दायित्व है और एक तरह से विभाजन के समय की भूल को सुधारने की कोशिश भी। यह शर्मनाक है कि कुछ दल और विशेष रूप से तृणमूल कांग्रेस एवं वामपंथी दल अभी भी नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने में लगे हुए हैं। उनके दबाव में आकर कांग्रेस भी यह कहने लगी है कि सत्ता में आते ही वह सबसे पहला काम इस कानून को खत्म करने का करेगी। आखिर कांग्रेस या फिर अन्य दल यह अमानवीय-अनैतिक काम करने का वादा क्यों करने में लगे हुए हैं?

चुनाव में धनबल

चुनाव में धनबल का प्रयोग कोई नई बात नहीं है और हर चुनाव में ऐसा करने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन इस बार का आंकड़ा चुनाव आयोग के लिए चिंता की बात है। चौथे चरण के चुनाव तक आयोग ने उत्तर प्रदेश में 420 करोड़ रुपये के मूल्य की ड्रग्स, शराब एवं नकदी जब्त की है, जो 2019 के चुनाव से दोगुना से अधिक है। इतनी बरामदगी के पीछे एक तो यही कारण है कि आयोग के पास इस बार अधिक संसाधन हैं और उसने लोगों को सी-विजिल जैसे एप का प्लेटफार्म उपलब्ध कराया है जिससे न सिर्फ उसे अधिक सूचनाएं मिल रही हैं, बल्कि कार्रवाई में भी तेजी है, लेकिन यह भी स्वीकार करना होगा कि चुनाव में प्रयुक्त किए जा रहे धनबल का यह आंशिक हिस्सा है। मतदाताओं को इसके इतर भी प्रलोभन देने की कोशिशें हो रही होंगी, जो चुनाव आयोग के अधिकारियों की निगाह में नहीं आ रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि आयोग ने अब तक 285 करोड़ रुपये से अधिक की शराब और ड्रग्स जब्त की है, जो युवाओं के लिए खतरनाक है। मतदाताओं को प्रलोभन देकर उनका वोट हासिल करने का प्रयास लोकतंत्र के लिए नासूर है, जिसका इलाज किया जाना चाहिए। यह इलाज कोई कर सकता है तो सिर्फ मतदाता। मतदाताओं को प्रत्याशियों का मंतव्य और अपने वोट का महत्व समझना होगा। ऐसे प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के बारे में न सिर्फ आयोग को सूचना देनी चाहिए, बल्कि सामूहिक रूप से उनके बहिष्कार का निर्णय किया जाना चाहिए। मताधिकार इतनी सस्ती चीज नहीं कि थोड़े से रुपयों या शराब की बोतल पर बिक जाए। ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं को प्रलोभन देने की कोशिश अधिक होती है। महिला सहायता समूह अपनी सक्रियता से इस पर रोक लगा सकते हैं। प्रत्याशियों का चयन मुद्दों के आधार पर, विकास के आधार पर और उसके आचरण के आधार पर किया जाए। ऐसा करके लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है।

एक-दूसरे के पूरक मोदी और शाह

उमेश चतुर्वेदी

जो विपक्षी नेता मोदी के बाद शाह की बात कर भाजपा में विभाजन दिखाने का प्रयास कर रहे, वे पार्टी की कार्यप्रणाली और चरित्र से परिचित नहीं

अवधेश राजपूत

अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने राजनीति के शांत तालाब में ऐसा पत्थर उछाला है, जिसकी लहरें दूर तक फैल गई हैं। उन्होंने शिगूफा छेड़ा है कि यदि आपने भाजपा को वोट दिया तो अगले वर्ष 75 साल के होने पर नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री पद छोड़कर अपनी जगह अमित शाह की ताजपोशी कराएंगे। इस बयान के बाद कुछ हलचल सी मची। इस तरह देखें तो नौकरशाह और उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता से नेता बने केजरीवाल राजनीतिक पैंतरेबाजी में पूरी तरह पारंगत हो गए हैं। केजरीवाल जानते हैं कि फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को चुनौती दे पाना आसान नहीं है और उन पर सीधा हमला भी अक्सर आत्मघाती होता है, लिहाजा उन्होंने अमित शाह के बहाने मोदी की गाड़ी को पटरी से उतारने का दांव चला। केंद्रीय राजनीति में नरेन्द्र मोदी के विराट उभार के बाद राहुल गांधी जैसे कुछ नेताओं को छोड़ दें तो अधिकांश विपक्षी नेताओं के नुकीले सियासी तीरों के निशाने पर अमित शाह ही रहते हैं। अपने इस दांव से केजरीवाल एक तीर से दो शिकार की कोशिश में लगे हैं। पहला यह कि वह मोदी समर्थकों को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका वोट बेकार जाएगा, क्योंकि मोदी 75 वर्ष से बड़ी उम्र के नेताओं को मार्गदर्शक बनाने की भाजपा की अघोषित नीति का पालन करते हुए सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगे।

केजरीवाल दूसरा निशाना भाजपा की अंदरूनी राजनीति पर लगा रहे हैं, ताकि भाजपा के भीतर मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर खींचतान बढ़े। केजरीवाल शायद यह भूल गए हैं कि भाजपा में 75 साल या उससे ज्यादा आयु वाले नेताओं को छूट देने की परंपरा भी है। इसी के तहत बीएस येदियुरप्पा को इस आयु सीमा से छूट देते हुए भाजपा कर्नाटक में मुख्यमंत्री बना चुकी है। केरल में जीतने के आसार न होने के बावजूद उसने 80 वर्ष से अधिक आयु के ई. श्रीधरन को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था। केजरीवाल के इस तुर्रे के तुरंत बाद भाजपा के दिग्गज नेताओं ने स्पष्ट किया कि मोदी ही अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। अमित शाह ने तो यहां तक कहा कि आगे भी मोदी ही नेतृत्व संभालते रहेंगे। स्पष्ट है कि मोदी के पीछे एकजुट भाजपा के दिग्गजों की लामबंदी उस अघोषित 75 पार वाले नियम के अपवाद की ही उद्घोषणा है।

जो नेता भाजपा में आंतरिक फूट को बढ़ावा देने की मंशा से कुछ बयान उछाल रहे हैं, वे शायद पार्टी की कार्यप्रणाली और चरित्र से या तो परिचित नहीं या फिर जानने-समझने के बाद भी उससे अनजान बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा को पहली बार सत्ता की देहरी तक अटल-आडवाणी की जोड़ी लेकर आई थी। पार्टी के इन दोनों दिग्गजों में अद्भुत तालमेल रहा। मुंबई में 1995 में आयोजित अधिवेशन के दौरान जब आडवाणी ने भाजपा की ओर से वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाने की घोषणा की थी, तब वह वाजपेयी से कहीं अधिक सक्रिय, प्रभावी और लोकप्रिय थे। इसके बावजूद उन्होंने एक तरह से खुद को वाजपेयी के हनुमान के तौर पर स्थापित किया। 1996 की 13 दिवसीय सरकार का आडवाणी इसलिए हिस्सा नहीं बन पाए, क्योंकि हवाला कांड में नाम आने के चलते उन्होंने खुद चुनाव लड़ने से इन्कार कर दिया था। हालांकि 1998 और 1999 की सरकारों में वह शामिल हुए और उप प्रधानमंत्री रहे। वाजपेयी और आडवाणी एक-दूसरे के पूरक बने रहे। संगठन और सरकार के हित में जिसने भी फैसला लिया, उस पर एक-दूसरे की सहमति रही। सही मायने में दोनों एक-दूसरे के मन की बात समझते थे और सहयोगी भाव से आगे बढ़ते रहे।

मोदी और शाह की जोड़ी भी तकरीबन वैसी ही है। शाह ने खुले तौर पर कभी नहीं कहा कि वह मोदी के हनुमान हैं, लेकिन इसमें दोराय नहीं कि वही मोदी के सबसे ज्यादा करीबी एवं विश्वासपात्र हैं। मोदी के मन को जितना शाह समझते हैं, उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं एवं एजेंडे को जिस तरह शाह जमीन पर उतारते हैं, वह इसका साक्षात प्रमाण है। भाजपा की मूल वैचारिक नीतियों को अमित शाह ने पूरी तत्परता और कुशलता से धरातल पर उतारा है। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी बनाने की कानूनी और प्रशासनिक कोशिश हो या फिर नागरिकता संशोधन कानून को पारित कराना या फिर प्रशासनिक मोर्चे पर आतंकवाद एवं नक्सलवाद को नेस्तनाबूद करने की कोशिश, हर मोर्चे पर शाह मोदी के सोच को ही प्रभावी ढंग से जमीनी हकीकत बनाते नजर आते हैं। सांगठनिक स्तर पर भी शाह कई बार कमाल दिखा चुके हैं।

2014 के आम चुनाव में राजनीतिक पंडित भी उत्तर प्रदेश से भाजपा के 73 सीटें जीतने का अनुमान नहीं लगा पाए थे। उसके पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा सिर्फ दस सीटें ही जीत पाई थी। ऐसी स्थिति में 73 सीटें जीतना पत्थर पर फूल खिलाने जैसा था, लेकिन यह करिश्मा शाह ने कर दिखाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भी जीत की बड़ी वजह शाह की रणनीति ही रही। इसलिए भाजपा में भी एक बड़ा तबका ऐसा है, जो उन्हें मोदी का स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानता है। इसके बावजूद शाह ही मोदी के राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे, अभी ऐसे दावे करना जल्दबाजी ही होगी। संभवतः केजरीवाल भाजपा के इन आंतरिक समीकरणों को समझते हों, पर राजनीतिक बढ़त पाने की चाह क्या न कराए।

चूंकि अमित शाह की छवि कड़क मिजाज और सख्त प्रशासक की है। इस वजह से उनसे देश के कथित संभ्रांत तबके का एक हिस्सा खार खाए बैठा है। 'मोदी नहीं, बल्कि शाह को जाएगा वोट' का नैरेटिव इस तबके के सोच को बढ़ावा देने की कोशिश भी कही जा सकती है। याद रहे कि राजनीति में हमेशा दो और दो का जोड़ चार नहीं होता। मोदी विरोधी भी इस तथ्य को जानते हैं। फिर भी चुनावी माहौल में अपनी राजनीतिक गोटियां स्थापित करने के लिए अपने तरीके से नैरेटिव फैला रहे हैं, ताकि वोटर बिदके और उनका राजनीतिक मकसद कामयाब हो सके। 'मोदी नहीं, अमित शाह' का नैरेटिव इसी राजनीति का विस्तार है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

रोजगार सृजन की तेज होती गति

अभिनव प्रकाश

पिछले कुछ समय से बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आ रही है और आज वह 3.2 प्रतिशत रह गई है

लगातार बढ़ रहे हैं रोजगार के अवसर। फाइल

भारत में रोजगार सृजन सदैव एक महत्वपूर्ण चुनौती रहा है। इसका मुख्य कारण जनसंख्या में अधिकांश हिस्सा युवा वर्ग का होना है। जब से नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला है, भारत में रोजगार सृजन में एक नई गति आई है। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने पांच लाख से अधिक युवाओं की भर्ती की है। जबकि कांग्रेस के दस वर्षों (2004-14) के शासनकाल में केवल दो लाख भर्तियां की गई थीं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 4.9 लाख से अधिक युवाओं की भर्ती की है। संघ लोक सेवा आयोग ने पिछले नौ वर्षों में 50,906 उम्मीदवारों की भर्ती की है, जो कांग्रेस शासनकाल से करीब 6,000 अधिक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा 10 लाख केंद्रीय सरकारी नौकरियों को भरने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से लगभग नौ लाख उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। इसी तरह आइटी, विनिर्माण, व्यापार और परिवहन सहित नौ संगठित क्षेत्रों में 1.5 करोड़ से अधिक नौकरियां सृजित हुई हैं। कोविड के बाद लगभग पांच करोड़ लोग कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के पेरोल में शामिल हुए हैं। इनमें करीब 3.5 करोड़ लोग पहली बार ईपीएफओ के दायरे में आए हैं। यानी इन्होंने संगठित क्षेत्र में नौकरियां प्राप्त की हैं। चूंकि संगठित क्षेत्र का हिस्सा भारत में रोजगार में करीब 10 प्रतिशत ही है, इसीलिए रोजगार सृजन की स्थिति के लिए असंगठित क्षेत्र के आंकड़ों को भी देखना महत्वपूर्ण होगा।

मोदी सरकार की मुद्रा योजना के माध्यम से 40 करोड़ छोटे उद्यमियों को ऋण प्रदान किए गए हैं। आठ करोड़ लोगों ने पहली बार स्वरोजगार शुरू किया है। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को आसान दर पर ऋण प्रदान कर सूदखोरी से मुक्त किया गया है। इन्हें अपने व्यवसाय का विस्तार करने और अधिक लोगों को रोजगार देने में सक्षम बनाया गया है। आजीविका योजना के तहत नौ करोड़ महिलाओं को 83 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया है, जिससे उनकी आय के अनेक मार्ग खुले हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ने अपने रोजगार सृजन लक्ष्य को पार करते हुए 60 लाख से अधिक नए कर्मचारियों को नामांकित किया है। कोरोना काल में इस पहल ने देश में आर्थिक पुनरुत्थान और रोजगार संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कोरोना काल में ही आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 3.63 लाख करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई। इसने 1.8 लाख करोड़ रुपये के एमएसएमई ऋण को एनपीए बनने से बचाया, जिससे 1.5 करोड़ नौकरियां बचीं और नए रोजगार भी सृजित हुए। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत 1,52,900 से अधिक प्रतिष्ठानों को लाभ मिला, जिसके 1.2 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत लगभग 13 लाख उम्मीदवारों को 56 सेक्टरों और 600 ट्रेडों में प्रशिक्षित किया गया है और 7.9 लाख को विभिन्न नौकरियों में सीधे नियोजित किया गया। ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थानों के तहत 64 पाठ्यक्रमों में 39.9 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और 28.11 लाख से अधिक उम्मीदवारों को स्वरोजगार में स्थापित किया गया है।

नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम के तहत अब तक कुल 13.38 लाख प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया गया है। एक वर्ष के भीतर असंगठित क्षेत्र के 29 करोड़ श्रमिकों को सरकारी 'ई-श्रम' पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 6.2 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। पिछले नौ वर्षों में 5.47 लाख कामन सर्विस सेंटर भी खोले गए हैं। प्रत्येक केंद्र में दो से पांच लोग कार्यरत हैं। ग्रामीण डिजिटल उद्यमों का भी सृजन हुआ है, जिनमें से 67,000 से अधिक महिलाएं उद्यमी हैं। स्टार्टअप इंडिया के तहत एससी/एसटी लाभार्थियों को 7,351 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण दिए गए हैं। स्टैंडअप इंडिया के तहत 25,000 से अधिक एससी/एसटी उद्यमियों को बैंक ऋण और व्यावसायिक सुविधा प्रदान की गई है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में 9,54,899 नई नौकरियां सृजित करके एक नया आयाम स्थापित किया है। वित्त वर्ष 2022-23 में 448 अरब डालर से अधिक का रिकार्ड निर्यात हुआ। प्रत्येक अतिरिक्त एक अरब डालर के निर्यात से 1.5 लाख नौकरियां सृजित होती हैं। पीएलआइ योजना से भी संगठित क्षेत्रों में 60 लाख से अधिक अतिरिक्त नौकरियां सृजित हुई हैं।

भारत का लक्ष्य 2025-2026 तक इलेक्ट्रानिक्स उत्पादन क्षमता को 24 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाना है, जिससे 10 लाख से अधिक नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। बायोगैस उद्योग में 85,000 नौकरियां सृजित हुई हैं। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से 2030 तक आठ लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश और छह लाख से अधिक नौकरियां सृजित होने की संभावना है। सरकारी प्रोत्साहन से इलेक्ट्रानिक वाहन उद्योग में 2030 तक पांच करोड़ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित हो सकती हैं। रिकार्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के कारण भी करोड़ों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए। रियल एस्टेट सेक्टर में ही करीब तीन करोड़ रोजगार उत्पन्न हुए हैं। स्टार्टअप की संख्या 2014 में 350 से बढ़कर आज 1.25 लाख हो गई है। इससे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाखों नौकरियां सृजित हुई हैं। इस प्रकार देखा जाए तो सरकारी नीतियों के कारण बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आ रही है, जो आज 3.2 प्रतिशत रह गई है। इसी वजह से पिछले दस वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

माता-पिता का सम्मान

इन दिनों माता के साथ पिता को भी वृद्धाश्रम में भेज दिए जाने की घटनाएं खूब देखी-सुनी जा रही हैं। प्रायः यह भी देखा जाता है कि घर में बूढ़े, अशक्त और बीमार माता-पिता को बच्चे किसी न किसी बात पर झिड़क देते हैं। उनको अपमानित करते हैं। इस तरह के आचरण से माता-पिता की उपेक्षा करने की बातें प्रायः सामने आती ही रहती हैं। ऐसे मामलों पर गौर किया जाए तो धर्म-ग्रंथों के अनुसार यह पूर्णतया अनुचित है, क्योंकि माता-पिता को प्रथम देवता माना गया है। ऐसी स्थिति में देवी-देवताओं के दर्शन-पूजन और चढ़ावा से मनोवांछित भौतिक कामनाएं किसी भी सूरत में पूरी नहीं होंगी।

मां की महत्ता के संदर्भ में श्रीमद्भागवत पुराण में प्रसंग आता है कि नन्हें कृष्ण द्वारा चोरी से माखन खाने की शिकायत पर मां यशोदा स्नेह से ही सही डांटती ही नहीं, बल्कि एक डंडा हाथ में लेकर उन्हें मारने की धमकी भी देती हैं। कृष्ण आकाश की ओर देखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें बचाने आएं। जब भी कृष्ण आकाश की ओर देखते थे तब आकाश में बहुसंख्य देवता उनकी बाल-लीला देखने के लिए प्रकट हो जाते थे, लेकिन मां द्वारा स्नेहपूर्ण प्रताड़ना के वक्त कोई देवता नहीं प्रकट हुआ। कृष्ण को आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है? अंत में कृष्ण के मन में यह विचार आया कि, 'संकट की घड़ी हो, कोई कष्ट दे रहा हो या मारपीट रहा हो तब सच्चे मन से इष्टदेव को याद करने पर ईश्वरीय मदद तो मिल सकती है, लेकिन जब मां ही दंड दे रही हो तब ब्रह्मांड में बचाने वाला कोई नहीं प्रकट हो सकता।'

मां को जब कष्ट दिया जाता है एवं उपेक्षा की जाती है तब उसके अंतर्मन को पीड़ा पहुंचती है। उसी अंतर्मन में स्थित देवी-देवताओं को भी खिन्नता होती है। ऐसी संतानों की उन्नति और प्रगति के रास्ते अवरुद्ध होने लगते हैं।

सलिल पांडेय

महिला लोको पायलट की परेशानी

आयुषी दवे

हमने बहुत प्रगति कर ली है, लेकिन अफसोस कि देश की ट्रेनों के लोको पायलट के लिए ड्यूटी के दौरान इंजन में एक अदद वाशरूम तक नहीं है। परेशान करने वाली सच्चाई यह है कि पुरुषों की इस दौरान तो फजीहत होती ही है, लेकिन महिला लोको पायलट की मुसीबतें और भी दयनीय हो जाती हैं। यह हाल उन यात्री ट्रेनों का भी है जिसमें हर डिब्बे में चार टायलेट होते हैं। अब इसे विडंबना कहें या अनदेखी, लेकिन इस सच्चाई से सबसे ज्यादा सामना महिला लोको पायलट का ही होता है। ड्यूटी के दौरान अनिवार्य रूप से चलती रहने वाली शारीरिक प्रक्रिया के चलते वाशरूम की जरूरत पड़ना और नहीं मिलने पर मानसिक और शारीरिक यातना की कल्पना से ही सिहरन होती है।

वर्तमान में 1,700 से अधिक महिलाएं देश भर के विभिन्न रेलवे जोनों में लोको पायलट और सहायक लोको पायलट हैं। लोको पायलट को इंजन में रहते हुए वाशरूम की जरूरत के दौरान कितनी और

समयसीमा तय कर अविलंब रेल इंजनों में ही वाशरूम बनें, ताकि खासकर महिला लोको पायलट आगे और मानसिक, शारीरिक यातनाएं न झेलें

किस-किस तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता होगा? हालांकि रेलवे में वाशरूम ब्रेक का वर्तमान में अनौपचारिक प्रविधान है। इसके लिए वाकी-टाकी से निकटतम स्टेशन को सूचना देनी होती है। विडंबना यह कि महिला लोको पायलट के लिए इसमें भी काफी जोखिम है। छोटे-छोटे स्टेशनों पर शौचालय के उपयोग के लिए इंजन से बाहर निकलना किसी खतरे से कम नहीं, क्योंकि आमतौर पर स्टेशनों पर बाहरी तत्वों का जमावड़ा रहता है। इस युग में पूरे देश में यह समस्या लजाने वाली है। मासिक धर्म के दौरान सैनिटरी पैड के उपयोग के लिए लगातार चलती ट्रेन में कई-कई किलोमीटर के इंतजार के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि कब सुरक्षित और सुविधाजनक जगह मिले। विवशता के चलते वे कम से कम पानी पीती हैं, ताकि शौचालय की जरूरत न पड़े।

1909 में सवारी गाड़ियों में पहली बार प्रथम श्रेणी के डिब्बों में टायलेट सुविधा प्रारंभ हुई, जो सुरक्षा कारणों से इंजन तक नहीं पहुंची। वह दौर स्टीम इंजन का था। जिसमें डिजाइन और जगह की कमी के चलते संभव नहीं था, लेकिन डीजल इंजन बनाते समय संभवतः नजरअंदाज किया गया होगा, वरना इतनी देर नहीं होती। काफी शोर-शराबा, ज्ञापनों और विभिन्न रेल संगठनों के ध्यानाकर्षण के बाद रेलवे की तंद्रा भंग हुई। 2016 में पहली बार लोको पायलट के लिए इंजन में टायलेट बनाना शुरू तो हुआ, लेकिन यह बहुत थोड़े तक सीमित रह गया। यह संख्या अब तक 100 भी पार नहीं कर पाई है। जबकि भारत में 14,000 से अधिक डीजल और विद्युत इंजन हैं। समयसीमा तय कर अविलंब इंजनों में ही वाशरूम बनें, ताकि लोको पायलट आगे और शर्मिंदगी एवं मानसिक, शारीरिक यातनाएं न झेलें।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

अतिक्रमण के लिए कौन जिम्मेदार?

'राजमार्गों पर अतिक्रमण' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय पढ़ा। देखा जाए तो देश में जहां भी अतिक्रमण की समस्या है, उसके लिए अतिक्रमण करने वाले लोग तो जिम्मेदार हैं ही उनसे से अधिक जिम्मेदार वहां का पुलिस-प्रशासन है। ऐसे कर्मचारियों-अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, जिन्होंने अपने क्षेत्र में अतिक्रमण को होने दिया है। कुछ समय पहले हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को यह आदेश दिया था कि सरकार अवैध कब्जा करने वाले लोगों के प्रति भावुकता अर्थात दया न दिखाए। कोर्ट ने सरकार को हिदायत दी थी कि राज्य के सभी हाईवे से अतिक्रमण हटाए जाएं। इसमें दोराय नहीं कि देश में यदि अतिक्रमण के खिलाफ समय रहते मुहिम नहीं चलाई गई तो भविष्य में यह विकट समस्या बनकर उभरेगी। आज लगभग हर छोटे-बड़े शहरों की यही कहानी है। बाजारों में भी देखा जाता है कि लोग दुकान से बाहर सड़कों पर सामान रखकर बेचने लगते हैं, जो ट्रैफिक और राहगीरों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। शरणार्थियों या रेहड़ी-पटरी या फिर किराए पर रहने वालों के लिए भी सख्त कानून बनाने की जरूरत है, ताकि जहां-तहां वे अवैध निर्माण न कर सकें। कुछ समय पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने का मुद्दा सुर्खियों में आया था। सवाल यह है कि अवैध निर्माण कैसे होता है? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार, प्रशासन और संबंधित विभाग के अफसर क्यों अवैध निर्माण को रोकने के लिए पहले सक्रिय नहीं होते? इन क्षेत्रों तक बिजली, पानी और अन्य सरकारी सुविधाएं कैसे पहुंच जाती हैं? लोग भी सरकारी जमीनों का अतिक्रमण कर उन पर अवैध निर्माण करने से पहले क्यों नहीं सोचते हैं? वास्तव में जब तक देश में भ्रष्टाचार रहेगा, भ्रष्ट नौकरशाही पर सत्ताधारियों की मेहरबानी रहेगी, तब तक अवैध निर्माण का सिलसिला शायद ही थमे, लेकिन लोगों को भी अपनी कमाई को अवैध निर्माण में लगाने से बचना चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

मेलबाक्स

चुनावी वादे

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने लखनऊ में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में घोषणा की है कि यदि आइएनडीआइए सत्ता में आता है, तो गरीबों को वर्तमान पांच किलो अनाज की जगह 10 किलो अनाज दिया जाएगा। वर्तमान भाजपा नीत केंद्र सरकार के द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए 81 करोड़ की आबादी को पांच किलो अनाज दिया जाता है। यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है कि लोकसभा चुनाव में आखिर क्यों राष्ट्रीय बहस के मुद्दे लुप्त होते जा रहे हैं। मुफ्त के वादों से एनडीए और आइएनडीआइए चुनाव जीतने की जुगत में लगे हैं। क्या वास्तविक मुद्दों से चुनाव नहीं जीता जा सकता है? देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है, स्वास्थ्य सेवाओं में भारी कमी है, कानून व्यवस्था एक बड़ा प्रश्न है, जनसंख्या एक बड़ा मुद्दा है, सीमा पार आतंकवाद की घटनाएं भी मुद्दा हैं और दलित पर हो अत्याचार को कैसे रोके जाएं भी एक बड़ा मुद्दा है। आखिर इन मुद्दों पर चुनाव क्यों नहीं लड़ा जा रहा है? भाजपा और कांग्रेस दोनों में होड़ मची है। कभी आरक्षण के मुद्दों को जोर-शोर से उठाया जाता है और अब यह मुफ्त में अनाज देने की योजना को जनता के बीच लाया जा रहा है। देश में करोड़ों लोग टैक्स पे करते हैं। इस राशि को इस तरह से यदि प्रयोग किया जाएगा, तो यह संदेह के घेरे में रहेगी। हमें रोजगार पर राष्ट्रीय बहस करनी चाहिए। देश के युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो उनके परिवार की स्थिति मजबूत होगी। युवा अपने पैरों पर खड़े होंगे। मुफ्त अनाज की योजना पर अब 10 लाख करोड़ रुपये खर्च होते हैं, तब करीब 14 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। आखिर इतनी धनराशि का इस तरह से प्रयोग करना कितना उचित नहीं है? इतनी बड़ी धनराशि से देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़े होने चाहिए, बड़े-बड़े अस्पताल बनने चाहिए। स्कूल और कालेज बनने चाहिए। यह बहुत जरूरी है।

विरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

संपादकीय जागरण

(10) शुक्रवार, 17 मई, 2024 : वैशाख शुक्ल-9 वि. 2081

विवेक के प्रकाश में ही कर्तव्य का दर्शन होता है

झूठ की पोल खुली

नागरिकता संशोधन कानून के नियमों को अधिसूचित करने के दो माह के अंदर तीन सौ से अधिक लोगों को नागरिकता प्रदान करने के अगले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने आजमगढ़ में एक सभा को संबोधित करते हुए यह बिल्कुल सही कहा कि इस कानून को लेकर झूठ का पहाड़ खड़ा किया गया और दंगे भी कराए गए। चूंकि झूठ का पहाड़ खड़ा करने का काम विपक्षी दलों की ओर से किया गया, इसलिए वे इस आरोप से बच नहीं सकते कि उन्होंने लोगों को गुमराह कर सड़कों पर उतारा। इन्हीं लोगों ने हिंसा और उपद्रव का सहारा लिया। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो हिंसक प्रदर्शन हुए, उनमें सरकारी एवं गैर-सरकारी संपत्ति को तो नुकसान पहुंचाया ही गया, जान माल की क्षति भी हुई। इन हिंसक प्रदर्शनों के कारण लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दुर्भाग्य से दिल्ली के लोगों को कुछ ज्यादा ही, क्योंकि यहां पर शाहीन बाग इलाके में एक व्यस्त सड़क को अवरुद्ध कर महीनों तक यातायात बाधित रखा गया। इसी अराजक धरने के कारण दिल्ली को भीषण दंगों का सामना करना पड़ा, जिनमें 50 से अधिक लोग मारे गए। इससे देश की बदनामी भी हुई, क्योंकि इन दंगों के समय तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति भारत में थे। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लोगों को किस तरह बरगलाया गया, इसका एक प्रमाण यह है कि दो माह पहले जब इस कानून के नियम अधिसूचित किए गए तो कहीं कोई विरोध देखने को नहीं मिला। विरोध के नाम पर केवल कुछ बयान जारी किए गए और वह भी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले विरोधी दलों के नेताओं की ओर से। स्पष्ट है कि लोग समझ चुके हैं कि इस कानून के विरोध में सचमुच झूठ का पहाड़ खड़ा किया गया था और यह कोरी अफवाह थी कि इस कानून से भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। यह कानून तो तीन पड़ोसी देशों- अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित किए गए वहां के उन अल्पसंख्यकों के लिए है, जो किसी तरह अपनी जान बचाकर भारत आ गए। बुधवार को ऐसे ही कुछ लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इन दीन-हीन लोगों को नागरिकता देने का विरोध क्यों? आखिर इन प्रताड़ित लोगों को नागरिकता देना गलत कैसे है? यह तो भारत का नैतिक दायित्व है और एक तरह से विभाजन के समय की भूल को सुधारने की कोशिश भी। यह शर्मनाक है कि कुछ दल और विशेष रूप से तृणमूल कांग्रेस एवं वामपंथी दल अभी भी नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने में लगे हुए हैं। उनके दबाव में आकर कांग्रेस भी यह कहने लगी है कि सत्ता में आते ही वह सबसे पहला काम इस कानून को खत्म करने का करेगी। आखिर कांग्रेस या फिर अन्य दल यह अमानवीय-अनैतिक काम करने का वादा क्यों करने में लगे हुए हैं?

समय सीमा जरूरी

जमीन-जायदाद के मामलों को लेकर सजग राज्य सरकार ने इससे संबंधित विवादों का निपटारा समय सीमा के अंदर करने का बेहतर निर्णय लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत भूमि सुधार उप समाहर्ता को जमीन से जुड़े विवादों का निपटारा 90 दिनों के अंदर करना होगा। यह भी कहा गया है कि संबंधित पक्षों की सुनवाई किए बिना किसी मामले को खारिज नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही उन्हें सप्ताह में चार दिन कोर्ट लगाने का भी निर्देश दिया गया है। साफ है, अगर इस समय सीमा पर अमल किया गया तो प्रारंभिक स्तर पर ऐसे मामलों का निपटारा त्वरित गति से हो सकेगा। आंकड़ों के अनुसार, बिहार भूमि विवाद निवारण अधिनियम के तहत दायर किए गए आधे से अधिक मामले अभी लंबित पड़े हुए हैं। इससे स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। अच्छी बात है कि सरकार ने जिलाधिकारियों को इसकी समीक्षा करने को कहा है, ताकि वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल सके। किंतु, इस संबंध में किया गया कोई भी प्रयास तबतक प्रभावी नहीं होगा, जबतक पूरी व्यवस्था को सुचारू तरीके से चलाने को इसकी सख्त मानीटरिंग न की जाए। हालांकि, बीते दिनों प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से कुछ हद तक स्थिति में सुधार हुआ है। विभागीय स्तर पर आला अधिकारियों को और सजग होने की जरूरत है। वहीं, विभाग में भ्रष्टाचार और लापरवाही की बात किसी से छिपी नहीं है। सरकारी कार्यालयों से किसी भी तरह के कागजात प्राप्त करने में आमजन को काफी परेशानी होती है और इसका असर उस मामले के निपटारे पर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि आवेदन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो तथा गंभीरता से वरीय अधिकारी इसकी आनलाइन ट्रैकिंग करें।

प्रारंभिक स्तर पर जमीन संबंधी मामलों के निपटारे से मुकदमों की संख्या तो कम होगी ही सरकार पर आमजन का भरोसा भी बढ़ेगा।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या टीम इंडिया के कोच के लिए विदेशी क्रिकेटर को प्राथमिकता देनी चाहिए?

आज का सवाल
क्या स्वाति मालीवाल प्रकरण आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहा है?

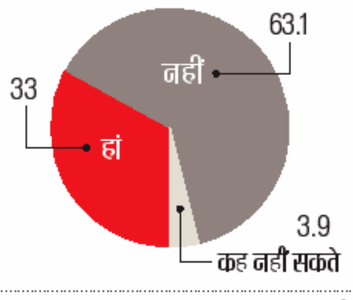

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

एक-दूसरे के पूरक मोदी और शाह

उमेश चतुर्वेदी

जो विपक्षी नेता मोदी के बाद शाह की बात कर भाजपा में विभाजन दिखाने का प्रयास कर रहे, वे पार्टी की कार्यप्रणाली और चरित्र से परिचित नहीं

अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने राजनीति के शांत तालाब में ऐसा पत्थर उछाला है, जिसकी लहरें दूर तक फैल गई हैं। उन्होंने शिगूफा छेड़ा है कि यदि आपने भाजपा को वोट दिया तो अगले वर्ष 75 साल के होने पर नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री पद छोड़कर अपनी जगह अमित शाह की ताजपोशी कराएंगे। इस बयान के बाद कुछ हलचल सी मची। इस तरह देखें तो नौकरशाह और उसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता से नेता बने केजरीवाल राजनीतिक पैंतरेबाजी में पूरी तरह पारंगत हो गए हैं। केजरीवाल जानते हैं कि फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को चुनौती दे पाना आसान नहीं है और उन पर सीधा हमला भी अक्सर आत्मघाती होता है, लिहाजा उन्होंने अमित शाह के बहाने मोदी की गाड़ी को पटरी से उतारने का दांव चला। केंद्रीय राजनीति में नरेन्द्र मोदी के विराट उभार के बाद राहुल गांधी जैसे कुछ नेताओं को छोड़ दें तो अधिकांश विपक्षी नेताओं के नुकीले सियासी तीरों के निशाने पर अमित शाह ही रहते हैं। अपने इस दांव से केजरीवाल एक तीर से दो शिकार की कोशिश में लगे हैं। पहला यह कि वह मोदी समर्थकों को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका वोट बेकार जाएगा, क्योंकि मोदी 75 वर्ष से बड़ी उम्र के नेताओं को मार्गदर्शक बनाने की भाजपा की अघोषित नीति का पालन करते हुए सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगे।

केजरीवाल दूसरा निशाना भाजपा की अंदरूनी राजनीति पर लगा रहे हैं, ताकि भाजपा के भीतर मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर खींचतान बढ़े। केजरीवाल शायद यह भूल गए हैं कि भाजपा में 75 साल या उससे ज्यादा आयु वाले नेताओं को छूट देने की परंपरा भी है। इसी के तहत बीएस येदियुरप्पा को इस आयु सीमा से छूट देते हुए भाजपा कर्नाटक में मुख्यमंत्री बना चुकी है। केरल में जीतने के आसार न होने के बावजूद उसने 80 वर्ष से अधिक आयु के ई. श्रीधरन को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था। केजरीवाल के इस तुर्रे के तुरंत बाद भाजपा के दिग्गज नेताओं ने स्पष्ट किया कि मोदी ही अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। अमित शाह ने तो यहां तक कहा कि आगे भी मोदी ही नेतृत्व संभालते रहेंगे। स्पष्ट है कि मोदी के पीछे एकजुट भाजपा के दिग्गजों की लामबंदी उस अघोषित 75 पार वाले नियम के अपवाद की ही उद्घोषणा है।

जो नेता भाजपा में आंतरिक फूट को बढ़ावा देने की मंशा से कुछ बयान उछाल रहे हैं, वे शायद पार्टी की कार्यप्रणाली और चरित्र से या तो परिचित नहीं या फिर जानने-समझने के बाद भी उससे अनजान बने रहने की कोशिश कर रहे हैं।

अवधेश राजपूत

भाजपा को पहली बार सत्ता की देहरी तक अटल-आडवाणी की जोड़ी लेकर आई थी। पार्टी के इन दोनों दिग्गजों में अद्भुत तालमेल रहा। मुंबई में 1995 में आयोजित अधिवेशन के दौरान जब आडवाणी ने भाजपा की ओर से वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाने की घोषणा की थी, तब वह वाजपेयी से कहीं अधिक सक्रिय, प्रभावी और लोकप्रिय थे। इसके बावजूद उन्होंने एक तरह से खुद को वाजपेयी के हनुमान के तौर पर स्थापित किया। 1996 की 13 दिवसीय सरकार का आडवाणी इसलिए हिस्सा नहीं बन पाए, क्योंकि हवाला कांड में नाम आने के चलते उन्होंने खुद चुनाव लड़ने से इन्कार कर दिया था। हालांकि 1998 और 1999 की सरकारों में वह शामिल हुए और उप प्रधानमंत्री रहे। वाजपेयी और आडवाणी एक-दूसरे के पूरक बने रहे। संगठन और सरकार के हित में जिसने भी फैसला लिया, उस पर एक-दूसरे की सहमति रही। सही मायने में दोनों एक-दूसरे के मन की बात समझते थे और सहयोगी भाव से आगे बढ़ते रहे।

मोदी और शाह की जोड़ी भी तकरीबन वैसी ही है। शाह ने खुले तौर पर कभी नहीं कहा कि वह मोदी के हनुमान हैं, लेकिन इसमें दोराय नहीं कि वही मोदी के सबसे ज्यादा करीबी एवं विश्वासपात्र हैं। मोदी के मन को जितना शाह समझते हैं, उनकी राजनीतिक आकांक्षाओं एवं एजेंडे को जिस तरह शाह जमीन पर उतारते हैं, वह इसका साक्षात प्रमाण है। भाजपा की मूल वैचारिक नीतियों को अमित शाह ने पूरी तत्परता और कुशलता से धरातल पर उतारा है। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी बनाने की कानूनी और प्रशासनिक कोशिश हो या फिर नागरिकता संशोधन कानून को पारित कराना या फिर प्रशासनिक मोर्चे पर आतंकवाद एवं नक्सलवाद को नेस्तनाबूद करने की कोशिश, हर मोर्चे पर शाह मोदी के सोच को ही प्रभावी ढंग से जमीनी हकीकत बनाते नजर आते हैं। सांगठनिक स्तर पर भी शाह कई बार कमाल दिखा चुके हैं।

वर्ष 2014 के आम चुनाव में बड़े से बड़े राजनीतिक पंडित भी उत्तर प्रदेश से भाजपा के 73 सीटें जीतने का अनुमान नहीं लगा पाए थे। उसके पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा सिर्फ दस सीटें ही जीत पाई थी। ऐसी स्थिति में 73 सीटें जीतना पत्थर पर फूल खिलाने जैसा था, लेकिन यह करिश्मा शाह ने कर दिखाया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भी जीत की बड़ी वजह शाह की रणनीति ही रही। इसलिए भाजपा में भी एक बड़ा तबका ऐसा है, जो उन्हें मोदी का स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानता है। इसके बावजूद शाह ही मोदी के राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे, अभी ऐसे दावे करना जल्दबाजी ही होगी। संभवतः केजरीवाल भाजपा के इन आंतरिक समीकरणों को समझते हों, लेकिन राजनीतिक बढ़त पाने की चाह क्या न कराए।

चूंकि अमित शाह की छवि कड़क मिजाज और सख्त प्रशासक की है। इस वजह से उनसे देश के कथित संभ्रांत तबके का एक हिस्सा खार खाए बैठा है। 'मोदी नहीं, बल्कि शाह को जाएगा वोट' का नैरेटिव इस तबके के सोच को बढ़ावा देने की कोशिश भी कही जा सकती है। याद रहे कि राजनीति में हमेशा दो और दो का जोड़ चार नहीं होता। दो और दो का जोड़ कई बार शून्य भी हो जाता है और कई बार आठ भी। मोदी विरोधी भी इस तथ्य को जानते हैं। फिर भी चुनावी माहौल में अपनी राजनीतिक गोटियां स्थापित करने के लिए अपने तरीके से नैरेटिव फैला रहे हैं, ताकि वोटर बिदके और उनका राजनीतिक मकसद कामयाब हो सके। 'मोदी नहीं, अमित शाह' का नैरेटिव इसी राजनीति का विस्तार है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

रोजगार सृजन की तेज होती गति

अभिनव प्रकाश

पिछले कुछ समय से बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आ रही है और आज वह 3.2 प्रतिशत रह गई है

लगातार बढ़ रहे हैं रोजगार के अवसर ● फाइल

भारत में रोजगार सृजन सदैव एक महत्वपूर्ण चुनौती रहा है। इसका मुख्य कारण जनसंख्या में अधिकांश हिस्सा युवा वर्ग का होना है। जब से नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला है, भारत में रोजगार सृजन में एक नई गति आई है। कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) ने पांच लाख से अधिक युवाओं की भर्ती की है। जबकि कांग्रेस के दस वर्षों (2004-14) के शासनकाल में केवल दो लाख भर्तियां की गई थीं। रेलवे भर्ती बोर्ड ने 4.9 लाख से अधिक युवाओं की भर्ती की है। संघ लोक सेवा आयोग ने पिछले नौ वर्षों में 50,906 उम्मीदवारों की भर्ती की है, जो कांग्रेस शासनकाल से करीब 6,000 अधिक हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा 10 लाख केंद्रीय सरकारी नौकरियों को भरने का लक्ष्य रखा था, जिसमें से लगभग नौ लाख उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। इसी तरह आइटी, विनिर्माण, व्यापार और परिवहन सहित नौ संगठित क्षेत्रों में 1.5 करोड़ से अधिक नौकरियां सृजित हुई हैं। कोविड के बाद लगभग पांच करोड़ लोग कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के पेरोल में शामिल हुए हैं। इनमें करीब 3.5 करोड़ लोग पहली बार ईपीएफओ के दायरे में आए हैं। यानी इन्होंने संगठित क्षेत्र में नौकरियां प्राप्त की हैं। चूंकि संगठित क्षेत्र का हिस्सा भारत में रोजगार में करीब 10 प्रतिशत ही है, इसीलिए रोजगार सृजन की स्थिति के लिए असंगठित क्षेत्र के आंकड़ों को भी देखना महत्वपूर्ण होगा।

मोदी सरकार की मुद्रा योजना के माध्यम से 40 करोड़ छोटे उद्यमियों को ऋण प्रदान किए गए हैं। आठ करोड़ लोगों ने पहली बार स्वरोजगार शुरू किया है। पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से 35 लाख रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को आसान दर पर ऋण प्रदान कर सूदखोरी से मुक्त किया गया है। इन्हें अपने व्यवसाय का विस्तार करने और अधिक लोगों को रोजगार देने में सक्षम बनाया गया है। आजीविका योजना के तहत नौ करोड़ महिलाओं को 83 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया है, जिससे उनकी आय के अनेक मार्ग खुले हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ने अपने रोजगार सृजन लक्ष्य को पार करते हुए 60 लाख से अधिक नए कर्मचारियों को नामांकित किया है। कोरोना काल में इस पहल ने देश में आर्थिक पुनरुत्थान और रोजगार संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कोरोना काल में ही आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 3.63 लाख करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई। इसने 1.8 लाख करोड़ रुपये के एमएसएमई ऋण को एनपीए बनने से बचाया, जिससे 1.5 करोड़ नौकरियां बचीं और साथ ही नए रोजगार भी सृजित हुए। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत 1,52,900 से अधिक प्रतिष्ठानों को लाभ मिला, जिसके 1.2 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत लगभग 13 लाख उम्मीदवारों को 56 सेक्टरों और 600 ट्रेडों में प्रशिक्षित किया गया है और 7.9 लाख को विभिन्न नौकरियों में सीधे नियोजित किया गया। ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थानों के तहत 64 पाठ्यक्रमों में 39.9 लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया है और 28.11 लाख से अधिक उम्मीदवारों को स्वरोजगार में स्थापित किया गया है।

नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम के तहत अब तक कुल 13.38 लाख प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया गया है। एक वर्ष के भीतर असंगठित क्षेत्र के 29 करोड़ श्रमिकों को सरकारी 'ई-श्रम' पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत 6.2 करोड़ लोगों को ट्रेनिंग दी गई है, जिससे जमीनी स्तर पर रोजगार की क्षमता बढ़ी है। पिछले नौ वर्षों में 5.47 लाख कामन सर्विस सेंटर भी खोले गए हैं। प्रत्येक केंद्र में दो से पांच लोग कार्यरत हैं। ग्रामीण डिजिटल उद्यमों का भी सृजन हुआ है, जिनमें से 67,000 से अधिक महिलाएं उद्यमी हैं। स्टार्टअप इंडिया के तहत एससी/एसटी लाभार्थियों को 7,351 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण दिए गए हैं। स्टैंडअप इंडिया के तहत 25,000 से अधिक एससी/एसटी उद्यमियों को बैंक ऋण और व्यावसायिक सुविधा प्रदान की गई है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में 9,54,899 नई नौकरियां सृजित करके एक नया आयाम स्थापित किया है। वित्त वर्ष 2022-23 में 448 अरब डालर से अधिक का रिकार्ड निर्यात हुआ। प्रत्येक अतिरिक्त एक अरब डालर के निर्यात से 1.5 लाख नौकरियां सृजित होती हैं। पीएलआइ योजना से भी संगठित क्षेत्रों में 60 लाख से अधिक अतिरिक्त नौकरियां सृजित हुई हैं।

भारत का लक्ष्य 2025-2026 तक इलेक्ट्रानिक्स उत्पादन क्षमता को 24 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाना है, जिससे 10 लाख से अधिक नौकरियां सृजित होने की उम्मीद है। बायोगैस उद्योग में 85,000 नौकरियां सृजित हुई हैं। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से 2030 तक आठ लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश और छह लाख से अधिक नौकरियां सृजित होने की संभावना है। सरकारी प्रोत्साहन से इलेक्ट्रानिक वाहन उद्योग में 2030 तक पांच करोड़ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित हो सकती हैं। रिकार्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के कारण भी करोड़ों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुए। रियल एस्टेट सेक्टर में ही करीब तीन करोड़ रोजगार उत्पन्न हुए हैं। स्टार्टअप की संख्या 2014 में 350 से बढ़कर आज 1.25 लाख हो गई है। इससे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाखों नौकरियां सृजित हुई हैं। इस प्रकार देखा जाए तो सरकारी नीतियों के कारण बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट आ रही है, जो आज 3.2 प्रतिशत रह गई है। इसी वजह से पिछले दस वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

माता-पिता का सम्मान

इन दिनों माता के साथ पिता को भी वृद्धाश्रम में भेज दिए जाने की घटनाएं खूब देखी-सुनी जा रही हैं। प्रायः यह भी देखा जाता है कि घर में बूढ़े, अशक्त और बीमार माता-पिता को बच्चे किसी न किसी बात पर झिड़क देते हैं। उनको अपमानित करते हैं। इस तरह के आचरण से माता-पिता की उपेक्षा करने की बातें प्रायः सामने आती ही रहती हैं। ऐसे मामलों पर गौर किया जाए तो धर्म-ग्रंथों के अनुसार यह पूर्णतया अनुचित है, क्योंकि माता-पिता को प्रथम देवता माना गया है। ऐसी स्थिति में देवी-देवताओं के दर्शन-पूजन और चढ़ावा से मनोवांछित भौतिक कामनाएं किसी भी सूरत में पूरी नहीं होंगी।

मां की महत्ता के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ श्रीमद्भागवत पुराण में प्रसंग आता है कि नन्हें कृष्ण द्वारा चोरी से माखन खाने की शिकायत पर मां यशोदा स्नेह से ही सही डांटती ही नहीं, बल्कि एक डंडा हाथ में लेकर उन्हें मारने की धमकी भी देती हैं। कृष्ण आकाश की ओर देखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें बचाने आएं। जब भी कृष्ण आकाश की ओर देखते थे तब आकाश में बहुसंख्य देवता उनकी बाल-लीला देखने के लिए प्रकट हो जाते थे, लेकिन मां द्वारा स्नेहपूर्ण प्रताड़ना के वक्त कोई देवता नहीं प्रकट हुआ। कृष्ण को आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है? अंत में कृष्ण के मन में यह विचार आया कि, 'संकट की घड़ी हो, कोई कष्ट दे रहा हो या मारपीट रहा हो तब सच्चे मन से इष्टदेव को याद करने पर ईश्वरीय मदद तो मिल सकती है, लेकिन जब मां ही दंड दे रही हो तब ब्रह्मांड में बचाने वाला कोई नहीं प्रकट हो सकता।' धर्मग्रंथों में यह कथन उद्धृत है कि 'पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कुमाता नहीं हो सकती'। मां को जब कष्ट दिया जाता है एवं उपेक्षा की जाती है तब उसके अंतर्मन को पीड़ा पहुंचती है। उसी अंतर्मन में स्थित देवी-देवताओं को भी खिन्नता होती है। ऐसी संतानों की उन्नति और प्रगति के रास्ते अवरुद्ध होने लगते हैं।

सलिल पांडेय

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

अतिक्रमण के लिए कौन जिम्मेदार?

'राजमार्गों पर अतिक्रमण' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय पढ़ा। देखा जाए तो देश में जहां भी अतिक्रमण की समस्या है, उसके लिए अतिक्रमण करने वाले लोग तो जिम्मेदार हैं ही उनसे से अधिक जिम्मेदार वहां का पुलिस-प्रशासन है। ऐसे कर्मचारियों-अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, जिन्होंने अपने क्षेत्र में अतिक्रमण को होने दिया है। कुछ समय पहले हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को यह आदेश दिया था कि सरकार अवैध कब्जा करने वाले लोगों के प्रति भावुकता अर्थात दया न दिखाए। कोर्ट ने सरकार को हिदायत दी थी कि राज्य के सभी हाईवे से अतिक्रमण हटाए जाएं। इसमें दोराय नहीं कि देश में यदि अतिक्रमण के खिलाफ समय रहते मुहिम नहीं चलाई गई तो भविष्य में यह विकट समस्या बनकर उभरेगी। आज लगभग हर छोटे-बड़े शहरों की यही कहानी है। बाजारों में भी देखा जाता है कि लोग दुकान से बाहर सड़कों पर सामान रखकर बेचने लगते हैं, जो ट्रैफिक और राहगीरों के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। शरणार्थियों या रेहड़ी-पटरी या फिर किराए पर रहने वालों के लिए भी सख्त कानून बनाने की जरूरत है, ताकि जहां-तहां वे अवैध निर्माण न कर सकें। कुछ समय पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने का मुद्दा सुर्खियों में आया था। सवाल यह है कि अवैध निर्माण कैसे होता है? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार, प्रशासन और संबंधित विभाग के अफसर क्यों अवैध निर्माण को रोकने के लिए पहले सक्रिय नहीं होते? इन क्षेत्रों तक बिजली, पानी और अन्य सरकारी सुविधाएं कैसे पहुंच जाती हैं? लोग भी सरकारी जमीनों का अतिक्रमण कर उन पर अवैध निर्माण करने से पहले क्यों नहीं सोचते हैं? वास्तव में जब तक देश में भ्रष्टाचार रहेगा, भ्रष्ट नौकरशाही पर सत्ताधारियों की मेहरबानी रहेगी, तब तक अवैध निर्माण का सिलसिला शायद ही थमे, लेकिन लोगों को भी अपनी कमाई को अवैध निर्माण में लगाने से बचना चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

बड़े स्तर पर बेरोजगारी नहीं

आइएनडीआइए के नेता इस चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। प्रश्न यह है कि जिस देश में विकास ने गत 10 वर्षों में अधिकतम गति पकड़ी हो, वहां बड़े स्तर पर बेरोजगारी होना कैसे संभव है। इस अवधि में 95 हजार किमी. हाई वे का निर्माण हुआ है। करोड़ों आवास एवं शौचालय भी बने। एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हो गई। हजारों किमी. रेल की पटरियां बिछाई गईं। देश के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंच गई। हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम पूरा होने वाला है। उज्ज्वला योजना में करोड़ों गैस के सिलेंडर की आपूर्ति हुई। सवा लाख स्टार्टअप प्रारंभ हुए। निर्बल वर्ग को व्यापार करने के लिए मुद्रा लोन दिए गए। रक्षा क्षेत्र में उत्पादन में इतनी तेज वृद्धि हुई कि अब हम निर्यात भी करने लगे। सीमा की सुरक्षा के लिए वृहद स्तर पर सड़कों, पुलों का निर्माण हो रहा है। प्रत्येक निर्माण में मानव श्रम के अतिरिक्त सीमेंट, स्टील आदि अनेक अवयवों का इस्तेमाल होता है, जिनके उत्पादन में भी आशातीत वृद्धि हुई है। वहां भी रोजगार का सृजन हुआ होगा। आज हमें प्लंबर, पेंटर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन आदि आसानी से नहीं मिलते।

धर्मेन्द्र नाथ रस्तोगी, दुर्गादेवी मंदिर मार्ग चौक, पटना

समय के साथ नहीं बदला मार्क्सवाद

विकास सारस्वत द्वारा लिखित आलेख 'मार्क्सवाद की खतरनाक खुराक' पढ़ा। समय के साथ परिवर्तन अनिवार्य है, लेकिन मार्क्सवाद के विचार में कोई बदलाव नहीं किया गया, इसलिए आज यह विचार पूरी दुनिया में सिमटता जा रहा है। भारत में पश्चिम बंगाल और केरल मार्क्सवाद का गढ़ था, लेकिन बंगाल की जनता ने उन्हें नकार दिया है। केरल में भी समर्थन घटा है। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात पूरी दुनिया को यह लगने लगा था कि वामपंथ समाप्त हो गया, परंतु अमेरिकी विश्वविद्यालय में हमास के समर्थन को लेकर प्रारंभ हुआ आंदोलन मार्क्सवाद का नया रूप है। मार्क्सवादी विचारधारा पूरी दुनिया को शोषक और शोषित वर्ग में विभाजित करती है। यह विचारधारा एक वर्ग का अंध विरोध और एक वर्ग को अंध समर्थन देने के लिए प्रोत्साहित करती है। आज अमेरिकी विश्वविद्यालय में हमास के प्रति अंध समर्थन देखा जा रहा है, जिसे रोकने के लिए सरकार को बल प्रयोग करना पड़ रहा है। इस आंदोलन में मार्क्सवादी विचारधारा को कट्टरता का साथ मिल रहा है। प्रारंभ में अमेरिका ने कट्टरता के प्रति दोहरा मापदंड अपनाया। भारत में कट्टरपंथी ताकतों का समर्थन किया, आज वहीं के विश्वविद्यालय कट्टरपंथी ताकतों का अखाड़ा बन गए। कट्टरपंथी सोच से किसी समाज व देश का भला नहीं हो सकता, इसके विरुद्ध सभी देशों को एक मंच पर आना होगा। अमेरिका की घटना पूरी दुनिया के लिए सबक है।

ई हिमांशु शेखर, केसपा, गया

पोस्ट

आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही, लेकिन अखिलेश यादव ने इस पार्टी के नेता को बगल में बिठाकर प्रेस कांफ्रेंस की।

रवि भदौरिया@ravibhadoria

जिन विभव कुमार पर स्वाति मालीवाल से दुर्व्यवहार के आरोप लगे हैं, वह एयरपोर्ट पर अरविंद केजरीवाल के साथ देखे गए। वह भी तब जब पार्टी ने इस मामले में कार्रवाई की बात की थी। यह स्पष्ट दिखाता है कि मामला गड़बड़ है और विभव कुमार का कुछ नहीं बिगड़ने वाला।

पल्लवी घोष@_pallavighosh

कल मुझे मुंबई में नए-नवेले आइकानिक ब्रिज पर जाने का अवसर मिला। यह बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। यह कितने शर्म की बात है कि हम लोग इसे साकार करने वाले शख्स को इसका उचित श्रेय नहीं देते।

तवलीन सिंह@tavleen_singh

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हेलीकाप्टर की तलाशी में उनके पूरे सामान की जांच हुई। यह चुनाव आयोग का एक रुटीन काम होता है। आप कल्पना कीजिए कि विपक्षी दल के किसी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा हुआ होता तो कितना विरोध होता और पता नहीं क्या-क्या आरोप लगाए जाते।

जितेंद्र प्रताप सिंह@jpsin1

जनपथ

ममता जी को हो गया शायद कुछ अंदाज,
चार जून के बाद का खोल रही हैं राज।
खोल रही हैं राज न सत्ता उनको चहिए,
जब धूमिल आसार तो बेहतर बाहर रहिए।
गठबंधन के हाथ न आने वाली बाजी,
तभी भूमिका बांध रही दिखतीं ममता जी।

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 35

****

धन को हमेशा ईमानदारी और न्याय से कमाया जाना चाहिए।
-स्वामी दयानंद सरस्वती

एफएआईएफए की ताजा रिपोर्ट देश में कृषि की जो तस्वीर पेश करती है, वह कृषि एवं रोजगार क्षेत्र में आ रहे बदलाव को भी रेखांकित करती है। बेशक कुछ चुनौतियां बरकरार हैं, लेकिन बढ़े हुए बजट, नवाचार और स्टार्ट-अप संस्कृति ने देश के कृषि क्षेत्र में दूसरे किस्म की क्रांति पैदा की है।

खेती का दूसरा पहलू

चरम मौसमी घटनाओं और भू-राजनीतिक तनावों के चलते कच्चे तेल की कीमतों के अस्थिर होने और मुद्रास्फीति के बढ़ने की आशंकाओं के बीच फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर्स एसोसिएशन (एफएआईएफए) की नवीनतम रिपोर्ट देश में कृषि की जो तस्वीर पेश करती है, वह उत्साहवर्धक तो है ही, तकनीक के दौर में देश के कृषि क्षेत्र के भविष्य को लेकर उम्मीदें भी जगाती है। रिपोर्ट बताती है कि पिछले नौ वर्षों के दौरान खेती-किसानी के लिए आवंटित बजट में 300 फीसदी की भारी वृद्धि हुई है, और यह तीस हजार करोड़ रुपये से बढ़कर 1.3 लाख करोड़ रुपये हो गया है। यही नहीं, व्यवसाय के अनुकूल माहौल और सरकार द्वारा मिल रहे समर्थन की वजह से पिछले नौ वर्षों में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में स्टार्ट-अप की संख्या भी सात हजार से अधिक हो गई है, जबकि 2014-15 तक ऐसे स्टार्ट-अप की संख्या पचास से ज्यादा नहीं थी। उल्लेखनीय है कि पिछले कुछ दशकों में देश की आर्थिक संरचना में काफी बदलाव आए हैं। वर्ष 1947 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में कृषि की हिस्सेदारी जहां 60 फीसदी थी, वह अब करीब 15 फीसदी पर पहुंच गई है। इसके बावजूद, आज देश की करीब 58 फीसदी आबादी आजीविका के लिए कृषि को ही प्राथमिकता वाला क्षेत्र मानती है। जाहिर है, इससे कृषि क्षेत्र में 'छिपी बेरोजगारी' को ही बढ़ावा मिला। लेकिन 2018-19 में कृषि क्षेत्र में नवाचार और आंत्रप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए लाई गई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत अब नए उद्यमियों को उभरने का मौका मिल रहा है। उत्साही युवा अब कॉरपोरेट नौकरियां छोड़कर कृषि स्टार्ट-अप शुरू कर रहे हैं। लिहाजा कृषि पर बोझ तो कम हुआ ही है, रोजगार की तस्वीर भी बदली है। रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम किसान योजना और पीएम फसल बीमा योजना से अब तक करोड़ों किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा, पीएम किसान सम्मान योजना के तहत अब तक किसानों को करीब पौने तीन लाख करोड़ की वित्तीय मदद मुहैया कराई जा चुकी है।

पर परिवहन और भंडारण की अपर्याप्त सुविधाओं के अलावा कमजोर बुनियादी ढांचा भी कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी बाधा है। अनियमित मौसम, अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, मुनासिब न्यूनतम समर्थन मूल्य का न मिलना, किसानों का बढ़ता कर्ज और आत्महत्या जैसी चुनौतियों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके, बढ़े हुए बजट, नवाचार और स्टार्ट-अप संस्कृति ने कृषि क्षेत्र में जो दूसरे किस्म की क्रांति पैदा की है, वह निश्चित ही किसानों के समग्र हित को बढ़ावा देने वाली है।

पाकिस्तान में 'दुबई अनलॉक्ड' बम

बदहाल पाकिस्तान में 'दुबई अनलॉक्ड' रिपोर्ट ने तहलका मचा रखा है। इससे पता चला है कि ऐसे समय में, जब मुल्क आर्थिक संकट से गुजर रहा है और आईएमएफ से दूसरे बेलआउट पैकेज के लिए गुहार लगा रहा है, पाकिस्तानियों ने दुबई में 11 अरब डॉलर की संपत्ति खरीदी है।

भारतीय मीडिया के पत्रकार इन दिनों देश में चल रहे लोकसभा चुनाव में व्यस्त हैं। उनके पास या तो समय नहीं है या पाकिस्तानी मीडिया में फूटे बम में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। 'दुबई अनलॉक्ड' शीर्षक से छपी अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में उन लोगों के नाम उजागर किए गए हैं, जिन्होंने दुबई में संपत्तियां खरीदीं।

कम से कम पाकिस्तान में 'दुबई अनलॉक्ड' प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों में सुर्खियों में है और आने वाले हफ्तों में इस पर बहस होगी। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि ऐसे समय में जब मुल्क आर्थिक संकट से गुजर रहा है और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से दूसरे बेलआउट पैकेज के लिए गुहार लगा रहा है, पाकिस्तानियों ने विदेश में 11 अरब डॉलर की संपत्ति खरीदी है। हालांकि दुबई अनलॉक्ड को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि भारतीय करोड़पतियों ने दुबई में निवेश के मामले में पाकिस्तानियों को पछाड़ दिया है। 29,700 भारतीय नागरिकों ने 17 अरब डॉलर की 35,000 संपत्तियां दुबई में खरीदी हैं।

मरिआना बाबर
वरिष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार

वैसे यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पाकिस्तान के बाहर संपत्ति खरीदना अवैध नहीं है। कई लोगों ने विदेशों में संपत्ति खरीदी है या कर चुकाई गई आय का उपयोग संपत्ति खरीदने में किया है। संपत्ति की वैधता तय करना संबंधित देश के कर अधिकारियों पर निर्भर है। लेकिन पाकिस्तान में सबसे दिलचस्प बात यह है कि कई मामलों में सैन्य और असैन्य अभिजात वर्ग ने अपने आयकर रिटर्न में दुबई की इन संपत्तियों का उल्लेख नहीं किया है, खासकर राजनेता, जिनके आयकर रिटर्न सार्वजनिक हैं।

गौरतलब है कि पाकिस्तान में नागरिकों के बीच भारी असमानता है, जहां उच्च मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के कारण हजारों पाकिस्तानियों के लिए भोजन जुटाना मुश्किल हो रहा है। दूसरी ओर पाकिस्तानी समाज के हर तबके में यह अभिजात वर्ग है, जिसने इतनी संपत्ति जमा कर ली है कि उनके पास दुबई में महल तक हैं।

पाकिस्तान की पिछली सरकारों ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अधिकारियों से इकामा (प्रवास वीजा) हासिल करने वाले पाकिस्तानी नागरिकों की संख्या और वहां किए गए निवेशों के नाम और विवरण पाने की कोशिश की थी, लेकिन यूएई अधिकारी इन विवरणों को साझा करने में अनिच्छुक रहे हैं। एक दर्जन से अधिक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारियों एवं उनके परिजनों सहित बैंकरों एवं नौकरशाहों ने दुबई के महंगे इलाकों में संपत्तियां खरीदी हैं। इनमें जनरल परवेज मुशर्रफ और कई अन्य जनरल शामिल हैं। राजनेताओं में पाकिस्तान तहरीक-ए इंसाफ (पीटीआई) नेता इमरान खान की बहनें, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का परिवार और यहां तक कि मौजूदा गृहमंत्री मोहसिन नकवी और इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की करीबी दोस्त शामिल हैं। जैसा कि एक टिप्पणी में कहा गया है कि एक विकासशील देश, जो आर्थिक पतन के कगार पर है, अंतरराष्ट्रीय ऋणदाताओं और मित्र देशों से भीख मांग रहा है, वहां के नागरिकों का विदेशों में इतनी भारी मात्रा में निवेश आश्चर्यजनक है।

इसके अलावा, पाकिस्तान में इन दिनों मुल्क की ताकतवर सेना और सुप्रीम कोर्ट के बीच तनाव की चर्चा है। पिछले नौ महीने से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद पीटीआई नेता इमरान खान ने हाल ही में कोर्ट में एक पेशी के दौरान संदेश दिया कि वह सैन्य नेताओं से बात करना चाहते हैं। लेकिन उनके संदेश का खंडन किया गया और इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के महानिदेशक ने चुप रहने के लिए कहा। उन्होंने एक मीडिया सम्मेलन में कहा कि अगर इमरान खान बात करना चाहते हैं, तो उन्हें राजनीतिक दलों से संपर्क करना चाहिए, न कि सेना से।

अब इमरान खान जिद पर अड़े हुए हैं और कहते हैं कि वह सेना प्रमुख को पत्र लिखेंगे, लेकिन पत्र का मजमून क्या होगा, इसका खुलासा नहीं करते। वह मुख्य राजनीतिक दलों, जिनमें से कई सरकार में शामिल हैं, से बात करने से इन्कार करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वे 'शक्तिहीन' हैं और असली ताकत रावलपिंडी में है। हालांकि सैन्य जनरल यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी अभी जेल में रहेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने संकेत दिया है कि उन्हें राहत मिलेगी और यहां तक कि उन्हें सभी मामलों में जमानत देकर जेल से बाहर रहने की इजाजत दी जाएगी।

फिलहाल एक बड़े घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को अदियाला जेल से वीडियो लिंक के माध्यम से अपने मामले की पैरवी करने पर मंजूरी दी है। हाल में सभी अदालती मामलों का सुप्रीम कोर्ट से सीधा प्रसारण किया जा रहा है और इससे आम पाकिस्तानी को पहली बार देश की शीर्ष अदालत से लाइव कार्यवाही देखने का मौका मिला है।

पिछले नौ महीनों से इमरान खान की कोई भी तस्वीर सार्वजनिक नहीं की गई है, इसलिए कोई नहीं जानता कि वह बदल गए हैं या नहीं। हालांकि उनके वकीलों, पार्टी नेताओं और परिवार को उनसे मिलने की अनुमति है, लेकिन फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है। यदि मामला अगले सप्ताह टेलीविजन पर लाइव दिखाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट सेना के अलिखित आदेशों की अवहेलना करेगी, जिसने जनता को उनकी कोई भी छवि देखने से मना किया है। इस बीच बिना नेतृत्व के इमरान खान के समर्थकों की रुचि भी घटती जा रही है और हाल ही में जब जुलूस और रैलियां निकालने का आह्वान किया गया, तो उपस्थिति नगण्य थी। पीटीआई के भीतर की अंतर्कलह खुलकर सामने आ गई है और सरकार की सख्ती के कारण कई पीटीआई कार्यकर्ता जेल में हैं और कुछ पर सैन्य मुकदमा चल रहा है, जिससे पार्टी सबसे कमजोर नजर आ रही है।

इस बीच राजनेताओं द्वारा एक गोलमेज सम्मेलन कर मुल्क की अर्थव्यवस्था तथा लगातार आतंकवादी हमलों से संबंधित तात्कालिक चुनौतियों पर चर्चा करने की कोशिश की जा रही है। इस सम्मेलन में कई लोग पीटीआई को लाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां राजनीतिक मतभेदों से परे मुल्क की स्थिरता के लिए एक न्यूनतम सहमति वाला कार्यक्रम तैयार किया जा सके। कई लोग सेना को भी आगाह कर रहे हैं कि उसे पीटीआई के प्रति भी उदार रुख अपनाना होगा और हाल के चुनावों में एक मजबूत वोट बैंक के साथ मजबूत होकर उभरने के बाद उसे जगह देनी होगी। उसे जनादेश से वंचित करने से केवल गतिरोध ही पैदा होगा।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

मालती जोशी
4 जून 1934-15 मई 2024

तीखे विरोध के बजाय शालीनता से रखें बात

यों तो मैंने अपने लेखन में हर वर्ग को समाहित किया है, लेकिन स्त्रियों को लेकर कुछ ज्यादा ही संजीदा रही हूं। मेरी कहानियां स्त्री मन के सूक्ष्म स्पंदनों को व्यक्त कराती हैं। 'पिया पीर न जानी' कहानी को ही लें, इस कहानी की पात्र रमा की दो बेटियां-रसिका और लतिका हैं। बड़ी बेटी रसिका के जन्म पर उसके पिता खुश नहीं थे, क्योंकि उनके मन में पुत्र की चाह थी। आज के समाज की भी कमोबेश यही स्थिति है। हालांकि पहले से नजरिया काफी बदला है। अब तो एक पुत्री का चलन भी बढ़ा है, लेकिन मन में कहीं न कहीं बेटे की इच्छा तो रहती ही है। लड़के का जन्म और जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है, जबकि बेटी के मामले में लोग संकोच करते हैं।

इसी कहानी में आगे, रमा एक दिन बैठी होती है, उसका पति चाय बनाने के लिए कहता है। जवाब में रमा ने कहा, आप ही बना लो। इस पर उसके पति की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। पत्नी के होते हुए पति काम करे, यह कहां बर्दाश्त होता है। भले ही पत्नी बीमार ही क्यों न हो। बेटियों के बड़ी होने पर रमा नौकरी करने का निर्णय लेती है। उसके पति ने रोकना भी चाहा, पर वह रुकी नहीं। दरअसल, स्त्री तभी तक बंधन में है, जब तक कि वह जागरूक होकर अपने अधिकारों की बात न करे। मैं शुरू से ही स्त्री स्वतंत्रता की पक्षधर रही हूं, लेकिन स्वच्छंदता की विरोधी हूं। आजकल महिलाओं और लड़कियों का रहन-सहन कुछ अजीब ही हो गया है। लड़कियां बेढब कपड़े पहनती हैं। ठीक है कि पहनना-ओढ़ना, खाना-पीना निजी पसंद की चीजें हैं, पर समाज का भी ख्याल रखना पड़ता है। तू-तड़ाक में बातें करती हैं। कई टीवी सीरियल में भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आधुनिकता और स्वतंत्रता कहां है? इसे तो स्वच्छंदता ही कहेंगे। स्वतंत्रता के नाम पर हम शालीनता तो नहीं छोड़ सकते।

मैं अपना ही उदाहरण देती हूं। महाराष्ट्रियन समाज में शादी के बाद नाम बदलने की परंपरा है। मेरे पति ने पूछा कि कौन-सा नाम पसंद है। मैंने बड़े ही शालीन ढंग से कहा कि इस नाम में क्या बुराई है। वह भी सहमत हो गए। एक बार मुझसे कहा गया कि जेठ की बेटी का कन्यादान आपको करना है। मुझे लगा कि कन्या दान करने की चीज थोड़े ही है। जेठानी के पास जाकर कहा, मैं कन्यादान नहीं करूंगी। वह मेरी बात से सहमत हो गईं। इसलिए अपनी बात को कहने का सलीका ठीक होना चाहिए। आधुनिक और स्वतंत्र होने का यह मतलब कतई नहीं है कि हम अपने व्यवहार में उग्रता लाएं। मैंने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया और लेखन भी जारी रखा। परिवार पर लेखन को कभी हावी नहीं होने दिया। कई लोग मुझसे कहते भी थे कि आप अपने लेखन में रसोई से बाहर निकलिए। देश में बेरोजगारी समेत कई समस्याएं हैं। जिस घरेलूपन का मुझ पर आरोप लगा, वही मेरी लोकप्रियता का आधार बना।

परिवार में संवाद जरूरी

सूत्र

महिलाएं चाहें तो वे एक साधारण, घरेलू स्त्री रहकर भी अपने विचारों को तराश सकती हैं। अपने मुकाम हासिल कर सकती हैं। आज युवा पीढ़ी व बुजुर्गों के बीच पीढ़ीगत अंतराल (जनरेशन गेप) बढ़ता जा रहा है। आपसी संवाद खत्म होते जा रहे हैं। ऐसे में संवाद के जरिये परिवार में आपसी सामंजस्य बढ़ाने के लिए टूटते रिश्तों और बिखरते परिवारों को फिर से एकसूत्र में पिरोने की जरूरत है।

(प्रख्यात कथाकार मालती जोशी के आत्मकथ्य का एक अंश। उनका हाल ही में निधन हुआ है।)

दूसरा पहलू

सहृदयालोक-लोचन, श्रीरामचरितमानस और *पंचतंत्र* की पांडुलिपियां यूनेस्को की 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर' में शामिल।

मानवता के लिए जरूरी तीन भारतीय ग्रंथ

यूनेस्को ने तीन भारतीय ग्रंथों की दुर्लभ पांडुलिपियों को 'मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर' में जगह दी है। ये ग्रंथ *पंचतंत्र, सहृदयालोक-लोचन* और *श्रीरामचरितमानस* हैं। *पंचतंत्र* और *लोचन* संस्कृत भाषा में लिखे हुए ग्रंथ हैं, जबकि *रामचरितमानस* की भाषा अवधी है। इन तीन ग्रंथों पर अनेक टीका-टिप्पणियां लिखी जा चुकी हैं। पशु-पक्षियों को पात्र बनाकर संस्कृत में लिखा गया *पंचतंत्र* जगविख्यात है। संसार की प्रायः सभी भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। पांच तंत्रों (भागों) में विभक्त इस ग्रंथ की रचना पंडित विष्णु शर्मा ने की थी। संस्कृत साहित्य के इतिहासकारों का मानना है कि इसके मूलरूप का रचना काल ईसा की दूसरी शती से पहले का है। आजकल जो *पंचतंत्र* उपलब्ध है, उसे जैन विद्वान पूर्णभद्र ने 1199 ईस्वी में संपादित किया था। कम लोगों को मालूम है कि सुप्रसिद्ध ध्येय वाक्य 'वसुधैव कुटुम्बकम' *पंचतंत्र* (5.38) का ही हिस्सा है।

शास्त्री कोसलेंद्रदास

कम लोगों को मालूम है कि सुप्रसिद्ध ध्येय वाक्य 'वसुधैव कुटुम्बकम' *पंचतंत्र* (5.38) का ही हिस्सा है। इस ग्रंथ की रचना पं. विष्णु शर्मा ने ईसा की दूसरी शती से पहले की।

कश्मीर के महामाहेश्वर अभिनवगुप्त भारत की शास्त्र परंपरा के शिखर हैं। उन्होंने दार्शनिक, साहित्यिक और तांत्रिक विषयों पर 39 ग्रंथ रचे थे। *सहृदयालोक* ग्रंथ पर उनकी लिखी *लोचन* टीका की शारदा पांडुलिपि भी यूनेस्को की सूची में शामिल है। *सहृदयालोक-लोचन* भारतीय-सौंदर्यशास्त्र के दार्शनिक और काव्यशास्त्रीय सिद्धांतों का प्रतिपादक ग्रंथ है। *सहृदयालोक* ही कालांतर में *ध्वन्यालोक* नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो अलंकार शास्त्र के महान आलोचक कश्मीरी आचार्य आनंदवर्धन की प्रसिद्ध कृति है।

मध्ययुग में जब हिंदू धर्म पर अनेक संकटों के बादल छाए थे, वेदों और शास्त्रों का अध्ययन बहुत कम हो गया था, तब *श्रीरामचरितमानस* ने संपूर्ण उत्तर भारत में हिंदू समाज में नए जीवन का संचार किया।

गोस्वामी तुलसीदास की रचना *श्रीरामचरितमानस* की सचित्र पांडुलिपि भी यूनेस्को के रजिस्टर में शामिल है। मानस की रचना 1575 ईस्वी में अयोध्या में शुरू हुई, लेकिन यह काशी में 1584 ईस्वी में पूरी हुई थी। मध्ययुग में जब हिंदू धर्म पर अनेक संकटों के बादल छाए थे, वेदों और शास्त्रों का अध्ययन बहुत कम हो गया था, तब इस ग्रंथ ने संपूर्ण उत्तर भारत में हिंदू समाज में नए जीवन का संचार किया। लोकभाषा में होने के कारण इसका जनसाधारण पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। आज भी सभी वर्गों के लोग *रामचरितमानस* का पारायण बड़ी श्रद्धा के साथ करते हैं। जन-मन में आज श्रीराम की जो छवि स्थापित है, वह *रामचरितमानस* में वर्णित श्रीराम की ही है। यूनेस्को ने इस बात को स्वीकारा है कि ये रचनाएं विश्व में नैतिकता, संस्कृति और मानवीय मूल्यों के साथ पूरे समाज को आदर्श एवं प्रेम के बंधन से जोड़ने में मदद करती हैं। इसके पीछे दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की भूमिका स्तुत्य है।

आंकड़े

महिला बेरोजगारी घटी

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के मुताबिक, देश में शहरी महिला बेरोजगारी दर में मार्च माह की तिमाही में गिरावट दर्ज की गई है।

अवधि	दर
जनवरी-मार्च 2023	9.2%
अप्रैल-जून 2023	9.1%
जुलाई-सितंबर 2023	8.6%
अक्तूबर-दिसंबर 2023	8.6%
जनवरी-मार्च 2024	8.5%

नोट : पुरुष बेरोजगारी दर 8% से बढ़कर 8.1% हो गई है। | स्रोत : NSSO

जिसे पता हो कि भूख क्या होती है, वह असहायों की सहायता करता है। करुणा तो इंसान का धर्म है। ऐसा नहीं करने वाला इंसानी धर्म नहीं निभाता है।

इंसानी धर्म

अंतर्यात्रा
संकलित

एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती घूमने निकले। माता पार्वती ने एक व्यक्ति को भूख से तड़पते देखा। देखा, तो शंकर जी ने भी, लेकिन वे आगे बढ़ गए। माता पार्वती से रहा नहीं गया। उन्होंने शंकर जी से पूछा कि आपको तो करुणा का सागर कहा जाता है, लेकिन आपने उस व्यक्ति के प्रति थोड़ी सी भी दया नहीं दिखाई!

भगवान बोले, तुम जानती नहीं हो, देवी। मनुष्य की आदत है मन के बहकावे में आ जाना। इस आदमी की सहायता के लिए मैंने कई बार परीक्षा ली है, लेकिन हर बार यह विफल हुआ। कभी मन, तो कभी अपने कर्मों के कारण। पार्वती जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने शंकर जी से एक बार और उसकी सहायता करने का निवेदन किया।

शंकर जी ने एक बार फिर उस आदमी की परीक्षा ली। उन्होंने उस आदमी को खाने के लिए खूब सारा अनाज और फल-फूल दिया। वह आदमी इतना सारा खाना देखकर प्रसन्न हो गया और अपनी भूख शांत की। कुछ ही क्षणों में भगवान शंकर वहां वेश बदल कर एक भूखे के रूप में पहुंचे। पर उस व्यक्ति ने उसकी सहायता न की। देखते ही देखते उसका सारा अनाज गायब हो गया। भगवान शंकर माता पार्वती से बोले, देवी, जिसे पता हो कि भूख क्या होती है, वह असहायों की सहायता करता है। दूसरों के प्रति करुणा तो इंसान का धर्म है। ऐसा नहीं करने वाला इंसानी धर्म नहीं निभाता है। पार्वती जी चुप हो गईं और शंकर जी के साथ आगे बढ़ गईं।

अमर उजाला — पुराने पन्नों से — 01 मई, 1952

पश्चिमी राष्ट्रों को भारत की गंभीर चेतावनी

भारत की पश्चिमी राष्ट्रों को गंभीर चेतावनी; जरा होश में आओ

न्यूयॉर्क टाइम्स का कथन है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजेश्वर दयाल ने दो बड़ी शक्तियों को पत्र लिखा कि यदि उन्होंने अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ा, तो हो सकता है कि संयुक्त राष्ट्र छिन्न-भिन्न हो जाए।

चुनावी मौसम में गन्ना किसानों की गुहार

देश में करीब पांच करोड़ गन्ना उत्पादक किसान परिवार हैं, पर चुनावी मौसम में भी उनकी गुहार कोई नहीं सुनता और न ही बात करता है।

वी.एम. सिंह | कृषि

देश 18वीं लोकसभा के लिए सांसद चुनने में लगा हुआ है। हर पार्टी लुभावने वादों से मतदाताओं को रिझाने में लगी है। मगर कृषि प्रधान इस देश में कोई भी पार्टी किसानों के संकट दूर करने की बात नहीं करती। कुछ पार्टियों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की बात की है, पर फसल की लागत कैसे तय की जाएगी, इस पर कोई चर्चा नहीं है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में करीब पांच करोड़ गन्ना उत्पादक किसान परिवार हैं और देश की आबादी का लगभग पांचवां हिस्सा गन्ना उगाने से जुड़ा है, पर उनकी गुहार कोई नहीं सुनता।

हालांकि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की सभा में प्रधानमंत्री ने गन्ना की बात की और कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ने गन्ना किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, जिससे किसानों का जीवन बहुत बेहतर हो गया। गन्ना किसानों का जो भी भला हुआ है, वह उच्च और सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से हुआ है। उच्चतम

न्यायालय ने गन्ने का रेट (एसएपी) निर्धारित कराने का अधिकार दिया, नहीं तो किसानों को एक तरफ केंद्र द्वारा निर्धारित गन्ना मूल्य मिलता और दूसरी तरफ मिल द्वारा 1996 से 2020 तक दी गई पर्चियों के कारण किसानों को प्रति एकड़ लगभग चार से पांच लाख रुपये मिलों को लौटाना पड़ता, क्योंकि हर पर्ची पर लिखा था कि लेन-देन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर होगा। मिल मालिक राज्य और केंद्र सरकार द्वारा घोषित गन्ना रेट का फर्क हर किसान से वसूलते।

उत्तर प्रदेश में गन्ना रेट की लड़ाई 1996-97 के गन्ना सत्र में शुरू हुई, जब यहां भाजपा व बसपा की सरकार थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिल मालिकों की रिट याचिका में 11 दिसंबर,1996 को आदेश देकर राज्य सरकार को गन्ना का रेट तय करने से मना कर दिया था, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई थी। संविधान पीठ के फैसले से राज्य सरकार को रेट तय करने का अधिकार मिला। संविधान पीठ ने पांच मई, 2004 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ की रिट याचिका 1997 को बरकरार रखा, जिसमें किसानों को विलंब से गन्ना मूल्य का भुगतान किए जाने पर ब्याज देने को कहा था। सरकार ने ब्याज देने का आदेश तो जारी किया, लेकिन जब किसानों को ब्याज का पैसा नहीं मिला, तो किसान मजदूर संगठन ने 2006 में रिट याचिका दाखिल की और किसानों को 1996 से अब तक का ब्याज दिलवाने की गुजारिश की।

किसानों ने अंतर मूल्य देने के लिए रिट याचिका दाखिल की। एक सोसाइटी-एक रेट और एक मिल-एक रेट के आधार पर पेराई सत्र 2009-10 में राज्य सरकार द्वारा घोषित 165 रुपये प्रति क्विंटल के बजाय आखिरी पर्ची पर 260 रुपये मिला। 2011-12 के गन्ना मूल्य एवं विलंब पर ब्याज देने के लिए रिट याचिका 6429/2012 दाखिल हुई थी। एक मई, 2024 को चार याचिकाएं हाईकोर्ट में लगी थीं। सरकार ने अपने जवाब में ब्याज एवं अंतर मूल्य देने से इन्कार कर दिया। मिल मालिकों के अधिवक्ता ने कहा, अगर किसानों को 1996 से ब्याज देंगे, तो मिलें बंद हो जाएंगी। हाईकोर्ट ने सरकार से 1996-97 से आज तक का गन्ना भुगतान, जिसमें विलंब होने पर ब्याज का भुगतान भी शामिल है, का पूरा ब्योरा मांगा है। अगली सुनवाई 27 मई को होगी।

वर्ष 2014 में जब हाईकोर्ट ने भुगतान के विलंब पर ब्याज देने का आदेश दिया, लेकिन मिल मालिकों की अर्जी पर तत्कालीन सरकार ने 2012-15 तक का ब्याज माफ कर दिया था, जिसे हाईकोर्ट ने 2017 में खारिज कर दिया और गन्ना आयुक्त को चार महीने में इसका फैसला करने के लिए कहा। जब गन्ना आयुक्त ने एक साल तक कुछ नहीं किया, तो उच्च न्यायालय ने गन्ना आयुक्त को तलब किया, उसके बाद 2019 में आयुक्त ने फैसला दिया कि घाटे में चल रही मिलें सात फीसदी और बाकी मिलें 12 फीसदी ब्याज देंगी। मगर आज तक किसानों को यह पैसा नहीं मिला है। दिसंबर 2022 में जब हाईकोर्ट ने कड़ा रुख लिया, तो राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे दी। यह अर्जी भी सरकार ने उस याचिका में लगाई, जिसमें सरकार द्वारा गन्ना भुगतान के विलंब पर ब्याज माफ करने के अधिकार को चुनौती दी थी।

राजनीतिक पार्टियां इस तरह वादे करती हैं, पर वास्तविकता कुछ और होती है। क्या किसानों को अंततः अपनी नई पार्टी बनाने से ही न्याय मिलेगा?

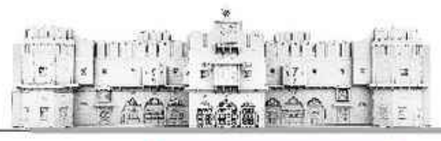

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। -वाल्तेयर

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

बंद नहीं होनी चाहिए काले धन व भ्रष्टाचार पर बहस

पुरानी कहावत है - 'चोर चोरी से जाए, हेराफेरी से न जाए।' ये कहावत किसी और पर लागू होती हो या नहीं लेकिन पाकिस्तान के राजनेताओं और सैन्य अफसरों पर सौ फीसदी लागू होती है। 'दुबई अनलॉक्ड' की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के भ्रष्ट नेताओं और सैन्य अफसरों ने दुबई में बारह अरब डॉलर मूल्य की सम्पत्तियां खरीदी हैं। विदेश में संपत्ति खरीदना अपराध भले ही नहीं हो, पर भारत समेत दुनिया के तमाम दूसरे देशों में 'पैसे वालों' के लिए ऐसा करना सामान्य बात है। ऐसे में जब बात पाकिस्तान की आती है तो वहां के उद्योगपतियों के बजाए नेताओं और सैन्य अफसरों के नाम ही ऐसी सूची में शुमार होते दिखाई देते हैं।

यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि पाकिस्तान लम्बे समय से कंगाली के दौर से गुजर रहा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मेहरबानी से ही वह 'दिवालिया' होने से बचा हुआ है। लेकिन कोई नहीं जानता कि यह मेहरबानी कितने दिन तक रहने वाली है? पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता स्थायी समस्या बन चुकी है। इसके चलते वहां की अर्थव्यवस्था चरमराती जा रही है। ऐसे में देश को चलाने वाले राजनेता और सैन्य अफसर वहां दोनों हाथों से देश को लूट रहे हैं। जो धन देश के काम में आना चाहिए, वह काले धन के रूप में विदेशी बैंकों में जमा हो रहा है। देखा जाए तो यह समस्या अकेले पाकिस्तान की नहीं है। भ्रष्टाचार का बोलबाला कमोबेश सभी जगह है, खास तौर पर एशियाई देशों में। यही कारण है कि इन देशों में अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बढ़ती ही जा रही है। देश तरक्की कर रहे हैं लेकिन इस तरक्की का लाभ सबको बराबरी से नहीं मिल रहा है। भारत में भी काले धन की कहानी दशकों से सुनी और सुनाई जाती रही है। खास बात यह है कि लम्बे अर्से के बाद यह पहला चुनाव है जब काले धन की कहीं चर्चा तक नहीं हो रही। भारत में 'बड़े लोगों' का काला धन स्विस बैंकों में जमा होने को लेकर भी दशकों से राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप लगते रहे हैं। वर्ष 1989 और 2014 के चुनाव तो काले धन और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही लड़े गए थे। लेकिन सब जानते हैं कि इसका नतीजा कुछ नहीं निकला। न तो काला धन ही वापस आ पाया और न ही इसे लेकर आरोप-प्रत्यारोप लगने कम हुए।

जनता भी अब शायद यह समझ चुकी है कि काले धन की समस्या ऐसी लाइलाज बीमारी है जो सिर्फ चुनावों में नेताओं की झोली भरने के काम आती है। यह इसलिए क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए आखिरकार काला धन ही काम आता है। ऐसे में बात सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं है, भारत जैसे देशों को भी काले धन के खात्मे को लेकर ठोस कदम उठाने होंगे।

महाराष्ट्र भाजपा की महायुति तगड़ी या कांग्रेस की महा विकास अघाड़ी ताकतवर

कई फैसले सुनाएगा महाराष्ट्र का मतदाता

■ बालासाहेब ठाकरे की विरासत के हकदार उद्धव या एकनाथ ■ एनसीपी के मालिक चाचा शरद पवार या भतीजा अजित पवार

मुंबई से
दौलत सिंह चौहान

यों तो महाराष्ट्र में इस बार के लोकसभा चुनाव में 6 बड़ी पार्टियां ताल ठोक रही हैं लेकिन गठबंधन की राजनीति ने इन पार्टियों को महायुति और महा विकास अघाड़ी नाम के दो धड़ों में बांट दिया है। इसी का नतीजा था कि महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर जद्दोजहद बहुत लंबी चली। राजनीतिक दलों ने सत्ता के लिए कितने ही समझौते किए, कितनों को चुप बैठाया और कितनों को ही भविष्य में बेहतर अवसरों के आश्वासन दिए। 20 मई को महाराष्ट्र के पांचवें और अंतिम चरण का मतदान होगा और महाराष्ट्र की पहेली का जवाब ईवीएम में बंद हो जाएगा।

महाराष्ट्र में मतदाता इस बार केवल लोकसभा के लिए अपना सदस्य ही नहीं चुन रहे हैं, वे फैसला देंगे कि बालासाहेब ठाकरे की विरासत का असली हकदार उद्धव ठाकरे हैं या एकनाथ शिंदे? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) का मालिक शरद पवार है या अजित पवार? महाराष्ट्र की पसंद भाजपा, शिवसेना शिंदे और अजित पवार की एनसीपी की महायुति है या शिवसेना उद्धव, कांग्रेस और एनसीपी (शरद पवार) का महा विकास अघाड़ी (एमवीए)? राज्य की 48 सीटों में से 35 पर मतदाता अपना फैसला ईवीएम में सुरक्षित कर चुके हैं। शेष 13 सीटों पर अपने फैसले को वे 20 मई को ईवीएम के हवाले करेंगे। सुरक्षित रखा गया फैसला 4 जून को सुनाया जाएगा।

राज्य में वैसे इस बार मुकाबला छह बड़ी पार्टियों के बीच है। महायुति में भाजपा 28, शिवसेना शिंदे 15, एनसीपी अजित पवार 4 और राष्ट्रीय समाज पार्टी 1 सीट पर, तो एमवीए में शिवसेना उद्धव 21, कांग्रेस 17 और एनसीपी शरद पवार 10 सीटों पर मैदान में है। राज्य की 15 सीटों पर कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर है। 13 सीटों पर दोनों शिवसेना आपस में भिड़ रही हैं। आठ सीटों पर भाजपा और शरद पवार की एनसीपी आमने-सामने हैं। पांच सीटों पर भाजपा की शिवसेना उद्धव से टक्कर है। दो सीटों पर कांग्रेस का मुकाबला शिवसेना शिंदे से है। तीन सीटों पर एनसीपी अजित पवार के सामने शिवसेना उद्धव है। सभी सीटों पर गठबंधन हो जाने से भाजपा नीत महायुति और कांग्रेस नीत एमवीए में अपवाद को छोड़ दें तो सभी सीटों पर दिलचस्प टक्कर है। दोनों गठबंधन एकजुट होकर एक-दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं, अंदरखाने कहीं-कहीं मतभेद के चलते कुछ सीटों पर भितरघात की आशंका जरूर है।

तय होगा असली एनसीपी किसकी

बारामती और शिरूर में एनसीपी शरद पवार और एनसीपी अजित पवार के बीच सीधी टक्कर है और इन दोनों सीटों के नतीजे से स्पष्ट होगा कि चाचा भतीजे में से जनता किसके साथ है। बारामती में जहां शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार यानी ननद-भोजाई के बीच कड़ी टक्कर है। धुआंधार प्रचार के बावजूद 2019 के मुकाबले इस बार 2.2% कम मतदान हुआ है। इसी तरह शिरूर में शरद पवार गुट से सांसद अमोल काल्हे और अजित पवार गुट से अलघराव शिवाजी दत्तात्रेय मैदान में हैं। काल्हे ने 2019 का चुनाव 58 हजार वोटों के अंतर से शिवसेना के अलघराव शिवाजी दत्तात्रेय को हरा कर जीता था। इस बार दत्तात्रेय एनसीपी अजित गुट के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। काल्हे का चुनाव चिह्न घड़ी की जगह तुरही बजाता व्यक्ति है, तो दत्तात्रेय का धनुष बाण की जगह घड़ी।

मतदाता बताएगा शिवसेना का मालिक कौन

सबसे दिलचस्प मुकाबला उन 13 सीटों पर है, जहां शिवसेना शिंदे और शिवसेना उद्धव के बीच सीधी टक्कर है। इन 13 में कुछ सीटें ऐसी हैं जो बंटवारे में शिवसेना शिंदे को मिल जाने से भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं का विरोध सामने आया तो कुछ ऐसी हैं जिनमें कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच विवाद की स्थितियां बनीं। हालांकि ऊपरी तौर पर ऐसी सीटों पर शांति का दावा है, लेकिन अंदरखाने काफी खदबदाहट है। सबसे तगड़ा मुकाबला कल्याण में है जहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बेटे डॉ. श्रीकांत शिंदे इस बार महायुति से किस्मत आजमा रहे हैं और शिवसेना उद्धव की वैशाली राणे उन्हें कड़ी टक्कर दे रही हैं।

48 सीटों का लेखा-जोखा

- **13 सीटें जहां शिवसेना शिंदे बनाम शिवसेना उद्धव:** मुंबई दक्षिण, मुंबई उत्तर-पश्चिम, मुंबई दक्षिण-मध्य, ठाणे, कल्याण, हातकणंगले, हिंगोली, यवतमाल-वाशिम, शिरडी, बुलढाणा, मावल, संभाजीनगर, और नासिक। इनमें से मुंबई महानगर की 5 सीटें मुंबई दक्षिण, मुंबई उत्तर-पश्चिम, मुंबई दक्षिण-मध्य, कल्याण और ठाणे हैं।
- **2 सीटों पर एनसीपी शरद पवार बनाम एनसीपी अजित पवार:** बारामती और शिरूर
- **इन 15 सीटों पर भाजपा बनाम कांग्रेस:** मुंबई उत्तर मध्य, मुंबई उत्तर, नंदुरबार, धुले, अकोला, अमरावती, नागपुर, भंडारा-गोंदिया, गढ़चिरोली-चिमूर, चंद्रपुर, नांदेड़, जालना, पुणे, लातूर और सोलापुर।
- **इन 7 सीटों पर भाजपा बनाम एनसीपी शरद पवार:** अहमदनगर, दिंडोरी, बीड़, माढ़ा, रावेर, वर्धा और सतारा।
- **इन 5 सीटों पर भाजपा बनाम शिवसेना उद्धव:** पालघर, मुंबई उत्तर-पूर्व, रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग, सांगली और जलगांव।
- **इन 4 सीटों पर एनसीपी अजित पवार बनाम शिवसेना उद्धव:** धाराशिव (उस्मानाबाद), परभणी, रायगड और भिवंडी।
- **इन 2 सीटों पर कांग्रेस बनाम एनसीपी अजित पवार:** कोल्हापुर और रामटेक।

कम मतदान प्रतिशत पर बड़ी उलझन

लोकसभा चुनाव के नतीजे इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए संकेत और महाराष्ट्र की आगे की राजनीति का रास्ता भी निर्धारित करेंगे। हैरत की बात तो यह है कि इतने अहम फैसले वाले इस चुनाव को लेकर भी मतदाताओं में कोई उत्साह नहीं है। अब तक हो चुके चार चरणों का मतदान 2019 के चुनाव से औसतन 4 से 5 फीसदी तक कम हुआ है। दोनों गठबंधन के नेता दावे भले ही कुछ भी करें, असल में नतीजों का अनुमान लगाने में राजनीतिक दलों को ही नहीं, सेफोलॉजिस्ट्स तक को पसीने आ रहे हैं।

मुंबई महानगर में क्या होगा

पांचवां चरण महाराष्ट्र में अंतिम चरण होगा। इसमें मुंबई महानगर की छह, उपनगरीय इलाकों की 3 सीटों समेत आसपास की कुल 13 सीटों पर मतदान होगा। राज्य में चार चरणों में मतदान का जो ट्रेंड रहा है, उसके अनुसार शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा कम वोट पड़े हैं। ऐसे में यह एक पहेली ही है कि मुंबई महानगर की 6 और उपनगरों की 3 सीटों वाली बची हुई 13 सीटों में मतदान का क्या हाल होगा, जहां 70 से 75 फीसदी मतदाता शहरी हैं। ऐसे में महायुति ही नहीं, महा विकास अघाड़ी के घटक दलों में भी चिंता व्याप्त है।

भुखमरी और कुपोषण

पौष्टिक आहार तक बनानी होगी हर व्यक्ति की पहुंच

विश्व में अरबपतियों की बढ़ती संख्या के बीच भुखमरी के आंकड़े मुंह चिढ़ाते नजर आते हैं। भारत भी इसका अपवाद नहीं है। हर वर्ष इंटरनेशनल फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व के विभिन्न देशों को शामिल करते हुए भुखमरी सूचकांक तैयार किया जाता है। इससे संबद्ध नवीनतम रिपोर्ट में बतलाया गया है कि वर्ष 2022-23 के बीच पूरे विश्व में भूख से पीड़ितों की संख्या 69 करोड़ से बढ़कर 78.3 करोड़ हो गई। इस प्रकार भूखे व्यक्तियों की संख्या में 9 करोड़ की वृद्धि हुई। कुल मिलाकर यह ज्ञात हुआ कि 2023 में विश्व की लगभग दस प्रतिशत जनसंख्या भुखमरी से पीड़ित थी।

सी. एस. बरला
कृषि अर्थशास्त्री, विश्व बैंक व योजना आयोग से संबद्ध रह चुके हैं
@patrika.com

पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार भी देश के लोगों के लिए खाद्यान्न की निशुल्क या रियायती वितरण की व्यवस्था कर रही है। वर्तमान में लगभग 80 करोड़ लोगों को निशुल्क अनाज दिया जा रहा है। इसके बावजूद उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 24 करोड़ लोग भूख से पीड़ित माने गए हैं। इसी कारण 'हंगर इंडेक्स' (भुखमरी सूचकांक) में भारत का स्थान 111वां माना गया है। इस दृष्टि से भारत की तुलना में श्रीलंका, नेपाल, बेलारूस, म्यांमार तथा चीन बेहतर स्थिति में हैं, पर यदि भुखमरी के साथ भोजन में पौष्टिकता की कमी को भी जोड़ लिया जाए तो, जैसा कि विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन ने कहा है, भारत सहित सभी विकासशील देशों की स्थिति काफी चिंताजनक है। इस संस्था का दावा है कि भारत में ही लगभग 30 प्रतिशत जिलों में जिला स्तर पर पौष्टिक तत्व भोजन में प्राप्त नहीं होते। आदिवासियों, दलितों तथा अधिक गरीबी वाले क्षेत्रों में भुखमरी के साथ पौष्टिकता का भी अभाव है।

विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, अपर्याप्त भोजन तथा पौष्टिकता के अभाव में भारत के बच्चों में कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। बड़ी संख्या में बच्चों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। जाहिर है कि दूध-फल-सब्जियों तक भी उनकी पहुंच नहीं होती। कुल मिलाकर, वे स्वास्थ्य की दृष्टि से कमजोर रहते हैं तथा आसानी से रोग के शिकार हो जाते हैं। भारत, दूध व दालों में विश्व का एक अग्रणी देश है लेकिन ये दोनों ही चीजें आम व्यक्ति की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। विशेष रूप से बच्चों को प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि 2029 तक देश के 80 करोड़ लोगों को निशुल्क अनाज का वितरण जारी रहेगा। यह निर्णय भुखमरी की समस्या को समाप्त करने में सहायक होगा, ऐसी आशा है। लेकिन एक ओर वितरित किए जाने वाले ऐसे अनाज की अच्छी गुणवत्ता हमें सुनिश्चित करनी होगी तो दूसरी ओर सरकार के लिए यह देखना भी जरूरी होगा कि आम जनता को पौष्टिक तत्वों वाला आहार वांछित मात्रा में मिले। वस्तुतः व्यक्ति की लम्बी आयु तथा उत्तम कार्यकुशलता के लिए यह जरूरी है कि उसे बाल्यकाल से ही पर्याप्त भोजन मिले और उसे पौष्टिक तत्व भी वांछित मात्रा में प्राप्त हों। इसके लिए अनाज के साथ दाल, दूध तथा विटामिन वाला आहार भी आवश्यक है। हमारी नीतियों में एक पैकेज होना जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ी स्वस्थ, निरोगी तथा गुणवान हो।

कमल खिलावन | **POLI नोक-झोंक** | पंजा सिंह

डिबेट जब होगी तब होगी, अभी तो मुशायरा लीजिए

*(**अमरीका** की तर्ज पर डिबेट कर लो, ऐसी चुनौतियां सुनने में आईं। डिबेट जब होगी तब होगी। अभी तो मुशायरा हो रहा है। कमल खिलावन और पंजा सिंह ने एक-दूसरे को लाइव मुशायरे का चैलेंज दे दिया। तालियां बजाने के लिए टीपू भैया, तेजू और केजू भैया भी हैं, कोरस में। आप और हम सामने, दर्शक दीर्घा में)*

कमल खिलावन: *महफिल में आए हैं लोग कैसे-कैसे अमेठी से भागे, वायनाड़ होते पहुंचे रायबरेली, ऐसे कैसे?*

पंजा सिंह: *न इधर घुमाओ, न उधर घुमाओ... किया क्या जुमले के अलावा, आज ये बताओ?*

कमल खिलावन: *दाढ़ी बनवाते हो, कभी गोश्त पकाते हो पोलेटिशियन हो भैया, यू-ट्यूबर क्यों बन जाते हो?*

पंजा सिंह: *छुक-छुक बेची, चीलगाड़ी बेची, बेची तुमने नाव, अबके आ गए तुम वापस तो नहीं होने दोगे चुनाव...*

कमल खिलावन: *छोटा भीम, मिक्की माउस और देखो शिनचैन सीट क्यों नहीं दे रही तुमको, बंगाल वाली बहन...*

पंजा सिंह: *डेमोक्रेसी की बजा दी है तुमने बैंड पूरी की पूरी, कभी तोड़ते हो एमएलए तो कभी कर देते हो राज्य सरकार अधूरी...*

कमल खिलावन: *देखो जरा पाक में, हो रही भारत की जय-जयकार, तुमने दे दिया मौका बदजुबानी से, अब होगा चूड़ी कारोबार...*

पंजा सिंह: *हमारे बयानवीरों की कहें क्या, कर देते हैं कूड़ा चुनाव में, न जाने कहां की लाए चूड़ी, कहां का लाए चूड़ा*

(तेजू भैया कान में फुसफुसाते हैं... ये तो अपने ही खिलाफ बोल दिया)

कमल खिलावन: *पीछे वाले तुम्हारे पीछे नहीं रह पाएंगे, ये जेल से आए हैं तुम्हें पीछे धकेल कर फिर जेल चले जाएंगे।*

पंजा सिंह: *गठबंधन है हमारा, इस पर है नाज, मिलकर दिखाएंगे तुम्हें, क्या हैं हम, ये आज*

कमल खिलावन: *खुद की बात करो, कुछ तो खुद्दारी रखो, अपनी उम्र से सीट न ज्यादा ला पाओगे, दिमाग में ये धरो।*

पंजा सिंह: *4 जून को आ रहे हैं बस हम, हम ही हम, उठा लो अपना झोला, हिमालय पर चले जाना तुम।*

कमल खिलावन: *चुनाव है ये देश के, कोई नानी का घर नहीं, आ रहे हैं हम ही फिर से, नहीं जा रहे और कहीं।*

(तेज आंधी चलती है। स्टेज पर पंजा सिंह के हाथ से हिंगलिश में लिखीं पर्चियां उड़ गईं। वो खामोश। हवा इतनी तेज कि टेलीप्रोम्प्टर भी गिर गए, वो भी खामोश, दर्शक फिर से मोबाइल पर रील स्क्रॉल करने में व्यस्त, पांचवें चरण के चुनाव तक।)

- सुप्रिया शर्मा

अमेठी संसदीय क्षेत्र: कांग्रेस ने खेला केएल पर दांव, पर चुनाव अब भी राहुल बनाम स्मृति

गांधी परिवार ने दूरी बनाई, फिर भी सबसे बड़ी लड़ाई

अमेठी से
विकास जैन

अब तक के सभी लोकसभा चुनावों में सबसे चर्चित सीट रहने वाली अमेठी में कुछ तो खास बात होगी ही..। इसी सोच के साथ रायबरेली से अमेठी की ओर रवाना हुआ। करीब 30 से 40 किलोमीटर की दूरी तय करते ही यह संसदीय क्षेत्र शुरू हो गया। जैसे-जैसे आगे बढ़ा, यह भी साफ होता गया कि राजनीतिक दृष्टि से यह क्षेत्र भले ही हॉट सीट हो, पर विकास के मामले में सामान्य ही है। देश के किसी भी सामान्य संसदीय क्षेत्र की तुलना में इस क्षेत्र में कोई बेहतर सुविधाएं नजर नहीं आईं।

अमेठी संसदीय क्षेत्र की चुनावी यात्रा के दौरान यह बात भी खुलकर सामने आई कि गांधी परिवार में पिछली हार की इतनी टीस है कि इस बार इस परिवार के नजदीकी किशोरीलाल शर्मा को चुनाव जिताने के लिए कांग्रेस के कई दिग्गज यहां डेरा डाले हुए हैं। कांग्रेस ने गांधी परिवार के नजदीकी और करीब 40 वर्ष से यहां सक्रिय किशोरीलाल शर्मा को प्रत्याशी बनाकर बड़ा दांव खेला है। वे यहां 'इंडिया' गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी हैं। उनका मुकाबला भाजपा की स्मृति ईरानी से है।

माना जा रहा है कि इस बार अमेठी का मुकाबला पिछली बार से भी रोचक और नजदीकी होगा। यहां 20 मई को मतदान होना है। अमेठी लोकसभा सीट से स्मृति ईरानी तीसरी बार चुनाव मैदान में हैं तो किशोरीलाल शर्मा के लिए यह पहली बार है। बातचीत में लोग कह रहे हैं कि अंदरूनी तौर पर लड़ाई तो अब भी राहुल बनाम स्मृति ही है। कांग्रेस ने यहां पूरा जोर लगा रखा है। कांग्रेस यहां भाजपा खेमे में सेंध लगाकर समीकरण अपने पक्ष में करने में लगी है।

अमेठी की गौरीगंज रोड पर 'पत्रिका' से बातचीत के दौरान स्थानीय लोग।

स्मृति और केएल, दोनों का जुड़ाव अमेठी से

इस सीट पर गांधी परिवार भले ही सीधा चुनाव न लड़ रहा हो, पर कांग्रेस उम्मीदवार किशोरीलाल शर्मा गांधी परिवार के सबसे नजदीकी कार्यकर्ताओं में से एक हैं। वह राजीव गांधी के करीबी थे और 1980 के दशक के पूर्वार्द्ध में उन्हीं के साथ इस क्षेत्र में पहली बार आए थे। स्मृति ईरानी भी एक चुनाव हारने के बाद दूसरे चुनाव में राहुल गांधी को शिकस्त देकर अलग पहचान बना चुकी हैं। क्षेत्र में एक दशक से सक्रिय हैं व मतदाताओं में उनकी पकड़ बन चुकी है। ऐसे में यहां इस बार मुकाबला दिलचस्प होगा। 2019 के चुनाव में सपा-बसपा गठबंधन कर चुनाव में उतरे थे, इस बार सपा का गठबंधन कांग्रेस के साथ है, तो बसपा से नन्हे सिंह चौहान ताल ठोक रहे हैं।

सड़क ने हिलाया पेट का पानी

करीब 60 किलोमीटर का सफर तय करने के दौरान मुख्य सड़क से सटे कई रास्तों पर कई जगह सड़क टूटी मिली। पेट का पानी भी हिल गया। पता चला कि पांच वर्ष पहले भी यहां हालत ऐसी ही थी। अमेठी की गौरीगंज रोड पर राशन की दुकान पर कई लोग थे। रमेश पांडेय, अशोक कुमार और विजय सहित कई महिलाओं से भी बात हुई। सभी का कहना था कि इस बार लड़ाई बराबर की है। सभाओं और दौरों से इस बार माहौल ज्यादा बन रहा है। गांधी परिवार के अब तक के राज और पांच साल के भाजपा राज की तुलना करते हुए सभी का कहना था कि अच्छे-बुरे पहलू दोनों के हैं। मुंशीगंज रोड के सागर तिराहे पर राममिलन ने कहा कि यहां बदलाव हो चुका है, जो इस बार भी नहीं बदलेगा। अमेठी के मुख्य बाजार में वी.आर. मौर्य और सूरज ने बताया कि राहुल भले ही पिछली बार हार चुके हों और चुनाव नहीं लड़ रहे, पर उन्हें यहां आना चाहिए। वह यहां आ ही नहीं रहे हैं। यह सीट सुपर पीएम सीट भले ही रही हो, पर क्षेत्र को कुछ विशेष कभी नहीं मिला।

नौ बार जीता गांधी परिवार

गांधी परिवार के प्रति आस्था रायबरेली की तरह ही इस क्षेत्र के मतदाताओं में भी प्रगाढ़ है। 1967 से लेकर 2019 तक हुए चुनाव में तीन बार के अलावा हर बार गांधी परिवार या कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। 1981 से 1991 तक यहां से राजीव गांधी लगातार चार बार जीते। 1999 में सोनिया गांधी और उसके बाद 2004 से 2014 तक राहुल गांधी चुनाव जीतते रहे। पिछले चुनाव में स्मृति ईरानी निर्वाचित हुईं। गत चुनाव में यहां स्मृति का 49.71 और राहुल का 43.84 प्रतिशत वोट शेयर रहा। यहां अब तक के 16 चुनाव में नौ बार गांधी परिवार जीता है।

खोई प्रतिष्ठा के लिए मशक्कत

यह सीट कांग्रेस के लिए सबसे प्रतिष्ठा वाली सीट है। यही कारण है कि कई दिग्गज नेता यहां डेरा डाले हुए हैं। राजस्थान कांग्रेस की एक बड़ी टीम पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में यहां मौजूद है। वह इस क्षेत्र के लिए कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। सचिन पायलट भी रायबरेली में सभाएं कर चुके हैं। रायबरेली से अमेठी तक राजस्थान के पूर्व मंत्री रघु शर्मा, विधायक रफीक खान व धर्मेन्द्र राठौड़ और दानिश अबरार भी लगे हुए हैं। अमेठी में राजस्थान नंबर की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती नजर आ रही हैं।

अमेठी का समीकरण

अमेठी लोकसभा सीट में शामिल तिलोई, जगदीशपुर, अमेठी और गौरीगंज विधानसभा सीट अमेठी जिले की हैं, जबकि सलोन विधानसभा सीट रायबरेली जिले में पड़ती है। तीन विधानसभा सीटें भाजपा और दो विधानसभा सीटें सपा के पास हैं। ओबीसी, मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण, राजपूत और यादव मतदाता अच्छी संख्या में हैं।

आज का सवाल

उंगली की जगह जीभ की सर्जरी जैसी लापरवाही के मामले कैसे रोके जा सकते हैं?

ईमेल करें: edit@epatrika.com

नई तकनीक का हो प्रयोग

खनन क्षेत्र मे हादसों को रोकने के लिए खनन में मानव श्रम को कम करते हुए रोबोट या अन्य तकनीक का सहारा लेना चाहिए। जो व्यक्ति खनन क्षेत्र से जुड़े हैं, उनकी सुरक्षा के पूरे उपाय होने चाहिए। **-कार्तिक प्रजापत,** जयपुर

सख्ती से लागू हों सुरक्षा मानक

सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन होना चाहिए। नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक व सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग सुनिश्चित हो। संचार प्रणाली बेहतर बने। श्रमिकों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाए। **-संजय माकोड़े,** बैतूल

अवैध खनन पर लगे प्रतिबंध

रिहायशी इलाकों में अवैध खनन पर तत्काल प्रतिबंध लगना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए खतरा पैदा करने वाले खनन पर भी रोक लगे। **-रेखा उपाध्याय,** मनेंद्रगढ़ एमसीबी (छ.ग.)

प्रकृति से न हो खिलवाड़

खनन क्षेत्रों में हादसों का सबसे बड़ा कारण अवैध खनन है। लाइसेंसधारी अक्सर सीमाएं तोड़कर प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। इनमें नेताओं-अधिकारियों भी शामिल रहते हैं। **-हरिप्रसाद चौरसिया,** देवास (मप्र)

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, 'खनन क्षेत्र में हादसों को कैसे रोका जा सकता है?' पाठकों की प्रतिक्रियाएं ऑनलाइन भी देखें।

इसे स्कैन करें

rb.gy/lw935a

कल्पमेधा

क्रोध वह तेजाब है जो किसी भी चीज पर डाले जाने से ज्यादा उस पात्र को अधिक हानि पहुंचा सकता है, जिसमे वह रखा हुआ है।

- मार्क ट्वेन

विस्थापन का दंश

दुनिया भर में हर वर्ष लाखों लोग विस्थापित होते हैं और उन्हें अकथनीय मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मगर इक्कीसवीं सदी का सफर तय करते विश्व में भी ऐसी ठोस पहलकदमी नहीं दिखाई देती जिसमें अपनी जड़ों से उखाड़ दिए गए लोगों के दुख पर गौर किया जा सके और एक दीर्घकालिक समाधान का रास्ता तैयार हो। यह बेवजह नहीं है कि आज भी अलग-अलग देशों से बड़ी संख्या में लोग अपना घर-बार छोड़ कर दूसरी जगहों पर जाने पर मजबूर कर दिए जाते हैं। अक्सर आने वाली रपटों में इस समस्या की जटिलताओं की ओर ध्यान दिलाया जाता रहा है, लेकिन अब तक विस्थापन का सिलसिला बदस्तूर कायम है। अब जिनेवा स्थित आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र यानी आइडीएमसी की ताजा रपट में यह दावा किया गया है कि सन 2023 में दक्षिण एशिया में कुल उनहत्तर हजार लोगों को विस्थापन का दंश झेलना पड़ा। इसमें अकेले मणिपुर से सड़सठ हजार लोग विस्थापित हुए। यानी दक्षिण एशिया के सभी देशों में जितने लोगों को अपने ठौर से उजड़ना पड़ा, उसमें सत्तानबे फीसद लोग मणिपुर के हैं।

गौरतलब है कि सन 2018 के बाद यानी पिछले पांच वर्षों में भारत में हुआ यह सबसे बड़ा विस्थापन है। देश के अन्य इलाकों में जहां बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदा और रोजी-रोटी जैसी वजहों से लोगों को दूसरी जगहों की ओर अपने जीने के रास्ते की खोज में निकलना पड़ा, वहीं मणिपुर में हुई व्यापक हिंसा ने वहां हजारों लोगों को विस्थापित होने पर मजबूर कर दिया। आइडीएमसी ने अपनी रपट में इस बात का उल्लेख किया है कि मार्च 2023 में मणिपुर उच्च न्यायालय ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के संदर्भ में जो रुख जाहिर किया था, उसके बाद राज्य के बड़े हिस्से में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। इसमें करीब दो सौ लोगों की जान जा चुकी है और इसकी वजह से हजारों लोगों को अपना घर छोड़ कर राहत शिविर या दूसरों जगहों पर शरण लेना पड़ा। आज भी वहां स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है। जाहिर है, एक साधारण विवाद से जो हालात पैदा हुए, उसके एक वर्ष बीत जाने के बावजूद उसे संभालने में सरकार अब तक नाकाम है और इसका खमियाजा हिंसक संघर्ष की वजह से बेठौर हुए लोगों को भुगतना पड़ रहा है।

विश्व भर में ऐसे लोगों की एक बड़ी संख्या है, जो बहुत मुश्किल से किसी जगह पर अपना ठिकाना और उनमें से कुछ लोग घर बनाते हैं। मगर इससे ज्यादा तकलीफदेह और क्या हो सकता है कि उन्हें वैसी वजहों के लिए उस जगह को छोड़ कर कहीं और जाना पड़ जाता है, जिसके लिए वे जिम्मेदार नहीं होते हैं। यही नहीं, अपने ठौर से वंचित लोग जब कहीं और जीने की जगह ढूंढ़ने निकलते हैं तो सभ्य कही जाने वाली व्यवस्थाओं वाले लोकतांत्रिक देशों में भी उनके लिए टिकना आसान नहीं होता। इससे अफसोसनाक और क्या होगा कि विश्व के आधुनिक होने के दावों के बीच पिछले दो वर्षों में संघर्ष और हिंसा की वजह से अपना घर छोड़ने पर मजबूर लोगों की संख्या में चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है। दुनिया के जिन हिस्सों में हालात में सुधार हो रहे थे, अब वहां भी यह समस्या अपने पांव पसार रही है। हिंसा या संघर्षों को रोकने और शांति की स्थापना करने में नाकामी दरअसल विश्व भर में अशांत इलाकों में सक्षम देशों की कूटनीतिक और रणनीतिक कवायदों के महज दिखावा होने को ही दर्शाती है।

गर्मी का कहर

पिछले कुछ दशकों से जलवायु में असंतुलन और बढ़ते तापमान की वजह से उपजी स्थितियों से जैसे हालात बन रहे हैं, उसमें मौसम के सामान्य रहने को लेकर एक आशंका बनी रहती है। दुनिया भर के जलवायु में हो रहे बदलाव का असर लगभग सभी मौसम में देखने को मिल रहा है, जिसमें ठंड, गर्मी या बरसात में एक विचित्र प्रकार की अनियमितता दिख रही है और इसकी मार समूचे जीव-जगत पर पड़ रही है। गौरतलब है कि आस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किए गए एक अध्ययन में यह तथ्य सामने आया है कि लू से जुड़ी मौतें गर्मी से मरने वालों की कुल संख्या का लगभग एक तिहाई और विश्व भर में हुई कुल मौतों का एक फीसद है। पिछले तीस वर्षों के आंकड़ों के अध्ययन के नतीजों में बताया गया है कि हर वर्ष गर्मी में एक लाख तिरपन हजार अतिरिक्त लोगों की जान चली जाती है, जिसमें से करीब आधी मौतें एशिया में और तीस फीसद से ज्यादा यूरोप में होती हैं। अकेले भारत में हर वर्ष तीस हजार से ज्यादा लोग लू की वजह से जान गंवा बैठते हैं।

दरअसल, गर्मी में लू तो बरसात में बिजली गिरने की वजह से अब जितने लोगों की जान जा रही है, उसमें साफ है कि मौसम के बदलते मिजाज और उसमें बचाव के इंतजामों को लेकर एक प्रकार की उदासीनता है। जबकि भीषण गर्मी के दौरान चेतावनी प्रणाली, शहरी नियोजन और हरित संरचना, सामाजिक सहायता कार्यक्रम, बिगड़े मौसम के अनुकूल स्वास्थ्य सेवाएं, जागरूकता के साथ सामुदायिक सहभागिता से जुड़े कार्यक्रमों के जरिए आम लोगों को बचाव को लेकर सजग किया जा सकता है। संसाधनों से लैस और वंचित समुदायों के बीच असमानताओं को कम करके दीर्घकालिक रणनीतियों को लागू करना भी एक जरूरी कदम होगा। अफसोस की बात है कि तापमान में अप्रत्याशित बदलाव की वजह से होने वाली मौतों को प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में मान लिए जाने से बचाव के उपायों को लेकर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा पाता। जरूरत इस बात की है कि जिस रफ्तार से मौसम के मिजाज में बदलाव आ रहा है और वह मनुष्य सहित समूचे जीव-जगत और पर्यावरण के लिए घातक साबित हो रहा है, उसे देखते हुए व्यापक दृष्टिकोण के साथ एक समग्र रणनीति बनाई जाए।

भारत-ईरान संबंधों का भविष्य

अब चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत और ईरान के बीच समझौता पूर्ण हो गया है। इसे सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से भारत के लिए महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके कई भू-राजनीतिक कारण हैं।

ब्रह्मदीप अलूने

ईरान, यूरेशिया और हिंद महासागर के मध्य एक प्राकृतिक प्रवेश द्वार है, जिससें भारत, रूस और यूरोप के बाजारों तक आसानी से पहुंच सकता है। एशिया महाद्वीप की दो महाशक्तियों, भारत और चीन, की सामरिक प्रतिस्पर्धा समुद्री परिवहन और पारगमन की रणनीति पर देखी जा सकती है। चीन की 'पर्ल आफ स्प्रिंग' के जाल को भेदने के तौर पर चाबहार बंदरगाह के रूप में अंततः भारत को सफलता मिल गई है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में ईरान की स्थिति और कूटनीतिक दांव-पेंचों के बीच यह कहा जा सकता है कि भारत की सामरिक और आर्थिक क्षमताओं की असली परीक्षा भी अब शुरू हो रही है।

दरअसल, ईरान एक ऐसा देश है, जो राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक प्रतिबंधों का सामना करते हुए अमेरिका विरोधी खेमों से जुड़ने के लिए हमेशा तैयार नजर आता है। 2021 में चीन ईरान के बीच रणनीतिक रिश्तों की शुरुआत हो या मध्यपूर्व में 'प्राक्सी' समूहों को मजबूत बनाए रखने की कोशिश, अमेरिका की चुनौतियां ईरान ने बढ़ाई हैं। इस बीच भारत अमेरिकी सहयोग बढ़ा है, हिंद महासागर से लेकर लद्दाख तक, चीन से निपटने के लिए भारत को अमेरिका की जरूरत है, ऐसे में भारत ईरान के संबंधों के दीर्घकालीन समय तक सामान्य बने रहने को लेकर गहरी आशंकाएं हैं।

ईरान चीन की 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' का सदस्य है और वह इसे पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु होने की ऐतिहासिक स्थिति को पुनः स्थापित करने के अवसर के रूप में देखता है। ईरान में परिवहन, बंदरगाहों, ऊर्जा, उद्योग और सेवाओं की विभिन्न परियोजनाओं में चीन अरबों डालर का निवेश कर रहा है तथा वह ईरान का एक मजबूत आर्थिक सहयोगी बनकर उभरा है। ईरान के पास विश्व में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार मौजूद है। वह अपना तेल बेचने के लिए भारत को एक बड़े बाजार के रूप में देखता है। भौगोलिक रूप से दोनों देश निकट हैं, जो इसकी लागत को कम करता है और इससे ईरान की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को सहारा मिल सकता है। मगर भारत वैश्विक नियमों में बंधा हुआ एक लोकतांत्रिक और जिम्मेदार देश है, इसलिए भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों को देखते हुए पिछले चार वर्षों से ईरानी तेल का आयात बंद कर दिया है। इससे भारत की ऊर्जा जरूरतें प्रभावित हुई, वहीं ईरान ने भी इसे ठीक नहीं समझा।

अब चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत और ईरान के बीच समझौता पूर्ण हो गया है, इसे सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से भारत के लिए महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके कई भू-राजनीतिक कारण हैं। चाबहार बंदरगाह परियोजना का विकास भारत ईरान की एक प्रमुख परियोजना है। भारत, ईरान और रूस के मध्य 16 मई 2002 को इस संबंध में एक समझौता हुआ था, जिसके द्वारा ईरान होकर मध्य एशियाई राज्यों तक निर्यात करने के लिए एक उत्तर दक्षिण गलियारे का निर्माण किया जा सके। ईरान में कैस्पियन सागर पर बने अस्तारा, बंदर अंजाली और अमीराबाद बंदरगाह रूस के अस्ताराखान बंदरगाह से बखूबी जुड़े हैं। अरब सागर के तट पर कराची बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह और चाबहार भी हैं। ओमान की खाड़ी में स्थित चाबहार बंदरगाह अब भारत के कब्जे में है। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित हो गया है कि ईरान

के दक्षिण समुद्र तट को भारत के पश्चिमी समुद्र तट से जोड़ने का रणनीतिक दांव कामयाब हो गया है। यहीं नहीं, इस परियोजना में अफगानिस्तान का सहयोग सामरिक संतुलन बनाने में भी मददगार होगा।

ईरान भी इस नए मार्ग को लेकर काफी उत्साहित है, क्योंकि भारत से जो माल पहले पाकिस्तान होते हुए सीधे अफगानिस्तान जाता था वह अब जहाजों के जरिए पहले ईरान के चाबहार बंदरगाह पर जाएगा और फिर वहां से ट्रकों द्वारा अफगानिस्तान पहुंचेगा। चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत अफगानिस्तान के साथ ही मध्य एशिया, रूस, पीटर्सबर्ग, मध्य एशिया का 'लैंड लाक्ड' इलाके तक जुड़ जाएगा। इस प्रकार इस बंदरगाह से भारत की सामरिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक स्थिति बेहद मजबूत होने की संभावना बढ़ेगी। चाबहार बंदरगाह भारत की आर्थिक ताकत बनने की आशा के प्रतीक के तौर पर भी देखा जा रहा है। गुजरात के कांडला बंदरगाह से केवल छह दिनों में चाबहार पहुंचा जा सकता है। वहां से रेल या सड़क के माध्यम से सामान आगे पहुंचाया जा सकता है। यही लाभ ईरान को भी होगा। भारत को ईरान से तेल, गैस और मध्य एशिया के लिए संपर्क चाहिए, ताकि पाइपलाइन के जरिए गैस लाई जा सके। मगर चाबहार बंदरगाह को लेकर भारत की दीर्घकालीन योजनाएं ईरान की जटिल धार्मिक और वैश्विक नीतियों के चलते कैसे पूरी होंगी, इसको लेकर गहरा असमंजस है।

> चाबहार बंदरगाह, वैश्विक बाजार में पहुंच बढ़ाने में भारत के लिए बहुत मददगार बन सकता है। मगर ईरान, चीन और रूस के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अमेरिका और यूरोप ईरान की ऐसी किसी भी योजना को फलीभूत नहीं होने देंगे, जिसका व्यापक लाभ उसे मिल सके। जाहिर है, चाबहार बंदरगाह के व्यापक फायदों के लिए ईरान में लोकतांत्रिक सरकार, पुतिन का पतन तथा जिनपिंग की साम्राज्यवादी आक्रामक नीतियों जैसे व्यापक परिवर्तनों की जरूरत होगी और इसकी उम्मीद फिलहाल कहीं दिखाई नहीं पड़ती।

चाबहार बंदरगाह से भारत को होने वाले फायदों के केंद्र में ईरान, अफगानिस्तान और रूस हैं। ये तीनों देश वर्तमान में कड़े वैश्विक प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। अमेरिका ने लंबे समय से तालिबान को किसी भी तरह के समर्थन को अपराध घोषित कर रखा है। ऐसे में अफगानिस्तान में काबिज तालिबान और भारत के बीच सहयोग की गुंजाइश बेहद सीमित है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस कड़े अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ-साथ आस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान सहित कई देशों ने रूस पर साढ़े सोलह हजार से अधिक प्रतिबंध लगाए हैं। रूसी बैंकों की लगभग 70 फीसद संपत्ति जब्त कर ली गई और कुछ को वित्तीय संस्थानों के लिए 'हाई स्पीड' मैसेजिंग सेवा 'स्विफ्ट' से बाहर कर दिया गया। अमेरिका और ब्रिटेन ने रूसी तेल और प्राकृतिक गैस पर प्रतिबंध लगा दिया है। यूरोपीय संघ ने समुद्री रास्ते से कच्चे तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

चाबहार बंदरगाह वाला ईरान भी गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन और परमाणु बम बनाने की कोशिशों के कारण कई वैश्विक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। फिर, ईरान की कूटनीति और भारत की स्थिति में गहरे अंतर्द्वंद्व और विरोधाभास हैं। ईरान के दो सबसे बड़े शत्रु राष्ट्र अमेरिका और इजराइल भारत के महत्त्वपूर्ण आर्थिक और सामरिक साझीदार हैं। भारत और अमेरिका व्यापक रणनीतिक भागीदार हैं और दोनों के बीच सहयोग व्यापार, रक्षा, बहुपक्षवाद, खुफिया, साइबर स्पेस, नागरिक परमाणु ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। भारत और इजराइल के बीच गहरे द्विपक्षीय आर्थिक, सैन्य और रणनीतिक संबंध हैं। रूस के बाद इजराइल भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता है। दोनों देशों के बीच सैन्य और रणनीतिक संबंध आतंकवादी समूहों पर खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण तक विस्तारित हैं।

चाबहार बंदरगाह, वैश्विक बाजार में पहुंच बढ़ाने के लिए भारत के लिए बहुत मददगार बन सकता है। मगर ईरान, चीन और रूस के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अमेरिका और यूरोप ईरान की ऐसी किसी भी योजना को फलीभूत नहीं होने देंगे, जिसका व्यापक लाभ उसे मिल सके। जाहिर है, चाबहार बंदरगाह के व्यापक फायदों के लिए ईरान में लोकतांत्रिक सरकार, पुतिन का पतन तथा जिनपिंग की साम्राज्यवादी आक्रामक नीतियों जैसे व्यापक परिवर्तनों की जरूरत होगी और इसकी उम्मीद फिलहाल कहीं दिखाई नहीं पड़ती। इसके साथ ही भारत ईरान के साथ सहयोग बढ़ाने को लेकर अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देशों से संबंध बाधित कर ले, इसकी संभावना भी बिल्कुल नहीं है।

स्पर्श की भाषा

सरस्वती रमेश

स्पर्श जिसे आम भाषा में छूना भी कहते हैं, एक जादुई क्रिया है। छूने से चट्टानी भावनाओं के विशाल हिम पिघल कर पानी हो जाते हैं। दर्द की शिलाएं टूटकर मिट्टी हो जाती हैं। अजनबीयत के धुंधलके में पहचान की किरणें फूटती हैं। नफरत की दीवारें ढहती हैं। स्पर्श से भरोसा जगता है। उम्मीद बंधती है और अंधेरे में भी रोशनी की लड़ियां जल उठती हैं, क्योंकि छूना स्नेह की मौन, लेकिन सबसे ताकतवर भाषा है। प्रेम के जिस अहसास को शब्द और भाषा कहने में असमर्थ होते हैं, उसे एक स्पर्श से बयां किया जा सकता है। प्रेम में स्पर्श का जादू कुछ ऐसा होता है कि प्रथम अहसास से उपजे भाव आजीवन स्मृति में दर्ज हो जाते है। प्रेम की नरमी शुचिता बताने के लिए महज एक मुलायम स्पर्श काफी होता है। जब मन में अथाह प्रेम भरा हो तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती। बस उस भाव में शामिल हो जाया जाए, जिनसे प्रेम है। हमारे भीतर मन में जो भी है, वह सब उस तक पहुंच जाएंगी, क्योंकि स्वर, व्यंजन से सजी भाषा मनुष्य ने बनाया है और स्पर्श की भाषा ईश्वरीय है। अपने नवजात के प्रेम में डूबी मां जब उसे अपनी गोद में समेटती है तो शिशु के जीवन का स्रोत क्या होता है?

हमारे पूर्वज भी स्पर्श के महत्त्व को अच्छी तरह जानते थे। इसलिए चरण छूकर प्रणाम और सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ससुराल से आई बेटी अपनी मां और भाभियों से 'भेंटाती' है, यानी गले मिलती है। रामकथा के मुताबिक, जैसे वन में राम के साथ उनके छोटे भाई भरत मिले थे। उस वक्त भरत का हृदय इतना विह्वल था कि वे शब्दों में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ थे। आलिंगन के स्पर्श से उन्होंने अपनी सारी पीड़ा बड़े भाई तक प्रेषित कर दी। सुबह उठकर धरती को छूकर प्रणाम करना, सूर्य को जल से अर्घ्य देना और मिट्टी में नंगे पांव चलने के पीछे भी स्पर्श का विज्ञान है। असल में शोध बताते हैं कि मिट्टी के स्पर्श से धरती की ऊर्जा पूरे शरीर में संचारित होती है।

एक नवजात से स्नेह जताने का सबसे पहला माध्यम स्पर्श ही होता है। मां की गोद पाते ही बच्चा महफूज महसूस करता है। रोता-बिलखता शिशु भी गोद में उठाते ही शांत हो जाता है। बच्चे की परवरिश में मां के स्पर्श का अहम रोल होता है। असल में मां और बच्चा स्पर्श की भाषा से ही एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं। जब एक मां शिशु की हथेलियों में अंगुली फंसाती है तो शिशु मुट्ठी भींचकर उस छुअन का प्रत्युत्तर देता है। बस यहीं से शुरू हो जाती है छुअन के अहसास की यात्रा। बच्चे बड़े हो जाएं तब भी मां स्पर्श के माध्यम से अपनी ममता जताना नहीं भूलती।

विशेषज्ञ कहते हैं कि जिन बच्चों को मां का प्यार और दुलार भरा स्पर्श मिलता है, वे मानसिक रूप से मजबूत और भावनात्मक रूप से सुलझे हुए होते हैं। जबकि मां-पिता के स्पर्श से वंचित बच्चों में नकारात्मक भावनाएं अधिक होती हैं। जर्मनी में हुए एक अध्ययन से पता चला है कि अगर मरीजों के सिर पर प्यार से हाथ फेरा जाए तो उनके स्वस्थ होने की रफ्तार बीस गुना बढ़ जाती है। यह अलग बात है कि आजकल एक दूसरे के करीब होने पर भी कोई बीमारी हो जाने की आशंका जताई जाने लगी है। जबकि चिकित्सा के मामले में स्पर्श की भूमिका पहले से सिद्ध रही है। मनोचिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों की भी राय है कि स्पर्श में जादू होता है। डाक्टर डेविड ईगलमैन के कथनानुसार, 'मनुष्यों में स्पर्श गैर-मौखिक संचार का एक शक्तिशाली माध्यम है। दैनिक जीवन में कुछ नया सीखने से लेकर किसी से संवाद करने तक स्पर्श की भूमिका काफी अहम है।'

देखा जाए तो प्रकृति में घटित होने वाली सभी घटनाएं स्पर्श की भाषा से ही संचालित होती हैं। हर सुबह धूप की चमकीली किरणें धरती का स्पर्श करती हैं तो पेड़-पौधे बढ़ने लगते हैं। फूलों की पंखुड़ियां चटखने लगती हैं। फल पकने लगते हैं। हवाएं फूलों कलियों और पत्तियों का स्पर्श कर उनकी गंध साथ में लेकर चल पड़ती हैं। इस तरह स्पर्श से जीवन चक्र चलता रहता है। एक फिल्म आई थी 'कोई मिल गया'। उसमें दूसरे ग्रह का एक प्राणी धरती पर आया दिखाया जाता है। वह धरती की भाषा और लोगों से अनजान है। जब पहली बार फिल्म का नायक उसे देखता है तो अपनी मित्रता जताने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। उसे छूते ही दूसरे ग्रह का प्राणी फौरन स्पर्श की भाषा समझ लेता है।

सच यह है कि स्पर्श के तरीके से व्यक्ति की भावनाएं स्पष्ट हो जाती हैं कि वह अच्छी भावना से छू रहा है या बुरी भावना से। छूने के तरीके से यह भी पता लगाया जा सकता है कि उसमें किस रस की प्रधानता है। प्रेम, वात्सल्य, क्रोध, भय, करुणा या घृणा। एक दृष्टिबाधित व्यक्ति छूकर ही इस दुनिया को महसूस करता है। इसके रंगों को पहचानता है। इसकी खूबसूरती को अपनी अंगुलियों के माध्यम से देखता है। कई बार किसी बेहद खूबसूरत कृति को आंखों से देखने के बाद भी हम छूकर देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारी अंगुलियों में भी अदृश्य आंखें होती हैं जो स्पर्श के माध्यम से संप्रेषण करती हैं।

दुनिया मेरे आगे

> प्रकृति में घटित होने वाली सभी घटनाएं स्पर्श की भाषा से ही संचालित होती हैं। हर सुबह धूप की चमकीली किरणें धरती का स्पर्श करती हैं तो पेड़-पौधे बढ़ने लगते हैं। फूलों की पंखुड़ियां चटखने लगती हैं। फल पकने लगते हैं। हवाएं फूलों, कलियों और पत्तियों का स्पर्श कर उनकी गंध साथ में लेकर चल पड़ती हैं।

रूस का दांव

रूस का दावा है कि उसने ताजा जमीनी हमले के दौरान यूक्रेन के खारकीव क्षेत्र में नौ गांवों पर कब्जा कर लिया है। इसी दौरान क्रेमलिन द्वारा इस बात की पुष्टि की गई कि उसने अपने पूर्व अर्थव्यवस्था सहयोगी आंद्रे बेलौसोव को नया रक्षा मंत्री बनाया है। निवर्तमान रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगू को पद से हटा दिया गया है। क्रेमलिन द्वारा इन्हें सौम्य पदावनति दी गई और सुरक्षा परिषद का प्रभारी बनाया गया है। रूसी मंत्रालयों में इस तरह के फेरबदल दुर्लभ में भी दुर्लभतम माना जाता है। दस वर्ष पूर्व जब रूस ने यूक्रेन से उसके क्रीमिया क्षेत्र को छीना, तब भी सर्गेई शोइगू ही पुतिन के करीबी रक्षा विभाग का कमान सम्हाले हुए थे। मगर अब लगता है, पुतिन यूक्रेन को लेकर परेशान हो गए हैं। ऐसा लगा था कि कुछ ही हफ्तों के आक्रमण के बाद संपूर्ण यूक्रेन रूसी सीमा क्षेत्र के अंदर समा जाएगा। मगर यह युद्ध अब तीसरे वर्ष में प्रवेश कर गया है और अब भी रूस सिर्फ पच्चीस फीसद भूमि पर ही कब्जा कर पाया है। सवाल है कि क्या इनके आने से यूक्रेन पर पलक झपकते ही क्रेमलिन का कब्जा हो जाएगा, या रूस को इस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ेगा?

- जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर

संबंधों की किरचें

भारतीय समाज परंपरावादी और सामाजिक संरचनाओं के ताने-बाने से बुना हुआ है। यहां विवाह को न सिर्फ एक आवश्यक पहलू के रूप में देखा जाता है, बल्कि इसे एक पवित्र सामाजिक बंधन भी माना जाता है। लेकिन मौजूदा समय में विवाह के बंधन की डोर कमजोर होती जा रही है और तलाक का प्रचलन काफी तेजी से बढ़ रहा है। पहले तलाक जैसे शब्द सुनने को नहीं मिलते थे, मगर आज यह शब्द, खासकर शहरी क्षेत्र में स्वाभाविक बनता जा रहा है। तलाक के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी भारतीय सामाजिक व्यवस्था के लिए एक चिंता का विषय है। युवाओं में तलाक जैसी घटनाओं के विकास के पीछे कई कारण हैं. मसलन, पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव, आपसी सूझबूझ का अभाव, एकल पारिवारिक रिश्ते, पारिवारिक व्यवस्था में बुजुर्गों की अहमियत कम होना आदि। वैवाहिक रिश्तों मे सकारात्मक सोच के जरिए तलाक जैसे मुद्दे का हल किया जा सकता है।

- विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

त्रासदी के बावजूद

पुराने दिनों को याद करें तो उस संदर्भ में विचार करें तो कुछ चिंतित करने वाली तस्वीरें और वीडियो केदारनाथ के पट खुलने के बाद सामने आईं हैं। मंदिर के सामने काफी संख्या में भीड़ का मौजूद होना चिंता का विषय है। यह चिंता इसलिए कि मानवीय हस्तक्षेप अब मैदानी इलाकों के साथ पहाड़ों पर भी होने लगा है। आस्था और श्रद्धा की आड़ में जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ देखने को मिल रहा है, वह विचलित करने वाला है। वहां मौजूद लोग शायद यह भूल रहे हैं कि अभी केदारनाथ त्रासदी को सिर्फ एक दशक हुआ है। पहाड़ों पर इतनी संख्या में लोगों के एक साथ जाने को किसी भी सूरत में नियंत्रित किया जाना चाहिए। इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, जिसके कारण ही प्राकृतिक आपदा अपना कहर बरपाती है। किसी भी धार्मिक स्थल पर आज के समय में श्रद्धाभाव से ज्यादा तो वीडियो बनाने और फोटो खींचने की ही होड़ में दिखते हैं।

- करुणा नयन चतुर्वेदी, दिल्ली विवि

निमंत्रण में नाम

भारतीय समाज में हमेशा पुरुषों के नाम पर ही आमंत्रण पत्र भेजे जाते रहे हैं। मगर हाल ही में एक परिवार ने अपने एक युवक की शादी में आमंत्रण पत्रों पर महिलाओं को प्राथमिक रूप से नाम अंकित कर ज्यादातर रिश्तेदारों को निमंत्रण पत्र भेजा। इसके लिए उस परिवार को काफी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया में थोड़े कुछ प्रयासों से ही सफलता मिल गई, जिसकी बदौलत किसी परिवार में उस महिला के नाम पर आमंत्रण पत्र पहुंचा, जिसका असली नाम उसके घर के सदस्य या करीबी रिश्तेदारों तक को पता नहीं था। ऐसे कामों का शुरुआत में कुछ लोग विरोध करते हैं, लेकिन अगर सिद्धांतों की लड़ाई पर टिके रहा जाए, तो बाद में सबको स्वीकार करना पड़ता है और बाद में यह भी संभव है कि इसका महत्त्व समझा जाए और ऐसा करने वालों को सराहा जाए।

दिनेश शाह, सिंगरौली, मप्र

www.readwhere.com

चिंतन

नव आर्थिक सुधार के बिना समावेशी विकास संभव नहीं

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (पीएमईएसी) के सदस्य संजीव सान्याल ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार को लेकर जो अगले वित्त वर्ष में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान जाहिर किया है, वह वास्तविता के करीब ही है। लेकिन अर्थव्यवस्था के आकार से समावेशी विकास और गरीबी उन्मूलन का कोई ताल्लुक नहीं है। अर्थव्यवस्था के आकार बढ़ने का मतलब विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने से भी नहीं है। कोविड उपरांत की अर्थव्यवस्था के सामने अनेक चुनौतियां भी हैं, जो भारत के विकसित देश बनने की राह की कांटें हैं। पीएमईएसी के मुताबिक, भारत वित्त वर्ष 2024-25 में 4,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था होगा और अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अभी भारत पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्ष 2027 तक भारत आकार के हिसाब से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके बावजूद भारतीय अर्थवयवस्था के सामने बुनियादी चुनौतियां बनी रहेंगी। प्रति व्यक्ति वार्षिक आय, मानव विकास सूचकांक, विश्व गरीबी सूचकांक, हर व्यक्ति तक शिक्षा व स्वास्थ्य की पहुंच, स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, गरीबी उन्मूलन, सबके लिए रोजगार, आर्थिक आत्मनिर्भरता आदि मानक हैं, जिनमें भारत की स्थिति एक लोअर मिडिल इनकम वाले देश की है। महज 23 वर्ष की अवधि में इन सभी मानदंडों पर खरा उतरना आसान नहीं है। वैश्विक वित्तीय संस्थान डेलायट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अगर अगले 20 वर्ष तक लगातार 8-9 फीसदी दर से जीडीपी ग्रोथ करेगा, तभी वर्ष 2047 तक विकसित देश बनने का लक्ष्य हासिल कर सकेगी। विकसित राष्ट्र बनने के लिए अर्थव्यवस्था के आकार बढ़ने के साथ मानवीय विकास के दूसरे सूचकांकों में भी बेहतर परिणाम हासिल करना होता है। पीएमईएसी के मुताबिक, कमजोर निर्यात समेत विभिन्न चुनौतियों को देखते हुए देश के लिए सात प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर अच्छी वृद्धि दर होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा था कि भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बाजार मूल्य पर भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 3,700 अरब डॉलर है। जापान अभी 4,100 अरब डॉलर के साथ हमसे थोड़ा ही आगे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार चुनाव संबोधनों में भारत के तीसरी अर्थव्यवस्था बनने और वर्ष 2047 तक विकसित देश बनने की बात दोहराते रहते हैं, लेकिन सरकार इसके लिए कभी कोई रोडमैप पेश नहीं करती है। अगर अर्थव्यवस्था की तरलता सब्सिडी व सरकारी योजनाओं पर निर्भर हो, अगर बैंकों में बचत जमा में कमी आ रही हो, पांच किलो मुफ्त राशन व अन्य मुफ्त स्कीमों से अगर सरकार बड़ी आबादी को आश्रित बना रही हो, तो अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भरता का लक्ष्य कैसे हासिल करेगी? एशियाई विकास बैंक और फिच रेटिंग्स ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। भारत का मौजूदा आर्थिक परिदृश्य वैश्विक तुलना में इंप्रेसिव है, लेकिन जब नई सरकार बनेगी, तो उसके सामने अर्थवयवस्था में सुधार की अनेक चुनौतियां होंगी। भारत को आर्थिक सुधार के अगले स्ट्रक्चरल व नीतिगत चरण में प्रवेश करने की जरूरत है।

विश्व उच्च रक्तचाप दिवस

आर.पी. पराशर

हाइपरटेंशन से बचाव के लिए एक्टिव जीवनशैली अपनाएं

उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन का अर्थ है धमनियों में रक्त प्रवाह का तेज हो जाना। जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लगातार 140 से ऊपर व डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से ऊपर रहे तो इसे हाइपरटेंशन कहा जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इस समय पूरे विश्व में हाइपरटेंशन के 130 करोड़ मरीज हैं जिनमें से 22 करोड़ अकेले भारत में ही हैं। दुनिया भर में हर साल एक करोड़ से अधिक मौतें हाइपरटेंशन के कारण हो जाती हैं। भारत में कुल होने वाली मौतों की 63% मौतें गैर संक्रामक रोगों के कारण होती हैं, जिनमें से 27 प्रतिशत हृदय रोगों के कारण होती हैं। देश में हाइपरटेंशन के मामलों में 25% तक कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित कर विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च व भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव की शुरुआत 2017 में की गई थी। गत 18 मार्च 2024 को इंटरनेशनल जनरल ऑफ पब्लिक हाइजीन में छपी आईसीएमआर की स्टडी के अनुसार देश में 15.9% लोग हाइपरटेंशन के शिकार हैं, जबकि 33.7% लोग प्री- हाइपरटेंशन की स्टेज में हैं। यह स्टडी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंतर्गत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 707 जिलों से लिए गए आंकड़ों के आधार पर की गई थी। हाइपरटेंशन के मरीजों के बारे में सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि देश में मात्र 12% हाइपरटेंसिव मरीजों का ब्लड प्रेशर नियंत्रण में है। इससे बचाव के उपायों और इलाज के बारे में लोगों को जागरूक और शिक्षित कर न केवल हाइपरटेंशन का इलाज कर लोगों को मौत से बचाया जा सकता है, बल्कि देश की 33.7 आबादी जो इस समय प्री हाइपरटेंसिव स्टेज में है, को हाइपरटेंशन से बचाया जा सकता है। हाइपरटेंशन से बचाव और इलाज के लिए दवा से भी महत्वपूर्ण है स्वस्थ जीवन शैली अपनाना। नियमित रूप से व्यायाम, योग, ध्यान के साथ-साथ हेल्दी फूड हाइपरटेंशन से बचाव और सफल इलाज के लिए अति आवश्यक हैं। हाइपरटेंशन होने के मुख्य कारण जंक फूड, फास्ट फूड, डिब्बाबंद फूड, प्रोसेस्ड फूड के अलावा गरिष्ठ व अधिक नमक, चीनी वसायुक्त भोजन का लगातार सेवन, व्यायाम का

अभाव तथा तनाव, चिंता, अवसाद जैसी मानसिक स्थिति का लगातार बने रहना। हाइपरटेंशन से बचाव और इलाज के लिए जरूरी है कि हम अपने आहार विहार और जीवन शैली में उपरोक्त कारणों को मद्देनजर रखते हुए परिवर्तन करें। आयुर्वेद के मतानुसार हाई ब्लड प्रेशर दो तरह के दोषों पित्त और वात की वजह से होता है। इसलिए हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में आयुर्वेदिक औषधियों की मदद से इन दोषों को ही संतुलित करने का प्रयास किया जाता है। सर्पगंधा, जटामांसी, पुनर्नवा, ब्राह्मी, वच, शंखपुष्पी आदि आयुर्वेदिक औषधियां हाइपरटेंशन के उपचार में मदद करती है। इसके अलावा तुलसी, पुनर्नवा, गुलकंद, तगर आदि दवाएं दिमाग की शांति के लिए उपयोगी हैं। मूड सही करने तथा तनाव को दूर करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है।

हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए शाकाहार सबसे अच्छा उपाय है। खीरा, तरबूज, खरबूज, अजवाइन, करेला और लहसुन को अपनी डाइट में शामिल करें तो हाइपरटेंशन में काफी आराम मिलेगा। टमाटर, खीरा, चुकंदर, संतरा, तरबूज व खरबूजे का जूस हाइपरटेंशन के इलाज के लिए फायदेमंद है। वनस्पति घी का प्रयोग कम मात्रा में करें, रिफाइंड तेल का प्रयोग बिल्कुल न करें। चाय, कॉफी, आदि कैफीन उत्पादों से परहेज करना हाई बीपी के मरीजों के लिए बेहद जरूरी है। हाइपरटेंशन के मरीज शराब व धूम्रपान को पूर्णतया त्याग दें। भोजन में नमक की मात्रा 1500 मिलीग्राम से 2300 मिलीग्राम प्रतिदिन से अधिक नहीं से अधिक नहीं होनी चाहिए। चूंकि नमक में विद्यमान सोडियम ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है इसलिए सोडियम के बजाय पोटेशियम युक्त खाद्य पदार्थो का प्रयोग करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, केला, संतरा, आलू, शकरकंदी, ड्राई फ्रूट, सब्जियों और फलों के बीच पोटेशियम के अच्छे स्त्रोत माने जाते हैं। हाइपरटेंशन से छुटकारा पाने के लिए नियमित रूप से व्यायाम, योग व ध्यान करना बेहद जरूरी है। सप्ताह में कम से कम 150 मिनट वॉकिंग, जॉगिंग, डांसिंग जैसी एरोबिक एक्सरसाइज व्यक्ति को हाइपरटेंशन से बचाए रखने में मददगार है। योग में ध्यान के नियमित अभ्यास से तनाव से मुक्ति पाई जा सकती है। पंचकर्म की स्नेहन, स्वेदन, विरेचन, वमन और शिरोधारा जैसी थेरेपी सहयाक है।

(लेखक मनोचिकित्सक एवं आयुर्वेद विशेषज्ञ, सीएमओ (आयुर्वेद), दिल्ली नगर निगम हैं।)

पहाड़ों पर बढ़ती भीड़ यानि आपदा की आहट

विचार

डॉ. संजय शुक्ला

उत्तराखंड के केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पट खुलने के बाद ही चारधाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ के चलते सरकारी व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। आलम यह है कि इस यात्रा के प्रवेश द्वार हरिद्वार से 170 किलोमीटर आगे बारकोट तक 45 किमी लंबा जाम है तो दूसरी ओर गंगोत्री-यमुनोत्री मार्ग पर हालात काफी बदतर हैं जिसमें हजारों श्रद्धालु 25 घंटे से फंसे होने का समाचार है। आलम यह है कि रास्ते में फंसे श्रद्धालु जहां हाड़ कंपाने वाली ठंड में सड़कों पर रात गुजारने के लिए मजबूर हैं वहीं लोगों को भोजन और पानी के लिए काफी जद्दोजहद करना पड़ रहा है। दूसरी ओर आपदा में अवसर ढूंढने वालों की भी कमी नहीं है वे श्रद्धालुओं से टैक्सी और खाने- पीने की चीजों के लिए दोगुनी - तिगुनी कीमतें वसूल रहे हैं। खबरों के मुताबिक यमुनोत्री - गंगोत्री मार्ग में जाम में फंसे 12 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। चारधाम यात्रा के पहाड़ों पर हजारों वाहनों और श्रद्धालुओं के बोझ के चलते भूस्खलन का खतरा भी मंडरा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में 44 फीसदी तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। पिछले साल 2023 में विपरीत मौसम और कोरोना प्रोटोकॉल के बावजूद जहां 54 लाख श्रद्धालुओं और पर्यटकों ने चारधाम यात्रा किया वहीं इस साल यह संख्या 80 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। गौरतलब है कि जैसे - जैसे पर्यटकों और श्रद्धालुओं की भीड़ इन इलाकों में बढ़ रही है वैसे-वैसे सरकार भी लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए विकास योजनाओं को बढ़ावा दे रही है।

केंद्र सरकार चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए ऑलवेदर रोड बना रही है लेकिन इससे पहाड़ कमजोर होने लगे हैं। दरअसल पहले लोग चारधाम यात्रा में आध्यात्मिक भाव लेकर जाते थे लेकिन अब एक बड़ा तबका इन स्थानों में सैर-सपाटे के लिए जा रहे हैं फलस्वरूप पहाड़ों पर ऐसे लोगों की भीड़ बढ़ रही है जिनका उद्देश्य धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि मौज-मस्ती करना है। बीते कुछ सालों के दौरान सोशल मीडिया में अपना फालोवर्स बढ़ाने के सनक के चलते 18 से 25 साल के यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया यूजर्स की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है जो हिमालय के वादियों में बसे चारधाम के खूबसूरत वादियों और धार्मिक माहौल का रील्स बनाने के उद्देश्य से पहाड़ों पर आ रहे हैं। इस तीर्थ क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई किया है जिन्होंने शराब या किसी अन्य मादक पदार्थों का सेवन किया हुआ था। इस साल अभी तक पुलिस ने 30 लोगों के खिलाफ नशाखोरी का मामला दर्ज कर चालानी की कार्रवाई की है।दूसरी ओर चारधाम में ऐसे श्रद्धालुओं के तादाद भी हर साल बढ़ रहे हैं जो ढोल - नगाड़ों के तेज आवाज में शोर शराबे के साथ भक्ति गीत पर नृत्य करते हैं। बीते 10 मई को केदारनाथ में ऐसे ही कुछ ग्रुप्स का पुरोहितों और श्रद्धालुओं ने विरोध किया है। बहरहाल ऐसे गतिविधियों से जहां देवस्थानों के मंदिरों की मर्यादा भंग हो रही है वहीं हिमालय के पर्यावरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। गौरतलब है कि अनेक पर्यावरणविदों ने चेतावनी दी है कि उत्तराखंड का यह क्षेत्र डेंजर जोन की श्रेणी में आता है और यहां कि चट्टानें बहुत नाजुक हैं जो किसी भी भारी आवाज से दरक सकते हैं लेकिन मौज- मस्ती करने वालों पर इस चेतावनी का कोई असर नहीं पड़ रहा है। बहरहाल यह हर धर्मावलंबी की जवाबदेही है कि वह अपने धार्मिक केंद्रों की मर्यादा और शुचिता के प्रति गंभीर हो और इसके लिए उन्हें आत्म अनुशासित होना होगा।

अलबत्ता हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र मनुष्य के लिए सदैव ही आस्था और आकर्षण का केंद्र रहा है हिंदू धर्म के अलावा अनेक धर्मों के प्रमुख तीर्थस्थल इन्हीं पहाड़ों पर हैं तो हिमालय के तराई की सुरम्यता सैलानियों को बहुत लुभाती भी है।वैश्विक महामारी कोरोना के बाद उत्तराखंड में चारधाम यात्रा केदारनाथ, गंगोत्री, यमनोत्री, बद्रीनाथ, जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ तीर्थक्षेत्र एवं वैष्णो देवी सहित हिमाचल प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों के धार्मिक और पर्यटक शहरों में श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों की भीड़ में लगातार इजाफा हो रहा है। इन तीर्थस्थलों और पर्यटन स्थलों पर खासकर गर्मियों और सर्दियों की छुट्टियों में इन स्थानों में लोगों की काफी भीड़ होती है। श्रद्धालुओं और सैलानियों की भारी भीड़ के चलते पहाड़ों और सड़कों पर घंटों वाहनों की लंबी-लंबी कतारें घंटों तक जाम में फंसने की खबरें अब आम हो चुकी है। हाल के वर्षों में पहाड़ों पर विकास योजनाओं और क्षमता से ज्यादा मानव बसाहट के चलते पहाड़ी इलाकों में लगातार आपदाएं बढ़ रही है। देश अभी भी 2013 में देवभूमि उत्तराखंड के केदारनाथ में हुए जल तांडव को नहीं भूला है। गौरतलब है कि 16 जून की रात केदारनाथ मंदिर के पीछे ग्लेशियर पर बादल फटने और उसके बाद आई भीषण बाढ़ ने केदारनाथ में भारी तबाही मचाई थी जिसमें 5000 लोगों की मौत हो गई वहीं हजारों लोग आज भी लापता हुए थे और 4500 गांव तबाह हो गए थे। उत्तराखंड यह मंजर भूला भी नहीं था कि 7फरवरी 2021 को चमोली जिले के रैणी गाँव के पास ऋषिगंगा घाटी में ग्लेशियर टूटने से हुई भारी तबाही हुई है।इस हादसे में 60 लोगों की मौत तथा लगभग 150 लोग लापता हुए थे।इस त्रासदी में अलकनंदा की सहायक नदियों धौलीगंगा और ऋषिगंगा के जलप्रलय ने दो हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट ऋषिगंगा और विष्णुगढ़ को तबाह कर दिया था। साल 2023 में भी उत्तराखंड में कुदरती हादसों ने एक बार फिर मनुष्य को चेताया है कि अब पहाड़ों का सब्र टूट रहा है। इस साल जोशीमठ में जमीन धंसने और घरों व सड़कों पर बड़ी - बड़ी दरार आने के फलस्वरूप प्रशासन को शहर खाली कराना पड़ा वहीं सिलक्यारा - बारकोट सुरंग धसकने से 41 मजदूरों का जान सांसत में आ गया था और उन्हें कई दिनों के जद्दोजहद के बाद बचाया जा सका।

विचारणीय है कि मानव सभ्यता का विकास प्रकृति के गोद में हुआ है लेकिन उसने सबसे ज्यादा असभ्यता कुदरत के साथ ही दिखाई है। आधुनिक विकास की अंधी दौड़ हमारी सभ्यता, संस्कृति के साथ प्रकृति को भी लगातार निगल रही है।विकास का सपना शुरू में बड़ा लुभावना लगता है लेकिन जब यह विनाश बनकर प्रकट होता है तो वह प्रलयंकारी और भयावह होता है।

दरअसल उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर सहित अन्य पहाड़ी राज्यों के सरकारों ने आर्थिक विकास के लिए पर्यटन उद्योग तथा पनबिजली संयंत्रों को प्राथमिकता में शामिल कर लिया है। आलम यह है कि इन राज्यों में पन बिजली संयंत्र के लिए नदियों के अविरल प्रवाह को रोककर,पहाड़ों को खोदकर टनल, बैराज,पुल, पावर प्रोजेक्ट , कृत्रिम पर्यटन स्थल बनाए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं और पर्यटकों के सुगम यातायात और आवास के लिए इन इलाकों के पहाड़ों को काटकर सड़कें बनाई जा रही है अथवा चौड़ी की जा रही हैं। तमाम पर्यावरणीय कानूनों को धता बताकर होटल, रिसॉर्ट, रोपवे और कृत्रिम पर्यटन स्थलों का निर्माण किया जा रहा है। यातायात दबाव से भी पहाड़ का परिस्थिकीय तंत्र बिगड़ रहा है। दैत्याकार क्रेन और भारी निर्माण उपकरण पहाड़ों को खोद रहे हैं, चट्टानी सीने को बारुद के विस्फोटों से तोड़ा जा रहा है।नदियों में बेतहाशा रेत खनन हो रहा है, नदियों के मुहाने पर क्रशर प्लांट लगा दिया गया है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है फलस्वरूप पहाड़ों की मिट्टी बांधकर रखने की क्षमता कमजोर हो रही है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंट्रीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की रिपोर्ट में कहा गया है कि हिमालयन क्षेत्र के ग्लेशियर बड़ी तेजी से टूट रहे हैं, ग्लेशियरों को जोड़े रखने के लिए सब-जीरो टेंपरेचर की जरूरत है। प्रकृति के साथ निर्ममता के कारण हिमालयन क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग का खतरा लगातार बढ़ रहा है फलस्वरूप बादल फटने जैसी घटनाएं बढ़ रही है। हिमालय इस समय बीते 20 सालों में सबसे गर्म है। अलबत्ता पहाड़ों के प्रति अनुदारता के लिए आम नागरिक भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। हिमालय क्षेत्र में चारधाम यात्रा सहित अन्य पर्यटन स्थलों में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के वाहनों के धुएं और हार्न उस इलाके में वायु और ध्वनि प्रदूषण फैला रहे हैं तो दूसरी ओर लोगों द्वारा हर महीने हजारों टन प्लास्टिक कचरा जिसमें प्लास्टिक बोतल, पॉलिथीन बैग, शीतल पेय के केन, स्ट्रा, चिप्स एवं अन्य खाद्य पदार्थों के पैकेट और अन्य डिस्पोजेबल सामान पहाड़ों, जंगलों या नदियों में फेंक दिए जाते हैं। एक एनजीओ "हीलिंग हिमालय" के प्रदीप सांगवान बताते हैं कि हिमालयन क्षेत्र के पर्यटन स्थलों से वे रोज 1.5 टन गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा इकट्ठा करते हैं। गौरतलब है कि ये प्लास्टिक कचरे हिमालय के तापक्रम को बढ़ाते हैं जिससे ग्लेशियर पिघलता है फलस्वरूप यहां आपदाओं की आशंकाएं बढ़ जाती है। इन परिस्थितियों में मानव समाज और सरकार को अपने व्यवहार और कार्यप्रणाली में पहाड़ों, नदियों और जंगलों को विमर्श लाना ही होगा अन्यथा प्रकृति का सब्र टूटेगा तो पहाड़ों पर त्रासदियां आती रहेंगी जिसका खामियाजा अंततोगत्वा मनुष्य को ही चुकाना होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

संपत्ति को परमार्थ में न लगाना ही असफलता

संकलित

दर्शन

संतोष सभी गुणों में सर्वोपरि है। जीवन में संतुष्टि है, तो सद्गुणों को अपनाना सहज है। जहां सद्गुणों का वास है, वहां दुर्गुणों का नाश हो ही जाता है। क्योंकि, असंतुष्टि अशांति व अवगुणों की जननी है। असंतुष्टि का कारण अप्राप्ति है, किसी न किसी इच्छा या अपेक्षा की अपूर्ति है। ईश्वरीय ज्ञान, गुण व शक्तियों की प्राप्ति, धारणा व उपार्जन से इंसान की सभी सदिच्छाओं व आवश्यकताओं की सहज पूर्ति हो जाती है। संतुष्ट आत्मा बनने का अर्थ है सदा सत्य और सदाचार के मार्ग पर चलना। संतोष द्वारा सर्व दिव्य गुणों का आह्वान होता है, जिससे सर्व अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाती है। जीवन में अप्राप्ति या असंतुष्टि का कारण अंदर की कमियां या कमजोरियां ही हैं, जो परमात्म ज्ञान और योग साधना की प्राप्तियों से दूर हो जाती हैं। जिन्हें सर्व प्राप्तियां हैं, उसके चिह्न उनके मुख और व्यक्तित्व में प्रसन्नता के रूप में दिखाई देते हैं। आजकल लोगों के चेहरे पर सदा प्रसन्नता की झलक देखने को नहीं मिलती है। इंसान कभी प्रसन्नचित्त है तो और कभी प्रश्नचित्त बन जाता है। किसी भी परिस्थिति में हम क्यों, क्या, कैसे, कब... जैसे प्रश्नों से प्रश्नचित्त बन जाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो सदा प्रसन्नचित्त होते हैं। उनकी किसी भी बात में प्रश्न नहीं होता है। जो प्राप्तियों से सम्पन्न होता है, उसमें हलचल नहीं होती है। जो खाली होता है, उसमें हलचल होती है। स्वयं से पूछिए कि क्या मैं सदा प्रसन्नचित्त रहता या रहती हूं? यदि प्रसन्नता कम होती है तो उसका कारण प्राप्ति की इच्छा है।

मन की शांति कैसे प्राप्त करें?

संकलित

प्रेरणा

सेठ अमीरचंद को हर पल कोई न कोई चिंता परेशान किये रहती थी। एक दिन वह कहीं जा रहा था तो रास्ते में उसकी नजर एक आश्रम पर पड़ी। वहाँ उसे किसी साधु के प्रवचनों की आवाज सुनाई दी। उस आवाज से प्रभावित होकर अमीरचंद आश्रम के अन्दर गया और बैठ गया। प्रवचन समाप्त होने पर सभी व्यक्ति अपने अपने घर को चले गये। लेकिन वह वही बैठा रहा। उसे देखकर संत बोलेः कहो, तुम्हारे मन में क्या जिज्ञासा है, जो तुम्हें परेशान कर रही है। इस पर अमीरचंद बोलाः बाबा, मेरे जीवन में शांति नहीं है। यह सुनकर संत बोलेः घबराओ नहीं तुम्हारे मन की सारी अशांति अभी दूर हो जायेगी। संत की बात सुनकर ज्यों ही अमीरचंद ध्यान की मुद्रा में बैठा त्यों ही उसके मन में इधर-उधर की बातें घूमने लगीं और उसका ध्यान उचट गया। सेठ बोलाः चलो, जरा आश्रम का एक चक्कर लगाते हैं। अमीर चंद ने एक सुंदर वृक्ष देखा तथा उसे हाथ से छुआ। हाथ लगाते ही उसके हाथ में एक कांटा चुभ गया और सेठ। बुरी तरह चिल्लाने लगे। यह देखकर संत वापस अपनी कुटिया में आए। कटे हुए हिस्से पर लेप लगाया। कुछ देर बाद वह सेठ से बोलेः तुम्हारे हाथ में जरा-सा कांटा चुभा तो तुम बेहाल हो गए। सोचो कि जब तम्हारे अन्दर ईर्ष्या, क्रोध व लोभ जैसे बड़े-बड़े कांटे छिपे हैं, तो तुम्हारा मन भला शांत कैसे हो सकता है ? संत की बात से सेठ अमीरचंद को अपनी गलती का अहसास हो गया। वह संतुष्ट होकर वहां से चला गया। उसके बाद सेठ अमीरचंद ने कभी भी ईर्ष्या नहीं की, क्रोध का भी त्याग कर दिया।

अंतर्मन

आज की पाती

टूटते परिवारों के लिए जिम्मेवार कौन?

दुनियाभर में परिवार के महत्व को समझाने और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र जनरल एसेंबली ने सन 1993 को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने की घोषणा की थी। अब हर वर्ष 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। बेशक इस दिवस की शुरुआत विदेश से हुई है, लेकिन हमें दूसरे देशों की अच्छी बातों को ग्रहण करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए और न ही यह तर्क देना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस हमारे देश की परंपरा नहीं है। परिवार का महत्व क्या है, इसकी अहमियत हमारे देश में बहुत ज्यादा है। हमारे देश में तो सारी पृथ्वी को अपना परिवार समझा जाता है, तभी तो हमारे देश में कहा जाता है 'वसुधैव कुटुम्बकम।'

- संतोष देवांगन, कुम्हारी

ट्रेंड

जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे

स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर गोलीबारी की खबर से गहरा सदमा लगा। मैं इस कायरतापूर्ण और कायरतापूर्ण कृत्य की कड़ी निंदा करता हूं और पीएम फिको के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। भारत स्लोवाक गणराज्य के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है।

-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

हमारी कर्मभूमि

रायबरेली और अमेठी हमारी कर्मभूमि है, जिसका कोना कोना पीढ़ियों की यादें संजोए हुए है। मां के साथ पुरानी तस्वीरें देखकर पापा और दादी की याद भी आ गयी, जिनकी शुरू की गयी सेवा की परंपरा मैंने और मां ने आगे बढ़ाई।

-राहुल गांधी, कांग्रेस नेता

सच्ची लड़ाई

जीवन की सच्ची लड़ाई यह है : विलुप्त होने वाले लोग जो संपूर्ण मानवता का विनाश चाहते हैं। वे किसी को कुछ नहीं समझते - बनाम -विस्तारवादी जो सितारों तक पहुंचना चाहते हैं और ब्रह्मांड को समझना चाहते हैं। वे पूरी कायनात को देखना चहाते हैं।

-एलन मस्क, उद्योगपति

लूटने आते हो

इस दुनिया में मज़े मारने नहीं आते हैं आप, लुटने आते हो। ये जगत है ही इसीलिए कि हमको मूर्ख बना-बनाकर हमें लूटता जाए। एक-एक चीज, एक-एक व्यवस्था, आप जिसमें शामिल हैं, आप अगर देख पाएं तो दिखेगा कि कैसे आपका शोषण होता है।

-आचार्य प्रशांत, आध्यात्मिक गुरु

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

करंट अफेयर

चीन और कंबोडिया में 15 दिवसीय सैन्य अभ्यास शुरू

कंबोडिया पर बढ़ते चीन के प्रभाव को लेकर उठ रहे सवालों के बीच दोनों देशों ने बृहस्पतिवार को 15 दिवसीय सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। कंबोडिया के लगभग 1,315 सैन्यकर्मी और चीन के 760 सैन्यकर्मी थल और जल सैन्याभ्यास 'गोल्डन ड्रैगन' में भाग ले रहे हैं। इसके अलावा चीन के तीन और कंबोडिया के 11 पोत भी इसका हिस्सा हैं। पहले चरण का अभ्यास कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह के उत्तर पश्चिम में लगभग 90 किलोमीटर दूर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में सैन्य अड्डों पर शुरू किया गया है। कंबोडिया की सेना के कमांडर इन चीफ जनरल वोंग पिसेन ने नए उपकरण उपलब्ध कराने और रीम नामक नौसैनिक अड्डे समेत अन्य सैन्य सुविधाओं को उन्नत बनाने में मदद करने के लिए चीन को धन्यवाद दिया। अमेरिका और अन्य देश इस बात को लेकर चिंचित हैं कि रीम पर एक गोदी के निर्माण में चीन की भागीदारी से यह थाईलैंड की खाड़ी पर चीन की नौसेना के लिए नयी निगरानी चौकी बन सकता है। इसके अलावा, चीन के युद्धपोत पांच माह से अधिक समय से गोदी पर खड़े होने से अमेरिका और अन्य देशों की चिंताओं को बल मिला है।

ऑफ बीट

हमारे शरीर में स्थित खून का रंग लाल क्यों होता है

रक्त हमारे शरीर के भीतर होता है, लेकिन जब हमें रक्तस्राव होता है तो हम इसे बाहर देखते हैं, जैसे कि जब हमें कट लगता है या नाक से खून बहता है।

रक्त हीमोग्लोबिन नामक वस्तु के कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन लाल होता है और यह हमारे रक्त को लाल बनाता है। लेकिन हीमोग्लोबिन किस काम के लिए होता है? दरअसल, हमें अपने रक्त में ऑक्सीजन ले जाने के लिए हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है। यह थोड़ा जटिल लग सकता है, तो आइए अधिक बारीकी से देखें कि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों है, और हमें अपने रक्त में ऑक्सीजन ले जाने के लिए हीमोग्लोबिन की आवश्यकता क्यों है। हर किसी को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हमारे शरीर को काम करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हमारा शरीर लाखों-करोड़ों छोटी-छोटी कोशिकाओं से बना है। हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं को जिस हवा में हम सांस लेते हैं उससे ऑक्सीजन और हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कोशिकाएं ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का उपयोग करती हैं ताकि वे अपना काम कर सकें।

https://t.me/AllNewsPaperPaid